वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
पांचवां अंक

भारतीय रिज़र्व बैंक

जून 2012

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट का फीडबैक **fsu@rbi.org.in** पर दिया जा सकता है।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा एल्को कार्पोरेशन,ए 2/73, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई 400013 में मुद्रित।

प्रस्तावना

यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो इस श्रृंखला में पांचवीं रिपोर्ट है, चिंताजनक वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि में प्रकाशित की जा रही है। ऋणों की चुकौती में सार्वभौमिक असफलता के बारे में चिंताएँ और यूरो आर्थिक क्षेत्र में बैंकों को पर्याप्त रूप से दोबारा पूँजी प्रदान करने की आवश्यकताओं से सब तरफ फैलती मंदी के बारे में भय बढ़ता ही जा रहा है। भले ही, सरकारें अपने व्यय में कटौती करें, फिर भी मितव्ययिता के संबंध में व्यापक विरोध तथा बेरोजगारी पैदा होने के इस दौर में उठाये गये अन्य कठिन उपायों से बहुत से नीतिविदों को अपने पदों से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व भर में लोकतंत्र में रहते हुए निर्णय लेना राजनैतिक ध्रुवीकरण का बंधक बन चुका है। ऐसा लगता है कि वित्तीय प्रणाली में विश्वास कम हो गया है तथा निवेशक जोखिम लेने में कतरा रहे हैं।

घरेलू मोर्चे पर, धीमी गति में हो रही वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति एवं राजकोषीय और चालू खाते में हो रहा भारी घाटा गंभीर चिंता के विषय बने हुए हैं। पहले से ही हो रहे भारी राजकोषीय घाटे की वजह से सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को गति देने की गुँजाइश बहुत कम रह गयी है । चालू खाते में हो रहे घाटे को ऋणों की मात्रा बढ़ा कर पूरा किया जा रहा है जिससे आनेवाले लंबे समय तक इसे बरकरार रखना कठिन बनता जा रहा है।

इसके सकारात्मक पक्ष की ओर देखें तो हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में जो गिरावट आयी है वह यदि बनी रहती है तो इससे कुछ राहत मिल सकती है। मानसून के सामान्य बने रहने की संभावना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतरनिहित मजबूती की वजह से वृद्धि को अपेक्षित गति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते घाटे को कम करने के लिए यथोचित नीतिगत उपाय किये जाएँ और निवेश के लिए उचित माहौल बनाया जाए। साथ ही, विशेषकर परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के संबंध में कुछ नकारात्मक संकेतों के बावजूद भारतीय वित्तीय क्षेत्र मजबूत एवं लचीला बना रहा। इस माहौल में बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी लगातार बनी रही और उनका स्तर स्वस्थ बना रहा।

इन अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों के माध्यम से रिज़र्व बैंक की अपेक्षा है कि वह विवेकपूर्ण व्यापक निगरानी में निकले निष्कर्षों के बारे में बाजार के साथ चर्चा करे, इसके बारे में चर्चा-परिचर्चा को प्रोत्साहन दे, प्रणाली की कमजोरियों के संबंध में जागरुकता पैदा करे यहाँ तक कि तत्परता के साथ सुधारात्मक कदम उठाए। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों की तरह ही, रिपोर्ट के इस अंक में भी वित्तीय स्थिरता में आने वाले संभाव्य जोखिमों के संबंध में वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद की उप समिति (एफएसडीसी) के समेकित मूल्यांकन भी शामिल किए गए हैं।

जैसे दुनिया की हर माँ हमेशा कहती आयी है कि 'अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं है'। यही उक्ति पहले केंद्रीय बैंकरों के बारे में भी लागू होती थी। लेकिन अब आज के माहौल में यह उक्ति निरर्थक सिद्ध हो गयी है। आज के माहौल में केंद्रीय बैंकरों और विनियामकों को यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी कि वे एक तरफ वास्तविकता का एकदम स्पष्ट और सही सही चित्र तो प्रस्तुत करें लेकिन उसके बारे में कोई अनावश्यक चिंता का माहौल न पैदा करें। रॉबर्ट शिलर ने 'सेंट्रल बैंक्स एंड देयर रोल इन ए गुड सोसायटी' नामक अपनी हाल ही की पुस्तक के बारे में केंद्रीय बैंकिंग जर्नल में प्रकाशित अपने साक्षात्कार में कहा है कि 'इसका सीधा संबंध केंद्रीय बैंक की नीति के मूलभूत प्रश्न से है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे जब भी कुछ सख्त कदम उठाते हैं तब उनकी आलोचना होती है। वे जब भी कुछ बात कहते हैं तब उससे बाजार में ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि कुछ खतरे की संभावना है। जब केंद्रीय बैंक अल्पावधि स्थिरता के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ही ऐसा लगता है कि वे कुछ इस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि वे समय समय पर भड़काउ बयान दे रहे हैं।'

हमारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रयास यह रहा है कि हमें जो जानकारी उपलब्ध है उसे और बेहतर तरीके से स्पष्ट करे और जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में संकेत दे। लोगों को समस्या के बारे में जागरुक कराने मात्र से ही उसकी तीव्रता बहुत कम होती जाती है। अर्थात, चेतावनी या खतरे की समय पर घंटी बजा देना ही बहुत महत्व रखता है। फ्रेंच उपन्यासकार मार्गरिट यूअर्सनर ने तो कहा ही है कि 'आवश्यकता से अधिक सतर्क रहना भी गलत है।'

डॉ. डी. सुब्बाराव
28 जून, 2012

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
प्रस्तावना		
संक्षिप्ताक्षरों की सूची		**i-ii**
विहगावलोकन		**1**
अध्याय I	**: मैक्रोइकोनोमिक जोखिम**	**6**
अध्याय II	**: वित्तीय बाजार**	**15**
अध्याय III	**: वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता और लचीलापन**	**21**
अध्याय IV	**: वित्तीय क्षेत्र विनियमन और इन्फ्रास्ट्रक्चर**	**39**
अध्याय V	**: प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन**	**51**
	प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	51
	प्रणालीगत चलनिधि संकेतक	53
	वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क विश्लेषण	54
	बैंकिंग स्थिरता उपाय तथा होनेवाली कमी का अनुमान	58
	बृहत् तनाव परीक्षण	60
अनुलग्नक: कार्य-प्रणाली		**64**

बाक्स की सूची

2.1	ग्रीस की अनिश्चितता	16
3.1	पावर तथा एयरलाईन : दबाव वाले क्षेत्र	27
3.2	चुनिन्दा बैंकों के डिरेवेटिव पोर्टफोलियो दबाव परीक्षण	30
3.3	गोल्ड ऋण कंपनियां और एसोसिएटेड जोखिम	31
4.1	भारत में बैंकों के लिए गतिशील (डाइनैमिक) ऋण हानि प्रावधानीकरण प्रारंभ करना	41
4.2	विदेशी मुद्रा बाजार और सीसीआइएल के यूएस डॉलर/ भारतीय रुपया निपटान में वर्धित अस्थिरता	44
5.1	बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क सांख्यिकी	56
5.2	बृहत तनाव परीक्षण - क्वांटाइल रिग्रेशन अभिगम	61

चार्ट की सूची

1	वित्तीय स्थिरता मैप	1
1.1	मैक्रोआर्थिक जोखिम मैप	6
1.2	2012 में वैश्विक सुधार में मंदी	7
1.3	कुल वित्तीयन आवश्यकताएं - उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	7
1.4	विश्व व्यापार मात्रा में वृद्धि	8
1.5	निम्न स्तर पर बाल्टिक ड्राइ इन्डेक्स	8

पृष्ठ सं.

1.6	ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी वृद्धि	8
1.7	तिमाही जीडीपी वृद्धि में प्रवृत्तियां (वर्ष-दर-वर्ष)	8
1.8	देशी मांग में वृद्धि	9
1.9	चुनिंदा पण्यों के थोक मूल्यों में तीव्र वृद्धि	10
1.10	दोनों घाटों के बीच संबंध	12
1.11	स्वर्ण के आयात की प्रवृत्ति	12
1.12	केंद्र के कुल व्यय में राजस्व व्यय का अनुपात	13
1.13	केंद्र के कुल व्यय में पूंजी व्यय का अनुपात	13
1.14	केंद्र के कुल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अनुपात	13
1.15	खुदरा ऋण, एनपीए तथा पीएफसीई में वृद्धि	14
1.16	कम होते लाभ मार्जिन तथा बढ़ती ब्याज लागत	14
2.1	अमरीकी डालर तथा यूरो में 2012 में मनी मार्केट स्प्रेड	15
2.2	2012 में यूरोप में सोवरेन सीडी स्प्रेड	16
2.3	विभिन्न आस्ति श्रेणियों की अस्थिरता	16
2.4	यूएस तथा यूरो तथा भारतीय दरों के बीच ब्याज दर अंतर	17
2.5	वित्तीय बाजार स्थिरता मैप	17
2.6	वित्तीय बाजार स्थिरता संकेतक	17
2.7	2012 में भारत सरकार की बांड आय	18
2.8	चालू खाते घाटे के साथ ईडीई की मुद्राएं	19
2.9	2012 में निफ्टी और डैफ्टी का साप्ताहिक लाभ	19
3.1	बैंकिंग स्थिरता मैप	21
3.2	बैंकिंग स्थिरता संकेतक	21
3.3	चुनिंदा बैंकों पर भारतीय बैंकों द्वारा दावे - दिसंबर 2011 की स्थिति	22
3.4	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों के अनुपात के रूप में चुनिंदा देशों के भारतीय बैंकों पर दावे	22
3.5	चुनिंदा क्षेत्रों को बैंक ऋण की वृद्धि दर	23
3.6	विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वृद्धि - बैंक समूहवार	23
3.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीडी/आईडी अनुपात और वृद्धिशील सीडी/आईडी अनुपात	23
3.8	बैंलेस शीट के चुनिंदा घटकों की वृद्धि दर	24
3.9	जमाराशियों और अग्रिमों का परिपक्वता प्रोफाइल	24
3.10	बैंक समूहों का सीआरएआर	24
3.11	चुनिंदा देशों में निवल अनर्जक आस्तियों का पूंजी के साथ अनुपात	25

पृष्ठ सं.

3.12	ऋणों और अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों में संवृद्धि दर की प्रवृत्ति	25
3.13	वसूली के अनुपात के रूप में स्लिपेज	25
3.14	अनर्जक आस्तियों और ऋणों की तुलना में पुनर्संरचित खातों में वृद्धि	25
3.15	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए अनुपात	26
3.16	चुनिंदा क्षेत्रों के एनपीए की संवृद्धि दर	26
3.17	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का विद्युत क्षेत्र एक्सपोज़र	27
3.18	विद्युत क्षेत्र में एनपीए और पुनर्गठित खाते	27
3.19	एयरलाईन क्षेत्र को बैंक ऋण	27
3.20	एयरलाईन क्षेत्र को दिए गए ऋण के संदर्भ में शीर्ष 10 बैंक	27
3.21	एनपीए (निवल) के वर्तमान स्टॉक राईट ऑफ किये जाने पर सीआरएआर	28
3.22	कमाई की संवृद्धि दर	28
3.23	लाभप्रदता अनुपात	28
3.24	तुलन पत्र की आस्तियों के अनुपात के रूप में तुलनपत्रेत्तर आस्तियां (नोशनल प्रिंसिपल)	28
3.25	बैंकों के सैंपल के लिए पूंजी निधियों के अनुपात के रूप में घनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट पोज़िशन	29
3.26	बैंकों के सैंपल हेतु पूंजी निधि के अनुपात के रूप में निवल मार्क-टू-मार्केट पोज़िशन	29
3.27	ऋण वृद्धिः बैंकों की तुलना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	29
3.28	पूंजी निधियों के अनुपात के रूप में ऋणात्मक एमटीएम दबावोत्तर (परिदृष्य)	30
3.29	पूंजी निधियों के अनुपात के रूप में दबावोत्तर ऋणात्मक एमटीएम (संवेदनशीलता)	30
3.30	निवल एमटीएम में परिवर्तन - परिदृष्य विश्लेषण	30
3.31	निवल एमटीएम में परिवर्तन - संवेदनशीलता विश्लेषण	30
3.32	एनबीएफसी-एनडी - एसआई के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	31
3.33	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	32
3.34	आरआरबी के चुनिन्दा तुलनपत्र घटकों की वृद्धि - मार्च 2012	32
3.35	आरआरबी के सकल एनपीए अनुपात	32
3.36	ऋण जोखिमः बैंकों के दबावग्रस्त सीआरएआर का वितरण	35
3.37	ब्याज दर जोखिम - बैंकिंग बही - बैंकों के दबावग्रस्त सीआरएआर का वितरण	37
3.38	बॉटम-अप दबाव परीक्षणः चुनिन्दा बैंकों के दबावग्रस्त सीआरएआर का वितरण	37
3.39	पूंजी स्थितियों पर आघातों का प्रभावः एसयूसीबी - मार्च-2012	38
3.40	तरलता जोखिम आघातों का प्रभावः यूएसयूबी-मार्च-2012	38
4.1	क्षेत्रों के बीच आरडब्ल्यूए घनत्त्व	42
4.2	आरडब्ल्यूए में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अंशदान	42

पृष्ठ सं.

4.3	विभिन्न बैंक समूहों में आरडब्लयूए घनत्त्व - मार्च 2012	42
4.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आरडब्ल्यूए घनत्त्व	42
4.5	समीक्षा अवधि, जिसके दौरान विनिमय दर अत्यधिक अस्थिर रही, में दो दिनों में प्रारंभिक मार्जिन में वृद्धि	44
4.6	आरटीजीएस में निपटान अंतर	45
4.7	एक मिनट के अंदर निपटान किए जाने वाले दैनिक औसत ग्राहक लेनदेन	45
4.8	एक मिनट के अंदर निपटान किए जाने वाले दैनिक औसत अंतरबैंक लेनदेन	45
4.9	कुल निपटान मूल्यों के प्रतिशत के रूप में एसोशिएट सदस्यों का औसत निपटान मूल्य	46
4.10	विनिर्दिष्ट निपटान बैंकों में सीसीआईएल का एक्सपोजर	46
4.11	माह के अंत में बकाया आनुमानिक आईआरएस मात्रा	47
4.12	विभिन्न श्रेणियों के बैंकों के निक्षेप बीमा का हिस्सा	49
4.13	2010 के अंत में व्याप्ति-स्तर की देश-वार तुलना	49
4.14	2010 के अंत में देश-वार रिज़र्व अनुपात की तुलना	50
5.1	अक्तूबर 2011 के जोखिम सर्वेक्षण में पता लगाए गए विशिष्ट जोखिम	51
5.2	अप्रैल 2012 के जोखिम सर्वेक्षण में पता लगाए गए विशिष्ट जोखिम	51
5.3	ऐसे जोखिम जिन्हें देश के द्वारा नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है	52
5.4	ऐसे जोखिम जिन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है	52
5.5	वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अधिक प्रभाव वाली घटनाओं की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया - अल्प अवधि में	52
5.6	वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अधिक प्रभाव वाली घटनाओं की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया - मध्य अवधि में	52
5.7	देशी वित्तीय प्रणाली की अधिक प्रभाव वाली घटनाओं की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया - अल्प अवधि में	53
5.8	देशी वित्तीय प्रणाली की अधिक प्रभाव वाली घटनाओं की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया - मध्य अवधि में	53
5.9	प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक	54
5.10	अंतरबैंक बाजार की प्रवृत्तियां	55
5.11	अंतर बैंक बाजार में एक वर्ष के दौरान कार्यकलापों में हुए परिवर्तन का प्रतिशत	55
5.12	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल उधार का अनुपात अल्पावधि निधि के रूप में (31 मार्च, 2012)	55
5.13	कुल बाह्य देयताओं के रूप में अल्पावधि निधि (31 मार्च 2012)	55
5.14	बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क - 31 मार्च 2011	56
5.15	बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क - 31 मार्च 2012	56
5.16	उच्च नेट उधारकर्ता की विफलता के कारण संक्रामकता	57
5.17	बड़े बैंकों के विफल होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में संभावित घाटा	57
5.18	बैंकों के विफल होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में संभावित घाटा	57
5.19	विभिन्न बैंक समूहों में बीमा कंपनियों का निवेश	57

पृष्ठ सं.

5.20 विभिन्न बैंक समूहों में म्युच्युअल निधियों का निवेश 58

5.21 संकट की संयुक्त संभाव्यता और बैंकिंग स्थिरता सूचकांक का उतार-चढ़ाव 59

5.22 बैंकों के टॉक्सिसिटी इंडेक्स का उतार-चढ़ाव 59

5.23 बैंकों के प्रभावित होने वाले सूचकांक का उतार-चढ़ाव 59

5.24 बैंकों के बीच प्रणालीगत अंतर-संबद्धता : कॅस्केड प्रभाव 60

5.25 समस्त प्रणाली पर बैंकों का डामिनो प्रभाव: कॅस्केड प्रभाव 60

5.26 कुल आस्तियों में प्रत्याशित कमी : प्रणाली स्तर 60

सारणियों की सूची

1.1 बाह्य क्षेत्र भेद्यता संकेतक 11

3.1 यूरोपियन बैंकों के समेकित विदेशी दावे 22

3.2 चुनिन्दा क्षेत्रों की आस्ति गुणवत्ता - मार्च 2012 26

3.3 ऋण जोखिम : सकल ऋण -पूंजी और एनपीए पर प्रभाव 35

3.4 ऋण जोखिम: क्षेत्रवार - पूंजी और एनपीए पर प्रभाव 35

3.5 ऋण जोखिमःजमघट-पूंजी और एनपीए पर प्रभाव 36

3.6 ब्याज दर जोखिम: बैंक बहिया- बैंकों पर प्रभाव 36

3.7 तरलता जोखिमः बैंकों पर प्रभाव 37

4.1 वर्ष 2011-12 के दौरान अस्थिरता मार्जिन के भार के ब्यौरे 44

5.1 वैश्विक प्रणालीगत घटनाओं का घरेलू वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव 53

5.2 वैश्विक और घरेलू वित्तीय प्रणाली में विश्वसनीयता 53

5.3 बैंक उधार राशियों में म्युचुअल निधि और बीमा कंपनियों का योगदान 58

5.4 बैंकिंग प्रणाली में बीमा कंपनियों और म्युचुअल निधियों के निवेश/उधार देना - प्रतिशत का वितरण 58

5.5 व्यापक आर्थिक परिदृश्य अनुमान 62

5.6 विभिन्न मॉडलों का प्रयोग कर प्रक्षेपित सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 62

5.7 विभिन्न मॉडलों का प्रयोग कर प्रक्षेपित सीआरएआर 62

5.8 बैंक-समूह-वार प्रक्षेपित अनर्जक आस्तियां 63

5.9 बैंक-समूह-वार प्रक्षेपित सीआरएआर 63

5.10 प्रक्षेपित सेक्टोरल सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 63

संक्षिप्ताक्षर

एई	विकसित अर्थव्यवस्था
एआइ	वैकल्पिक निवेश
एएमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनियां
बीसीबीएस-आइएडीआइ	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति - निक्षेप बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ
बीआइएस	अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए बैंक
ब्रिक्स,	ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका देशों का संगठन
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक
बीएसएमडी	बैंकिंग प्रणाली की पोर्टफोलियो बहुआयामी सघनता
बीएसएम	बैंकिंग स्थिरता उपाय
सीएबी	चालू खाता शेष/चालू खाते में जमा शेष राशि
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीबीएलओ	संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व/ऋणदायी बाध्यता
सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीपी	केन्द्रीय प्रतिपक्ष
सीडी	जमाराशि की तुलना मे ऋण का अनुपात/ जमा प्रमाण पत्र
सीडीएस	क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
सीईटी 1	कामन इक्विटी टायर 1
सीआइएस	सामूहिक निवेश योजना
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति
सीआरएआर	जोखिमभारित संपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
डीबी	निश्चित लाभ
डीसी	निश्चित योगदान /अंशदान
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा व प्रत्यय गारंटी निगम
डीएमए	प्रत्यक्ष बाजार अभिगम / पहुंच
डीपी	गतिशील / गत्यात्मक प्रावधान
डीएसबी	निर्दिष्ट निपटान बैंक
ईसीबी	यूरोपीयन केन्द्रीय बैंक / बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईडीई	उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था
ईईएफसी	एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी (Exchanges Earner's Foreign Currency)
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ईएस	संभावित गिरावट
ईयू	यूरोपीयन यूनियन
एफसीएनआरबी	अनिवासी विदेशी मुद्रा बैंक
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफएमआइ	वित्तीय बाजार संरचना
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एचएफआर	उच्च आवृति व्यापार
आइएआइएस	बीमा पर्यवेक्षकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन
आइएएसबी	अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड
आइडी	जमा की तुलना में निवेश
आइएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आइओएससीओ	प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन

आइआरडीए	बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण
आइआरएस	ब्याज दरों का विनिमय
जेपीओडी	आपात की संयुक्त संभावना
केवायसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एल ए आर	जोखिम आधारित तरलता / चलनिधि
एलजीडी	चूक से हुई हानि (लॉस गिवेन डिफॉल्ट)
एलआइबीओआर	लंदन अंतरबैंक प्रस्तावित दर
एलटीआरओ	दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रक्रिया
एलटीवी	मूल्य की तुलना में ऋण
एमएफ	पारस्परिक निधि
मूव (MOVE)	मैरिल लिंच आप्शन वौलेटैलिटी एस्टिमेट
एमएससीआइ	मोर्गन स्टेन्ली कैपीटल इंटरनैशनल
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमटीएम	बाजार भाव पर दर्शाना
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीडी	गैर परिवर्तनीय डिबेंचर
एनडीटीएल	निवल मांग और सावधि देयताएँ
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनआइआइपी	निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
एनआईएम	निवल ब्याज सीमा
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरई	बाहरी अनिवासी
एनआरआइ	अनिवासी भारतीय
एनआरओ	सामान्य अनिवासी
एनएसई	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज
ओबीएस	तुलनपत्रेतर
ओआइएस	ओवरनाइट(रातोंरात) अनुक्रमित विनिमय / स्वैप
ओएमओ	खुला बाजार परिचालन
ओटीसी	कांऊटर पर
पीएफआरडीआए	पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण
पीओडी	आपदा की संभाव्यता
आरडी	भू-राजस्व घाटा
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आर ओ ए	आस्तियों पर लाभ
आर ओ ई	इक्विटी पर लाभ
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	तत्काल (रियल टाइम) सकल भुगतान
एस & पी	स्टैंडर्ड एंड पुअर
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एसईबीआइ	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसईबी	राज्य विद्युत बोर्ड
एसआइएफआइ	प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएँ
एसएलआइ	प्रणालीगत चलनिधि /तरलता सूचकांक
एसएलआर	सांविधिक तरलता /चलनिधि अनुपात
एस पी	विशेष प्रावधान
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
टीआइ	विषाक्तता सूचकांक
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
वी ए आर	जोखिम आधारित मूल्य
वीएआर	वेक्टर ऑटो रिग्रेशन
वीआइ	भेद्यता सूचकांक
वीआईएक्स	उतार चढ़ाव सूचकांक
डब्ल्यू ई ओ	विश्व आर्थिक दृष्टिकोण
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
वाय ओ वाय	वर्ष-दर-वर्ष

विहगावलोकन

देश की वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बनी हुई है, तथापि, दिसंबर 2011 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के प्रकाशित होने के बाद स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ गये हैं। निराशाजनक वैश्विक समष्टि आर्थिक स्थिति और घरेलू मोर्चे पर मंद आर्थिक निष्पादन के मिले-जुले प्रभाव से स्थिरता के लिए जोखिम में अत्यल्प वृद्धि हो गई। तथापि, वित्तीय क्षेत्र के हितधारकों का घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में भरोसा भले ही कुछ कम हो गया हो, पर बना रहा जैसा कि रिज़र्व बैंक के दूसरे प्रणालीगत सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है । वैश्विक सार्वभौमिक ऋण संकट और जोखिम प्रतिकूलता, घरेलू राजकोषीय स्थिति, चालू खाते का घाटा बढ़ना और खाद्य मुद्रास्फीति के संरचनागत पहलुओं के कारण स्थिरता के लिए खतरे पैदा हो गए हैं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सामान्य मानसून, आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। जहाँ विदेशी मुद्रा और ईक्विटी बाज़ार में भारी अस्थिरता पैदा हुई वहीं निवेशकों का आत्मविश्वास और मनोबल भी कमजोर रहा। भारतीय बैंकों के सुदृढ़ता के संकेतक मजबूत रहे परंतु परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के बारे में आशंकाएं बनी रहीं। जमाराशियों में मंद गति से बढ़ोतरी होती रही जिसके कारण बैंकों की विशेषत: अल्पावधि राशियों पर निर्भरता बढ़ गयी। देश का बुनियादी वित्तीय बाज़ार बिना किसी बाधा के कार्यरत रहा। तथापि, तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली में निपटान की त्रुटियां और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा अपनाये गये व्यापक असंपार्श्वीकृत अंतर-दिवसीय निवेश जैसी संभाव्य कमजोरियों की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है। प्रतिकूल समष्टि आर्थिक झटकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अपनाए गये तनाव परीक्षणों की श्रृंखलाओं के परिणामों ने यह दर्शाया है कि बैंकिंग प्रणाली अत्यंत तनाव की स्थितियों में भी लचीली बनी रही है।

वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है तथापि, वित्तीय स्थिरता के जोखिम बदतर बने हुए हैं

1. दिसंबर 2011 से वित्तीय स्थिरता के जोखिम, मुख्यत: वैश्विक जोखिम और घरेलू समष्टिगत आर्थिक स्थिति के कारण बदतर हो गये हैं। राजकोषीय एवं बाह्य क्षेत्र के असंतुलन के कारण घरेलू विकास में जो जोखिम थे उनमें वृद्धि हो गयी है। वित्तीय बाजारों में विशेष रूप से विदेशी मुद्रा बाजारों में धीमी गति से सुधार हो रहा है और उनमें तीव्र उतार चढाव पाये गये हैं। हाल ही में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जो गिरावट आयी है, यदि वह बनी रहती है तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। यदि मानसून सामान्य रूप से होता है तो वह भी विकास के मोर्चे पर आये हुए दबाव को कम कर सकता है तथा घरेलू अर्थव्यवस्था को, जो मूलत: मजबूत है उसे दोबारा मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बैंकों के पास अच्छी खासी पूंजियाँ मौजूद हैं, भले ही, उनकी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और तरलता के दबाव झेलने की उनकी क्षमता में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता मजबूत बनी हुई है जैसा कि वित्तीय स्थिरता की स्थिति दर्शाने वाले मैप में दिया गया है (चार्ट 1)[1]।

चार्ट 1 : वित्तीय स्थिरता मैप

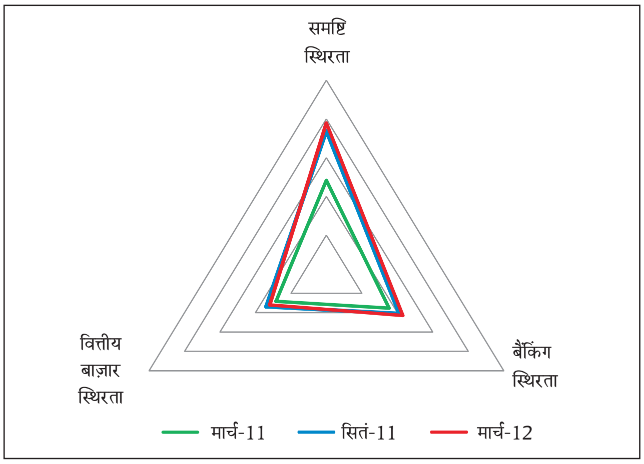

टिप्पणी: केंद्र[2] से जितनी अधिक दूरी उतना ही अधिक जोखिम।
स्रोत: भा.रि.बैं, कर्मचारी परिकलन

[1] संयुक्त वित्तीय स्थिरता मैप, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की तीन प्रमुख आयामों पर जोखिमों की गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास करता है, वे है समष्टि आर्थिक, वित्तीय बाज़ार तथा बैंकिंग क्षेत्र / विस्तृत कार्यप्रणाली अनुबंध में दी गई है।

[2] वित्तीय बाज़ार स्थिरता सूचकांक की स्थिति मई 2012 की है।

सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने विश्वव्यापी जोखिमों एवं दुतरफा घाटे के संबध में चिंता जताई एवं समष्टि तथा वित्तीय स्थिरता के संबंध में आश्वस्त रहे

2. अप्रैल 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये द्वितीय प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने वैश्विक स्तर पर उभरते नये जोखिमों एवं चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, बैंकों की परिसंपत्ति-गुणवत्ता तथा संभावित वित्तपोषण- जोखिमों जैसे अनेक आंतरिक कारकों के संबंध में चिंता व्यक्त की। हांलाकि, ये उत्तरदाता आंतरिक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के बारे में, तुलनात्मक दृष्टि से, आशावादी रहे। अक्तूबर 2011 में किये गये पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले इस बार उनके विश्वास के स्तर में कमी देखने को मिली।

वैश्विक परिवेश

वैश्विक समष्टि आर्थिक जोखिमों में वृद्धि हुई

3. यूरो क्षेत्र में गहराते संकट और निरंतर वैश्विक मंदी ने वैश्विक जोखिमों को और बढ़ा दिया है। यूरो क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, वैश्विक असंतुलन की निरंतरता, राजकोषीय दबाव,और धूमिल वृद्धि की संभावनाओं के कारण वैश्विक मैक्रो अर्थव्यवस्था के प्रति, आनेवाले महीनों में, डाउनसाइड जोखिमों में तीव्र वृद्धि हो सकती है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ए ई) में सरकारी ऋण और सकल वित्त को निरंतर उच्च बनाये रखने की आवश्यकता है, बल्कि कुछ यूरो क्षेत्र के देशों में सरकारी यील्ड का बढ़ना भी जारी हैं।

अन्य उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था में यूरो क्षेत्र के संक्रमण का प्रवेश

4. यूरोजोन की घटनाओं का असर व्यापार, वित्त और कारोबारी विश्वास के चैनलों के माध्यमों से अन्य उन्नत देशों (ए ई) और उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर देखने में आया है। यूरोप में बैंकों द्वारा लीवरेज हटा लेने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहे पूंजीप्रवाह के संभावित असर के मद्देनजर निर्यात के लिए कमजोर पड़ती मांग, ट्रेड वित्त में कमी की परछाई निरंतर वैश्विक रिकवरी को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। कई देशों में निरंतर चली आ रही उच्च बेरोजगारी दरें और कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आंतरिक मांग में आती जा रही कमी समस्याओं को और विकराल बना रही हैं।

वैश्विक वित्तीय बाजार दबाव में

5. समीक्षाधीन अवधि के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजार में दबाव की स्थिति बनी रही तथा वहां अत्यधिक अस्थिरता का अनुभव हुआ । यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किये गये दो दीर्घ-कालीन पुनर्वित्तपोषण परिचालनों के बाद बाज़ार के रुझान में थोडी अवधि के लिये सुधार आया । यूरोपीय क्षेत्र की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी बांडों (sovereign bonds) के लिए संस्थागत मांग कम होने के कारण यूरोपीय बैंकों पर निधीयन संबंधी दबाव बना। अप्रतिभूत निधियों के लिए अवसर कम होने के कारण, ये बैंक केंद्रीय बैंकों के समर्थन पर निर्भर रहते हैं क्योंकि उन्हें बाज़ार से निधियां उपलब्ध नहीं हो रही है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीतियां ज़ारी रखने पर सुभेद्यता पैदा हो सकती है

6. अमेरिका और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई कम नीतिगत दरों की वर्तमान व्यवस्था सामान्य तौर पर कुछ और समय के लिए जारी रहने की उम्मीद है। इससे इक्विटी की लागत की तुलना में ऋण पूंजी की लागत और कम हो गयी है। भविष्य में इसके कारण अधिक लिवरेज लिया जा सकता है तथा निवेशक यील्ड की खोज में अग्रसर होंगे।

समष्टि आर्थिक परिवेश

घरेलू अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट

7. वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चक्रीय एवं संरचनात्मक कारकों के परिणामस्वरूप घरेलू सकल उत्पाद (जीडीपी) विकास दर पिछले वर्ष के 8.4 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 के दौरान घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई। यह प्रवृत्ति उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EDEs), विशेषकर BRICS देशों के अनुभव के समान है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में हुई यह मंदी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में, अर्थात - कृषि, सेवा, और उद्योग के क्षेत्रों में परिलक्षित हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था से मिले संकेतों और निजी एवं सरकारी खपत और निवेश मांग में हुई गिरावट को देखते हुए वृद्धि के अधोगामी जोखिमों में निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है।

मुद्रा स्फीतिकारक दबाव में कमी परंतु जोखिम अभी भी बरकरार

8. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोर मुद्रा स्फीति में कमी आई है। तथापि वृद्धि में महत्त्वपूर्ण गिरावट के बाद भी समग्र मुद्रास्फीति का लगातार बना रहना गंभीर आपूर्ति अवरोध (bottleneck) और हठी मुद्रा स्फीति अपेक्षाओं को दर्शाता है। आने वाले महीनों में वैश्विक वस्तुओं की कीमत में कमी जहां मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोकने में मदद कर सकता है, वहीं रुपया मूल्यह्रास, ऊर्जा और खादों में दमित मुद्रा स्फीति और संभावित राजकोषीय घाटे (slippage) के बाद के संभावित परिणाम से निरंतर खतरा बना हुआ है।

बाह्य क्षेत्र जोखिमों में वृद्धि ; तेल की कीमतों में हाल की प्रवृत्ति राहतकारी है

9. बाह्य क्षेत्र सुभेद्यता सूचक बढ़े जोखिम की ओर इशारा करते हैं। सोने और कच्चे तेल की निरंतर मांग के कारण आयात की अधिकता बनी रहने और निर्यात में कमी के कारण चालू खाता घाटा बढ़ा है। कुल बाह्य सरकारी ऋण के प्रति अल्पावधि सरकारी ऋण में वृद्धि के कारण देश की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति खराब हुई। यदि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट जारी रहती है तो बाह्य क्षेत्र जोखिम कम होने में मदद मिलेगी। परंतु विनिमय दर में तेजी से हो रही गिरावट, पूँजी आगमन में कमी और देश की सरकारी रेटिंग में डाउनग्रेडिंग के जोखिम जैसे घरेलू कारक घाटे के वित्तपोषण के लिए चुनौती बने हुए हैं।

राजकोषीय घाटे की संरचना की प्रवृत्तियां चिंताजनक हैं

10. 2011-12 के दौरान राजकोषीय और प्राथमिक दोनों में घाटे के कारण राजकोषीय जोखिम में उच्चता बनी हुई है। कुल राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का उच्च अनुपात और पूंजी परिव्यय के प्रति राजस्व व्यय के बढ़ते अनुपात के संदर्भ में हाल की प्रवृत्तियां भी चिंताजनक हैं। सरकार की कुल वित्तपोषण आवश्यकताओं में अधिकता बनी रही जिसका प्रभाव निजी निवेश और विकास पर पड़ा।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हेतु योजनाएं तैयार हैं ; घाटे का जोखिम बना हुआ है

11. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए यूनियन बजट 2012-13 में एक रूपरेखा तैयार की गई। 2012-13 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मूलत: सरकार के राजस्व जुटाने के प्रयासों पर आधारित है। जीडीपी के प्रति प्रस्तावित सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में कमी की प्राप्ति तभी संभव है जब सरकार 2012-13 में अनुदान संबंधी अपना व्यय जीडीपी के 2 प्रतिशत की विनिर्दिष्ट सीमा में रखने की प्रतिबद्धता पर कायम रहे।

वित्तीय बाजार

भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार और अस्थिरता का बने रहना

12. समीक्षाधीन अवधि के दौरान यूरो क्षेत्र में भारी गड़बड़, चालू खाते का बढ़ता घाटा और भारत में नीति बनाते समय रही मंदी की धारणा ने घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हुआ। तथापि, ये प्रवृत्तियाँ व्यापक रूप से उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई), विशेष रूप से चालू खाते के उच्च घाटेवाले देशों की मुद्रा के मामलों में स्पष्ट रूप से नजर आयी। दबाव को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक उपायों का सम्मिश्रण और विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप का संयोजन किया गया।

संभावित रेटिंग में परिवर्तन विदेशी उधार पर प्रभाव डाल सकता है

13. यूरोपियन बैंकों में डेलिविरेजिंग की प्रक्रिया से भारतीय कंपनियों और बैंकों की उधार लेने की लागत पर प्रभाव पड़ा। देश की वर्तमान बाह्य रेटिंग में परिवर्तन का 'क्लिफ एफेक्ट' हो सकता है जिससे भारतीय बैंकों तथा फर्मों के लिए विदेशी मुद्रा उधार की उपलब्धता और लागत दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

घरेलू ईक्विटी बाजार कमजोर रुझान दर्शाता है

14. कैलेंडर वर्ष के पहले दो महीने में घरेलू ईक्विटी बाजार बढ़ा। उसके बाद बिगड़ते वैश्विक परिदृश्य, कमजोर घरेलू रुझान और भारतीय रुपये के तेज मूल्यह्रास, विदेशी संस्थागत निवेश का प्रवाह उल्टा हो जाने के कारण बाजार दिसंबर 2011 के अपने स्तर पर चला गया।

एल्गोरिथमिक और उच्च बारंबारता व्यापार के बढ़ते उपयोग के प्रभाव पर नजर रखना आवश्यक

15. भारतीय बाजारों में हाल ही में जो घटनाएँ हुईं उससे यह बात स्पष्ट रूप से उजागर हुई है कि टेक्नॉलॉजी की उन्नति, जैसे प्रत्यक्ष बाजार एक्सेस जो एल्गोरिथमिक और उच्च बारंबारता व्यापार के लिए समर्थन प्रदान करती है, के लिए सतर्क कैलिबरेटेड दृष्टिकोण अपनाना होगा। वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार की उन्नति के लाभ, यदि उनके द्वारा पैदा किए गए जोखिमों से उनकी तुलना की जाए, पर पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है।

वित्तीय संस्थाएं

उधार ली गयी निधियों पर बैंकों की निर्भरता बढ़ रही है

16. बैंकिंग क्षेत्र में ऋण की बढ़ोतरी में मार्च 2011 के अंत में आयी लगभग 22.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 16.3 प्रतिशत की गिरावट आयी। इससे अर्थव्यवस्था में आयी समग्र गिरावट प्रतिबिंबित हुई। जमाराशियों की वृद्धि में भी गिरावट पायी गयी जो मार्च 2012 के अंत में 14 प्रतिशत से भी कम थी। यह पिछले 10 वर्षों के दौरान देखी गयी गिरावट का सबसे निचला स्तर था। ऋणों की बढोतरी की तुलना में जमाराशियों की वृद्धि में आयी गिरावट की इस गैर अनुपातिक मात्रा से बैंकों को उधार राशियों पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ा। इसका नतीजा संभवत: चलनिधि की जोखिमों में हो सकता है।

आस्ति गुणवत्ता चिंताएं बनी रहीं; अच्छी पूंजी स्थिति कुशन के रूप में कार्य करती हैं

17. गिरावट (स्लिपेज) के अनुपात में वृद्धि, पुनर्गठित आस्तियों की मात्रा में बढ़ोत्तरी और ऋण-वृद्धि सापेक्ष अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में भारी मात्रा में वृद्धि से पता चलता है कि बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताएं ऊंचे स्तर पर बनी रही हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल एनपीए अनुपात मार्च 2012 के अंत में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गया (मार्च 2011 के अंत में 2.4 प्रतिशत)। वर्तमान समय में, यह स्थिति चिंताजनक नहीं है और बैंकों की मजबूत नकदी स्थिति के कारण कुछ अच्छी स्थिति पायी गयी है।

अधिकाधिक अंतर-संबद्धता के कारण 'अधिकाधिक रूप में संबद्ध' बैंकों की गहनता से निगरानी आवश्यक

18. बैंकों के बीच मजबूरन निर्भरता काफी बढ़ती जा रही है जो बैंकिंग स्थिरता उपायों के रूझानों से देखी गई है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि 'अधिकांशत: संबद्ध' बैंकों के फेल हो जाने के कारण बैंकिंग प्रणाली में अधिकतम संभाव्य हानि में वर्ष 2011 के दौरान बढ़ोतरी हुई है। इन रुझानों की 'अधिकांशत: संबद्ध' बैंकों के कड़े सूक्ष्म-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण द्वारा गहनता से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

विनियामक उपाय स्वर्ण एनबीएफसी की तेजी से वृद्धि से उत्पन्न जोखिम को कम करने के प्रति लक्षित हैं

19. स्वर्ण की जमानत पर उधार देने का काम करनेवाली एनबीएफसी में हाल ही के वर्षों में, तेजी से हुई वृद्धि, ऐसी कंपनियों के कारोबारी मॉडल, कुछ कंपनियों के बीच कारोबार के संकेंद्रीकरण और बैंकिंग प्रणाली के साथ उनकी बढ़ती अंतर-संबद्धता से जोखिम का कारण बन सकती है। इन जोखिमों को विभिन्न विनियामक उपायों (प्रिस्क्रिप्शनों) के माध्यम से संबोधित किया जाना है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली की अंतर-संबद्धता से जोखिम हो सकता है

20. भारतीय वित्तीय प्रणाली में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंक जो प्रमुख उधारकर्ता होते हैं, सहित बीमा कंपनियां और म्युचुअल फंड प्रमुख ऋणदाता हैं। इसलिए बीमा कंपनियां और म्युचुअल फंड बैंकिंग प्रणाली से संक्रामक जोखिम के चपेट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ, बैंक इन संस्थाओं से उधारी के लिए काफी निर्भर रहते हैं। चूंकि म्युचुअल फंड से उधारी ज्यादातर कम अवधि के लिए होती है, वे इससे बैंकिंग प्रणाली में बढ़ी चलनिधि जोखिम का कारण हो सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय खंड के मैक्रो मैपिंग की जरूरत है (को वारंटड किया जाना)

21. विनियामक ढ़ांचे को बैंकों के लिए मजबूत बनाए जाने से वैश्विक रूप से वित्तीय क्षेत्र की गतिविधि के अपेक्षाकृत कम विनियमित 'बैंकवत(शैडो) बैंकिंग' क्षेत्र में अंतरित हो जाने के जोखिम बढ़ गए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, देश का गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र इन संस्थाओं द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त विनियामक ढ़ाचे का कार्य करता है। इस पर भी, सर्वांगीण रूप से महत्त्वपूर्ण गतिविधियों और संस्थाओं पर विनियामक रुख (ध्यान) के साथ वर्तमान विनियामक व्यवस्था और सभी प्रकार की क्रेडिट मध्यस्थ गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय सुधारों के परिप्रेक्ष्य में एक पूरी मैक्रो मैपिंग समीक्षा आवश्यक हो सकती है।

वित्तीय संस्थाएं क्रेडिट, बाजार एवं चलनिधि (तरलता) जोखिम के लिए लचीली बनी हुई है

22. क्रेडिट जोखिम बैंकों के लिए अस्थिरता का प्राथमिक स्त्रोत बना रहा, जबकि ब्याज दर में प्रतिकूल घट-बढ़ से उत्पन्न जोखिम प्रबंधनीय पाए गए जो अतिसंवेदनशीलता तनाव परीक्षण की श्रृंखला के परिणामों से स्पष्ट है। तथापि, समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली, गंभीर क्रेडिट जोखिम तनाव को भी अवशोषित करने में सक्षम है। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश से बैंकों को अपने चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन में सहायता प्राप्त होती है। कुछ नमूना बैंकों ने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में एक सकारात्मक निवल मार्क टू मार्केट (एमटीएम) स्थिति सूचित की है, जो इस बात को इंगित करते हैं कि वे कृत्रिम ऐतिहासिक तनाव परिदृश्यों और आकस्मिक अतिसंवेदनशील आघातों के मामले में प्रतिकूल बाजार गतिविधियों को अवशोषित करने की स्थिति में हैं।

23. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी अपनी पूंजी पर्याप्तता की अच्छी स्थिति के कारण ऋण (क्रेडिट) जोखिम का पूरी तरह से सामना करने की स्थिति में भी हैं। शहरी सहकारी बैंकों के तनाव टेस्ट में क्रेडिट एंव चलनिधि जोखिम दोनों ही में कुछ अस्थिरता पायी गई।

विनियामक ढ़ांचा

प्रमुख सुधार उपायों के अनपेक्षित परिणामों का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है

24. संकट स्थिति के पश्चात सुधारों के कार्यान्वयन में कमी और चुनौतियां, विशेष रूप से ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में सुधार और सर्वांगीण रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान-संरचना के संबंध में, उभरती जा रही हैं। इन सुधारों, विशेष रूप से

'ईडीई', के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में सुधारात्मक उपायों को अंशांकित करने में विद्यमान भिन्नता के कारण विनियामक अंतरपणन की गुंजाईश हो सकती है।

देशी बासेल III दिशानिर्देश निर्बाध रूप से परिवर्तन के प्रति लक्षित

25. वर्तमान नियामक आवश्यकताओं एवं बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार भारत के बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे जोखिम भारित आस्तियों के 9 प्रतिशत का पूंजी अनुपात बनाए रखें जो कि बासेल समिति द्वारा निर्धारित 8 प्रतिशत के पूंजी अनुपात से अधिक है। बासेल समिति द्वारा सुझाई गई समयपरकता बनाए रखी जाए ताकि परिवर्तन सुचारु रूप से हो। आगे बढ़ते हुए, चूंकि बैंकों की पूंजी लागत एवं इक्विटी पर प्रतिलाभ विशेषत: अल्पकालीन, से प्रभावित होंगें अत: अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं के राजकोषीय परिणामों को भी हिसाब में लेना होगा।

26. बासेल समिति द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात की तुलना में भारतीय बैंकों के वर्तमान के काफी अधिक लीवरेज अनुपात को देखते हुए समानान्तर रूप से कार्य करने की अवधि (पैरेलल रन) के लिए कुछ अधिक कठोर, लीवरेज अनुपात निर्धारित किया गया है।

बासेल II के अंतर्गत चूंकि बैंक उच्चस्तरीय प्रणालियों की तरफ बढ़ रहे हैं, अत: जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में परिवर्तनों की निगरानी की जानी होगी

27. सभी कार्यक्षेत्रों में और एक ही क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में आरडब्ल्यूए की सघनता (कुल आस्तियों की तुलना में आरडब्ल्यूए) में उल्लेखनीय भिन्नताएं देखी गई हैं। ये सामान्यत: बैंकों के जोखिम प्रोफाइल, उनके संमिश्र कारोबार और क्षेत्राधिकार के विनियामक परिवर्तन स्तर के कारण पाई गईं। तथापि, जोखिम मापदंडों को अंशांकित करने में व्यवहार आधारित असंगतियां हो सकती हैं। बासेल II के अंतर्गत चूंकि बैंक उच्चस्तरीय प्रणालियों की तरफ बढ़ रहे हैं अत: संप्रेषणीय अंतर उत्पन्न होने की भी संभावना है। साथ ही, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, बैंकिंग खंड में आरड्ब्ल्यूए सघनता अंतर देखा गया है, इसलिए इस क्षेत्र में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन भी जरुरी है।

वित्तीय बाजार की बुनियादी व्यवस्थाएं

तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) ने जोखिम को कम किया है लेकिन ....पायी जानेवाली कमियों पर निगरानी रखना जरूरी है

28. बैंकों द्वारा सक्रिय आंतर दिवसीय चलनिधि प्रबंधन, केंद्रीय बैंक से आंतर दिवसीय चलनिधि की व्यवस्था और विवेकपूर्ण आरक्षित निधि शेष की उपलब्धता के होते हुए भी आरटीजीएस प्रणाली में लेनदेनों में होनेवाले विलंब जोखिम पैदा करा सकते हैं। विभिन्न बैंकों के बीच विद्यमान भिन्नताओं की निहित प्रवृत्तियों की भी निगरानी की जाने की आवश्यकता है।

निपटानकर्ता बैंकों द्वारा नए जारी किए गए मानकों और जोखिमों के कारण सीसीआईएल के जोखिम प्रबंधन ढ़ांचे की समीक्षा करने की जरूरत है

29. नए जारी किए गए आंतरराष्ट्रीय 'वित्तीय बाजार बुनियादी व्यवस्था संबंधी सिद्धांत' जिनमें कड़ाई से जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता प्रस्तावित है, के कारण सीसीआईएल जैसे देशी केंद्रीय घटकों की जोखिम प्रबंधन पद्धतियों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है। सीसीआईएल के नामित निपटानकर्ता बैंकों जो आभासी भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, द्वारा भी जोखिम खड़े किए जा रहे हैं और सीसीआईएल को इन संस्थाओं के प्रति काफी मात्रा में असंपार्श्विक आंतर दिवसीय एक्सपोजर की परिकल्पना करना जरूरी हो रहा है। इस संबंध में विद्यमान प्रवृत्तियों का मूल्यांकन सीसीआईएल के वित्तीय संसाधनों/ स्रोतों और उसके चलनिधि एवं जोखिम प्रबंधन ढ़ांचे की तुलना में किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 1
मैक्रोइकोनोमिक जोखिम

पिछली एफएसआर के प्रकाशन के पश्चात वैश्विक और घरेलू परिदृश्य और भी अधिक खराब हुए हैं। यूरो एरिया सरकारी ऋण की समस्या का असर अभी भी वैश्विक रिकवरी पर लगातार पड़ रहा है। धीमी होती जा रही वैश्विक वृद्धि ने एक ओर जहाँ जिंसों की कीमतों पर बुरा असर डाला है, वहीं जोखिम न्यून रखने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके परिणामस्वरूप पूंजी आप्रवाह में शिथिलता का विपरीत प्रभाव उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) पर होने की संभावना है। यद्यपि घरेलू फ्रंट पर वृद्धि में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है ,मुद्रास्फीति का जोखिम बना हुआ है। विशुद्ध मुद्रास्फीति में कमी होने पर भी समग्र मुद्रास्फीति का बने रहना वह भी वृद्धि में महत्त्वपूर्ण रूप से कमी के परिप्रेक्ष्य में, गंभीर आपूर्ति रुकावटों और जमे रहनेवाले मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की ओर इंगित करता है। वृद्धि मंद पड़ने के बावजूद चालू खाते में घाटा (सीएडी) रहना मांग-आपूर्ति के असंतुलन का लक्षण है तथा इस ओर इंगित करता है कि आपूर्ति में आनेवाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। चालू खाते के बढ़ते घाटे, वह भी बद से बदतर होते जा रहे वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियों में, और रुके हुए पूंजी प्रवाह के कारण रुपया अवमूल्यन के दबाव में चल रहा है। पूंजी प्रवाह को बढ़ाने की संभावना वैश्विक परिस्थितियों, विशेष रूप से विशेष रूप से यूरो एरिया परिस्थितियों के ठोस समाधान पर, और घरेलू निवेश की स्थितयों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, घरेलू मैक्रोआर्थिक परिवेश का जन्म प्रतीत होता है कि वैश्विक सरकारी ऋण की समस्या और जोखिम से दूर रहने ,घरेलू राजकोषीय स्थितियों, चालू खाते के बढ़ते घाटे और खाद्यान मुद्रास्फीति के संरचनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है।

पिछले मूल्यांकन के बाद से वित्तीय स्थिरता के प्रति मैक्रोआर्थिक जोखिमों में वृद्धि

1. अनिश्चित वैश्विक स्थितियां, जोखिम वितृष्णा में वृद्धि और मंद होता पूंजी प्रवाह, ये सभी आम तौर पर यूरो एरिया सरकारी ऋण की समस्या की उपज हैं, ईडीई को प्रभावित करते हैं। ये भारत की वृद्धि और भुगतान संतुलन परिदृश्य के लिए खतरा बन जाते हैं। अपने देश में बढ़ते जा रहे सीएडी, पूंजी प्रवाह का न्यून स्तर और कुल सरकारी ऋणों में अल्पावधि ऋण की बढ़ती भागीदारी के कारण बाह्य सेक्टर के जोखिमों में वृद्धि होती है। राजकोष में कमी और हाल की तिमाहियों में वृद्धि में आई गिरावट ने आघातों के प्रति सुभेद्यता को बढ़ाया है। घरेलू और मैक्रोआर्थिक परिवेश अपेक्षाकृत अननुकूल रहने यथा- निराशाजनक घरेलू उपभोग और निवेश मांग, सामग्रियों की बढ़ती कीमत,निर्यात में कमी और असुरक्षित विदेशी मुद्रा से उपजित जोखिम के कारण कारपोरेट सेक्टर तुलनपत्रों के जोखिम उच्च् स्तर पर बने रहे। तथापि हाउसहोल्ड सेक्टर के जोखिमों में कमी आई (चार्ट-1.1)।

चार्ट 1.1: मैक्रोआर्थिक जोखिम मैप

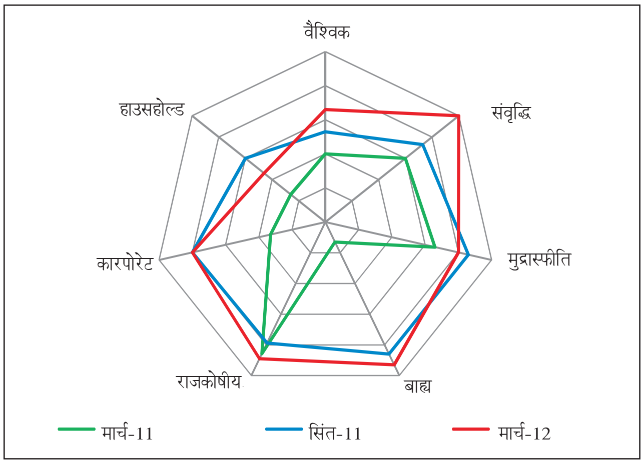

टिप्पणी: केन्द्र से दूरी के साथ-साथ जोखिम बढ़ा।
स्रोत: भा.रि.बैं, कर्मचारी परिकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में मंदी पहले से अधिक

1.2 समीक्षाधीन तिमाही के दौरान वैश्विक रिकवरी की रफ्तार धीमि ही रही। 2011 की अंतिम तिमाही और 2012 की पहली तिमाहीके दौरानउन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) वृद्धि धीमी रही।

आइएमएफ और यूरोपियन कमीशन , इन दनों ने ही इंगित किया है कि 2012 में यूरो एरिया धीमी मंदी से ग्रस्त रहेंगे (चार्ट 1.2)।

------ अधोमुखी जोखिमों का बने रहना

1.3 व्यापार,वित्त और भरोसा चैनलों के माध्यमों से यूरो क्षेत्र में आई मंदी का संक्रमण अब एई में और ईडीई में हो रहा है। थोड़े ही अंतराल में वित्त समेकन के उपाय,विशेष रूप से यूरो जोन में,मांग और वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में यूरो क्षेत्र की सरकारों और बैंको की रेटिंग में एक के बाद एक आई गिरावट ऋण की लागत में वृद्धि कर सकती है। वृद्धि,यूरो जोन और विश्व के अन्य देशों में भी,पर ईयू आधारित बैंकों द्वारा डेलिवरेजिंग का प्रभाव भी पड़ सकता है।[1] ईडीई खास तौर पर निभावी मौद्रिक नीतियों,जो एई में तथा विशेष रूप से यूरोजोन में प्रचलित हैं, के स्पिलओवर के प्रति भेदनीय बना हुआ है (अध्याय II)।

वैश्विक राजकोषीय जोखिम में वृद्धि हुई

1.4 यूरोजोन में हाल की गतिविधियों ने विश्व स्तर पर राजकोषीय जोखिमों को तीव्रता से फैलाया है। सरकारी ऋण और सकल वित्तीयन की आवश्यकताएं कई एई देशों में आज भी सर्वोच्च हैं जबकि सरकारी प्रतिफल में वृद्धि जारी है (चार्ट 1.3)। चिंताजनक बात यह है कि यूरोजोन में आई मंदी का उपयोग देशों द्वारा वित्तीय समेकन उपायों से पीछे हटने/ उन्हें आस्थगित करने,विशेष रूप से विद्यमान राजनीतिक घटनाक्रमों में,के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में आइएमएफ की अपनी फिसिकल मॉनिटर,अप्रैल 2012 में की गई टिप्पणियां संगत हैं,''*... यदि वृद्धि और भी धीमी पड़ जाए तो राजकोषीय महत्त्ववाले देशों को चाहिए कि वे ऑटोमेटिक स्थिरकारकों को अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करने दें और राजकोषीय संकुचन की अधिकता,जो आर्थिक स्थितियों को अत्यधिक खराब कर सकती है, को न होने देने के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ जाने दें। लेकिन मध्यमावधि की तुलना में अल्पावधिक सावधानी कहीं बहाना न बन जाए लोक वित्त को मज़बूती प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को शिथिल करने या उन्हें बिलंबित करने का... ।*''

अमरीका में शिखरोन्मुख बेरोजगारी और यूरोजोन में बढ़ती बेरोजगारी जोखिमों को बढ़ा सकती है

1.5 एई में बेरोजगारी का स्तर उच्च ही बना रहा जो रिकवरी और राजकोषीय समेकन में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। अमरीका

चार्ट 1.2: 2012 में वैश्विक सुधार में मंदी

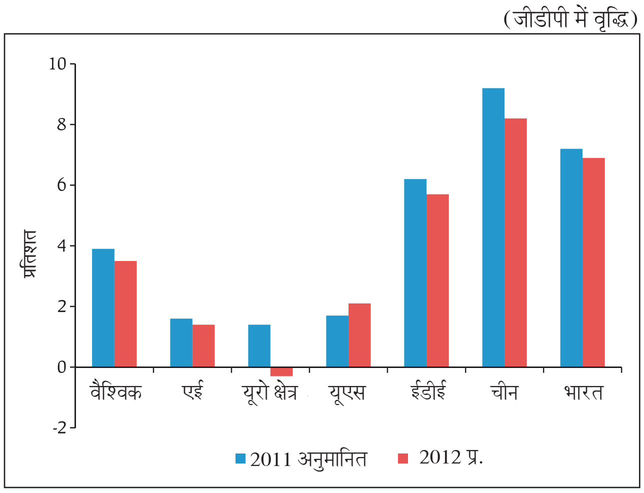

प्र:प्रस्तावित
स्रोत: आईएमफ डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2012

चार्ट 1.3 : कुल वित्तीयन आवश्यकताएं - उन्नत अर्थव्यवस्थाएं

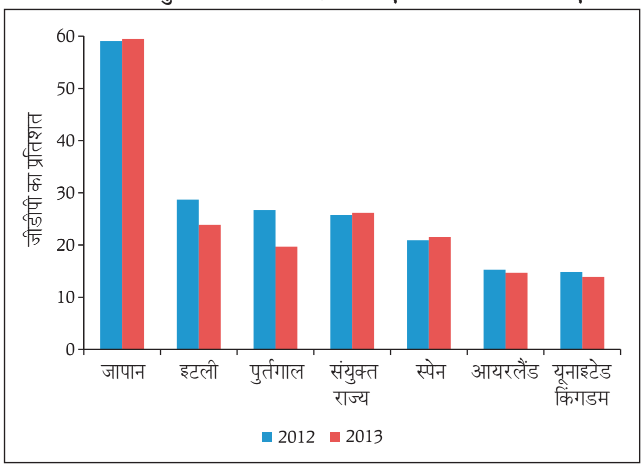

टिप्पणी : प्रस्तावित आंकड़े
स्रोत: आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर, अप्रैल 2012

[1] ग्लोबल फाइनेंनशियल स्टैबिलिटि रिपोर्ट(जीएफएसआर)अप्रैल 2012 के अनुसार यूरोपियन बैंकों द्वारा डेलिवरेजिंग के परिणामस्वरूप 2013 के अंत तक बड़े बैंकों के साझा तुलनपत्र का आकार 2.6 ट्रिलयन डॉलर (2.0 ट्रिलियन क्रोनर) से घट जाएगा अर्थात् कुल आस्तियों का लगभग 7प्रतिशत। जीएफएसआर में टिप्पणी की गई है कि इस डेलिवरेजिंग के एक चौथाई को उधार देना कम करके प्रभावी किया जा सकता है।

चार्ट 1.4 : विश्व व्यापार मात्रा में वृद्धि

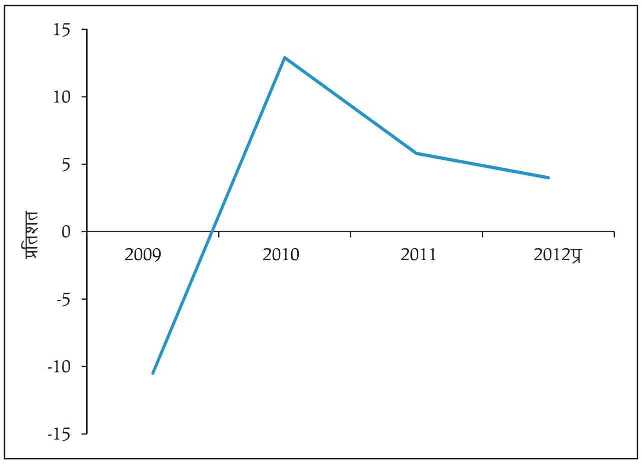

प्र:प्रस्तावित
स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2012

चार्ट 1.5 : निम्न स्तर पर बाल्टिक ड्राइ इन्डेक्स

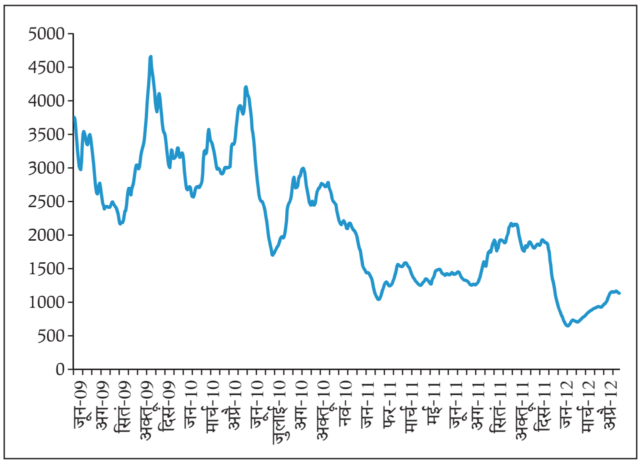

स्रोत: ब्लूमबर्ग

में बेरोजगारी दर अप्रैल में रही 8.1 प्रतिशत से बढ़कर मई 2012 में 8.2 प्रतिशत हो गई जो 11 महीनों में पहली बार बढ़ी है। यूरो क्षेत्र में अप्रैल 2012 में बेरोजगारी बढ़कर11 प्रतिशत पर पहुँच गई- जो अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई है। बेरोजगारी दर स्पेन में विशेष रूप से अत्यधिक (लगभग 24.3 प्रतिशत) है और इसके आस-पास फैले यूरो क्षेत्र में भी।

वैश्विक वृद्धि की प्रवृत्तियां विश्व व्यापार की मात्रा में प्रतिबिंबित होती हैं...

1.6 वैश्विक वृद्धि में आई मंदी अंतरराष्ट्रीय व्यापार (चार्ट 1.4 और चार्ट 1.5) में धीमी प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है। ये प्रवृत्तियां वैश्विक वृद्धि के परिदृश्य में अनिश्चितताओं के रहने तक बदलनेवाली नहीं हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वैश्विक और घरेलू कारकों के परिप्रेक्ष्य में घरेलू वृद्धि घटी

1.7 घरेलू जीडीपी वृद्धि पिछले वर्ष रही 8.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 के दौरान 6.5 प्रतिशत पर आ गई जो वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चक्रीय तथा संरचनात्मक कारकों के चलते थी। यह प्रवृत्ति कई ईडीई,विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करता है (चार्ट 1.6)।

1.8 विशेष उल्लेखनीय है कि तिमाही वृद्धि दरें पिछली चार तिमाहियों से गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती आ रही हैं जबकि चौथी तिमाही की वृद्धि दर घटकर 5.3 प्रतिशत पर जा पहँची-7 वर्षों के दौरान तिमाहियों में सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि दर थी(चार्ट-1.7)।

चार्ट 1.6 : ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी वृद्धि

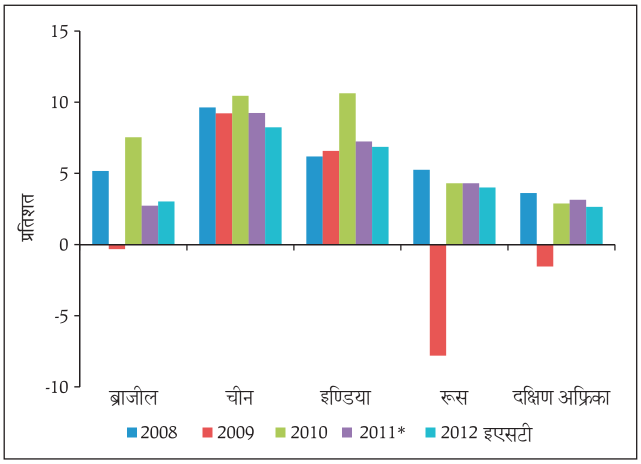

*दक्षिण अफ्रिका के लिए अनुमानित आंकड़े
स्रोत: आईएमएफ डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2012

चार्ट 1.7 : तिमाही जीडीपी वृद्धि में प्रवृत्तियां (वर्ष-दर-वर्ष)

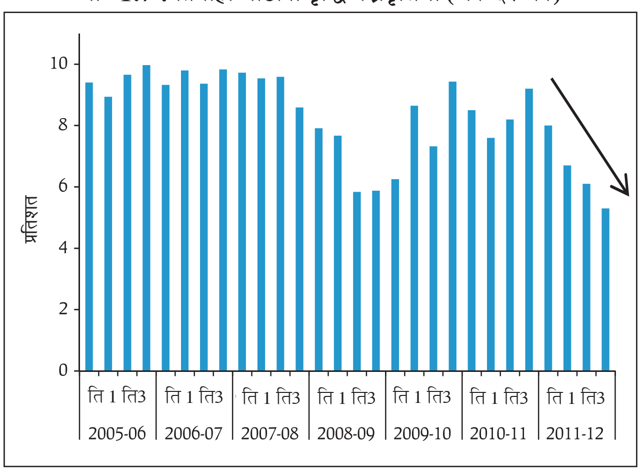

स्रोत: सीएसओ

1.9 सभी प्रमुख क्षेत्रों में यह मंदी देखने को मिली। कृषि क्षेत्र में जो 2.8 प्रतिशत की वृद्धि रही है वह बेस प्रभाव (2010-11 में कृषि वृद्धि दर लगभग 3.0 प्रतिशत प्रवृत्ति दर के मुकाबले 7.0 प्रतिशत थी) के कारण थी। औद्योगिक गतिविधियों में आई मंदी के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की कमजोर मांग, ब्याज दर की संवेदनशीलता,बाह्य मांग में घटी और उम्मीद से कम निवेश की मांग तथा साथ ही ब्याज दर के प्रचलित परिवेश के बीच कारोबारी विश्वास में कमी जिम्मेदार हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 2010-11 में रही 7.6 प्रतिशत की दर 2011-12 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई। इसी कालावधि में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हो गई और क्षेत्र के कई सेगमेंट में यह गिरावट पाई गई।

कारपोरेट निवेश में मंदी और निवल निर्यात में कमी के कारण कुल मांग में गिरावट आ गई....

1.10 वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान घरेलू मांग के सभी मुख्य कारकों में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 1.8)। वर्ष 2010-11 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में बाजार मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद तेजी से घटकर 6.9 प्रतिशत हो गया जिसका प्रभाव कुल मांग के सभी घटकों जैसे खपत (निजी और सरकारी), निवेश और निवल निर्यात पर दिखा। निवेश में कमी का प्रभाव विशेषकर सन्निकट और मध्यम अवधि की वृद्धि संभावना पर पड़ेगा।

... बचत और निवेश दर में कमी से चिंताएं बढ़ी हैं

1.11 वर्ष 2010-11 में निवेश और बचत दर दोनों में कमी आई। सकल घरेलू बचत दर 2009-10 में 33.8 प्रतिशत थी जो वर्ष 2010-11 में घटकर 32.3 प्रतिशत हो गई जबकि सकल पूंजी निर्माण 36.6 प्रतिशत से घटकर 35.1 प्रतिशत हो गया। घरेलू और वैश्विक वृद्धि संभावना, उच्च ब्याज दर और बढ़ते सामग्री मूल्य के प्रभाव के कारण कारपोरेट पाइपलाइन निवेश संकुचित हो गया है और नए निवेशों में मंदी बनी हुई है। इन प्रवृत्तियों के कारण निकट समय में घरेलू वृद्धि में उन्नति की संभावना कम है।

1.12 वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर आगामी तिमाहियों में घरेलू वृद्धि पर पड़ता रहेगा। आगे वर्ष 2012-13 में वृद्धि में गिरावट जोखिम बने रहने की संभावना है, विशेषकर यदि मानसून लंबी अवधि औसत से काफी कम हुआ तो। अप्रैल 2012 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मात्र 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि मई 2012 के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक के सूचकांक (पीएमआई) ने यह संकेत दिया है कि औद्योगिक गतिविधि में विस्तार हुआ है लेकिन इस विस्तार की गति काफी कम हो गई

चार्ट 1.8 : देशी मांग में वृद्धि

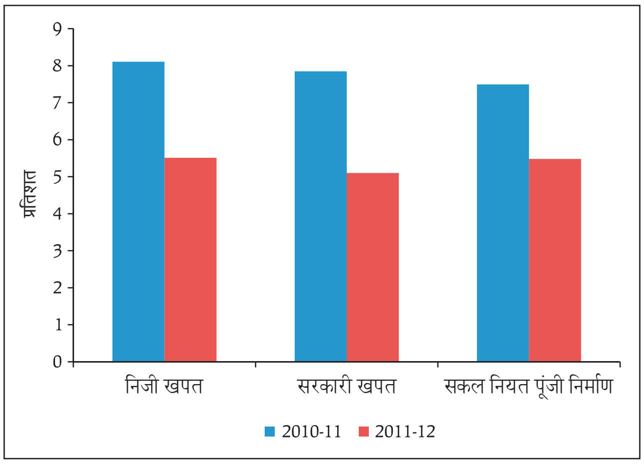

स्रोत: सीएसओ

है। मांग की स्थिति में सुधार हो सकता है हालांकि कम पाइपलाइन निवेश के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है लेकिन जोखिम बना हुआ है

1.13 हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में गिरावट प्राय: अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों के दाम में मौसमी कमी जैसे अस्थायी कारकों के कारण दर्ज की गई है। हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जो अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक थी, मार्च 2012 के अंत तक घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 प्रतिशत के सांकेतिक अनुमान क बराबर है। प्रारंभ में, यह कमी खाद्यान्न के मूल्यों में कमी के कारण हुई और उसके बाद विनिर्मित खाद्येतर वस्तुओं की मुद्रास्फीति में कमी के कारण हुई जो दो वर्ष की अवधि में पहली बार घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई थी। हालांकि बाद में हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2012 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक पहुंच गई जो मुख्यत: खाद्यान्न और ईंधन की मूल्यवृद्धि के कारण हुआ (चार्ट 1.9)। अत: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) मुद्रास्फीति (नई सीरीज़ आधार वर्ष ॐ 2010 के अनुसार गणना की गई) जनवरी 2012 के 7.7 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2012 में 10.7 प्रतिशत हो गई।

1;14 हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में घरेलू दबाव होने के बावजूद मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की संभावित प्रवृत्तियां, अग्रगामी रहते हुए, अनिश्चित बनी हुई है। इसके अलावा, रुपये के अवमूल्यन के दौर के बाद के प्रभाव से ऊर्जा और खाद में मुद्रास्फीति दबी रही और संभावित राजकोषीय कमी बड़ा खतरा बना रहा। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता कर सकती है और कम-से-कम रुपये के आंशिक अवमूल्यन द्वारा इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। समग्र मुद्रास्फीति के परिदृश्य में मुद्रास्फीति का जोखिम उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है, यहां तक कि वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट की स्थिति में भी, जो आपूर्ति संबंधी अवरोधों और जिद्दी मुद्रास्फीति अपेक्षाओं की ओर इंगित करती है।

बाह्य क्षेत्र में सुभेद्यता के संकेतकों की स्थिति बदतर हुई है जिससे जोखिम गहराया है

1.15 समीक्षाधीन अवधि के दौरान बदतर हो रहे चालू खाता घाटे, बढ़ते विदेशी कर्ज और निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की कमजोर स्थिति के कारण बाह्य क्षेत्र की स्थिति कमजोर हुई है।

चार्ट 1.9 :चुनिंदा पण्यों के थोक मूल्यों में तीव्र वृद्धि

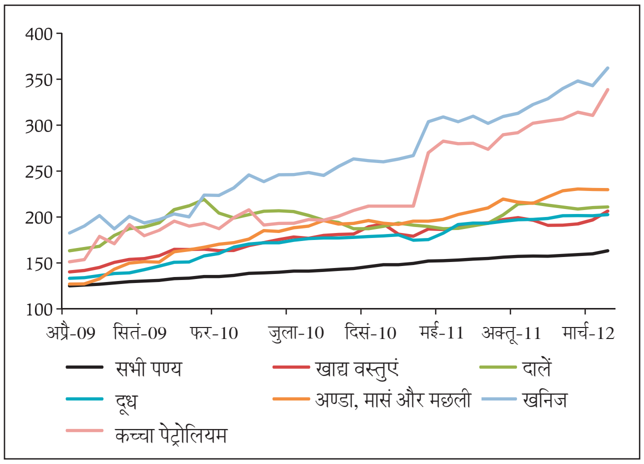

टिप्पणी : आधार 2004-05 = 100
स्रोत: भारत सरकार

1.16 बाह्य क्षेत्र में सुभेद्यता के सभी संकेतक यथा आयातों के रिज़र्व कवर, कुल विदेशी कर्ज की तुलना में अल्प अवधि के कर्ज का औसत, कुल कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार का औसत, डेट सर्विस औसत और एनआईआईपी-जीडीपी औसत में गिरावट आई है।

मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के कारण चालू खाता घाटे का जोखिम बढ़ा है.....

1.17 वैश्विक स्तर पर मांग की कमी और तेल आयात की स्थिति में बदलाव न होना व्यापार घाटे का मुख्य कारण रहा। गैर-तेल आयात उच्च स्तर पर रहने के कारण घाटे पर दबाव आगे और बढ़ता गया।

1.18 अनिश्चित वैश्विक स्थिति के कारण निकट भविष्य में चालू खाता घाटा उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। यद्यपि निर्यात बाजार को ईडीई में परिवर्तित करने के कारण निर्यात मांग में वृद्धि हुई थी लेकिन निर्यात वृद्धि निम्न स्तर पर बने रहने की संभावना है क्योंकि एई में मंदी के कारण ईडीई पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है। वृद्धि में गिरावट और मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद वृद्धिशील चालू खाता घाटा मांग-आपूर्ति असंतुलन को दर्शाता है और इंगित करता है कि आपूर्ति संबंधी अवरोधों को तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में कमी और हाल क दिनों में स्वर्ण आयात में कमी के कारण विदेशी घाटे का दबाव थोड़ा कम हो सकता है। सॉफ्टवेयर निर्यात, बिजनेस सेवाओं और निवेश आय में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां कम हुई जिसके कारण चालू खाते घाटे का खतरा बना हुआ है।

.....विदेशी घाटे को फाइनैंस करने में जोखिम बढ़ना

1.19 हाल के महीनों में चालू खाता घाटे को फाइनैंस करने में जोखिम बढ़ा है। यूरोप के बैंकों द्वारा डिलीवरेजिंग करने जैसी वैश्विक गतिविधियों के कारण पूंजी प्रवाह पर, विशेष तौर पर भारत जैसे उभरते बाजार पर प्रभाव बढ़ा है (अध्याय-II)। हाल ही में पूंजी आगमन में कमी के कारण चालू खाता घाटे को विदेशी मुद्रा रिजर्व में से फाइनैंस करना आवश्यक हो गया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इससे अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र संबंधी आघात सहनीयता कम हुई है।

1.20 भविष्य में पूंजी आगमन वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थितियों के साथ-साथ उभरते घरेलू मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण पर निर्भर करेगा जिसमें घरेलू नीतिगत सुधार भी शामिल है। मंदी, रेटिंग एजेंसिज द्वारा डाउनग्रेड किए जाने की संभावना और घटते विनिमय दर जैसे घरेलू कारकों की वजह से पूंजी आगमन पर प्रभाव पड़ सकता है। ये सभी कारक चालू खाता घाटे को फाइनैंस करने में चुनौती पेश करेंगे।

सारणी 1.1 : बाह्य क्षेत्र भेद्यता संकेतक

	जून 2011 के अंत में	सितं 2011 के अंत में	दिसं 2011 के अंत में
आयात का रिज़र्व कवर (महीने में)	9.2	8.5	7.7
कुल बाह्य ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	21.6	22.1	23.3
कुल बाह्य ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा रिज़र्व (%)	99.6	96.2	88.6
ऋण चुकौती अनुपात (%)	4.8	5.2	7.9
जीडीपी (वार्षिक) अनुपात में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (%)	-12.4	-11.4	-12.0

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

पूंजी आगमन बढ़ाने के लिए हाल में किए गए उपायों से इन जोखिमों को दूर किया जा सकता है

1.21 बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) और एनआरआई डिपॉजिट के रूप में आगमन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। ईसीबी दिशानिर्देशों में ऑल-इन-कॉस्ट सीलिंग बढ़ाने और अन्य छूट देने से कारपोरेट जगत के लोग विदेश से अधिक उधार ले सकेंगे। साथ ही, नवंबर 2011 में एनआरआई और एनआरओ खातों पर ब्याज दर पर विनियमों को हटाकर और मई 2012 में एफसीएनआरबी पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा बढ़ाकर अनिवासी भारतीयों से जमाराशि इकट्ठा करने में बैंकों को अधिक छूट दी गई है। निर्यातकों से यह कहा गया है कि वे विदेशी मुद्रा की जमाराशि को ईईएफसी खातों में घरेलू करेंसी में बदलें। भारतीय कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड में एफआईआई निवेश की सीमा बढ़ाकर 25 बिलियन अमेरिकी डालर कर दी गई है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 20 बिलियन अमेरिकी डालर कर दी गई है। ऐसे उपायों से विदेशी क्षेत्र पर दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सहायता से बाह्य जोखिम को कम किया जा सकता है.......

1.22 यदि बजट घाटा बढ़ता है और निजी क्षेत्र बचत तथा निवेश शेष यथावत रहते हैं, तो उच्च राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चालू खाता घाटे को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध तेल की कीमतों का है। चूंकि घरेलू बाजार में कई पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें नियंत्रित हैं और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से अछूते नहीं हैं, अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने से घरेलू अर्थव्यवस्था की मांगों में कोई कमी नहीं आने के परिणामस्वरूप आयात बिलों में बढ़ोतरी हो रही है और चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। दूसरी ओर पेट्रोलियन उत्पादों की कीमत वास्तविक कीमतों से कम रखने और घरेलू मांग में कोई कमी न आने से पेट्रोलियन पर दी

जाने वाली सब्सिडी बढ़ रही है जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है (चार्ट 1.10)।

.............और सोने का आयात घट जाएगा

1.23 चर्चा के अनुसार, तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और सोने के लिए घरेलू मांग निरंतर बने रहने के कारण आयात की अधिकता आगे बनी रहेगी। पारम्परिक रूप से भारत विश्व में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक रहा है। इससे जोखिम बढ़ने की सम्भावना है, क्योंकि सोने का घरेलू उत्पाद न के बराबर है और मांग पूरी करने के लिए हम पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हैं। 2011-12 में भारत ने 45 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का सोना आयात किया था, यह वर्ष-दर-वर्ष 03 प्रतिशत अधिक है (जबकि सोने का भौतिक आयात 1034 टन से घटकर 854 टन अर्थात 17 प्रतिशत कम हो गया था)। कुल आयातों में सोने के आयात का हिस्सा 10 प्रतिशत रहा। विभिन्न एजेंसी के माध्यम से सोने का आयात किया जाता है और बैंकों, एमएमटीसी लि.,स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आदि सोने का आयात करने के लिए प्राधिकृत हैं। सोने की कीमतों में प्रतिकूल चलन के कारण वाणिज्यिक बैंकों और और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लोन पोर्टफॉलियों में हानि हो रही है (अध्याय III)। हाल में किए गए नियंत्रित उपायों के कारण *अन्य बातों के साथ-साथ* सोने के आयातों में भी कुछ कमी आई है (चार्ट 1.11)।

1.24 भारत में सोने की मांग सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में इसके उपयोग के कारण बहुत अधिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में सोने के कुल आयातों में से 23 प्रतिशत का इस्तेमाल निवेश के उद्देश्य से होता है। 75 प्रतिशत सोना गहने के रूप में इस्तेमाल होता है वह भी एक प्रकार से घरेलू जरूरतों के लिए निवेश के रूप में काम आता है। बैंकों द्वारा लोगों को खुदरा बिक्री के लिए सोने के सिक्के का आयात करना चिंता का विषय है। बैंकों द्वारा 2009-10 में किए गए कुल आयातों में जहां यह मात्र एक प्रतिशत था वहीं यह 2011-12 में बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। घरेलू बचतों का उपयोग सोना खरीदने के लिए होना वित्तीय क्षेत्र को निधि उपलब्ध कराने पर प्रतिकूल असर डाल रहा है और इसका प्रभाव विकास पर भी पड़ रहा है। हाल के दिनों में सोने के निवेश से उच्च प्रतिफल मिलने के कारण मांग को मजबूती मिली है और इससे चालू खाता घाटे पर निरंतर दवाब बना हुआ है।

राजकोषीय जोखिम बढ़ रहा है......

1.25 वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय और प्राथमिक घाटे बढ़ने के साथ-साथ समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजकोषीय जोखिम

चार्ट 1.10 : दोनों घाटों के बीच संबंध

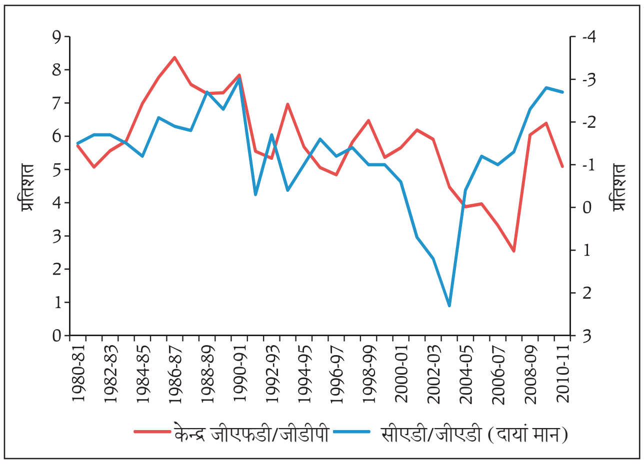

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 1.11 : स्वर्ण के आयात की प्रवृत्ति

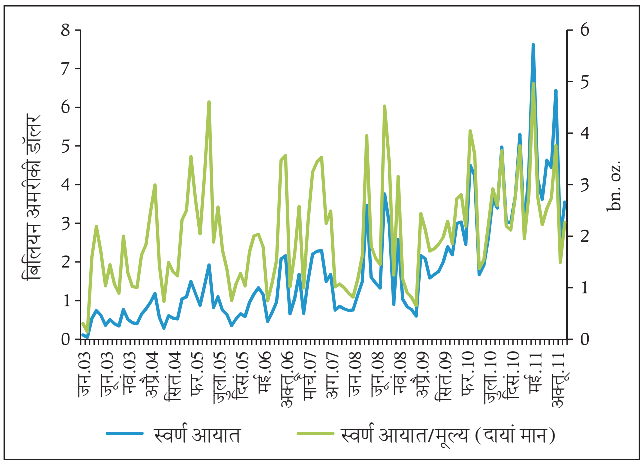

स्रोत: डीजीएसआईसी, ब्लूमबर्ग

बढ़ा है। सरकार द्वारा बाजार से अधिक उधारी लेने के कारण निजी निवेश घट सकता है जिसका दुष्परिणाम वृद्धि पर पड़ने के अलावे इससे मुद्रा प्रबंध के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। 2012-13 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्यत: केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के प्रयास पर आधारित है। जीएफडी-जीडीपी अनुपात में बजटीकृत कमी की प्राप्ति भी सरकार की इस प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी कि 2012-13 में सब्सिडी पर किए जा रहे खर्च को जीडीपी के दो प्रतिशत के निर्धारित कैप के अंतर्गत नियंत्रित रखा जाए।

....राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों में पाई जा रही प्रवृत्ति चिंता का कारण है

1.26 केन्द्र के राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों में पाई जा रही प्रवृत्ति कुछ परेशान करने वाली है। केन्द्र के कुल खर्च में राजस्व खर्च का हिस्सा बढ़ता जा रहा है और कुल खर्च में पूंजी खर्च का हिस्सा घटता जा रहा है (चार्ट 1.12 और 1.13)। सब्सिडी का भार निरंतर बढ़ने से सार्वजनिक निवेश घट रहा है, खासकर मौजूदा समय में जब निजी निवेश घट रहा है, चिंता का विषय है। एक और चिंता यह है कि केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा चक्रीय न होकर मुख्यत: संरचनात्मक बना हुआ है।

1.27 सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) की तुलना में राजस्व घाटे (आरडी) का अनुपात, जो वर्तमान खपत को वित्त उपलब्ध कराने के लिए उधार ली गई राशि के अनुपात को दर्शाता है, 2008-09 से अधिक मात्रा में बढ़ा है जिससे पूंजी निवेश के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम हुई है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने बजट में 2012-13 के लिए राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात को कमकर 68.7 रखा है जो 2011-12 में 75.7 प्रतिशत था (आरई) (चार्ट 1.14)।

हाल के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों से जोखिमों को कम किया जा सकता है.... लेकिन यह कर वसूली में ऊँची उछाल और सब्सिडी घटाने पर निर्भर है

1.28 यूनियन बजट 2012-13 ने सकल राजकोषीय घाटे के प्रति सकल रजकोषीय उत्पाद के अनुपात में 2012-13 के प्रारंभ से ही पर्याप्त कमी लाकर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का रोडमैप तैयार किया है और इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 'तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि' की प्राप्ति के लिए मंच तैयार किया गया।

1.29 आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय सुधार मुख्यत: राजस्व बढ़ाने पर केन्द्रीत रहेगा जिसके लिए सेवा कर के दायरे को बढ़ाया जाना, सेवा-कर के संबंध में छूट प्राप्त वर्गों की नकारात्मक सूची

चार्ट 1.12 : केंद्र के कुल व्यय में राजस्व व्यय का अनुपात

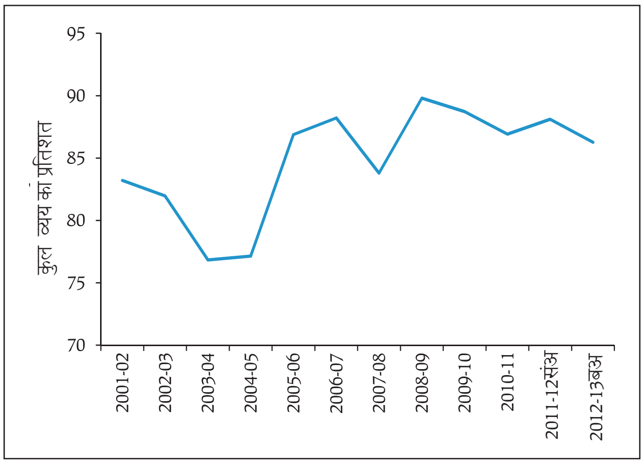

स्रोत: भारत सरकार

चार्ट 1.13 : केंद्र के कुल व्यय में पूंजी व्यय का अनुपात

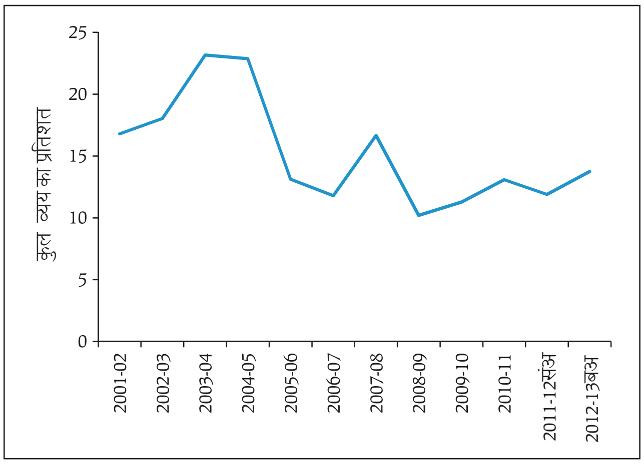

स्रोत: भारत सरकार

चार्ट 1.14 : केंद्र के कुल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अनुपात

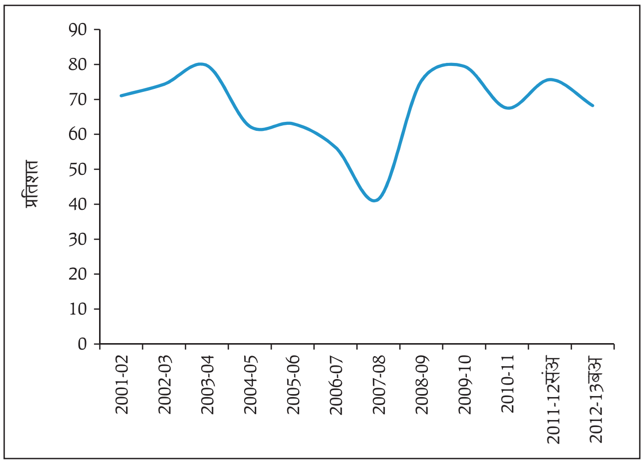

स्रोत: भारत सरकार

निर्धारित करना, सीमा-शुल्क दरों को संगत बनाना और विभिन्न अप्रत्यक्ष कर दरों में आपदा संबंधी की गई कटौती की आंशिक वापसी करना होगा। हालांकि 2012-13 में राजस्व परिणाम निर्भर करेगा बजटीकृत सकल कर की उछाल पर जो 2012-13 में 1.39 प्रतिशत रहा है, जो 2003-04 से 2011-12 तक की अवधि के 1.11 प्रतिशत और 2010-11 से 2011-12 तक की अवधि के 1.14 प्रतिशत के दीर्घावधि औसत कर उछाल की तुलना में उल्लेखनीय ढंग से अधिक है।

1.30 व्यय पक्ष को देखें तो 2012-13 के लिए केन्द्र सरकार के वित्त पर परोक्ष दबाव है। पेट्रोलियम सब्सिडी फ्रंट की बात करें तो कच्चे तेल की अंतर्राष्टीय कीमतों में देखी जा रही अस्थिरता और विनिमय दर में भारी उतार-चढ़ाव से कीमतों में वृद्धि का जोखिम बढ़ा है। खाद्यान्न सुरक्षा बिल के कार्यान्वयन के संदर्भ में देखा जाए तो 2012-13 में खाद्यान्न सब्सिडी पर 03 प्रतिशत की बजटीकृत वृद्धि कम प्रतीत होती है। इस पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत पर रखना स्वागतयोग्य कदम है और इसके लिए राजकोषीय कमी से बचने के लिए कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और उर्वरक की कीमतों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की अनुमति मिल सके।

पारिवारिक क्षेत्र (household) जोखिम कम हुआ है

1.31 समष्टि अर्थशास्त्र जोखिम नक्शे में देखी जा रही प्रवृत्तियों से पता चलता है कि पारिवारिक क्षेत्र के जोखिमों में कमी आई है। खुदरा क्षेत्र में चुकौती में चूक की स्थिति में कमी आई है जबकि खुदरा ऋण की वृद्धि धीमी हुई है। चूंकि भारत में डेट -फाइनैंस्ड खपत निरंतर कम रही है इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पूरी प्रणाली के लिए यह कोई बड़ा जोखिम खड़ा कर सकता है (चार्ट 1.15)।

लागत बढ़ने और मुनाफा घटने से कॉरपोरेट क्षेत्र जोखिम बढ़ा है

1.32 अर्थव्यवस्था में कॉरपोरेट क्षेत्र का स्वास्थ जोखिम उच्च ही बना रहा है। हाल के कॉरपोरेट परिणाम लाभप्रदता में गिरावट की ओर इंगित करते हैं जो कच्ची सामग्री में वृद्धि के कारण है, जिसमें ब्याज लागत और बाह्य तथा घरेलू मांग में कमी भी सम्मिलित है (चार्ट 1.16)। स्थिर तेल कीमत, विनिर्माण सामग्री कीमतों में बढ़ोतरी, विनिमय दरों में मूल्यह्रास के साथ जुड़ी उच्च आयात लागत और बाह्य तथा घरेलू मांगों में निरंतर कमी ने कॉरपोरेट क्षेत्र के तुलन-पत्र के जोखिमों का मुख्य स्रोत रहा है और इसे मॉनिटर करने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि हाल की औद्योगिक मंदी आगे कुछ समय तक बनी रहेगी।

चार्ट 1.15 : खुदरा ऋण, एनपीए तथा पीएफसीई में वृद्धि

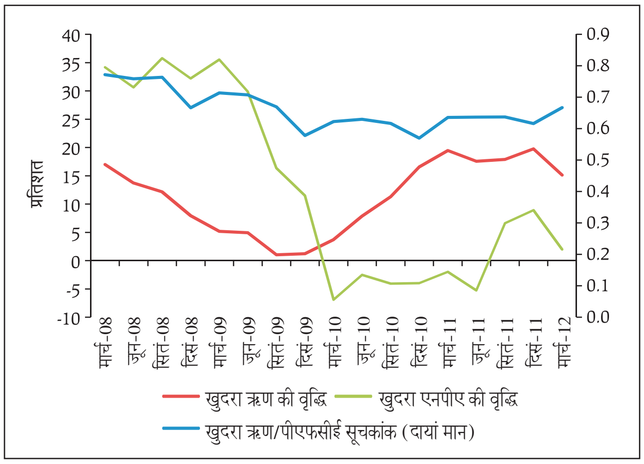

पीएफसीई: निजी अंतिम खपत व्यय
रिट क्र : रिटेल क्रेडिट
स्रोत : सीएसओ, भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 1.16 : कम होते लाभ मार्जिन तथा बढ़ती ब्याज लागत

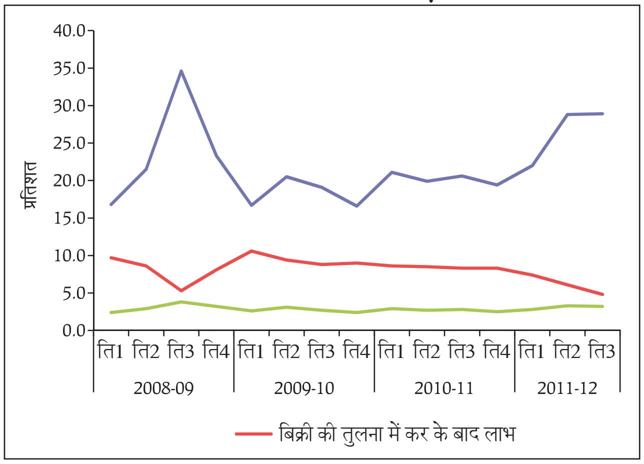

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्याय II
वित्तीय बाजार

पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में सोवरेन जोखिम, बैंकिंग क्षेत्र में अनिश्चितता और सोवरेनों एवं बैंकों के समक्ष निधियों के लिए तनावों के कारण यूरो क्षेत्र में भय, अनिश्चितता और जोखिम से बचने का माहौल बना रहा। नीति निर्माताओं को नयी चुनौतियों के मद्देनज़र आशंकाओं के समाधान के लिए बाजार को स्थिर रखने की दृष्टि से निरंतर नये-नये उपाय करने पड़े। पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारों और केन्द्रीय बैंकों द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए गैर पारम्परिक नीतिगत उपाय प्रारम्भ किये गये हैं। इन उपायों से वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं को अस्थायी तौर पर राहत तो मिली है परंतु संरचनात्मक प्रकृति की समस्यायें बरकरार हैं जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को अभी भी खतरा बना हुआ है। 2012 के शुरुआत में परिवेश में सुधार भी उत्साहवर्धक परिणाम नहीं ला पाये क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के लिए कठोर किफायती उपायों ने स्थिति को कठिन बना दिया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान यूरोपीय मौद्रिक यूनियन से ग्रीस बाहर होने की चिंताओं ने अनिश्चितता को और बढा दिया है। भारत में विकास में गिरावट के रुख, बढ़ते चालू खाते के घाटे और राजकोषीय अंतर से निवेशकों का विश्वास क्षय होने की ओर बढ़ रहा है। बाहरी झंझावातों से घरेलू वित्त और बांड बाजार अपेक्षाकृत अप्रभावित रहे हैं परंतु विदेशी मुद्रा और इक्विटी बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता बनी रही। विदेशी मुद्रा बाजार में दखल और प्रशासनिक उपायों के मिश्रण से विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव को कम करने में मदद मिली है। भारतीय इक्विटी बाजार वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित रहेगा।

1. वैश्विक बाजार

यूरोपीय ऋण संकट के बरकरार रहने की वित्तीय बाजार पर छाया

2.1 वित्तीय संकट के शुरुआती दौर से ही यूरोपीय सोवरेन ऋण संकट ने सोवरेनों और यूरोपीय बैंकों के लिए निधियन तनाव पैदा किये हैं। इन तनावों में 2011 के अंत में और बढोतरी हुई है। ग्रीस के लिए राजकोषीय राहत की मात्रा के निर्धारण पर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। यूरोपीय बैंकों और सोवरेनों की साख दर में गिरावट ने वित्तीय बाजारों पर दबाव को और बढ़ा दिया है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नीति समर्थन से परिवेश में अस्थायी सुधार

2.2 अमरीकी आर्थिक आँकड़ों के अपेक्षा से अधिक मजबूत रहने और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दिसम्बर 2011 में प्रथम त्रिवर्षीय एल टी आर ओ के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि 2012 के आरम्भ में बाजार परिवेश में परिवर्तन का मुख्य कारण है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने एल टी आर ओ के विषय में दिसम्बर 2011 में पहली और फरवरी 2012 में दूसरी बार अनुवर्ती कार्रवाई की और इस उपाय से 1 ट्रिलियन यूरो का नीति समर्थन मिला। दबाव झेल रहे सोवरेन और बैंकों को एल टी आर ओ[1] से वित्त उपलब्ध हुआ। बैंक और सोवरेन के सी डी एस स्प्रैड में महत्त्वपूर्ण रूप से सख्ती आयी है। अमेरिकी डालर निधियन बाजार पर दबाव में राहत देखने में आयी है (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: अमरीकी डालर तथा यूरो में 2012 में मनी मार्केट स्प्रेड

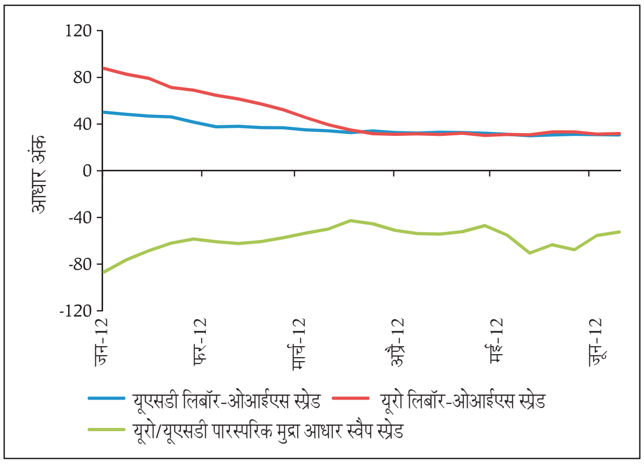

स्रोत: ब्लूमबर्ग

[1] यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा रेपो ओवरनाइट, साप्ताहिक और मासिक आधार पर किया जाता है। वित्तीय संकट के दौरान 1 वर्ष की परिपक्वता की लम्बी अवधि के लिए रेपो किया जाने लगा। इस कार्यक्रम को और बढ़ाकर असीमित राशियों के साथ तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया और संपार्श्विक प्रतिभूतियों की गुणवत्ता और प्रकृति को भी काफी उदार बनाया गया।

सोवरेन ऋण धारणीयता के मामले में दुश्चिन्ताएं फिर सामने...

2.3 नीतिगत उपाय निरंतर राहत प्रदान करने में विफल रहे। 2011 के अंत में तथा 2012 के प्रारम्भ में गैर पारम्परिक मौद्रिक नीति उपायों के क्रम में विस्तृत वित्तीय बाजार सुधार धीमे हो गये। समीक्षाधीन अवधि के दौरान वैश्विक बाजार ग्रीस की वजह से बढ़े हुए जोखिम से चिंतित रहे (देखें बाक्स 2.1)। यूरोप में राजकोषीय जोखिमों के लिए लक्ष्मणरेखा को बढ़ाया गया है लेकिन स्पेन और इटली जैसे बड़े संसर्गी देशों को समर्थन में संदेह ने बाजार के प्रति विश्वास को कमजोर किया है।

...सोवरेन बांड्स पर स्प्रैड में विस्तार

2.4 स्पेन और इटली के सोवरेन सीडीएस स्प्रैड में काफी विस्तार किया गया है (चार्ट 2.2)। अनेक संस्थाओं ने यूरोजोन की आपदाग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं वाले सोवरेन बांड्स के मामले में ऐसे बांडों की धारिताओं को (अत्यधिक अस्थिरता के कारण) नकारात्मक परिस्थितियों और उच्चतर आनुमानिक हानियों के कारण जोखिम सीमाओं को कम कर दिया है। इस परिस्थिति के कारण संस्थाओं की बांड्स खरीदने में रुचि कम हो गयी और इससे उनकी तरलता प्रभावित हुई है। बांडों, स्टॉकों और विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर्निहित अस्थिरता के कारण परिवेश में अनिश्चितता का माहौल है (देखें चार्ट 2.3)।

संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

2.5 कुछ यूरोपीय बैंक होलसेल निधियन पर अभी भी बहुत अधिक निर्भर हैं परंतु बैंक उधार की परिपक्वता अवधि वर्तमान हालत के कारण कम कर दी गयी है। साथ ही असुरक्षित निधियों की ओर उनकी पहुँच में गिरावट हुई है। ऐसी अस्थिरता से बैंक

चार्ट 2.2: 2012 में यूरोप में सोवरेन सीडी स्प्रेड

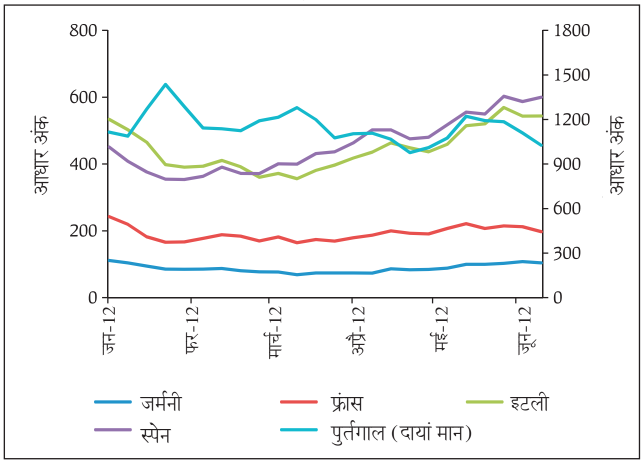

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.3: विभिन्न आस्ति श्रेणियों की अस्थिरता[2]

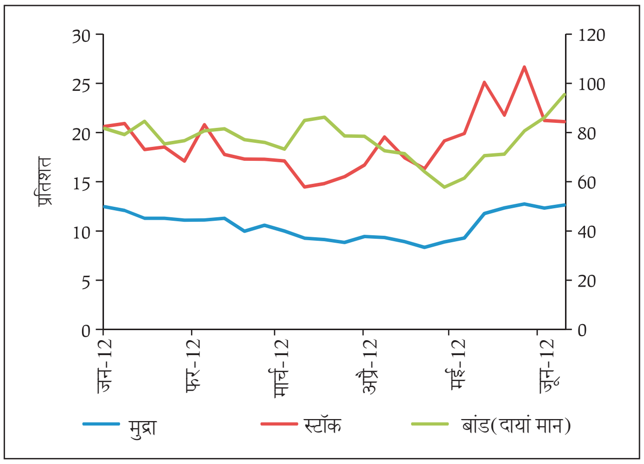

स्रोत: ब्लूमबर्ग

बाक्स 2.1: ग्रीस की अनिश्चितता

अपेक्षानुरूप सीमा तक राजकोषीय परिस्थितियों में सुधार न हो पाने के कारण फरवरी 2012 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-योरोपीय यूनियन-योरोपीय सेंट्रल बैंक तीनों ने ग्रीस की मदद के लिए दूसरा पैकेज उपलब्ध कराया। दूसरी पुनर्संरचना में निजी बांड धारकों में 75% की सीमा तक प्रभावी कमी की गयी है ताकि ग्रीस पर ऋण भार कम हो सके। यूरोप के हाल ही के चुनावों के परिणाम मितव्ययी उपायों के कारण शासनकर्ता पार्टी के विरुद्ध रहे हैं। आयरलैंड और आइसलैंड के विरोधाभासी अनुभव ग्रीस की स्थिति के लिए संकेतक हैं। आयरलैंड यूरो करेंसी यूनियन का सदस्य भी है और उसकी विकास दर ऋणदाताओं द्वारा थोपे गये मितव्ययी उपायों के बावजूद अभी भी नकारात्मक बनी हुई है। इसके विपरीत अपनी मुद्रा के अवमूल्यन और घाटे को ऋणदाताओं के खाते में डाल कर आइसलैंड ने अच्छी विकास दर प्राप्त की है। यूरोपीय यूनियन की 0% की तुलना में आइसलैंड की विकास दर 2012 की पहली तिमाही में 4.5% रही। वस्तुत: आइसलैंड का सेंट्रल बैंक 2011 की तीसरी तिमाही से ब्याज दर में बढ़ोतरी कर रहा है। जून 2012 के दूसरे चुनाव के परिणाम ग्रीस के मौद्रिक यूनियन में शामिल रहने का समर्थन करते हैं।

[2] मुद्रा की आस्थिरता को यूरो/अमरीकी डॉलर की 1 माह की अंतर्निहित अस्थिरता द्वारा, इक्विटी की अस्थिरता को यूएस' वीआईएक्स इंडेक्स द्वारा तथा बांडों की आस्थिरता को यूएस ट्रेजरी के मेरिल लिंच मूव इंडेक्स द्वारा प्रकट किया जाता है।

निधियन बाजार निष्क्रियता की चपेट में आ जाते हैं और इससे बैंकों की केन्द्रीय बैंक की सहायता पर निर्भरता में काफी बढोतरी हुई है। मूडीज़ इनवेस्टर सर्विस नामक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जून 2012 के मध्य में रेटिंग कम करने के दूसरे दौर में 15 प्रमुख बैंकों की रेटिंग में एक से तीन स्तरों(नॉच) तक की कमी की है।

अग्रणी देशों में निभावात्मक मौद्रिक नीति के बाह्य प्रभाव

2.6 अमरीका में समष्टि निर्देशक धीमे सुधार के संकेत दे रहे हैं यद्यपि सुधार के जारी रहने बारे में स्थिति अनिश्चित है। अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निभाव वाली मौद्रिक नीति को जारी रखे हुए हैं। अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले अनेक देशों की नीतिगत दरें अब तक के इतिहास के सबसे निचले स्तर पर अथवा उसके आस-पास बनी हुई हैं और फिलहाल इसी स्तर पर बनी रहेंगी। यह स्थिति अधिक लीवरेज और ऋण मानकों को क्रमिक रूप से आसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। कार्पोरेट जारीकर्ता की दृष्टि में ईक्विटी की तुलना में बांड जारी करके निधियाँ जुटाना अधिक आकर्षक है। निगमित ऋणों में तेजी से बढोतरी प्रक्रिया में प्रणालीगत लीवरेज को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरों का निरंतर कम बने रहना वैश्विक वित्तीय बाजारों का रुख लाभकारी व्यवहार की ओर कर देगा (देखें चार्ट 2.4)।

II. घरेलू बाजार

विदेशी मुद्रा बाजार में भारी दबाव के संकेत

2.7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव के कारणों में यूरो क्षेत्र की गतिविधियाँ और वैश्विक समष्टि अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति शामिल हैं। वित्तीय बाजार स्थिरता मैप के दूसरे तीन घटक (देखें चार्ट 2.5) यथा बैंकिंग सेक्टर निधियन, ऋण और ईक्विटी बाजार तुलनात्मक समग्र रूप से यथास्थिति बने रहे। रुपये के मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट और उसकी अस्थिरता के कारण वित्तीय बाजार स्थिरता संकेतकों में वृद्धि (चार्ट 2.6) रही।

सोवरेन बांड प्रतिलाभ से राजकोषीय गिरावट

2.8 निरंतर तरलता की सख्त स्थिति और 2012-13 के लिए बजट में निर्दिष्ट सरकारी ऋणों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के कारण मार्च के अंत में और अप्रैल 2012 के शुरु में बांडों पर प्रतिलाभ में वृद्धि दर्ज हुई। बाद में ये दस वर्ष की परिपक्वता के साथ 8.5 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत की सीमा में बने रहे। राजकोषीय घाटे

चार्ट 2.4: यूएस तथा यूरो तथा भारतीय दरों के बीच ब्याज दर अंतर[3]

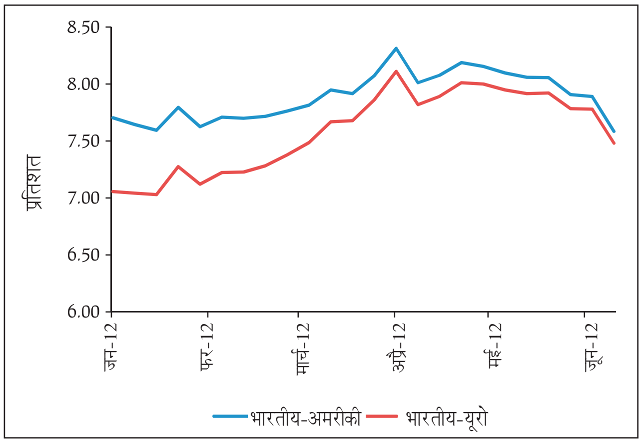

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.5: वित्तीय बाजार स्थिरता मैप

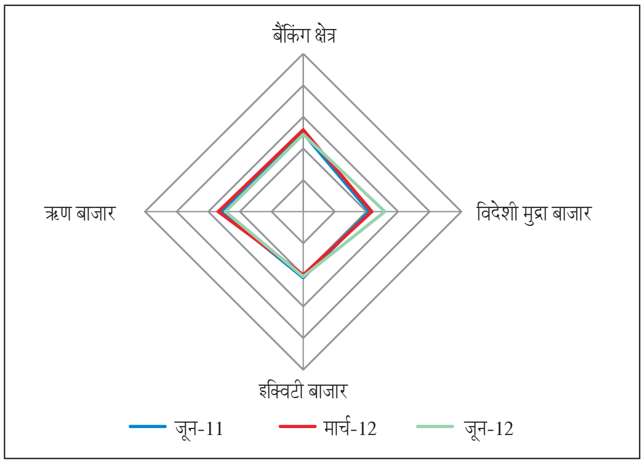

टिप्पणी : केन्द्र से दूरी उच्च जोखिम की दर को इंगित करती है।

चार्ट 2.6: वित्तीय बाजार स्थिरता संकेतक

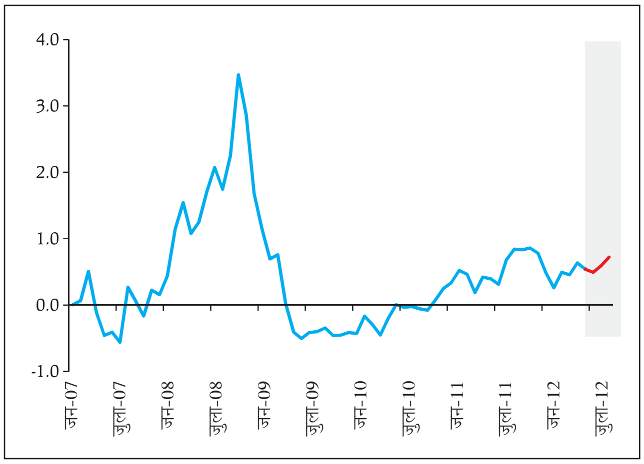

टिप्पणी : अधिक मूल्य उच्चतर जोखिम का द्योतक है। लाल रंग में रेखांकित भाग पूर्वानुमान दर्शाता है।

[3] निवेश के लिए भारत सरकार के बांडों पर दस वर्षीय दरें उपयोग में ली जाती हैं और उधार दरों के लिए अमरीकी डालर और यूरो लाइबोर दरें उपयोग में ली जाती हैं।

को उसके उच्च स्तर से नीचे लाने की सरकार की क्षमता के बारे में वित्तीय बाजार असंतुष्ट ही बने रहे। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार का सकल और शुद्ध उधार क्रमश: 5696 बिलियन रूपये और 4790 बिलियन रूपये माना गया। यह पिछले वर्ष के मुकाबले क्रमश: 11.7 और 9.8 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार ने बजट का केवल 2 प्रतिशत वित्त ट्रेजरी बिल के माध्यम से करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 2011-12 के 22 प्रतिशत से काफी कम है। अन्य बातों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की पॉलिसी दर में 50 आधार अंकों की कटौती 10 साल के सरकारी बांड से प्राप्त आय को 8 प्रतिशत के करीब ले आयी।

भारतीय सोवरेन बांड बाजार विदेशी दबाव से काफी हद तक अछूता रहा

2.9 समीक्षा अवधि के दौरान रेटिंग एजेंसियों एस एंड पी और फिच ने भारतीय संप्रभु ऋण और 11 बैंकों/संस्थानों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल कर स्थिर से नकारात्मक कर दिया। हालांकि रेटिंग दृष्टिकोण में हुए बदलाव की खबर पाकर सरकारी बांड से हुई आय में मामूली वृद्धि हुई लेकिन वह जल्दी ही पलट गई। चूंकि केंद्रीय सरकार अपतटीय बाजारों से उधार नहीं लेती है और विदेशी संस्थागत निवेश के माध्यम से बाहरी निवेशकों पर निर्भरता सीमित है, अत: इसका प्रभाव सीमित रहा।

मार्च की तंगी के बाद नकदी की स्थिति में सुधार आया

2.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय मुद्रा बाजार में तरलता की स्थिति सख्त रही चूँकि यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सुविधास्तर बैंक की निवल माँग और मीयादी देयता के एक प्रतिशत (+)/(-) से अधिक रही। दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नकदी का औसतन शुद्ध अंतःक्षेपण अप्रैल-सितंबर 2011 के लगभग 0.5 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर मार्च 2012 में लगभग 1.6 ट्रिलियन रुपये हो गया। मुद्रा संचलन में वृद्धि, सभी फर्मों के तिमाही कर खर्च और विदेशी मुद्रा बाजार की हस्तक्षेप कार्यवाही ने बैंकिंग प्रणाली से नकदी को सोख लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार के कार्य संचालन द्वारा और नकद आरक्षित अनुपात को 125 आधार अंक कम करके नकदी अंतःक्षिप्त की। प्रणालीगत तरलता सूचक बैंकों और दूसरों के लिए तरलता के वित्तपोषण में महसूस किए गए तनाव को दर्शाता है।

रेटिंग में बदलाव विदेशी मुद्रा ऋण की लागत और उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है

2.11 यूरोपीय बैंकों के बीच चल रही डीलीवरेजिंग प्रक्रिया से भारतीय कंपनियों और बैंकों के लिए उधार लागत बढ़ी है। छोटे

चार्ट 2.7: 2012 में भारत सरकार की बांड आय

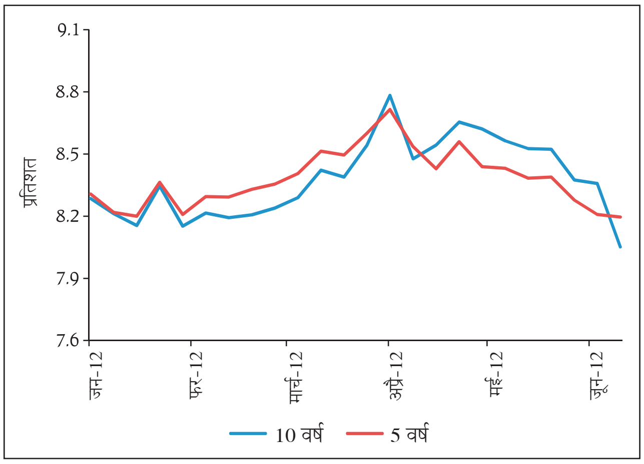

स्रोत : ब्लूमबर्ग

उधारकर्ताओं ने यह पाया कि धन उधार देने के उनके पारंपरिक तरीके वापस ले लिए गए हैं। भारतीय कंपनियों और बैंकों के विदेशी मुद्रा ऋण का अधिकांश भाग बांड के बजाय लोन (बाह्य वाणिज्यिक ऋण) के रूप में है। भारत की वर्तमान बाह्य रेटिंग बीबीबी (एस और पी तथा फिच के नकारात्मक आंकलन के साथ एवं मूडी द्वारा बीएए3) है। रेटिंग में बदलाव के कुछ 'क्लिफ प्रभाव' हो सकते हैं। यह भारतीय कंपनियों की भविष्य में ऋण उपलब्धता और मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इससे आगे चलकर भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण लाइनों की उपलब्धता और लागत दोनों प्रभावित हो सकती है। इसका असर भारतीय बैंकों द्वारा भी महसूस किया जाएगा क्योंकि भारतीय कंपनियों जैसे बायर्स क्रेडिट के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में निधि उपलब्ध कराने के ये प्राथमिक स्रोत हैं। अतीत में सरकारी क्षेत्र की भारतीय वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) एफआईआई ऋण में निवेश की बड़ी लाभार्थी थी। यह संस्थाएं भी विदेशी संस्थागत निवेश में कमी के प्रभाव का सामना कर सकती हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार अस्थिर बने रहे

2.12 देश के उच्च जुड़वां घाटे पर चिंता, उच्च वैश्विक व्यापक आर्थिक तनाव और यूरोपीय सार्वभौमिक ऋण संकट का फिर से उपस्थित होना रुपये के कमजोर होने का प्रमुख कारक रहा है। बाजार में तनाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप और प्रशासनिक उपायों के मिश्रण का उपयोग कर रहा है। रुपए के ह्रास ने ईडीई मुद्राओं की सामान्य प्रवृत्ति का पालन किया, विशेष रूप से वे जो उच्च चालू खाता घाटे वाली थी (चार्ट 2.8)।

आरक्षित निधि में मामूली गिरावट

2.13 आरक्षित निधि की पर्याप्तता बाहरी झटके को अवशोषित करने की देश की क्षमता को मापने में एक महत्त्वपूर्ण मानदंड के रूप में उभरी है। सितंबर 2011 के अंत में आयात कवर में गिरावट दर्ज हुई और यह मार्च 2011 के अंत में मौजूद 9.6 माह से गिरकर 8.5 माह हो गया। अल्पावधि ऋण के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात मार्च 2011 के अंत में 21.3 प्रतिशत था और यह सितम्बर 2011 के अंत में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। आरक्षित निधि के अस्थायी पूंजी प्रवाह के अनुपात में (संचयी पोर्टफोलियो प्रवाह और अल्पकालिक ऋण को शामिल करने के लिए परिभाषित) मार्च 2011 के अंत में मौजूद 67.3 प्रतिशत में वृद्धि हुई और सितम्बर 2011 के अंत में 68.3 प्रतिशत हो गया।

2.14 पूंजी प्रवाह की बदलती पृष्ठभूमि के साथ, आयात कवर के मामले में आरक्षित निधि की पर्याप्तता का आकलन करने के परंपरागत दृष्टिकोण को व्यापक बनाया गया और उसमें ऐसे मानदंड शामिल किए गए जो आकार, संरचना और विभिन्न प्रकार के पूंजी प्रवाह की जोखिम प्रोफाइल तथा साथ-साथ अर्थव्यवस्था को जोखिम पहुंचाने वाले बाह्य आघातों को भी ध्यान में रखते हैं। वर्तमान समय में आरक्षित निधि की पर्याप्तता के आकलन के लिए कुछ नए उपाय काम में लिए गए, जिनमें 'जोखिम में चलनिधि' (एलएआर) शामिल है। एलएआर दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि विदेशी मुद्रा की तरलता की स्थिति की गणना प्रासंगिक वित्तीय चरों जैसे विनिमय दरों, वस्तु की कीमतों, क्रेडिट स्प्रेड के लिए संभव परिणामों की सीमा के अंतर्गत किया जा सकता है।

हाल ही में आयी रुपये की कमजोरी का शेयर बाजार के परिवेश पर प्रभाव

2.15 2012 की प्रथम तिमाही में उभरते बाजार सूचकांक मोर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल ने 13.2 प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। भारतीय शेयर बाजार ने एशिया और अन्य बाजारों में हो रही गतिविधियों को प्रतिबिम्बित किया। प्रारंभिक आशा ईसीबी द्वारा बढ़ी हुई तरलता प्रदान करने से मिली और ग्रीस के दूसरे ऋण पैकेज से संबंधित अनिश्चितताओं का संकल्प जल्दी ही कम हो गया, भारत में (जैसी की विदेश में भी थी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई छँटनी ने भारतीय शेयर सूचकांकों में उनके दिसम्बर 2011 की कमी में सुधार किया। विदेशी निवेशकों को प्राप्त होने वाली अमेरिकी डॉलर के प्रतिलाभ की दर भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के साथ बदतर हो गई और इस कारण भारतीय इक्विटी (चार्ट 2.9) के प्रति आकर्षण कम हो गया।

चार्ट 2.8: चालू खाते घाटे के साथ ईडीई की मुद्राएं

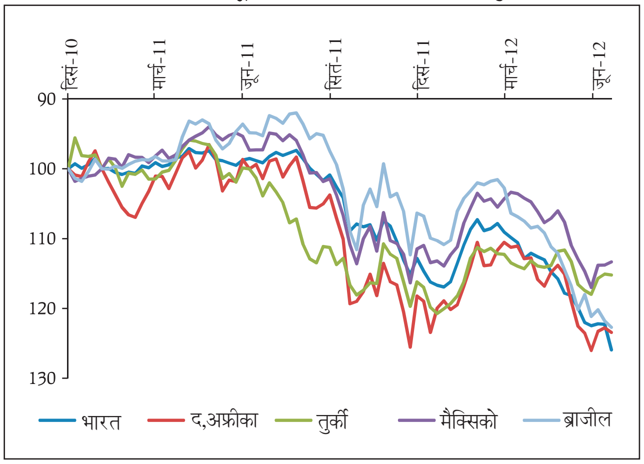

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.9: 2012 में निफ्टी और डैफ्टी[4] का साप्ताहिक लाभ

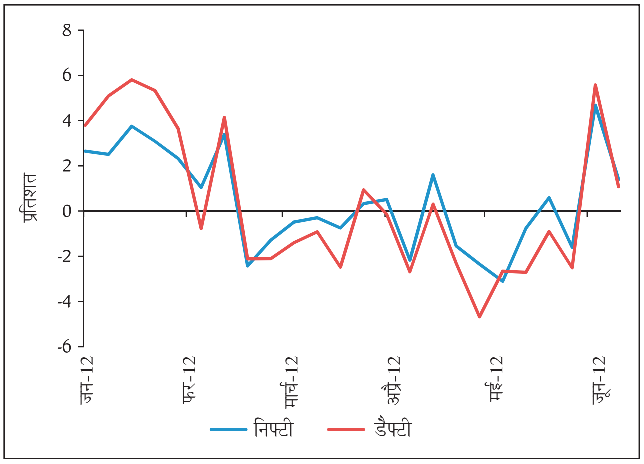

स्रोत: ब्लूमबर्ग

[4] डेफ्टी एस एंड पी सीएनएक्स डेफ्टी सूचकांक है और एनएसई निफ्टी सूचकांक का एक मूल्य डॉलर मूल्यवर्ग अनुसार है।

कुछ घटनाओं ने एल्गो और उच्च आवृत्ति ट्रेडों से संभावित खतरों पर प्रकाश डाला

2.16 हाल ही के समय में ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जब विभिन्न कारणों से भारतीय शेयर बाजार भारी अस्थिरता और रुकावट का साक्षी रहा है तथा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से एल्गोरिथम[5] (एल्गो) और उच्च आवृति ट्रेड (एचएफटी)[6] को बढ़ाने का मुख्य कारण हो सकता है। जून 2011 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने तकनीकी विकास जैसे भारतीय शेयर बाजार के लिए एल्गो ट्रेडिंग और एचएफटी सुविधाएं प्रदान करने वाले बाजार तक सीधी पहुंच (डीएमए)[7] की शुरुआत की ओर तेजी से बढ़ने पर होने वाले संभावित जोखिम प्रभावों का उल्लेख किया है। हाल ही के महीनों में भारत में नकदी कारोबार का लगभग केवल 17 प्रतिशत और 11 प्रतिशत ही क्रमश: एनएसई और बीएसई में एल्गो और एचएफटी के लिए लगा हुआ है। यह अनुपात यूएस और यूरोप के विकसित बाजारों की तुलना में काफी कम है।

2.17 भारतीय शेयर बाजार में पहले से ही कई विशेषताएं हैं जैसे शेयर (डेरीवेटिव कारोबार वाले) पर सर्किट ब्रेकर्स और सूचियां, बिना बैंड वाली प्रतिभूतियों के लिए छद्म मूल्य सीमा, क्वांटिटी अलर्ट चेक, समेकित लेखा परीक्षा परीक्षण और धोखेबाजी का पता लगाने एवं संभावित खतरों से निपटने के लिए अन्य जोखिम न्यूनीकरण प्रविधियां। नवोन्मेषों के लक्षित लाभों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण वाली तकनीकी प्रगति की आवश्यकता को संतुलित करने की जरूरत है। यह भारत के लिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण मान लिया गया है जैसे कि बाजार के बड़े संस्थागत चरित्र को बदलने के लिए भारतीय प्रतिभूतियां बाजार में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय बाजारों के व्यापक विकास के लिए यह आवश्यक है कि नियामक और नीति निर्माता वर्तमान प्राथमिकता के नजरिए से इस तरह के व्यापार के व्यापक प्रभाव का आकलन जारी रखें।

[5] एल्गो व्यापार समय, कीमत, या क्रम की गुणवत्ता जैसे पहलुओं पर निर्णय का निर्धारण एक कंप्यूटर प्रोग्राम (एल्गोरिथम) के साथ व्यापार में प्रवेश करने के आदेश, या कई मामलों में मानव हस्तक्षेप के बिना आदेश शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों का उपयोग दर्शाता है।

[6] एचएफटी एल्गो व्यापार का एक विशेष वर्ग है जिसमें इससे पहले कि मानव व्यापारी अपने द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्णय लें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्राप्त आर्डर को आरंभ करने के लिए बहुत तेज गति(माइक्रो सैकण्ड में) से विस्तृत निर्णय लेता है।

[7] सीधे बाजार पहुंच (डीएमए) वह सुविधा है जो दलाल द्वारा किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना ग्राहक को सीधे ही दलाल व्यापार की बुनियादी सुविधाओं (विनिमय व्यापार प्रणाली से सम्बद्ध) के उपयोग की अनुमति देती है, इससे कई लाभ होते हैं जैसे ग्राहक के ऑर्डर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और तेज निष्पादन। मैनुअल आदेश प्रविष्टियों के साथ जुडी त्रुटियों के कम जोखिम, अधिक से अधिक पारदर्शिता, तरलता में वृद्धि, बड़े ऑर्डरों पर कम प्रभाव लागत, बेहतर लेखा परीक्षा ट्रेल और व्यापार के लिए निर्णय का समर्थन करने वाले उपकरणों/एल्गोरिदम के प्रयोग के माध्यम से हेजिंग और अंतरपणन के अवसरों का बेहतर इस्तेमाल।

अध्याय III

वित्तीय संस्थाए: सुदृढ़ता और लचीलापन

सितंबर 2011 से बैंकिंग क्षेत्र की दशा थोड़ी सी खराब हुई है। पर बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक मजबूत बने रहे। आस्ति गुणवत्ता दबाब बना रहा ,जबकि ऋण वृद्धि कम हुई ,जो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मंदी को द्योतित करता है। जिस तरह ऋण और जमाराशि में वृद्धि के बीच अपसरण बढ़ा ,बैंकों की उधार ली धनराशि पर निर्भरता भी बढ़ गई,जिससे संबंधित तरलता जोखिम में भी वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 में भारतीय बैंकों के लिए ,कमजोर होते वैश्विक परिदृष्य, प्रतिकूल घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिति और नीतिगत अनिश्चिततताओं के बीच चुनौतीपूर्ण बने रह सकते हैं। भारत में बैंक उन्नत देशों में डिलवरेजिंग से प्रभावित हो सकते हैं परंतु प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित रह सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का क्रेडिट ग्रोथ घटा है। बैंकों को गोल्ड लोन कंपनियों से होने वाले जोखिमों पर लगाम कसने के लिए विनियामक अंकुश डाला गया है। बैंकों पर किये गये कई तरह के दबाब परीक्षणों से पता चलता है कि उनकी पूंजी स्थिति में आधारभूत परिदृष्य की तुलना में ह्रास हुआ है, परंतु बैंकिंग प्रणाली अतिश्य दबाबों के बाबजूद टिकी रही। कुछ बैंकों के पोर्टफोलियो डेरिवेटिवस पर किए गये कई परिदृश्य और संवेदनशीलता दबाब परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि वे परिणामी बाज़ार जोखिमों का सामना अच्छी तरह कर सकते हैं।

वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता

बैंकिंग स्थिरता मैप तथा संकेतक[1]

बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम कम नहीं हुए

3.1 जैसे कि बैंकिंग स्टेबिलिटी मैप से दिखाई पड़ता है कि बैंकिंग क्षेत्र में कमज़ोरियों ने मार्च 2012 में मिली-जुली प्रवृत्ति दर्शाई है। मज़बूती और लाभप्रदता संकेतकों ने दर्शाया है कि स्थिति में सितंबर अन्त 2011 के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। पर मज़बूती संकेतकों ने अपनी स्थिति में मार्च 2011 की तुलना में गिरावट दर्शायी है। आस्ति गुणवत्ता में खिंचाव और अधिक हो गया है। नकदी के अभाव से बैंकिंग क्षेत्र में तनाव में वृद्धि हुई।

3.2 बैंकिंग स्थिरता संकेतक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की स्थिति में सितंबर 2012 की तुलना में मार्च अन्त 2012 में गिरावट की ओर इंगित करते हैं। अगली 2 तिमाहियों के लिए संकेतकों ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके अनुसार निकटावधि में बैंक क्षेत्र को जोखिमों में कमी नहीं होने वाली है।

चार्ट 3.1: बैंकिग स्थिरता मैप

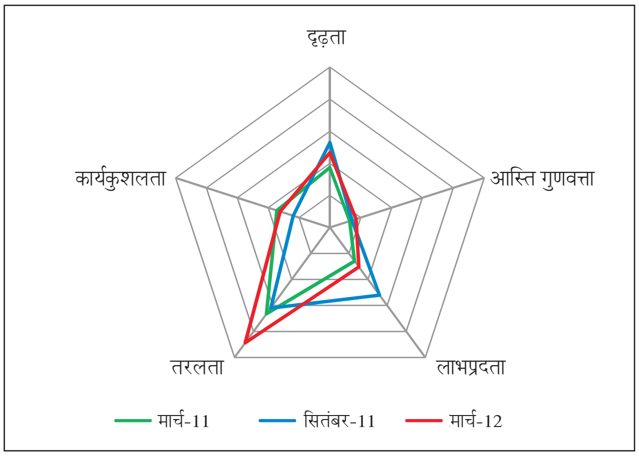

नोट: केन्द्र से दूरी जोखिम वृद्धि का द्योतक है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा परिकलन

चार्ट 3.2: बैंकिग स्थिरता संकेतक

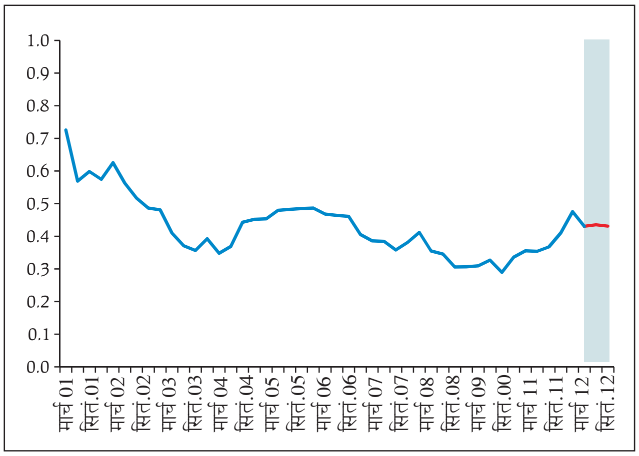

टिप्पणी : (i) संकेतक मूल्य में वृद्धि कम स्थिरता को दर्शाती है।
(ii) आच्छादित क्षेत्र द्वारा उल्लिखित पूर्वानुमान का जून 2012 और सिंतबर 2012 का मूल्य है।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ द्वारा परिकलन

[1] कार्यप्रणाली और जानकारी के लिए कृपया अनुबंध देखें

बैंकिग क्षेत्र में डिलिवरेजिंग की प्रवृति बने रहने की संभावना...

3.3. निधियन तनाव और सोवरेन जोखिम के मिलने से डिलिवरेजिंग प्रक्रिया तेज़ होने का डर पैदा हो सकता है, जिससे आस्तियों की बिक्री और ऋण में संकुचन के माध्यम से वित्तीय बाज़ार और व्यापक अर्थव्यवस्था को धक्का लग सकता है(अध्याय I और II)। बहुत से यूरोपियन बैंकों ने आस्तियां कम करने के लिए मध्यावधि व्यवसाय योजनाएं घोषित की हैं। इसका प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकता है, इसका अधिक प्रभाव एशि्या अथवा लातीनी अमरीकी की बनिस्वत उभरते यूरोप पर अधिक होने की उम्मीद है (सारणी 3.1)। भारतीय संदर्भ में, यूरोपीय बैंकों के दावों की राशि 146 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि समेकित विदेशी दावों का 53 प्रतिशत बनता है। इनमें से 56 प्रतिशत दावे युनाईटेड किंगडम से सबंधित हैं।

...घरेलू ऋण की उपलब्धता के लिए सीमित संभावनाएं

3.4 इस बात की प्रत्याशा है कि यूरोज़ोन संकट का भारतीय बैंकों पर सीधा असर अधिक नहीं होगा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में देशी बैंकों का प्रभुत्व है, समग्र बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों में विदेशी बैकों का हिस्सा 8 प्रतिशत और बैंकिंग क्षेत्र ऋण में 5 प्रतिशत है। परंतु अन्य देशों विशेषकर यूरोज़ोन में बैंकिंग निवेश के कारण उनका भारतीय बैंकों पर परोक्ष प्रभाव हो सकता है (चार्ट 3.3 एवं 3.4)।

3.5. घरेलू ऋण की उपलब्धता पर डिलिवरेजिंग का प्रत्यक्ष प्रभाव अधिक होने की संभावना नहीं है, फिर भी खास किस्म के वित्तपोषण जैसे कि स्ट्रक्चर्ड दीर्घवाधिक वित्तपोषण, परियोजना वित्तपोषण और व्यापार वित्तपोषण पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी 3.1 : यूरोपियन बैंकों के समेकित विदेशी दावे

	जून-2011	दिसं-2011
विकासशील यूरोप	1304	1137
विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र	935	841
जिसमें से भारत	159	146
विकासशील लातीनी अमरीकी और केरेबियन	855	770

स्रोत: लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकी - दिसंबर- 2011, बीआईएस

चार्ट 3.3: चुनिंदा बैंकों पर भारतीय बैंकों द्वारा दावे - दिसंबर 2011 की स्थिति

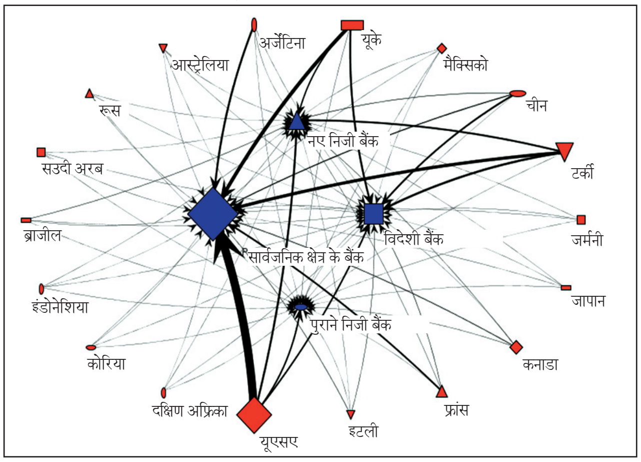

टिप्पणी: आंकड़े 50 बैंक के नमूमों से लिए गए हैं जो बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों का 90 प्रतिशत भाग है।

चार्ट 3.4 : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों के अनुपात के रूप में चुनिंदा देशों के भारतीय बैंकों पर दावे

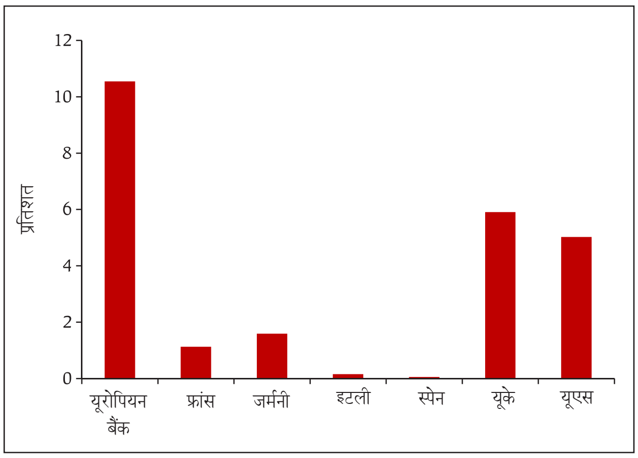

स्रोत: लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकी - दिसं. 2011, बीआईएस

अनुसूचित वाणिज्य बैंक(एससीबी)

ऋण और जमाराशि वृद्धि कमज़ोरियां, अर्थव्यवस्था में गहरी होती मंदी संबंधी चिन्ताएं

3.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वर्ष 2011-12 के दौरान 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2010-11 के 18. 8 प्रतिशत से कम थी। ऋण और जमा दोनों की वृद्धि दर में गिरावट परिलक्षित हुई। बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि की दर 2011 -12 में 16.3 प्रतिशत पर 2010-11 के 22. 6 प्रतिशत से कम थी। दो वर्षों के लिए वृद्धि दर क्रमशः 13.7 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत रही। 2011-12 के दौरान जमाराशियों में वृद्धि दर गत 10 वर्षों में सबसे कम रही।

3.7 मोटे तौर पर इन प्रवृत्तियों में अर्थव्यवस्था में मंदी परिलक्षित हुई है क्योंकि मामूली सा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरावट वर्ष 2010-11 में 18.8 प्रतिशत से गिर कर 2011-12 में 15.4 प्रतिशत रह गई। बैंकों की जमाराशियों की वृद्धि में गिरावट में छोटी बचत योजनाओं पर बाज़ार निर्धारित ब्याज दरों पर न्यून्तम मानदण्ड तय किये जाने और उच्च प्रतिफल वाली निधियों की उपलब्धता तथा उससे जुड़े कर संबंधी लाभों का भी योगदान हो सकता है।

कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में मंदी द्वारा संचालित ऋणों में मंदी...

3.8 ऋण वृद्धि में जो सुस्ती परिलक्षित हुई वह विशेष कर , प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, रियल एस्टेट और बुनियादी सुविधाओं के सेगमेंट में उल्लेखनीय है, जो कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र ऋणों का 60 प्रतिशत बैठता है (चार्ट 3.5)।

...और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मध्य

3.9 सुस्ती का यह आलम सबसे अधिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि में साफ दिखाई देता है जब कि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों ने ऋण वृद्धि में 24 प्रतिशत की तेज़ी दर्ज की। ऋण वृद्धि में जो प्रवृत्ति दिखाई दी वो थी पुराने निजी बैंकों द्वारा खुदरा और रियल एस्टेट क्षेत्रों को अधिक ऋण दिया जाना-यदि यह हालात बकरार रहता है तो ज़रूर इस की निगरानी की जानी चाहिए (चार्ट 3.6)।

ऋण और जमाराशि वृद्धि दर में भिन्नता के कारण ऋण जमाराशि अनुपात में वृद्धि हुई...

3.10 ऋण और जमाराशि (सीडी) अनुपात में जमाराशि और ऋण दर में फर्क की वजह से मार्च अन्त 2012 को 76 प्रतिशत इज़ाफा हुआ (सितंबर 2011 के 73.5 और मार्च 2011 के आखिर में 74.3 प्रतिशत के मुकाबले)। 88 प्रतिशत के साथ वृद्धिशील ऋण और जमाराशि (सीडी) अनुपात उच्च स्तर पर टिका रहा। वृद्धिशील निवेश जमाराशि (आईडी) अनुपात निवेशों में 17 प्रतिशत इज़ाफे के सहारे तेजी से बढ़े (चार्ट 3.7)।

चार्ट 3.5: चुनिन्दा क्षेत्रों को बैंक ऋण की वृद्धि दर

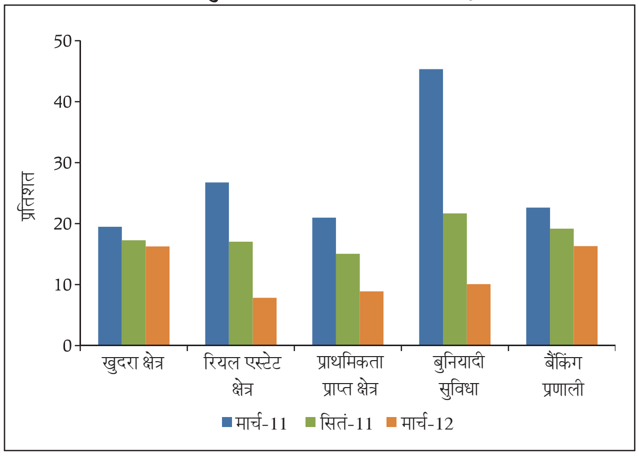

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 3.6: विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वृद्धि - बैंक समूहवार

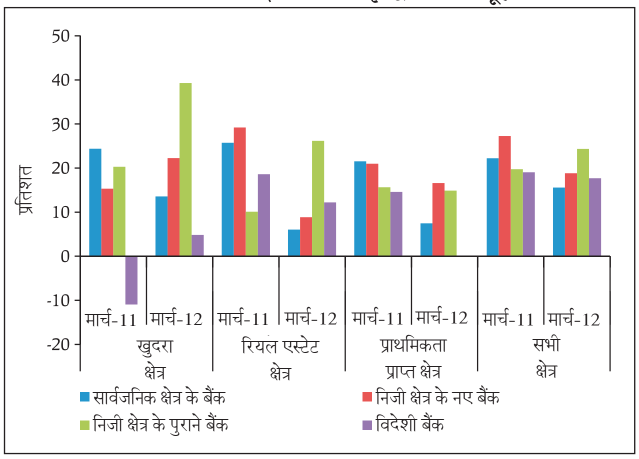

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 3.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीडी/आईडी अनुपात और वृद्धिशील सीडी/आईडी अनुपात

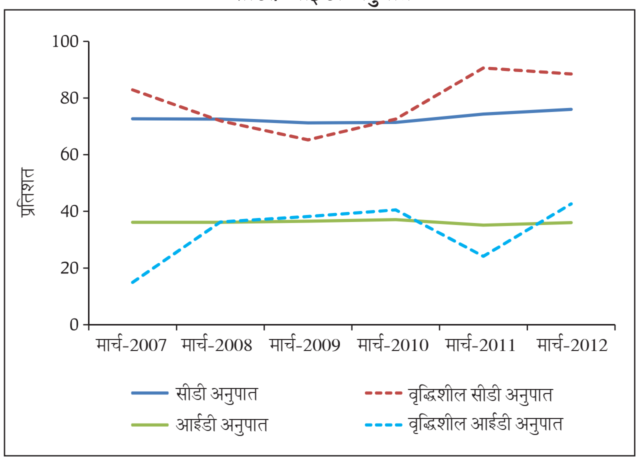

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

...और बैकों की निर्भरता उधार लिये गये फंडों पर बढ़ी

3.11 वर्ष 2011-12 के दौरान बैंकों को अपने ऋणों के निधियन एवं निवेश बढ़ाने के लिए उधारों पर निर्भरता और अधिक निर्भर होना पड़ा। इस के सबूत हैं अग्रिमों और निवेशों की मिली-जुली वृद्धि तथा जमाराशियों और पूंजी में चौड़ी होती खाई (चार्ट 3.8)। साथ ही बैंकों के बैलेंस शीट लघुआवधिक परिपक्वताओं में कोई सामंजस्य नहीं था (चार्ट 3.9)। इन प्रवृत्तियों से जुड़े रोलओवर और नकदी जोखिम आंके और नियंत्रित किए जाने चाहिए।

ऋण वृद्धि धीमी होने से पूजी अनुपात संभले

3.12 सितंबर 2011 से एससीबी के पूंजी अनुपातों में कुछ सुधार हुआ,इसका मुख्य कारण ऋण वृद्धि धीमी होना था। पर मार्च 2011 की स्थिति की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई। कैपिटल टू रिस्क वेटिड ऐसेट्स रेशो (CRAR) मार्च 2011 के 14.2 प्रतिशत से गिर कर सितंबर 2011 में 13.5 प्रतिशत रह गया परंतु मार्च 2012 में सुधरकर 14. 1 प्रतिशत हो गया। कोर सीआरएआर मार्च 2011 के 10 प्रतिशत से गिरकर सितंबर 2011 में 9.6 प्रतिशत हो गया लेकिन मार्च 2012 में सुधरकर 10.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.10)।

आस्ति गुणवत्ता को लेकर चिन्ताएं बरकरार रहीं क्योंकि उच्च एनपीए अनुपात बने रहे

3.13 अनर्जक आस्तियों में वृद्धि तीव्र होने से आस्ति गुणवत्ता चिन्ताएं बनी रहीं और यह ऋणवृद्धि से आगे ही रही। भारतीय रिजर्व बैंक (खंड V) द्वारा किये गये द्वितीय प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के प्रतिवादियों ने आस्ति गुणवत्ता की पहचान एक ऐसे चिन्ताजनक जोखिम के रूप में की है, जिसका सामना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने किया है।

3.14 जब सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2012 में मार्च 2011 के 2.4 प्रतिशत और सितंबर, 2011 में 2.8 प्रतिशत के मुकाबले 2.9 प्रतिशत हो गया। निवल अनर्जक आस्ति मार्च 2012 में मार्च 2011 के 0.9 प्रतिशत के मुकाबले 1.3 प्रतिशत थी। जब इसकी तुलना समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के साथ की गई तो निवल अनर्जक आस्ति का पूंजी के साथ अनुपात (प्रावधान का निवल) कम था (चार्ट 3.11)।

चार्ट 3.8: बैलेंस शीट के चुनिन्दा घटकों की वृद्धि दर

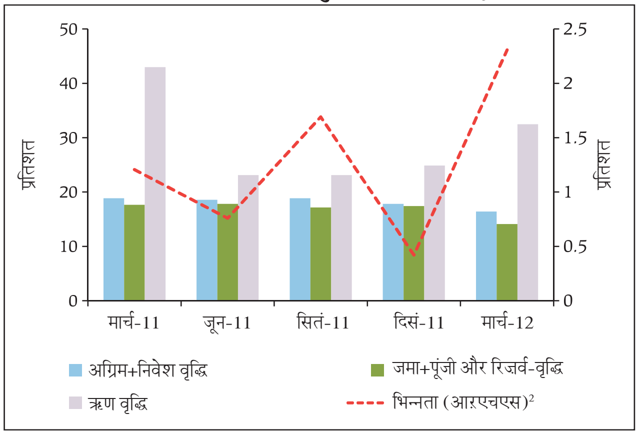

नोट: अग्रिम+निवेश-वृद्धि : अग्रिम और निवेश की वृद्धि दर
जमा+पूंजी और रिजर्व-वृद्धि : जमा, पूंजी और रिजर्व की वृद्धि दर
ऋण वृद्धि : ऋण की वृद्धि दर

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.9: जमाराशियों और अग्रिमों का परिपक्वता प्रोफाइल

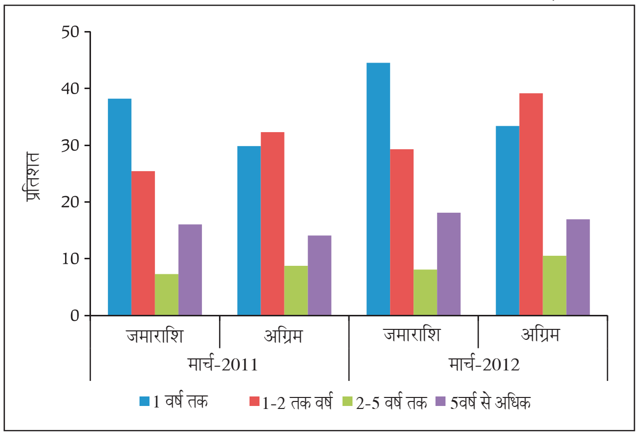

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.10: बैंक समूहों का सीआरएआर

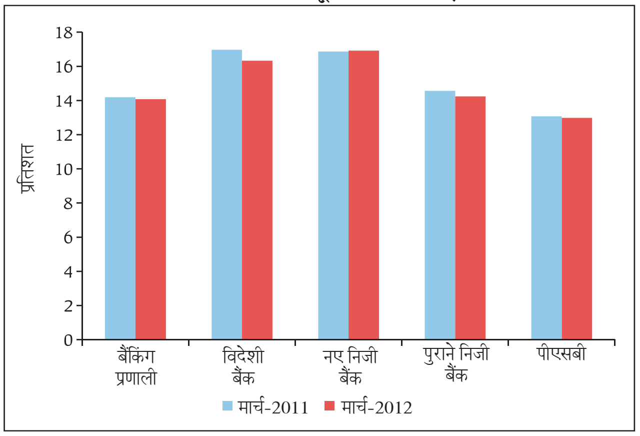

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

[2] विचलन अग्रिमों के विकास दर और निवेश और जमा और पूंजी के बीच के अंतर को दर्शाता है। एक सकारात्मक अंतर का तात्पर्य है कि वृद्धि की दर जमा और पूंजी अग्रिमों और निवेश की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे उधार ली गई रकम पर निर्भरता बढ़ी।

चार्ट 3.11: चुनिन्दा देशों में निवल अनर्जक आस्तियों का पूंजी के साथ अनुपात

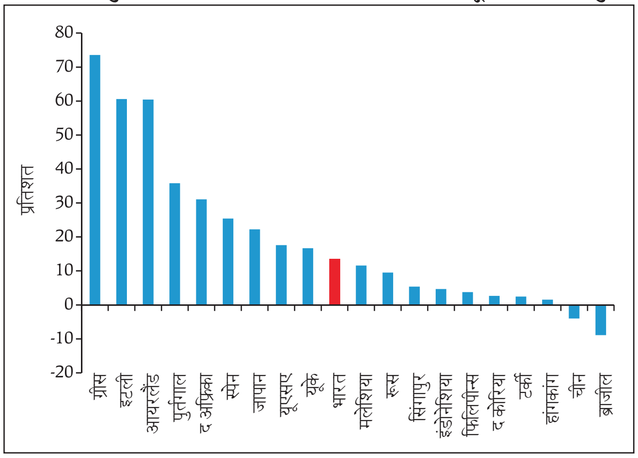

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता सूचक - दिसंबर 2011, आईएमएफ

चार्ट 3.12: ऋणों और अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों में संवृद्धि दर की प्रवृत्ति

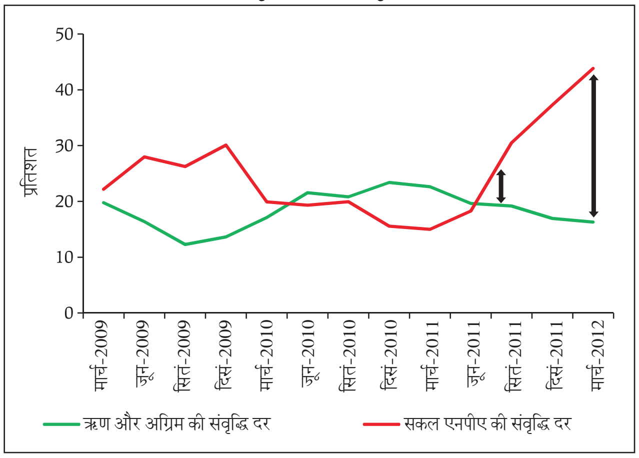

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

अनर्जक आस्ति में वृद्धि ने ऋण वृद्धि को बड़े अन्तर से पछाड़ा

3.15 मार्च 2012 में अनर्जक आस्तियों ने 43.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 16.3 प्रतिशत से बढ़ती ऋण वृद्धि को काफी पीछे छोड़ दिया। ऋण और अनर्जक आस्ति वृद्धि दर में विचलन हाल के दिनों में और अधिक हो गया है, जो निकट भविष्य में आस्ति गुणवत्ता पर दबाब डाल सकता है (चार्ट 3.12)।

अनर्जक आस्तियों में वृद्धि

3.16 मार्च 2011 में 1.6 प्रतिशत और सितंबर 2011 में 1.9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2012 के अंत में स्लिपेज अनुपात[3] बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया। स्लिपेज के अनुपात तथा वसूल की गयी राशियों (अपग्रेडेशन को छोड़कर) में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के अनुपात में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जिससे आस्ति गुणवत्ता के संबंध में चिंता तथा बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन दिखलाई पड़ता है (चार्ट 3.13)।

अग्रिमों का पुनर्गठन बढ़ रहा है...

3.17 वैश्विक वित्तीय संकट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े छींटों के कारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 के उतरार्ध में अस्थायी आधार पर पुनर्गठन के लिए कतिपय छूटों[4] की अनुमति दी गई,जिससे रियल सेक्टर को हो रही कठिनाईयों का सामना करने में मदद मिली। पर इससे वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान पुनर्गठित मानक आस्तियों के स्तर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई, जिसके बाद पुनर्गठित आस्तियों की मात्रा घटी। वर्ष 2011-12 में पुनर्गठित खातों की मात्रा में फिर से तेज से वृद्धि हुई। इस वृद्धि ने ऋण और सकल अनर्जक आस्ति में वृद्धि दर को तेजी से पीछे छोड़ दिया (चार्ट 3.14)।

चार्ट 3.13: वसूली के अनुपात के रूप में स्लिपेज

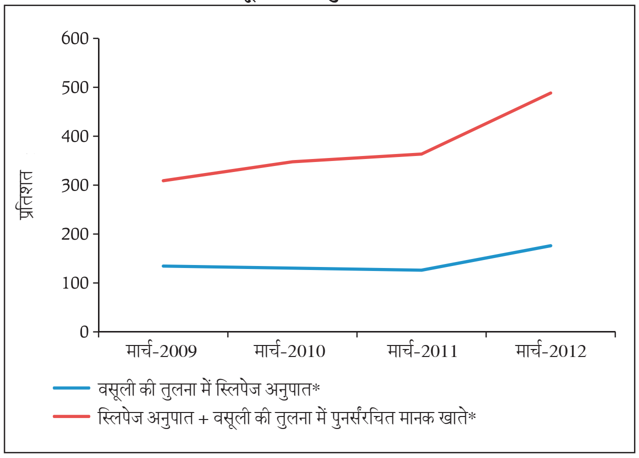

टिप्पणी: वसूलियों में बट्टे की रकम शामिल है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 3.14: अनर्जक आस्तियों और ऋणों की तुलना में पुनर्संरचित खातों में वृद्धि

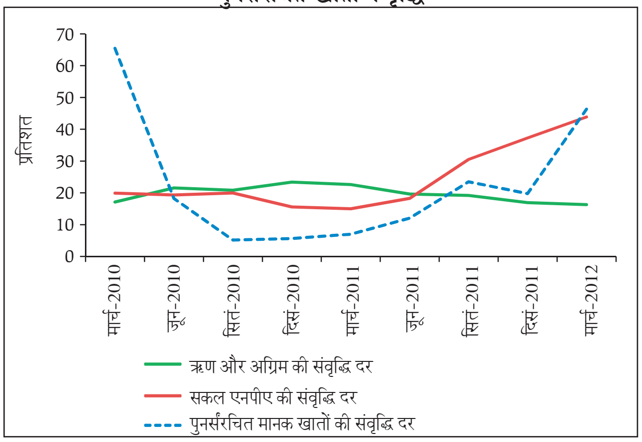

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

---

[3] स्लिपेज अनुपात की परिभाषा इस प्रकार है अर्थात् साल के प्रारंभ में मानक अग्रिमों की वर्ष के दौरान एनपीए में नवीन अभिवृद्धि।

[4] भारतीय रिजर्व बैंक "बैंकों द्वारा प्रूडेंशियल अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश" (सं/आरबीआई/2008-09/143 डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.सं.37 21.04.132/2008-09 शीर्षक परिपत्र दिनांक 27 अगस्त, 2008)

...और आगे अग्रसर एनपीए आस्ति अनुपात पर भारी पड़ेंगे.

3.18 बैंकों द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा बट्टे खाते किये गये अग्रिमों को वापस जोड़ते हुए और यह मानते हुए कि बैंकों के पुनर्गठित खातों का 15 प्रतिशत बिगड़े हुए खातों में चले गये हैं बैंकों के अग्रिम संविभाग आस्तियों की गुणवत्ता का एक अनुभाविक विश्लेषण (अलग से) किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अनुपातों ने वृद्धिशील प्रवृत्ति दर्शाई उस पर बैंकों द्वारा किए गये एनपीए के अंतर्निहित प्रबंधन पर नजदीकी नज़र रखनी होगा (चार्ट 3.15)।

कुछ प्रमुख क्षेत्रों में आस्ति की गुणवत्ता पर दबाव बरकरार रहा

3.19 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में सकल अनर्जक आस्ति वृद्धि में कुछ प्रमुख क्षेत्र यथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, रिटेल और रियल एस्टेट ने पर्याप्त योगदान दिया। बुनियादी सुविधा क्षेत्र में अनर्जक आस्ति वृद्धि दर में मार्च 2012 को समाप्त वर्ष संरचना परियोजनाओं (सारणी 3.2 और चार्ट 3.16) को ऋणों में मूल प्रभाव और तीव्र मितव्ययिता से थोड़ी सी सुस्ती आई। कतिपय क्षेत्र, जैसे कि विद्युत और एयरलाईन ने दुर्बलताओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी (बॉक्स 3.1)।

चार्ट 3.15: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए अनुपात

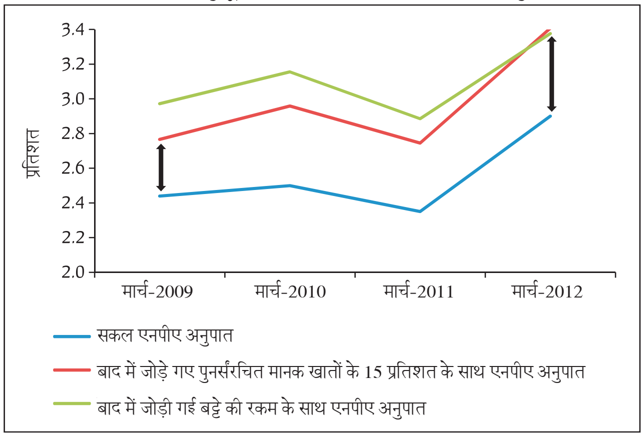

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 3.16: चुनिन्दा क्षेत्रों के एनपीए की संवृद्धि दर

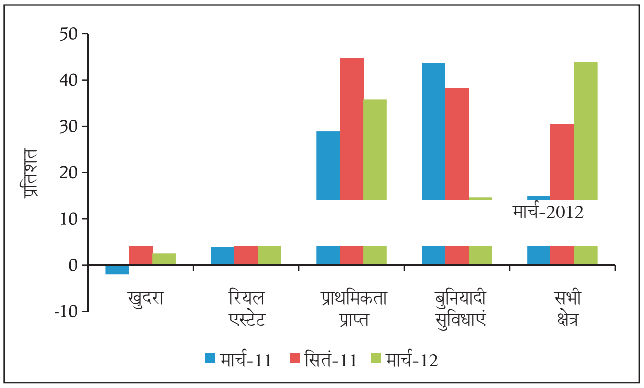

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 3.2: चुनिन्दा क्षेत्रों की आस्ति गुणवत्ता - मार्च 2012

सं.	क्षेत्र	मूल्य प्रतिशत में		
		सकल एनपीए अनुपात	बैंकिंग प्रणाली ऋण में हिस्सा	बैंकिंग प्रणाली सकल अनुपात में हिस्सा
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	4.4	30.6	47.8
2	रिटेल	2.8	18.5	18.3
3	कृषि	4.6	10.3	18.2
4	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	4.8	9.8	17.9
5	रियल एस्टेट	1.7	16.7	9.7
6	लोहा और इस्पात	3.2	3.8	4.7
7	वस्त्र	4.4	2.7	4.5
8	इंजिनीयरिंग	2.9	2.4	2.6
9	केमिकल, डाई और पैन्ट	3.1	2.2	2.6
10	बुनियादि सुविधाएं	0.6	11.0	2.5
11	खाद्य प्रसंस्करण	3.4	1.4	1.9
12	रत्न और आभूषण	3.8	1.1	1.5
13	खनन	3.6	0.6	0.8
14	ऑटोमोबाईल	1.2	1.0	0.4
15	सीमेंट	1.5	0.7	0.4
16	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	0.3	3.9	0.4
17	कोयला	8.1	0.1	0.3

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

बॉक्स 3.1 : पावर तथा एयरलाईन : दबाव वाले क्षेत्र[5]

बकाया ऋण के अनुपात के तौर पर हानि में कमी होने के बाबजूद बैंकों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों की बढ़ती हानियों और ऋण स्तर के कारण विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना किये गये जोखिमों तथा विद्युत के लिए ईंधन की कमी की चर्चा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के दिसंबर 2011 अंक में की गयी थी। विद्युत क्षेत्र को बैंक ऋणों का पुनर्गठन किये जाने से आस्ति गुणवत्ता पर संभावित दबाव और गहरा गया है[6], जो विशेष कर 2011-12 की अन्तिम तिमाही में तेजी से बढ़े (चार्ट 3.17 और 3.18)।

चार्ट 3.17: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का विद्युत क्षेत्र एक्सपोज़र

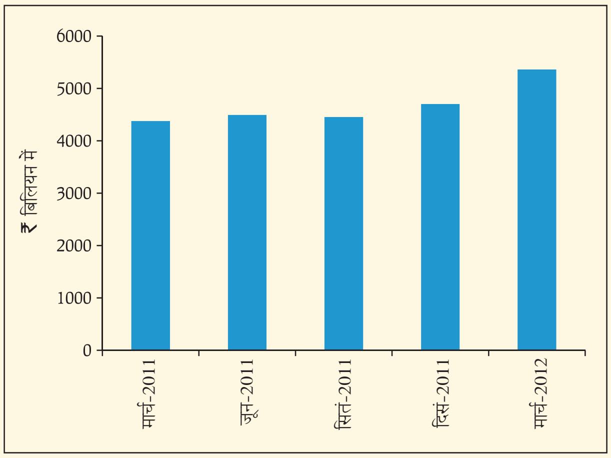

टिप्पणी : एक्सपोजर में निवेश के साथ-साथ निधि और गैर निधि आधारित ऋण शामिल हैं।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 3.18: विद्युत क्षेत्र में एनपीए और पुनर्गठित खाते

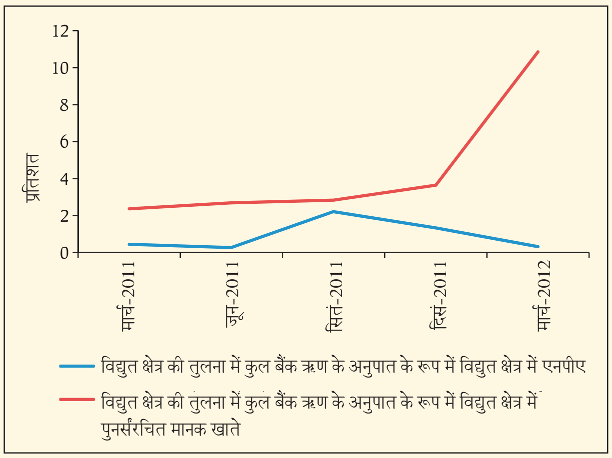

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

कुछ विशेष एयरलाईन कंपनियों के कार्य निष्पादन से हाल की अवधि में बैंको की एयरलाईन उद्योग को ऋण की आस्ति गुणवत्ता थोड़ी सी दबाव ग्रस्त हो

चार्ट 3.19: एयरलाईन क्षेत्र को बैंक ऋण

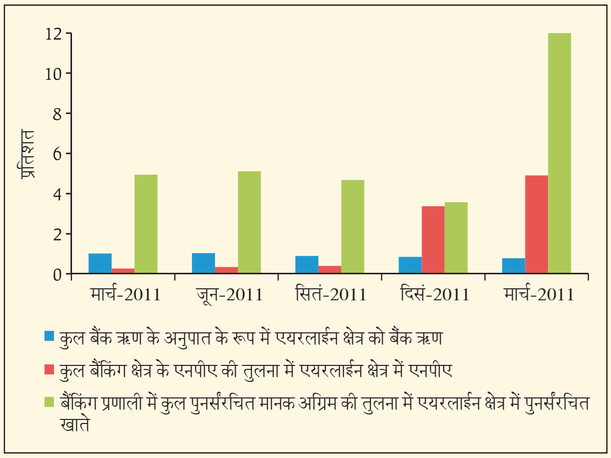

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

गई है। तेजी से बढ़ती हानियों और इस क्षेत्र में पुनर्गठन से कुल बैंकिंग प्रणाली एनपीए और पुनर्गठित आस्तियों में वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र ऋण(चार्ट-3.19) में इस क्षेत्र के अंश के अनुपात में नहीं है। एयरलाईन क्षेत्र को बैंक ऋण वितरण में संकेन्द्रण स्पष्ट दिखाई देता है दस बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को प्रदत्त कुल बैंक ऋण का लगभग 86 प्रतिशत इसका द्योतक है। मार्च 2012 के अन्त में बैंक अग्रिमों का लगभग तीन चौथाई ,जो कि एयरलाईन उद्योग को ₹10 बिलियन से अधिक का एक्सपोज़र या तो हानिकारक था या पुनर्गठित था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का इस एक्सपोज़र में प्रमुख अंश है (चार्ट-3.20)।

चार्ट 3.20: एयरलाईन क्षेत्र को दिए गए ऋण के संदर्भ में शीर्ष 10 बैंक

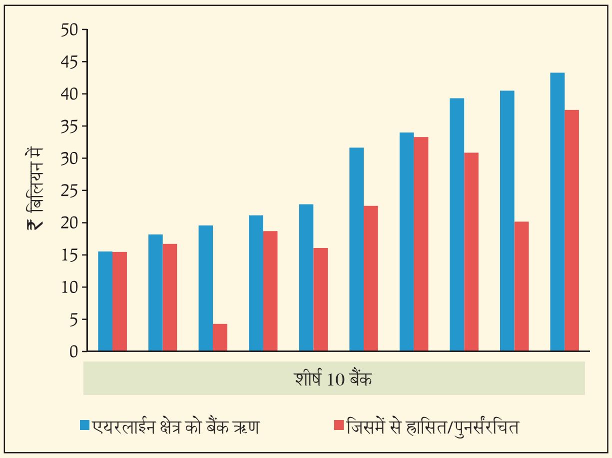

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

आगे जा कर कंपनियों को फंड संबंधी दबाबों का सामना करना पड़ सकता है और नीतिगत अनिश्चितताओं का भी प्रभाव पड़ सकता है। ये इन क्षेत्रों को ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं।

[5] आंकड़े 67 बैंकों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित हैं जो जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों का 91 प्रतिशत हैं।
[6] क्रिसिल द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार 2010-11 में बिजली वितरण कंपनियों का शुद्ध नुकसान ‘लगभग ₹400 बिलियन था।

आस्ति गुणवत्ता पर और तनाव आ सकते हैं, हालांकि मज़बूत पूंजी स्थिति इसमें कवच का काम करती है

3.20 अस्पष्ट आर्थिक पृष्ठभूमि और वैश्विक वातावरण से आस्ति गुणवत्ता में और ह्रास हो सकता है। स्थिति इस समय भयानक नहीं है और बैंकों की पूंजी पर्याप्तता कुछ सुकून प्रदान कर रहा है, जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि बैंकिंग प्रणाली में अनर्जक आस्तियों की संपूर्ण मात्रा समाहित करने की असंभाव्य अनिश्चितता में भी मज़बूती बनी रह सकती है (चार्ट 3.21)। ऋण जोखिम दबाब परीक्षणों से भी बैंकों की क्षमता प्रमाणित होती है (पैराग्राफ 3.43 से 3.45)।

लाभप्रदत्ता संकेतकों ने मिली-जुली प्रवृत्ति दर्शाई

3.21 राज्य सहकारी बैंकों स्वस्थ लाभप्रदता दर्शाते रहे हालांकि आय की वृद्धि दर में कमी आई (चार्ट 3.22)। मार्च 2012 में मार्च 2011 (चार्ट 3.23) की तुलना में आस्तियों, इक्विटियों और निवल ब्याज दर में थोड़ी सी घटी। आगे जा कर आय की वृद्धि कम ऋण लिये जाने और आस्ति गुणवत्ता चिन्ताओं की वजह से प्रभावित हो सकती हैं।

ब्याज दर स्वैप बैंकों के तुलनपत्रेत्तर आस्तियों पर हावी

3.22 राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्रेत्तर आस्तियों की अनुमानित समग्र राशि उनके तुलन पत्रों पर उल्लिखित आस्तियों के परिमाण से कहीं अधिक थी (चार्ट 3.24)। तुलनपत्रेत्तर आस्तियों के कुल संवितरण (अनुमानित राशि के अनुसार) से दिखा कि उनका संकेन्द्रण विदेशी बैंकों में लगभग 64 प्रतिशत और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 17 प्रतिशत था। जहां तक व्युत्पन्नियों का प्रश्न है उनमें विदेशी बैंकों का हिस्सा 70 प्रतिशत बनता था,उसके बाद नये निजी

चार्ट 3.23: लाभप्रदता अनुपात

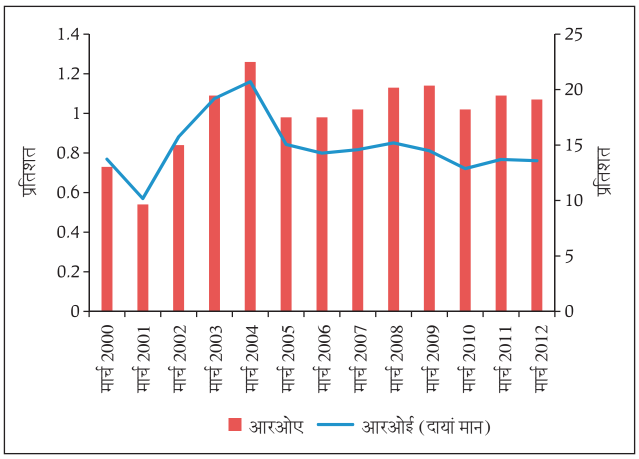

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.21: एनपीए (निवल) के वर्तमान स्टॉक राईट ऑफ किये जाने पर सीआरएआर

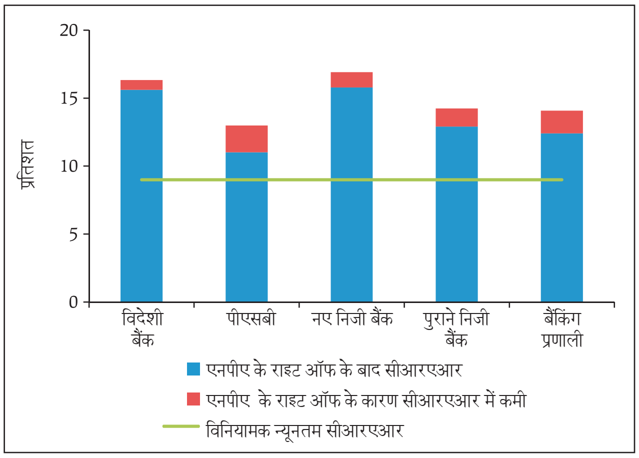

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.22: कमाई की संवृद्धि दर

टिप्पणी : ईबीपीटी : प्रावधान और कर पूर्व अर्जन
पीएटी : कर उपरांत लाभ

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.24: तुलन पत्र की आस्तियों के अनुपात के रूप में तुलनपत्रेत्तर आस्तियां (नोशनल प्रिंसिपल)

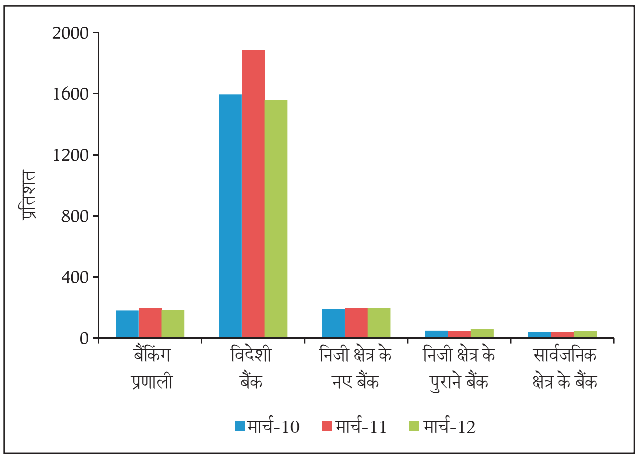

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

श्रेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत थी। ओबीएस घटकों में सबसे अधिक उल्लेखनीय खंड ब्याज दर स्वैप थे।

अपने व्युत्पन्नि संविभाग से बाज़ार जोखिम झेलने के लिए तैयार बैंकों को परिणामी ऋण जोखिम संभालने की आवश्यकता पड़ेगी

3.23 बैंकों[7] का जब व्युत्पन्नि संविभाग के संबंध में नमूना विश्लेषण करने से पता चला कि अधिकतर बैंकों नें मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) स्थिति की सकारात्मक रिपोर्ट दी है। नमूना विश्लेषण से व्युत्पन्नि खण्ड में विदेशी बैंकों का वर्चस्व इस बात से साबित होता है कि पूंजी के साथ सकल सकारात्मक और नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) अनुपात विदेशी बैंकों के संबंध में औसतन 250 प्रतिशत और अन्य बैंकों के साथ 16 प्रतिशत था। पूंजी के अनुपात के तौर पर निवल एमटीएम, 30 प्रतिशत सकारात्मक से लेकर 10 प्रतिशत नकारात्मक के बीच था (चार्ट 3.25 एवं 3.26)।

3.24 कतिपय चुनिन्दा बैंकों ने व्युत्पन्नि संविभाग पर ऐतिहासिक परिदृष्यों के समूह और यादृच्छिक संवेदनाशीलता आघातों के आधार पर कई दबाब परीक्षण किये (बॉक्स 3.2)। अधिकतर बैंकों के संदर्भ में दबाबोत्तर निवल सकारात्मक एमटीएम पोजिशन यह दर्शातें है कि बैंक प्रतिकूल बाज़ार गतिविधियों को झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। तथापि गत अनुभव बतातें है कि बैंक प्रतिपक्षी विफलता के जोखिम के लिए एक्सपोज़ड रहे, विशेषकर भुगतान के संबंध में उठे विवादों के संदर्भ में।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

गिरती आस्ति गुणवत्ता से ऋण वृद्धि में सुस्ती आई

3.25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने ऋण वृद्धि की दर में सुस्ती देखी हालांकि ऋण वृद्धि बैंकिग क्षेत्र की तुलना में अधिक तीव्र थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण में बढ़ोत्री हुई इसी तरह फंड के स्रोत के रूप में उनकी बैंकों पर निर्भरता भी बढ़ी। यदि बैंक इस क्षेत्र को ऋण देने की स्थिति में न हों अथवा ऋण देना नहीं चाहें तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है (चार्ट 3.27)।

3.26 प्रणालीगत तौर पर जमा राशि नहीं लेने वाली महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों ने उनकी सुदृढ़ता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के संबंध में बिगड़ती प्रवृत्ति दर्शायी है (आरओ के संदर्भ में)। सीआरएआर 15 % की विनियामक अपेक्षाओं से अधिक रही, तथापि समीक्षाधीन अवधि में यह घट गई

चार्ट 3.25: बैंकों के सैंपल के लिए पूंजी निधियों के अनुपात के रूप में घनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट पोज़िशन

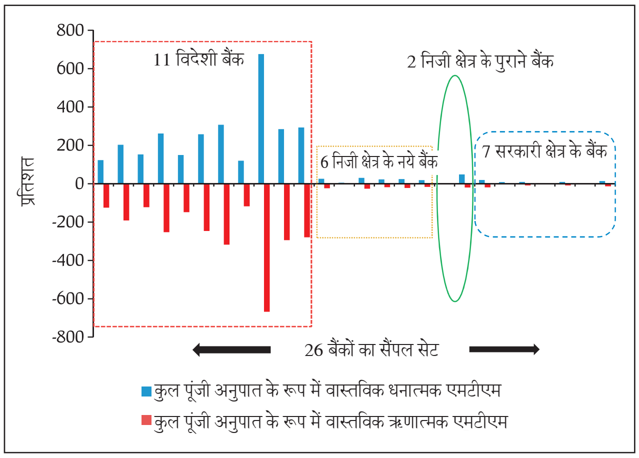

स्रोत: सैंपल के बैंक

चार्ट 3.26: बैंकों के सैंपल हेतु पूंजी निधि के अनुपात के रूप में निवल मार्क-टू-मार्केट पोज़िशन

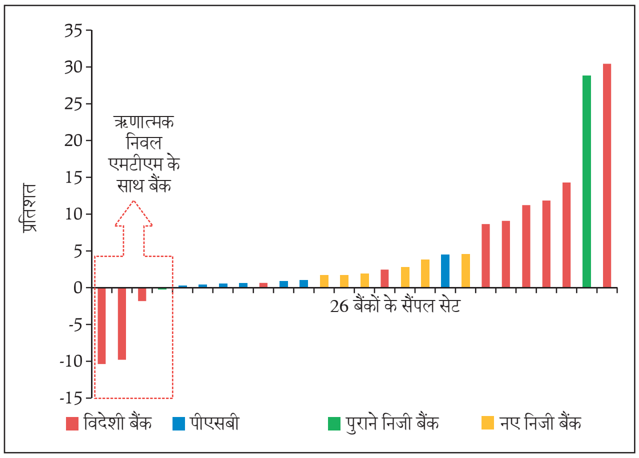

स्रोत: नमूने में बैंक

चार्ट 3.27: ऋण वृद्धि: बैंको की तुलना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

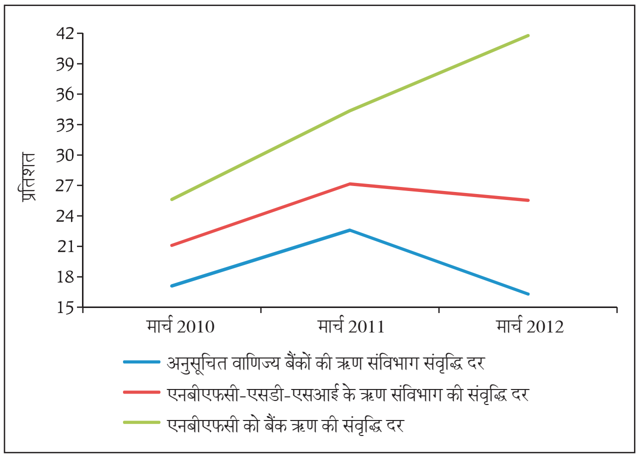

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

[7] 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार सैम्पल में डेरिवेटिव जोखिम की कुल अनुमानित राशि में 26 बैंको की 88 प्रतिशत राशि और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल 64 प्रति आस्तियां सम्मिलित थीं।

बॉक्स 3.2 : चुनिन्दा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो दबाव परीक्षण

कुछ बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाब परीक्षण करने का बीड़ा उठाया गया। इस दबाब परीक्षण में 6 ऐतिहासिक और 4 ब्याज दर विनिमय दर आघात[8] शामिल थे। परीक्षणों ने बैंकों और बैंक समूहों पर प्रभावों में पर्याप्त विभिन्नता दर्शाई। ऋणात्मक एमटीएम में वृद्धि के अनुसार विदेशी बैंक उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुए जबकि बकाया बैंक समूह पर परीक्षण का प्रभाव हल्का था। पुनश्च संवेदनशीलता के लिए प्रयोग किए गये आघातों के कारण अधिकतर बैंकों के मामले में ऐतिहासिक परिदृष्य की तुलना में अधिकतम दबाब पडा (चार्ट 3.28 और 3.29)।

चार्ट 3.28: पूंजी निधियों के अनुपात के रूप में ऋणात्मक एमटीएम दबावोत्तर (परिदृष्य)

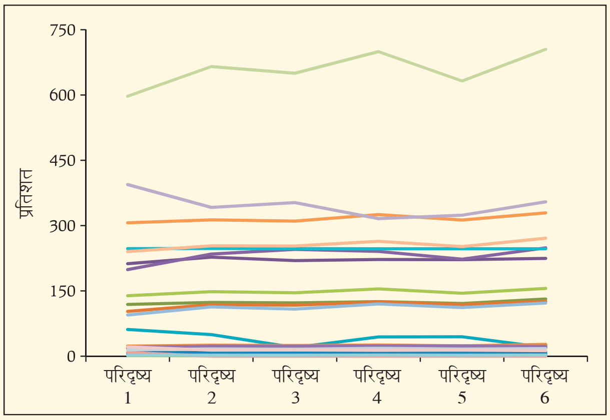

चार्ट 3.29 : पूंजी निधियों के अनुपात के रूप में दबावोत्तर ऋणात्मक एमटीएम (संवेदनशीलता)

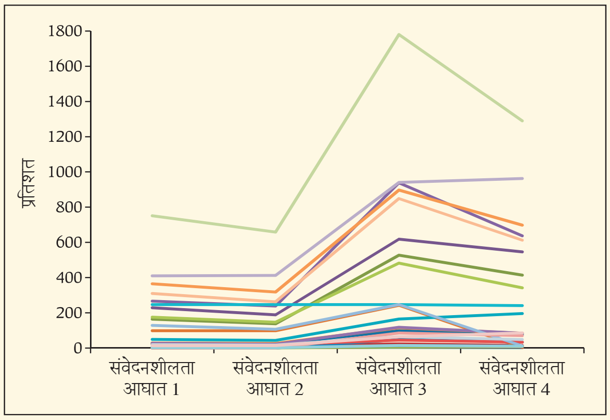

टिप्पणी : सैंपल सेट में प्रत्येक पंक्ति एक वैयक्तिक बैंक का प्रतिनिधित्व करती है।
स्रोत: सैंपल बैंक

अधिकतर मामलों में देखा गया कि सैम्पल में बैंकों के निवल एमटीएम स्थिति और तनाव स्थितियों पर दबाब अपेक्षतया हलके थे। संवेदनशीलता के लिए प्रयोग किए गये आघातों के कारण अधिकतर बैंकों के मामले में जिनकी संवेदनशीलता विश्लेषण के संदर्भ में निवल एमटीएम, परिदृष्य विश्लेषण के 66 प्रतिशत की तुलना 344 प्रतिशत था में औसत परिवर्तन से ऐतिहासिक परिदृष्य की तुलना में अधिकत्तम दबाव पड़ा। तथापि , कुछ बैंक ऐसे थे जहां पर प्रभाव उल्लेखनीय था और इन बैंकों को इन्हें अन्तर्निहित जोखिमों के प्रति सावधानी से नियंत्रित करना है (चार्ट-3.30 और 3.31)।

चार्ट 3.30:निवल एमटीएम में परिवर्तन - परिदृष्य विश्लेषण

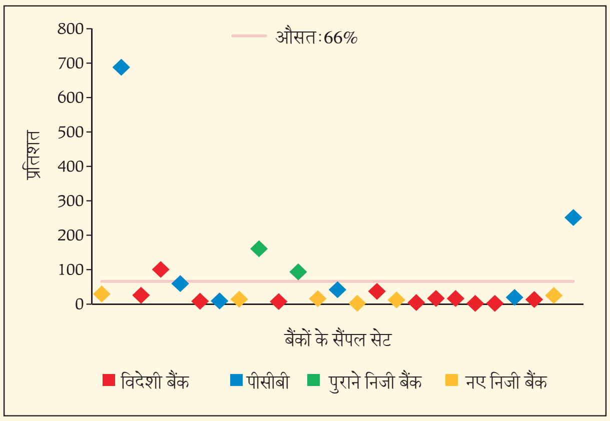

चार्ट 3.31: निवल एमटीएम में परिवर्तन - संवेदनशीलता विश्लेषण

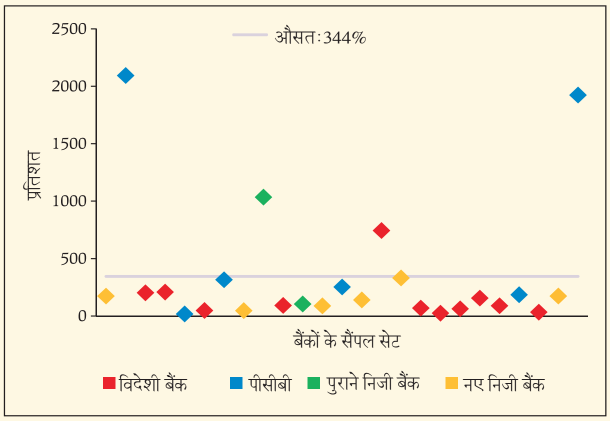

नोट: सबसे खराब मामला विश्लेषण पर आधारित (परिदृष्य /संवेदनशीलता दबाब परीक्षणों में निवल एमटीएम स्थिति पर अधिकतम दबाब)
स्रोत: सैम्पल बैंक

[8] कार्यप्रणाली और विवरण के लिए कृपया अनुबंध देखें।

चार्ट 3.32: एनबीएफसी-एनडी - एसआई के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

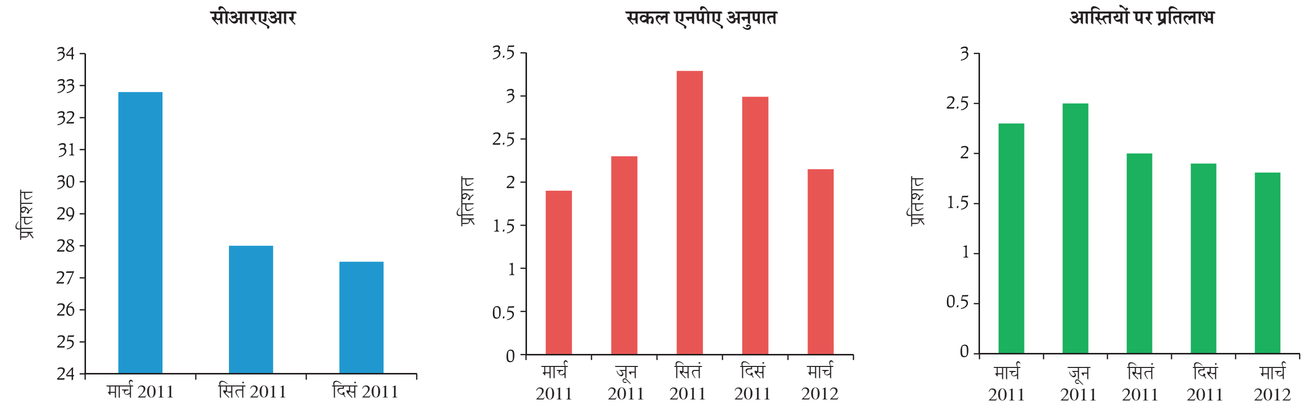

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

(चार्ट 3.32)। सीआरएआर में गिरावट अंशता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बढ़ती आस्ति आधार द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पुनश्च, लगभग 2 प्रतिशत पर आर ओ ए मज़बूत बना रहा।

तेजी से उभरती गोल्ड लोन कंपनियां चिन्ता का सबब बन सकती हैं

3.27 हाल के वर्षों में स्वर्ण के बदले ऋण देने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों के बैलेंस शीट में तीव्र वृद्धि,तेजी से बढ़ते स्वर्ण मूल्य और उनकी शाखाओं में विस्तार चिन्ता का सबब हो सकती है (बॉक्स 3.3)। गोल्ड लोन कंपनियों[9] ने अपने संसाधनों के लिए बैंकिंग प्रणाली पर भारी निर्भरता दर्शाई है जो इन कंपनियों के व्यवसाय मॉडल के लड़खडा जाने की स्थिति में बैंकों को खतरे में डाल सकते हैं। गोल्ड लोन कंपनियों की बैंकों के साथ इस अंतर्संयुक्तता को हाल के विनियामक उपायों अर्थात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वर्णाभूषणों की ज़मानत पर लोन देने के लिए बैंक वित्त हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैसियत समाप्त करके और

बॉक्स 3.3 : गोल्ड ऋण कंपनियां और एसोसिएटेड जोखिम

स्वर्ण की ज़मानत पर ऋण प्रदान करना कोई नई बात नहीं है एनबीएफसीज के गोल्ड लोन बाज़ार में प्रमुख खिलाड़ियों के तौर पर उभरने के साथ हाल के वर्षों में इस कार्यकलाप में तेज़ी आई है। सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये कुल गोल्ड लोन में एनबीएफसीज़ के भाग में मार्च 2010 और 2011 के बीच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एनबीएफसीज़ से स्वर्ण की ज़मानत पर ऋण लेने वालों में सबसे बडी संख्या अकेले व्यक्तियों की है और इसके अंतर्गत कुल ऋण लेने वालों में इनकी संख्या 95 प्रतिशत है। इन एनबीएफसीज से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि इनके समग्र आस्ति आकार में मार्च 2009 में 54.8 बिलियन ₹ बढ़ कर 31 मार्च 2012 में 445.1 बिलियन ₹ हो गया है। वृद्धि में ज़्यादातर उधार शामिल थे। अग्रिमों की वृद्धि में अधिकत्तर योगदान दो कंपनियों द्वारा दिये जाने से कंपनियो के बीच में उल्लेखनीय जमावाड़ा हुआ है। इन दो कंपनियों का उधार मार्च 2010 और 2011 के बीच में 200 प्रतिशत बढ़ा। तिस पर भी एनबीएफसी से संबंधित इस सेगमेंट में कई चिन्ताएं हैं। चिन्ता के प्रमुख कारण हैः

(i) **जमघट जोखिम**

90 प्रतिशत से अधिक आस्तियों के मात्र एक उत्पाद अर्थात स्वर्ण आभूषणो द्वारा संपार्श्विकीकृत किये जाने से गोल्ड लोन कंपनियों के बिज़नेस मॉडल में जमघट का अन्तर्निहित जोखिम है। पर जोखिम स्वर्ण के मूल्य तेज़ी से गिरने पर ही हो सकता है।

(ii) **ऑपरेशनल रिस्क**

कंपनियों द्वारा तत्काल वितरण के वादों को देखते हुए ड्यू डिलिजेंस , जिसमें अपने ग्राहक को जानिये (केवाईआसी) स्वामित्व जानने और स्वर्ण आदि के स्तर को निर्धारित करने संबंधी मानदण्डों के बारे में समझौते किए जा सकते हैं।

(iii) **खुदरा आधार पर एनसीडी के प्रायवेट प्लेसमेंट संबंधी चिन्ताएं**

गोल्ड लोन कंपनियां बार बार विशेषकर प्रायवेट प्लेसमेंट के ज़रिये अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधिक खुदरा नॉन कन्वर्टीबल डिबेंटर जारी करते रहते हैं। चिन्ता इस बात की है कि इन एनसीडी में से कुछ का स्वरुप ' पब्लिक डिपोजिट ' जैसा है , परंतु यह संस्थाएं एनबीएफसी की तरह विनियमित नहीं होती हैं।

(iv) **उधारों, विशेषकर बैंक निधियों पर निर्भरता**

गोल्ड लोन कंपनियों के व्यवसाय मॉडल उधारों से संचालित होते है, जिसमें बैंक उधार इसका एक प्रमुख घटक है और यह तेज़ी से बढ़ रहा है। इन एनबीएफसीज के द्वारा वसूली में कोई बात उलटी पड़ जाने अथवा स्वर्ण के मूल्य में उल्ट-फेर हो जानेसे बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव फैल सकता है।

[9] एनबीएफसी जो मुख्य रूप से सोने के आभूषण की ज़मानत पर ऋण प्रदान करने में लगे हुए हैं उन्हें 'गोल्ड लोन कंपनियों' के रूप में भी जाना जाता है।

चार्ट 3.33: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

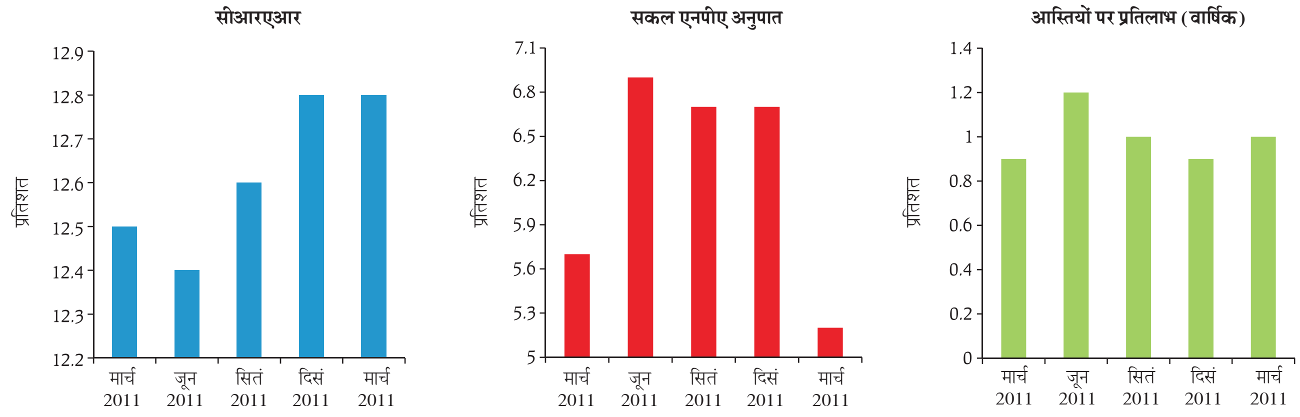

टिप्पणी : मार्च 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त की एकेसपोज़र लिमिट निर्धारित करके कम करने की मांग की गयी है। आगे एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने गोल्ड लोन कंपनियों को यह भी निदेश दिया है कि वे स्वर्णाभूषण की कोलेटरल जमानत पर दिये गये लोन के लिए 60 प्रतिशत न्यूनतम लोन - टू - वेल्यू अनुपात रखें।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों ने कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाया

3.28 मार्च, 2012 को अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ने समीक्षाधीन अवधि में सुधार दर्शाया(चार्ट 3.33)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आस्ति गुणवत्ता में स्पष्ट तनाव

3.29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिनका वित्तीय प्रणाली में हिस्सा 1.5 प्रतिशत है ने मार्च 2012 अन्त में मज़बूती दर्शायी है, हालांकि आस्ति गुणवत्ता में ह्रास हुआ है (चार्ट 3.34 और 3.35)।

बीमा क्षेत्र[10]

जीवन बीमा-निगमेतर क्षेत्र ने मज़बूती दर्शाई जबकि जीवन बीमा क्षेत्र में गिरावट आई

3.30 जीवन बीमा-निगमेतर क्षेत्र में मार्च 2012 में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह मार्च 2011 अन्त में 22.4 प्रतिशत थी। जीवन बीमा निगम उद्योग ने प्रीमियम एकत्रित करने में 2010-11 के 15.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2011-22 में 9.2 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई।

चार्ट 3.34: आरआरबी के चुनिन्दा तुलनपत्र घटकों की वृद्धि - मार्च 2012

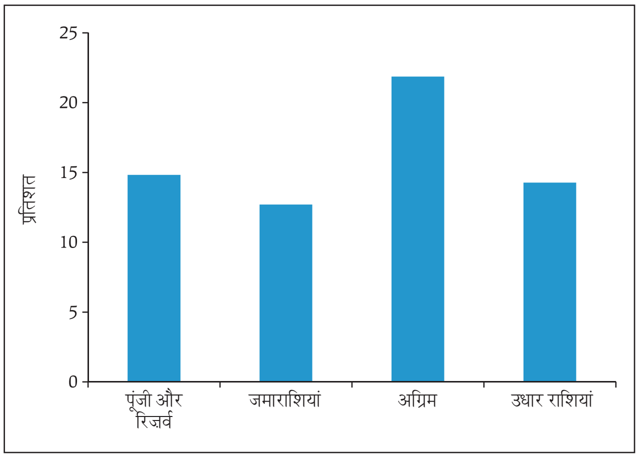

टिप्पणी : मार्च 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.35: आरआरबी के सकल एनपीए अनुपात

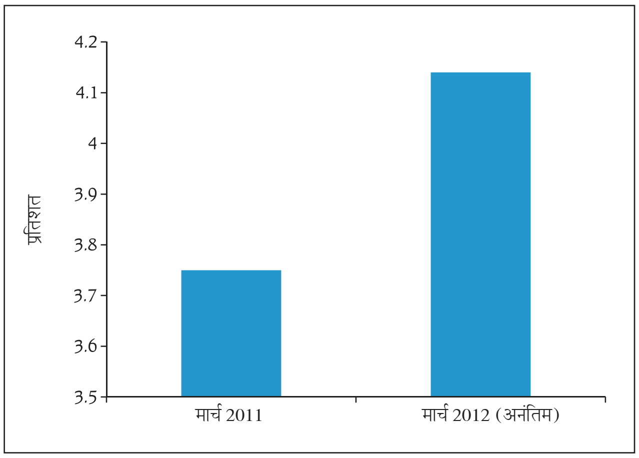

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

[10] स्रोत: बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए).

सोलवेन्सी II के समय में चुनौतियां तो आगे हैं

3.31 भारतीय जीवन बीमा-निगम फैक्टर आधारित सोलवेन्सी प्रणाली द्वारा चलायी जा रही है जिसकी तुलना सोलवेन्सी I[11] से की जा सकती है। यह ढांचा नियम आधारित है और उद्योग स्तर पर कई किस्म के जोखिम प्रतिबिम्बित करता है जबकि आस्तियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तत्वों में समाविष्ट अन्तर्निहित लाभ, ऋण चुकाने की क्षमता के ढांचे को विवेकपूर्ण और सुदृढ़ करता है।

3.32 सोलवेन्सी II जोखिम आधारित विनियामक शासन पद्धित के तौर पर यूरोपियन यूनियन में सभी बीमा संस्थाओं पर लागू होगी। प्रणाली आर्थिक जोखिम आधारित ऋण चुकौती क्षमता अपेक्षाएं लागू करती हैं और इसका ध्येय इस धारणा को बदलना है कि विफलताओं के सामने पूंजी ही एक मात्र उपाय है। सोलवेन्सी II सांविघिक प्रावधानीकरण के स्थान पर (बाज़ार विश्वसनीयता) 'बेस्ट एस्टीमेटस' पर आधारित प्रावधान करता है।यह देखते हुए कि भारत में कार्यरत अधिकांश बीमा कंपनियों के संयुक्त उद्यम भागीदार यूरोप स्थित निकाय हैं, सोलवेन्सी II के प्रयोजनार्थ भारतीय ऑपरेशन का भी मूल्यांकन किया गया है। जबकि इन निकायों की तैयारियों का स्तर पर्याप्त ऊँचा हो सकता है, सार्वजनिक बीमा के संबंध में जीवन बीमा और जीवन बीमा इतर दोनों क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियां विद्यमान हैं।

3.33 भारत में वर्तमान पूंजी प्रणाली का सोलवेन्सी II के साथ संपूर्ण ताल-मेल नहीं है और जोखिमों के आकलन, आन्तरिक मॉडलों के विकास, आंकड़ों की प्रचुरता, आईआरडीए और बीमा उद्योग दोनों के भीतर क्षमता निर्माण के संदर्भ में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने हेतु एक रूप-रेखा तैयार करना आवश्यक हो जाएगा। इस दिशा में पहले कदम के तौर पर आईआरडीए ने चुनिन्दा कार्यअधिकार क्षेत्रों में सोलवेन्सी प्रणाली की जांच तथा अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

पेन्शन निधियां [12]

3.34 भारत की पेन्शन पारिस्थितिकी तंत्र भारी-भरकम है और यह तेजी से बढ़ रही है। इसके वर्ण-पट के एक छोर पर यथा परिभाषित लाभ पेन्शन योजनाएं विद्यमान हैं, जिनमें से दो प्रमुख योजनाएं हैं केन्द्र/राज्य सरकारों की सुधार-पूर्व नागरिक सेवा पेन्शन (जिसके बदले में नये भर्ती हुए लोगों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना लागू की गई है) तथा 'संगठित क्षेत्र' में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना। साथ ही परिभाषित श्रेणी में कई योजनाएं हैं जो राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही है ,जिनमें सबसे बड़ी है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेन्शन योजना। राज्य सरकारें कई व्यवसायिक पेन्शन योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से बहुत से असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित हैं और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग हैं।

3.35 इस वर्ण-पट के दसरे छोर पर परिभाषित अंशदान(डीसी) योजनाएं हैं, जिनमें से जनवरी 2004 में लागू राष्टीय पेन्शन योजना है जो कि भारतीय पेन्शन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। राष्टीय पेन्शन योजना पहले- पहल नागरिक सेवाओं के लिए स्थानापन्न योजना के रूप में लागू की गई थी। यह योजना सर्व प्रथम केन्द्र सरकार द्वारा तथा बाद में पश्चिम बंगाल, केरला और त्रिपुरा को छोड़ सभी राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गई है। वर्ष 2009 में राष्टीय पेन्शन योजना निजी क्षेत्र में लागू की गई और भारत सरकार ने 2010 में अंसगठित क्षेत्र के लिए राष्टीय पेन्शन योजना के मंच से सह-अंशदान योजना(स्वालंबन नाम से) शुरू की। सीधी अंशदान के अंतर्गत भी कई योजनाएं हैं जो बीमा कंपनियों द्वारा प्रायवेट व्यक्तियों और कोरपोरेटस के लिए चलाईं जाती हैं।

3.36 डीबी योजनाओं के मामले में सबसे दुष्कर चुनौती देयताओं की मात्रा तय करना है। चूंकि 2004 पूर्व पेन्शन योजना वेतन आयोग द्वारा अनुंशसित मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि द्वारा अनुक्रमित है इस लिए दूर भविष्य में भुगतान तय करना दुष्कर हो जाता है। समस्या इस बात से भी बहुत गहरी हो जाती है कि यह 'पूर्व भुगतान' प्रणाली है जो स्पष्टतया एक अनिधिक देयता है। पेन्शन देयता में किसी तरह की भारी वृद्धि से राजकोषीय घाटे पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। 2012-13 के बज़ट में अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभों पर ही 631 बिलियन ₹ निकल गये जो कि 2011-12 के संशोधित आकलन के 561 बिलियन ₹ के ऊपर 12 प्रतिशत की वृद्धि है। 1970 और 1980 के दशक में सरकार द्वारा भर्ती में तेजी से विस्तार हुआ हालांकि 90 के दशक में इसे नियंत्रित किया गया। पूर्व के दशकों में भर्ती हुए कर्मचारियों का पेन्शन का भुगतान शीघ्र ही बड़ी समस्या का आकार लेने लगेगा। जैसे कि 1970 और 1980 के दशकों में भर्ती कर्मचारी सेवानिवृत्ति

[11] सोलवेन्सी 1 यूरोपीय संघ बीमाकर्ता सोलवेन्सी प्रणाली को 2002 में परिवर्तित किया गया नाम है। परिवर्तन का प्रयोजन यूरोपीय संघ में बीमा उपक्रमों के लिए न्यनूतम सुसंगतता तथा आपसी मान्यता की अवधारणा के आधार पर सामूहिक ढांचा बनाना

[12] स्रोत: पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)।

होने वाले हैं तो भुगतान में भी वृद्धि होगी. जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का प्रश्न है यह परिभाषित लाभ योजना है जिसमे कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान करते हैं। पर चूंकि अंशतः लाभ निश्चित हैं और उनमें कमी हो जाए तो उसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995[13] पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदान की वर्तमान दर कम है और योजना को कायम रखने के लिए अंशदान में वृद्धि करनी की आवश्यकता होगी। साथ ही कर्मचारी पेन्शन निधि की राशि 31 मार्च, 2011 को 1420 बिलियन ₹ थी। यह भारी भरकम आकार प्रणाली के लिए खतरे की घंटी की सूचक है, बशर्ते कि आकार कोई मानदण्ड हो। वर्तमान में क्रियान्वयन अधीन बहुतसी परिभाषित लाभ योजनाएं तथा नवघोषित योजनाओं के मामलों, विशेषकर ऐसे विश्व में जहां मनुष्य के जीने की ऊमर बढ़ रही है, में देयता की गणना की कमी भारी मात्रा में भुगतान किए जाने वाले वर्षों में राजकोषीय तनाव का एक बड़ा स्रोत बन सकती हैं।

3.37 परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम की पहचान करना पहली दृष्टि में एक चुनौती है, कोई यह कारण नहीं खोज सकता कि कब सारे जोखिम अन्तरित किए जाएं और इसे उन अंशदातों की बडी संख्या के बीच विभाजित किया जाए जिनके लाभ परिभाषा के तहत परिभाषित नहीं किये गये हैं। यह कार्य और चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब पेन्शन विनियामक के पास केवल राष्ट्रीय पेन्शन योजना प्रणाली विनियमत करने का अधिदेश है और प्रणालीगत जोखिम की पहचान के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध और लागू नहीं है। राष्ट्रीय पेन्शन योजना का आकार इतना छोटा है कि इससे किसी प्रकार की स्वाभाविक अथवा प्रणाली गत जोखिम की संभावनाएं न के बराबर रह जाती हैं। राष्ट्रीय पेन्शन योजना (परिभाषित - अंशदान अनरक्षित) परिभाषा सोलवेन्सी अथवा पूंजी अपेक्षाओं से संबंधित तनाव परीक्षणों की संभावनाओं को नकारता है। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि प्रणालीगत जोखिम के नज़रिये से नहीं बल्कि सार्वजनिक प्रकटीकरण से संबंधित मसलों को असरदार तरीके से हल करने के लिए किसी तरह के परिदृष्य विश्लेषण पर विचार किया जाए। यह अनुमानित मुनाफे तथा लाभ के संदर्भ में विशेषकर प्रासंगिक है,जिनके आगे चल कर मिसालें दी जा सकती हैं। जब किसी खास किस्म के जोखिम का परीक्षण किसी संस्था अथवा संविभाग(अर्थात इक्विटी मार्केट डिकलाईन अथवा प्रतिकूल ब्याज दर उतार-चढ़ाव) पर किये जाएं तो वह भी प्रासंगिक हो सकते हैं।इसी तरह एतिहासिक परिदृष्यों अथवा काल्पनिक(आम तौर पर चरम) घटनाओं का उपयोग करके बृहद दबाब परीक्षणों की व्यापक मॉडलिंग तकनीकों प्रयोग करके हुए बहुत से दबाब परीक्षण से जोखिमों के बारे में अंशदाताओं को अवगत कराने पर विचार किया जा सकता है। यह मॉडलिंग नियतात्मक अथवा चंचल हो सकता है।

3.38 अंतरराष्ट्रीय मानक सेटिंग संगठनों जैसे अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संगठन (IAIS) और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने दबाब परीक्षण के लिए दो मुख्य भूमिकाएं तय की हैं (क) यह सुनिश्चित करना कि क्या वित्तीय संस्थाओं के पास अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं (परिभाषित अंशदान पेन्शन जिन्हें कोई देयताएं पूरी नहीं करनी है के लिए अपेक्षित), (ख) सामान्य जोखिम उपकरण, जिन्हें वित्तीय संस्थाओं पर विभिन्न कारकों अथवा परिदृष्यों का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है (परिभाषित अंशदान जिनके पास पूंजी अपेक्षाएं नहीं हैं)।

3.39 फिर भी दबाब परीक्षण जोखिम कम करने के लिए वैकल्पिक व्यूह रचना के विकास और आकलन में मदद दे सकते हैं। दबाब परीक्षण के तीन उपयोग हो सकते हैं। पहला पेन्शन पर्यवेक्षक आम निरीक्षण के एक हिस्से के रूप में कुछ पेन्शन फंडो द्वारा की गई जांच के नतीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरे पर्यवेक्षक सभी पर्यवेक्षित निकायों पर तुलना के प्रयोजन अथवा संपूर्ण उद्योग के तौर पर मानक परीक्षण लागू कर सकते हैं। तीसरे पर्यवेक्षक विशिष्ट संस्थाओं, जिनके संबंध में उन्हें चिन्ता है, वैकल्पिक तौर पर विशेष परीक्षण लागू करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस समय अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तत्वों और कारकों के तुलनात्मक विश्लेषण पर कोई ऐसा दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है जिन्हें पेन्शन फंड और पेन्शन पर्यवेक्षक दोनों दबाब परीक्षण मॉडल डिज़ाईन करने, लागू करने और मूल्यांकन करने में उपयोग कर सकें।

3.40 इसी प्रकार विशेषज्ञ समिति द्वारा किये जा रहे कठोर परीश्रम की तरह पारंपरिक व्यापक रेज मॉडलिंग तकनीक और सोलवेन्सी संबंधी परीक्षण इन डीबी पेन्शनों पर लागू किये जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के पास अपनी प्रतिबद्धताएं (भावी) पूरी करने के लिए यथेष्ट संसाधन हैं। विशिष्ट जोखिम कारकों जैसे कि सामान्य आर्थिक मंदी, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति) के संबंध में दबाब परीक्षण जोखिम करने के लिए वैकल्पिक उपाय विकसित और निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं।

[13] www.epfindia.com/Circulars/Y2011-12/EPS95_Expert_Report.pdf

वित्तीय संस्थाओं का ललीचापन

3.41 मार्च 2012 के अन्त के पर्यवेक्षी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं के ललीचेपन का आकलन कई दबाब परीक्षणों जिन्होंने अतिश्य परंतु विश्वसनीय लगने वाले शॉक[14] दिये, के आधार पर किया गया। राज्य सहकारी निकायों की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति परीक्षण टॉप डाऊन और बॉटम अप दोनों दृष्टियों तथा कई स्थूल दबाब परीक्षणों[15] के माध्यम से किया गया। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-जमाराशि नहीं लेने वाली- सिस्टमिकली महत्त्वपूर्ण कंपनियों पर विभिन्न परिस्थितियों में उनकी कमज़ोरियों और मजबूती का आकलन करने के लिए कई एकल कारक संवेदनशीलता दबाब परीक्षण भी किए गये थे।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

3.42 बैंकिंग प्रणाली(60 अनुसूचित वाणिज्य बैंक,जिसमें सारे बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों का 99 प्रतिशत है) पर ऋण, विदेशी मुद्रा, इक्विटी, ब्याज दर और नकदी जोखिमों पर कई टॉप- डाऊन दबाब परीक्षण किय गये। उसी के समान सैट शॉक का प्रयोग 25 चुनिन्दा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (कुल आस्तियों का 75 प्रतिशत) द्वारा बॉटम-अप दबाब परीक्षण करने के लिए किया गया। बॉटम-अप दबाब परीक्षणों ने मोटे तौर पर टॉप डाऊन परीक्षण ही प्रतिबिम्बित किये और बैंकिंग प्रणाली का विभिन्न शॉको के प्रति मजबूती की फिर से पुष्टि की।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण जोखिम असुरक्षा का प्रमुख स्रोत रही

3.43 मार्च 2012 के अनुसार बैंकों के लिए विभिन्न ऋण जोखिम परिदृश्यों के तहत शॉक का प्रभाव दर्शाता है कि प्रणाली स्तरीय सीआरएआर 9 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से ऊपर रही और प्रणाली शॉक्स झेलने के लिए तैयार रही; हालांकि कुछ बड़े बैंकों सहित दबाब में आ सकते हैं, क्योंकि उनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम हो सकता है (चार्ट-3.3 और 3.36)।

बैंक क्षेत्रीय ऋण जोखिम का सामना कर पाये

3.44 विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि, बिजली, रियल एस्टेट, दूरसंचार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से निकले ऋण जोखिम शॉक के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतम झटका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर पड़ा है और उसके बाद रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। परंतु बैंक यह झटका सहने में समर्थ थे (सारणी 3.4)।

सारणी 3.3: ऋण जोखिम : सकल ऋण - पूंजी और एनपीए पर प्रभाव

(बैंकों की संख्या को छोड़ कर अंक प्रतिशत में हैं)

	प्रणाली स्तर			प्रभावग्रस्त बैंक (सीआरएआर < 9%)		प्रभावग्रस्त बैंक (कोर सीआरएआर < 6%)	
	सीआर-एआर	कोर सीआर-एआर	एनपीए अनुपात	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों में हिस्सा	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों में हिस्सा
आधार रेखा:							
सभी बैंक	**14.1**	**10.3**	**2.9**	–	–	–	–
चुनिन्दा 60 बैंक	**13.9**	**10.1**	**2.8**	–	–	–	–
शॉक 1:	11.9	7.9	5.8	5	6.7	11	30.0
शॉक 2:	11.1	7.2	7.2	12	30.2	18	41.9
शॉक 3:	12.7	8.8	4.2	3	1.5	4	6.5

शॉक 1: एनपीए में 100 प्रतिशत वृद्धि
शॉक 2: एनपीए में 150 प्रतिशत वृद्धि
शॉक 3: एनपीए में वृद्धि 40 प्रतिशत पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के एनपीए हो जाने के कारण हुई है।

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और आरबीआई स्टाफ द्वारा परिकलन

चार्ट 3.36: ऋण जोखिम: बैंकों के दबावग्रस्त सीआरएआर का वितरण

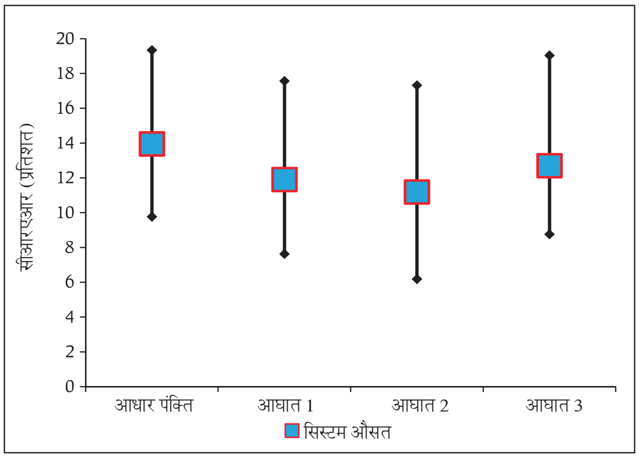

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

सारणी 3.4 : ऋण जोखिम: क्षेत्रवार - पूंजी और एनपीए पर प्रभाव

(प्रतिशत)

	प्रणाली स्तर		
	सीआरएआर	कोर सीआरएआर	एनपीए अनुपात
बेसलाईन:			
सभी बैंक	**14.1**	**10.3**	**2.9**
चुनिन्दा 60 बैंक	**13.9**	**10.1**	**2.8**
शॉक: प्रत्येक सैक्टर में एनपीए में 5 प्रतिशत अंक वृद्धि			
विद्युत	13.7	9.8	3.2
दूर संचार	13.8	10.0	3.0
कृषि	13.4	9.6	3.5
रियल एस्टेट	13.3	9.4	3.7
सभी 4 सैक्टर: कृषि+ विद्युत+रियल एस्टेट+ दूर संचार	12.6	8.8	4.7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	12.8	8.9	4.4

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और आरबीआई स्टाफ परिकलन।

[14] कार्यप्रणाली तथा ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय के लिए कृपया अनुबंध देखें।

[15] इस रिपोर्ट के अध्याय V में बृहत् तनाव परीक्षण (मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट) के परिणामों के बारे में चर्चा की गई है।

ऋण संकेन्द्रण उल्लेखनीय नहीं था

3.45 बैंकों के ऋण संविभाग के संकेन्द्रण के अध्ययन से मालूम हुआ कि प्रणाली स्तर पर संकेन्द्रण मध्यम प्रतीत होता है, हालांकि कुछ बैंकों के मामले में संकेन्द्रण अधिक था (सारणी 3.5)। सबसे बड़े समूह उधारकर्ता के प्रति बैंकों का औसत एक्सपोज़र कुल अग्रिमों का 4.7 प्रतिशत था। यद्यपि अधिकतम एक्सपोज़र 26.1 प्रतिशत पर काफी अधिक था।

बैंक ब्याज दर आघात सहने में समर्थ रहे

3.46 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आघात सहने की क्षमता जिसमें प्रतिफल वक्र पर समानांतर और गैर-समानांतर दोनों बदलाव शामिल हैं, का आकलन किया गया। बैंकिंग और व्यापारिक बहियों के लिए परीक्षण अलग-अलग किये गये। व्यापारिक बहियों पर किए परिणामों से पता चलता है कि ब्याज दर जोखिम सीमित होंगें और किसी भी बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंकिंग बही के परिणाम भी यही बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली अनुमानित दबाब परिदृष्यों का सामना कर सकते हैं, हालांकि कुछ बैंकों के सीआरएआर निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हो गया था। सबसे अधिक प्रभाव 250 आधार अंक के साथ भारतीय राष्ट्रीय रुपये के प्रतिफल वक्र में समानांतर ऊपर की ओर बदलाव में है।

प्रतिकूल विनिमय दर और इक्विटी मूल्य उतार-चढ़ाव का असर मामूली होगा

3.47 मुद्राओं के मूल्यों में 10/20 प्रतिशत घट/बढ़ का अलग अलग बैंकों के निवल द्विपक्षीय मुद्रा स्थिति पर प्रभाव का आकलन किया गया। दबाव परीक्षण इंगित करते हैं कि प्रभाव उल्लेखनीय नहीं होगा। चूंकि बैकों का इक्विटी बाज़ार एक्सपोज़र उल्लेखनीय नहीं था इसलिए इक्विटी मूल्यों में 40 प्रतिशत गिरावट का बैंकों की पूंजी पर प्रभाव बताते हैं कि आघात का असर मामूली सा हुआ है। दबाव से प्रणाली स्तरीय सीआरएआर 14.1 प्रतिशत बेस-लाईन से गिरकर 13.4 प्रतिशत हो गया। सभी बैंकों के लिए दबाबोत्तर सीआरएआर 9 प्रतिशत रहा।

चलनिधि जोखिमों को कम करने में एसएलआर निवेश बहुत महत्वपूर्ण हैं

3.48 सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश नकदी जोखिम[16] कम करने में प्रमुख 3.48 नकदी जोखिम के प्रति बैंकों की मज़बूती

सारणी 3.5: ऋण जोखिम:जमघट-पूंजी और एनपीए पर प्रभाव

(बैंकों की संख्या को छोड़ कर अंक प्रतिशत में हैं)

	प्रणाली स्तर			प्रभावग्रस्त बैंक (सीआरएआर < 9%)		प्रभावग्रस्त बैंक (कोर सीआरएआर < 6%)	
	सीआर-एआर	कोर सीआर-एआर	एनपीए अनुपात	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों में हिस्सा	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों में हिस्सा
आधार रेखा:							
सभी बैंक	**14.1**	**10.3**	**2.9**	-	-	-	-
चुनिन्दा 60 बैंक	**13.9**	**10.1**	**2.8**	-	-	-	-
आघात 1	12.7	8.8	5.6	1	0.19	1	3.0
आघात 2	12.2	8.3	7.8	1	0.19	2	5.1
आघात 3	11.6	7.7	10.6	1	0.19	9	30.4
आघात 4	12.3	8.4	7.5	1	0.19	2	5.1

आघात 1 : सर्वोच्च वैयक्तिक उधारकर्ता चूक
आघात 2 : सर्वोच्च 2 वैयक्तिक उधारकर्ता चूक
आघात 3 : सर्वोच्च 3 वैयक्तिक उधारकर्ता चूक
आघात 4 : सर्वोच्च समूह उधारकर्ता चूक

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और आरबीआई स्टाफ परिकलन।

सारणी 3.6 : ब्याज दर जोखिम: बैंक बहियां- बैंकों पर प्रभाव

(बैंकों की संख्या को छोड़ कर अंक प्रतिशत में हैं)

	प्रणाली स्तर		प्रभावग्रस्त बैंक (सीआरएआर < 9%)		प्रभावग्रस्त बैंक (कोर सीआरएआर < 6%)	
	सीआर-एआर	कोर सीआर-एआर	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों में हिस्सा	बैंकों की संख्या	कुल आस्तियों में हिस्सा
आधार रेखा::						
सभी बैंक	**14.1**	**10.3**	–	–	–	–
चुनिन्दा 60 बैंक	**13.9**	**10.1**	–	–	–	–
बैंकिग बहियों पर निवल प्रभाव (कमाई+पोर्टफोलियो)						
आघात 1	10.9	7.1	16	25.9	18	41.3
आघात 2	13.9	10.1	0	0.0	0	0.0
आघात 3	13.4	9.6	0	0.0	0	0.0
आघात 4	12.0	8.3	3	3.4	7	10.5
बैंकिग बहियों पर आय प्रभाव (कमाई)						
आघात 1	13.8	10.0	1	1.8	1	1.8
आघात 2	13.9	10.1	0	0.0	0	0.0
आघात 3	13.8	10.1	0	0.0	0	0.0
आघात 4	13.8	10.0	1	1.8	1	1.8
बैंकिग बहियों पर मूल्यांकन प्रभाव (अवधि अन्तराल विश्लेषण)						
आघात 1	11.0	7.2	14	23.1	17	40.2
आघात 2	13.9	10.1	0	0.0	0	0.0
आघात 3	13.4	9.7	0	0.0	0	0.0
आघात 4	12.1	8.4	2	1.5	7	10.2

आघात 1: भारतीय राष्ट्रीय रुपये प्रतिफल वक्र में 250 बैसिंक बिंदु समानांतर उर्ध्वगामी परिवर्तन
आघात 2: 250 आधार रेखा अधोमुखी परिवर्तन का समानांतर
आघात 3: ब्याज दर में लीनियरली स्प्रेड 1 माह से 10 वर्ष की परिपक्वता पर ब्याज दर 100 बैसिंक बिंदु वृद्धि से भारतीय राष्ट्रीय रूपये प्रतिफल वक्र का सीधा होना
आघात 4: भारतीय राष्ट्रीय रूपये प्रतिफल वक्र में एक वर्ष दर में 250 बिन्दु रेखिक ऊपर की ओर पलटना और 10 वर्षीय दरें 100 बीपीस गिरावट

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और आरबीआई स्टाफ परिकलन।

[16] दबाब परीक्षण इस विचार से किया गया कि (i) सिस्टम वाईड रन ऑन डिपोजिटस अवधि के दौरान एसएलआर सिक्योरिटीज प्रयोग के लिए उपलब्ध रहेंगी और (ii) सिर्फ अतिरिक्त एसएलआर सिक्योरिटीज तरल हैं। नकदी ,सीआरआर, अंतर बैंक जमाराशियों और निवेशों को अलग-अलग संयोजित करके तरल आस्तियों की पाँच अलग-अलग परिभाषाओं का प्रयोग किया गया।

चार्ट 3.37: ब्याज दर जोखिम - बैंकिंग बही - बैंकों के दबावग्रस्त सीआरएआर का वितरण

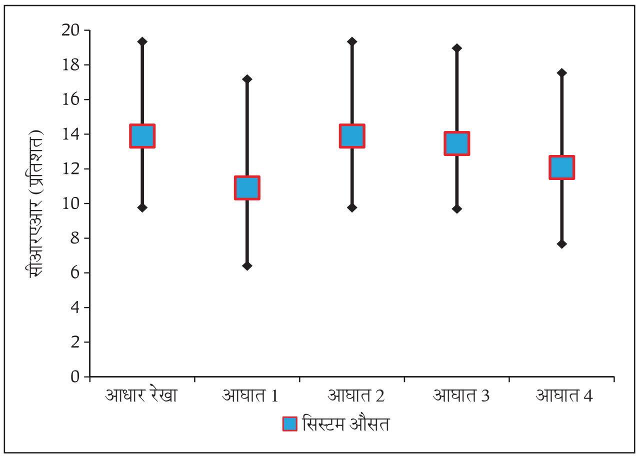

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

का दबाव परिदृष्य के आकलन बताते हैं कि कुछ बैंकों की नकदी स्थिति में ह्रास हुआ है। सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की उपलब्धता से तथापि बैंकों को नकदी दबाव दूर रखने में मदद मिली (सारणी 3.7)।

बॉटम-अप दबाव परीक्षण भी बैंकिंग प्रणाली की मज़बूती प्रतिबिम्बित करते हैं

3.49 चुनिन्दा बैंकों (पैरा 3.42) द्वारा किए गये बॉटम-अप दबाव परीक्षण भी अलग तरह की संवेदनशीलता विश्लेषण के प्रति बैकों की मजबूती ही सिद्ध करते हैं। जैसे कि टॉप डाऊन दबाव परीक्षण के मामले में दबाव परीक्षण का प्रभाव कुछ बैंकों पर अपेक्षतया रूप से अधिक गंभीर था। उनकी दबाव परिक्षणोत्तर सीआरएआर स्थिति न्यूनतम निर्धारित सीमा के अनुसार नहीं थी (चार्ट 3.38)।

सारणी 3.7: तरलता जोखिम: बैंकों पर प्रभाव

(बैंकों की संख्या को छोड़ कर अंक प्रतिशत में हैं)

	तरल आस्तियों की परिभाषा	घाटे का सामना कर रहे बैंक			चल आस्तियों का अनुपात
		बैंकों की संख्या	जमा राशियों का हिस्सा	आस्तियों का हिस्सा	
आधार रेखा: 1	**नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाली अंतर बैंक जमाराशियां- सभी एसएलआर निवेश**				22.9
आघात 1:	30 दिन में कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत आहरण	0	0.0	0.0	14.2
आघात 2:	5 दिन तक प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत जमाराशि का आहरण	0	0.0	0.0	11.0
आधार रेखा: 2	**नकदी अतिरिक्त सीआरआर, एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाली अंतर बैंक जमाराशियां- और एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाले निवेश**				7.4
आघात 1:	30 दिन में कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत आहरण	40	85.4	81.2	-2.8
आघात 2:	5 दिन तक प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत जमाराशि का आहरण	44	90.7	87.0	-6.7
आधार रेखा: 3	**नकदी अतिरिक्त सीआरआर, एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाली**				3.1
आघात 1:	30 दिन में कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत आहरण	57	99.9	99.6	-7.7
आघात 2:	5 दिन तक प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत जमाराशि का आहरण	57	99.9	99.6	-11.8
आधार रेखा: 4	**नकदी अतिरिक्त सीआरआर, एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाली अंतर बैंक जमाराशियां- और एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाले निवेश**				11.2
आघात 1:	30 दिन में कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत आहरण	26	59.9	56.8	1.3
आघात 2:	5 दिन तक प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत जमाराशि का आहरण	36	77.8	73.3	-2.4
आधार रेखा: 5	**नकदी अतिरिक्त सीआरआर, एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाली अंतर बैंक जमाराशियां- और एक महीने के अन्दर परिपक्व होने वाले निवेश**				6.8
आघात 1:	30 दिन में कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत आहरण	54	99.5	98.9	-3.5
आघात 2:	5 दिन तक प्रत्येक दिन 3 प्रतिशत जमाराशि का आहरण	57	99.9	99.6	-7.4

स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ डारिकलन

चार्ट 3.38: बॉटम-अप दबाव परीक्षण: चुनिन्दा बैंकों के के दबावग्रस्त सीआरएआर का वितरण

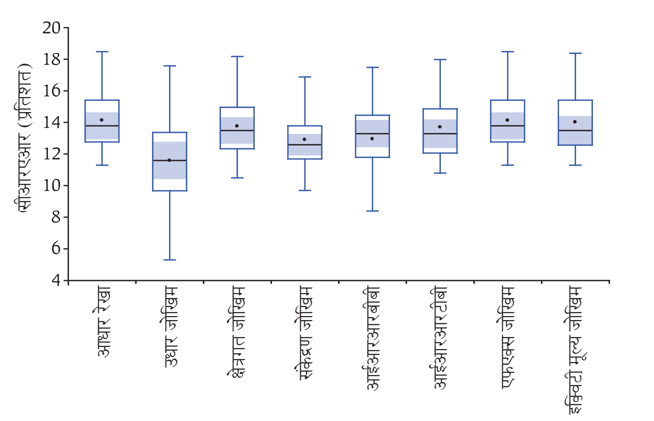

उधार जोखिम	एनपीए 150 प्रतिशत बढ़ा
क्षेत्रगत जोखिम	प्रत्येक क्षेत्र में एनपीए 5 अंक बढ़ा (कृषि+उर्जा+स्थावर संपदा + टेलीकाम)
संकेद्रण जोखिम	सर्वोच्च तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं की चूक
ब्याज दर जोखिम- बैंक बही (आईआरआर-बीबी)	250 आधार अंकों द्वारा एनआरआई लाभ में समानांतर उर्ध्वगामी परिवर्तन
ब्याज दर जोखिम- व्यापार बही (आईआरआर-टीबी)	250 आधार अंकों द्वारा एनआरआई लाभ में समानांतर उर्ध्वगामी परिवर्तन
विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिम	सभी मुद्राओं के प्रति रुपये में 20 प्रतिशत का अवमूल्यन
ईक्विटी मूल्य जोखिम	ईक्विटी की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट

स्रोत: चुनिन्दा बैंक

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों की ऋण जोखिम आघातों के प्रति भेद्यता...

3.50 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का ऋण जोखिम पर दबाब परीक्षण उनके मार्च 2012 के तुलन पत्र डेटा का प्रयोग करते हुए किया गया। बैंको के सीआरएआर पर ऋण जोखिम आघात का प्रभाव दो भिन्न परिदृष्यों के अधीन यह मान कर किया गया कि सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में क्रमशः 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत वृद्धि होगी। परिणाम बताते हैं कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक प्रथम परिदृष्य के तहत माने गये आघात आसानी से सह सकते हैं, हालांकि दूसरे परिदृष्य के तहत यह थोड़े दबाव में आ सकते हैं (चार्ट 3.39)।

...नकदी तरलता जोखिम के प्रति भी

3.51 नकदी तरलता जोखिम पर दबाव परीक्षण दो भिन्न परिदृष्यों के अधीन यह मान कर किया गया कि नकदी बहिर्गमन में 1 से 28 दिन अवधि समूह में क्रमशः50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत वृद्धि होगी। यह माना गया कि दोनों परिदृष्यों के तहत नकदी प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यह समझा गया था कि दबाब के परिणाम स्वरूप यदि 1 से 28 दिन अवधि समूह में बेमेल अथवा नकारात्मक अन्तर (अर्थात कैश इन्फलो लेस आऊट फ्लो) आऊट फ्लो के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाएं तो बैंक प्रभावित हो सकते हैं। दबाब परीक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक कम गंभीर परिदृष्य में भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हो सकते हैं (चार्ट 3.40)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां ऋण जोखिम आघात का सामना कर सके

3.52 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र पर दिसंबर 2012 में समाप्त अवधि में दो भिन्न परिदृष्यों क तहत यह मान कर एक दबाब परीक्षण किया गया कि सकल अनर्जक आस्तियों में क्रमशः 200 प्रतिशत तथा 500 प्रतिशत वृद्धि होगी।

चार्ट 3.39: पूंजी स्थितियों पर आघातों का प्रभाव: एसयूसीबी - मार्च-2012

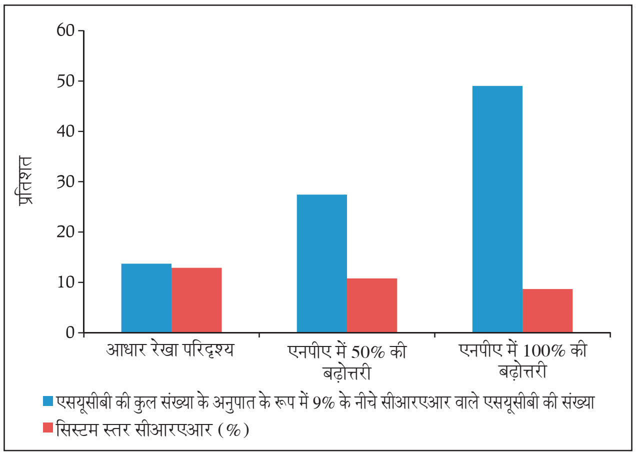

टिप्पणी : मार्च 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.40: तरलता जोखिम आघातों का प्रभाव: यूएसयूबी-मार्च-2012

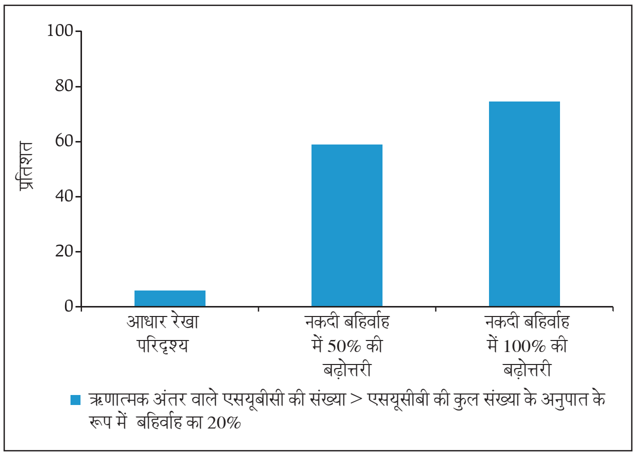

टिप्पणी : मार्च 2012 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

3.53 यह पाया गया कि पहले परिदृष्य में सीआरएआर में 27.5 प्रतिशत से मामूली सी कम हो कर 26.8 प्रतिशत रह गया, जबकि दूसरे परिदृष्य में सीआरएआर घटा कर 24.3 प्रतिशत किया गया। मुख्यत: सीआरएआर की स्थिति सहज होने के कारण अधिक कड़े दबाव परिदृश्य में भी, यह क्षेत्र गतिशील रहा। लेकिन कुछ अलग-अलग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई की कुल आस्तियों का 5 प्रतिशत) का सीआरएआर 15 प्रतिशत के विनियामक स्तर से कम हो गया।

अध्याय IV
वित्तीय क्षेत्र विनियमन और इंफ्रास्ट्रक्चर

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कई देशों द्वारा प्रारम्भ किये गये वित्तीय क्षेत्र सुधार उपाय गति और विस्तार के साथ अलग-अलग देशों और बाजारों पर लागू किये जा रहे हैं। मानक निर्धारक निकायों द्वारा नीतिगत सुधारों के संबंध में अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं इन्हें व्यापक अध्ययन और बहस के बाद लागू किया जाना चाहिए ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकें और अनपेक्षित दुष्परिणामों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, बासेल III के संदर्भ में अंतिम दिशा-निर्देश तथा त्वरित प्रावधानीकरण पर चर्चा पत्र जारी किये जा चुके हैं। अधूरी कार्यसूची में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करना, ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार तथा वित्तीय संस्थानों की संकल्प संरचना के लिए अधिक सुधार का अभिसरण भी शामिल है। निपटान के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए हुए देश में भुगतान तथा निपटान प्रणाली के और अधिक मजबूत बने रहने की आवश्यकता है। कुछ चुनिंदा मामलों जैसे आरटीजीएस प्रणाली की निपटान गति में कमी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(सीसीआईएल) द्वारा कल्पित निपटान बैंकों के लिए एक दिवसीय (इंट्रा डे) बड़े गैर संपार्श्विक जोखिमों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। सुरक्षा तंत्र प्रणालियों का कार्य सुचारु है लेकिन जमा बीमा निधि की पर्याप्तता और लचीलेपन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

वैश्विक नियामक सुधारों में गति आ रही है लेकिन कार्यान्वयन की चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता है

4.1 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुई अंतरराष्ट्रीय पहल में गति आने लगी है और सुधारों के लिए नीतिगत ढांचा परिलक्षित होने लगा है। तथापि कार्यान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उभरने लगी हैं।

4.2 कई देशों ने बासेल III की अपेक्षाओं के अंतर्गत आने के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय नीतिगत संरचना की घोषणायें की जिसने सीमा पार संगतता के बारे चिंता बढ़ा दी है। व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान तंत्र और ओटिसी डेरिवेटिव्ज बाज़ारों में सुधार लागू करने में अंतर जैसे कारणों से इसके कार्यान्वयन में भी फर्क उभर रहा है। भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए सुधारों के अनभिप्रेत परिणाम चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं। संभावित डिलीवरेजिंग से संबंधित महत्त्वपूर्ण चिंता के विषयों में उभरते बाज़ारों के लिए नए पूँजी और तरलता मानकों के कारण ट्रेड क्रेडिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस आदि से संबंधित चिंतायें शामिल हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बासेल III के तहत प्रस्तावित कुछ पूंजी लिखतों जैसे आकस्मिक पूँजी लिखतों के लिए बाजार की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। बासेल III तरलता मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित तरल आस्तियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और घरेलू वित्तीय बाजार पर इस प्रकार की अपेक्षाओं के प्रभावों के बारे में भी चिंता है।

नए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

4.3 रिज़र्व बैंक ने बासेल III पर 02 मई 2012 को अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बासेल III पूंजी आवश्यकता का कार्यान्वयन 01 जनवरी 2013 से शुरू हो जाएगा। 31 मार्च 2018[1] से मानदंड पूरी तरह से कार्यान्वित किये जाएंगे। नए मानकों के तहत बैंकों से अपेक्षा है कि :

- न्यूनतम 9 प्रतिशत की कुल पूँजी बनाये रखना जिसमें 7 प्रतिशत टियर 1 की पूँजी हो और इस टियर 1 पूँजी में कॉमन ईक्विटी की जोखिम भारित परिसम्पत्तियाँ 5.5प्रतिशत हों।
- कॉमन ईक्विटी के रूप में जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 2.5 प्रतिशत के रूप में पूँजी संरक्षण बफर बनाना। पूंजी संरक्षण बफर का कार्यान्वयन 31 मार्च 2015 से शुरू होगा।

[1] कार्यान्वयन को नौ माह आगे बढ़ाया गया है ताकि प्रति वर्ष 31 मार्च को बैंकों की वित्तीय लेखाबंदी के साथ-साथ इसका पूरा अनुपालन किया जा सके।

4.4 एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, भारत में मौजूद पूंजी पर्याप्तता, बासेल III समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से एक प्रतिशत अधिक है और उच्च अपेक्षाएं बासेल III के तहत जारी रहेंगी। एक और अधिक कठोर लीवरेज अनुपात भी इस तथ्य के आधार पर निर्धारित किया गया है कि अधिकांश भारतीय बैंक एक अपेक्षाकृत आरामदायक स्थिति में हैं जो बासेल समिति द्वारा प्रस्तावित 3 प्रतिशत से बहुत अधिक है। समानांतर व्यवस्था के दौरान बैंकों को उनके लीवरेज अनुपात के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के प्रयास करने चाहिएं लेकिन, किसी भी हालत में लीवरेज अनुपात 4.5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बैंक का लीवरेज अनुपात 4.5 प्रतिशत से कम हो तो उसे इस अनुपात को 4.5 प्रतिशत के स्तर से ऊपर लाने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करने चाहिएं। बासेल समिति द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए समानांतर व्यवस्था के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीवरेज अनुपात आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाएगा।

4.5 बासेल III प्रस्तावों के कार्यान्वियन के परिणामों के दूरगामी होने की आशा की जाती है। भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में यह कार्यान्वियन ऐसे समय पर हो रहा है जब विकास की बाध्यताओं के कारण ऋण की मांग बढ़ने की संभावना है, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आवश्यकता है और बढ़ते वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही, अतिरिक्त पूंजी (बफ़र) अपेक्षाओं पूर्ति और बढ़ती ऋण आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी हो सकती हैं। बासेल III के पूर्ण कार्यान्वियन के दौरान ईक्विटी और नॉन ईक्विटी दोनों प्रकार की अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएं बढ़ने की संभावना है। बैंकिंग प्रणाली पर अल्पकालिक रूप से इसके परिणामस्वरूप पूंजी बाजार पर दबाव बढ़ेगा, पूंजी की लागत बढ़ेगी और ईक्विटी पर प्रतिलाभ कम होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं के राजकोषीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। फिर भी मध्यावधि से दीर्घावधि उपायों द्वारा बैंकिंग प्रणाली को निवल और अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से व्यापक लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा भारत में बासेल II के प्रावधानों (31 मार्च 2012 तक तक सीआरएआर 14 प्रतिशत से अधिक और कोर सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक) के तहत बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की सुखद स्थिति यह दर्शाती है कि यह सशक्तता के साथ बासेल III की अपेक्षाओं का आसानी से पालन कर सकेगी। बासेल III के पूर्ण कार्यान्वियन के लिए विस्तारित परिवर्ती व्यवस्थाओं से बैंकों को पूंजी अपेक्षाओं को सावधानीपूर्वक निर्धारित करने और बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल पायेगा।

4.6 पिछले एफएसआर में भारतीय बैंकों के ऋण जोखिम के लिए भविष्य के प्रावधानों पर ध्यान दिया गया था। रिज़र्व बैंक ने गतिशील प्रावधानीकरण पर मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं[2]। वर्ष के दौरान बनाए गए गतिशील प्रावधानों को एक वर्ष के लिए पोर्टफोलियो की दीर्घावधि संभावित हानि और वर्ष के दौरान वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधानों के बीच अंतर के रूप में दर्शाया गया है (बॉक्स 4.1)।

आइएफआरएस के साथ कनवर्जेन्स की धीमी प्रगति

4.7 बैंकिंग क्षेत्र की आइएफआरएस कनवर्जेन्स की चुनौतियां घरेलू कनवर्जेन्स कार्यक्रम के बारे में अस्पष्टता तथा वित्तीय लिखतों से संबंधित आइएफआरएस 9 को अंतिम रूप देने में अनिश्चितता से उत्पन्न होती हैं। वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण और गणना के संबंध में इसके पहले अंतिम रूप प्रदान की गयी अपेक्षाओं के दुबारा खोलने के आईएएसबी प्रस्तावों के साथ अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकीकरण बोर्ड द्वारा क्षति और लेखाकरण के संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के कारण आइआफआरबी 9 के संबंध में अनिश्चितताएं पैदा हो रही हैं। कंवर्जन के दौर में भारतीय बैंकों के समक्ष कुछ प्रमुख तकनीकी समस्याएं भी आ रही हैं। आईएफआएएस और वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के बीच वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और गणना के तरीकों में भी अंतर है। आईएफआरएस तथा वित्तीय संपत्ति का वर्गीकरण और नापतौल पर वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों के बीच का अंतर, बैंकों द्वारा कारोबार मॉडल के स्तर पर ध्यान केंद्रीत करना और इस क्षेत्र में प्रबंधन के समक्ष के चुनौतियाँ, निपुण कर्मचारियों की अपर्याप्तता और सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणाली और पद्धति में संशोधन जैसी अन्य चुनौतियों पर भी यथा-समय ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले एफएसआर में हुई चर्चा के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल कार्यान्वियन संबधित पहलुओं की जांच कर रहा हैं।

देश में मौजूदा समाधान व्यवस्था में सुधार की जरूरत

4.8 समाधान के वर्तमान नियम, वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा, वित्तीय संस्थानों के लिए अपनाई गई प्रभावी समाधान व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं[3]। वर्तमान में एक बैंक के विघटन का प्रयास बैंकिंग विनियमन

[2] आरबीआई डिस्कशन पेपर ''इंट्रोडक्शन ऑफ डाइनैमिक प्रोविज़निंग फ्रेमवर्क फॉर बैंक इन इंडिया'' मार्च, 30, 2012 (http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=26219)

[3] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf

बॉक्स 4.1 : भारत में बैंकों के लिए गतिशील (डाइनैमिक) ऋण हानि प्रावधानीकरण प्रारंभ करना

वर्तमान में भारतीय बैंकों ने चार प्रकार के ऋण हानि प्रावधान किए हैं. जैसे (क) मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान (ख) गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान (एनपीए), (ग) अस्थायी (चल) प्रावधान, और (घ) एक पुनर्निर्मित संपत्ति के उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान। मौजूदा प्रावधानीकरण नीति में निम्नलिखित कमियां पाई गई, (i) मानक आस्तियों के प्रावधानों की दर, किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण या बैंकों के क्रेडिट हानि के इतिहास के आधार पर निर्धारित नहीं की गई है (ii) बैंक पूर्व- निर्धारित नियमों के बिना, अपने विवेक पर अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों का निर्धरण करते हैं और सभी बैंक अस्थायी प्रावधानों का निर्धारण नहीं करते। (iii) हालांकि रिजर्व बैंक ने मानक आस्ति प्रावधानीकरण की दरों में प्रतिचक्रीय बदलाव की नीति अपनायी है, किंतु यह कार्यप्रणाली ऋणचक्रों अथवा हानि के इतिहास के विश्लेषण के बजाय मुख्यत: वर्तमान में उपलब्ध डेटा और धारणाओं के आधार पर निर्धारित की गयी है और इसलिए प्रावधानीकरण के ढ़ांचे में प्रतिचक्रीय या सुगमीकरण के तत्त्व नहीं हैं।

पिछले लगभग एक दशक में क्रेडिट जोखिम मॉडलिंग में प्रगति के कारण एक क्रेडिट पोर्टफोलियो में संभावित नुकसान को मापने के लिए प्रत्याशित हानि (ईएल) और अप्रत्याशित हानि(यूएल) की अवधारणा शुरू की गई है। आम तौर पर यह माना गया है कि बैंकों को अप्रत्याशित नुकसान पूंजी द्वारा और अपेक्षित घाटे को प्रावधानों द्वारा कवर करना चाहिए। आम तौर पर ईएल को क्रेडिट नुकसान वितरण के साधन के रूप में लिया जाता है। ईएल आधारित प्रावधानीकरण में आगे का देखने के तत्व हैं। क्योंकि इसमें बाय डीफाल्ट संभावित चक्र - के माध्यम से दृष्टिकोण शामिल करने की क्षमता है। बासेल समिति भी ईएल दृष्टिकोण का समर्थन करती है जिसमें वास्तविक हानियां अधिक पारदर्शी दिखती हैं तथा यह वर्तमान की गई हानि दृष्टिकोण से कम प्रो- साईक्लिक भी है।

गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे का उद्देश्य चक्रीय लाभ पर किए गए नुकसान के प्रभाव को कम करना है, न कि अपेक्षित हानि के लिए सामान्य प्रावधानीकरण की गुंजाइश प्रदान करना। भारत में प्रस्तावित गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे में दो घटक हैं, अर्थात्,

क. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान घटना के उपरांत किए गए विशिष्ट प्रावधान (जो लाभ-हानि लेखे में नामे डाले जायेंगे) किये जाने अपेक्षित हैं, और

ख. डाइनैमिक प्रावधान (डीपी) $\alpha C_t - \Delta SP$ अर्थात् एक वर्ष के लिए निवेश संविभाग में दीर्घावधि औसत प्रत्याशित हानि और वर्ष के दौरान किये गये विशिष्ट प्रावधानों के बीच अंतर (α-EL और C_t - ऋणों का स्टाक दर्शाता है।

यह माना जाता है कि जब पहली बार कोई दृष्टिकोण लागू किया जाता है तो बैंक के पास अपनी अनर्जक आस्तियों को कवर करने के लिए पर्याप्त विशिष्ट प्रावधान होते हैं। αC_t - ΔSP का धनात्मक मान डीपी लेखे में क्रेडिट शेष बढ़ा देगा। नकारात्मक मान डीपी लेखे से आहरण द्वारा गिरावट को दर्शाएगा। यह सामान्यतः सुनिश्चित करेगा की प्रति वर्ष विशिष्ट प्रावधानों और डीपी के कारण लाभ-हानि लेखे को प्रभार αC_t के स्तर पर बनाए रखा जाता है।

एक डाइनैमिक प्रावधानीकरण के ढांचे के कार्यान्वयन के संदर्भ में यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सभी बैंक एक ही स्तर पर आ जायेंगे. वे बैंक जिनके पास क्षमताएं हैं वे सैद्धांतिक मॉडल के आधार पर एक डी पी ढ़ांचे की शुरूआत कर सकते हैं जिनका उल्लेख प्रारूप दिशानिर्देशों में किया गया है। नमूना बैंकों से प्राप्त आंकड़ा आधारित आंतरिक अनुमान यह बताते हैं कि बैंकों के लाभ-हानि पर प्रभाव के अर्थ में इस दृष्टिकोण का आशय यह होगा कि वार्षिक रूप से सकल अग्रिमों के 1.37 प्रतिशत के बराबर लाभ-हानि लेखे में कुल प्रावधान प्रभार करना होगा। पर्यवेक्षी आंकड़े दर्शाते हैं कि 2003 से 2010 की अवधि में मानक आस्ति प्रावधानों और सकल बट्टे खाते के लिए विशेष प्रावधानों के कारण लाभ-हानि को औसत वार्षिक प्रभार कुल अग्रिमों का 1.04 प्रतिशत रहा,जोकि सकल अग्रिमों की 0.58 प्रतिशत से 1.87 प्रतिशत की सीमा में है।यह अतिरिक्त प्रभार मुख्य रूप से डाउनटर्न लॉस गिवेन डिफाल्ट (एलजीडी) पर आधारित α के कैलिब्रेशन को दिया जा सकता है।

अधिनियम, 1949 के अधीन अनिवार्य या स्वैच्छिक विलयन के माध्यम से किया जाता है. किसी भी संकल्प के प्रयास के मूल उद्देश्यों में से एक है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा. हालांकि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अधीन अनिवार्य समामेलन में शेयरधारकों को मुआवजा मिलने से पूरी तरह से मना नहीं किया गया है।

4.9 भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए विघटन के वर्तमान दौर में कमियों और उसके प्रमुख घटकों / करणों की जांच करने और इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक विधायी और विनियामक परिवर्तनों का स्वरूप और विस्तार सुझाने के लिए रिजर्व बैंक में एक कार्यदल का गठन किया गया है। यह मुद्दा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप समिति के भी विचारधीन है।

जैसे जैसे बैंक बासेल II के प्रगतिशील दृष्टिकोण में अंतरण कर रहे हैं आरडब्ल्यूए घनत्व के अंतर अधिक स्पष्ट होते जाएंगे

4.10 स्थिरता के दृष्टिकोण से बैंकों, विशेषत: अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले बड़े बैंकों का बासेल II के प्रगतिशील दृष्टिकोण में अंतरण वांछनीय है। जब बैंक इन दृष्टिकोणों में अंतरित हो जाएंगे, आरडब्ल्यूए की प्रवृत्तियों पर निगरनी रखना आवश्यक होगा।

चार्ट 4.1: क्षेत्रों के बीच आरडब्ल्यूए घनत्त्व (प्रतिशत)

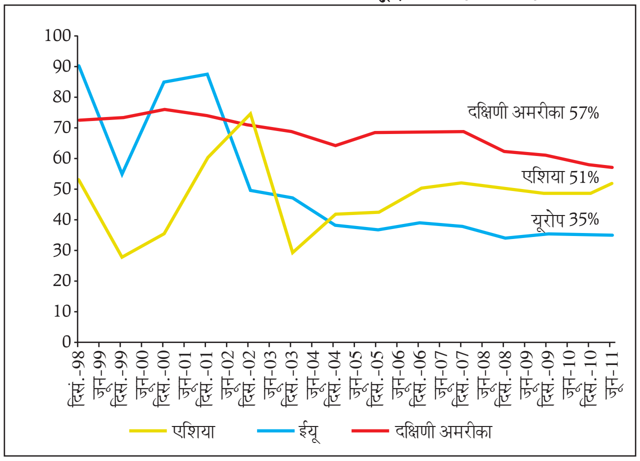

स्रोत: आईएमएफ वर्किंग पेपर - जोखिम भारित आस्तियों का पुनर्निवेश "देशों के बीच आरडब्ल्यूए में क्यों अंतर होता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है?", मार्च 2012

चार्ट 4.2 :आरडब्ल्यूए में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अंशदान

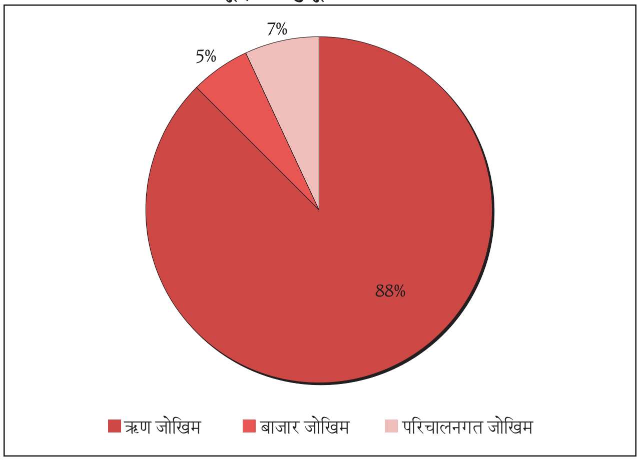

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

4.11 पूंजी अनुपात बैंक की ऋणशोधन क्षमता और आघात सहनीयता के महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं। कुल आस्तियों (आरडब्ल्यूए घनत्व) में आर डब्ल्यू ए का अनुपात, जोकि बैंकों की जोखिम स्थिति दर्शाने के संकेतक के रूप में कार्य करता है, के साथ बैंकों के पूंजी अनुपातों की गणना करने के लिए आर डब्ल्यू ए महत्त्वपूर्ण हैं। तथापि, पूरे आधिकारिक क्षेत्र में आरडब्ल्यूए घनत्व में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है (देखें चार्ट 4.1)। ऐसे अंतर उसी क्षेत्राधिकार में बैंकों के बीच भी दिखाई देते हैं। अधिकतर आरडब्ल्यूए घनत्व में अंतर जोखिम आधारित हैं, अर्थात् वे निवेश संविभाग में छुपी जोखिम और बैंक के मिले-जुले कारोबार में अंतर को दर्शाते हैं। ये उतार-चढ़ाव विनियामक विकास में अंतरों के कारण भी पैदा होते हैं - बासेल-I, बासेल-II प्रगतिशील दृष्टिकोणों, आदि तथा इस दिशा में राष्ट्रीय विवेक को अपनाने से आए हैं। तथापि, इन उतार-चढ़ावों के संबंध में चिताएं उभरती हैं जिनका कारण मानकों की व्याख्या में परिवर्तन है, जिसकी वजह से आगे चलकर जोखिम पैरामीटरों के कैलीब्रेशन में व्यवहार आधारित असमानताएं आती हैं।

4.12 भारतीय संदर्भ में, क्रेडिट जोखिम आरडब्ल्यूए का सबसे बड़ा घटक है जो औसतन बैंकिंग क्षेत्र के कुल आर डब्ल्यू ए के 71 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है (चार्ट 4.2)। तथापि, पूरे बैंकों के बीच आर डब्ल्यू ए घनत्त्व में महत्त्वपूर्ण अंतर है, हालांकि समग्र रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए समय के साथ आर डब्ल्यू ए घनत्व बढ़ता रहा है (चार्ट 4.3 और 4.4)।

.. परिणामत: पूंजी अनुपातों में संभाव्य घटता विश्वास

4.13 बासेल I से बासेल II में क्रमिक शिफ्ट और आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोणों से बैंकों को निम्नतर जोखिम भारित

चार्ट 4.3 :विभिन्न बैंक समूहों में आरडब्लयूए घनत्त्व -मार्च 2012

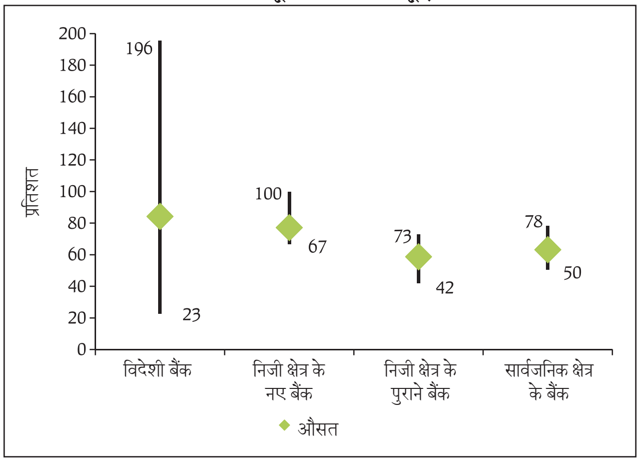

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 4.4: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आरडब्ल्यूए घनत्त्व (प्रतिशत)

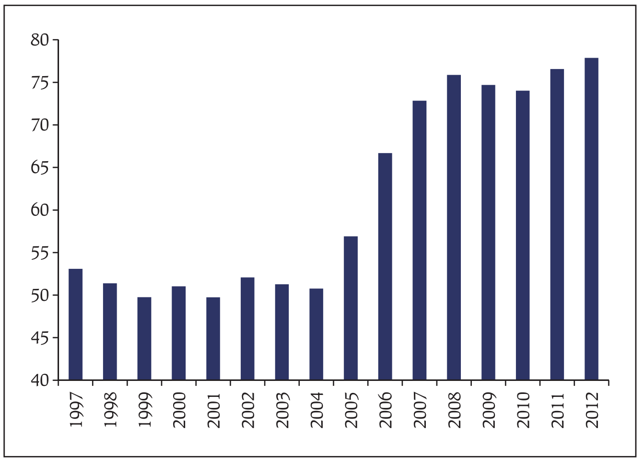

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवणियां

आस्तियों से कुछ हद तक लाभ हुआ। तथापि देशों के भीतर और देशों में जोखिम भारित आस्तियों के संबंध में समझे गये फर्क़ ने जोखिम भारित आस्तियों और पूंजी अनुपातों की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े किये।

4.14 बासेल समिति ने बासेल III के कार्यान्वियन की व्यापक निगरानी के भाग के रूप में यह प्रस्ताव किया है, अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम भारित आस्तियों की गणना में महत्त्वपूर्ण असंगतता के क्षेत्र पहचाने जाएं। इस अभ्यास के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, पहचानी गयी असंगतताओं के निराकरण के लिए नीतिगत सिफारिशों का निर्माण संभव होगा।

बैंकों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्युचुअल फंडों के साथ आपसी विचार- विमर्श (इंटरऍक्शन) पर नजदीकी निगरानी रखना न्यायसंगत है...

4.15 आभासी (शैडो) बैंकिंग गतिविधियों की जिम्मेदारी और नियमन मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास जारी हैं। इस खंड के नियमन की चुनौती है सभी महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करते हुए नियमन के अंतर्गत लाना कि कम कठोर नियमन खंडों की ओर जाने के लिए कोई प्रोत्साहन न हो। इस समय नीतिगत सुधार पांच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अर्थात् (क) नियमित बैंकिंग प्रणाली और आभासी बैंकिंग प्रणाली के बीच फैलने वाले परिणामों में घटाव; (ख) मुद्रा बाजार निधियों में 'रन' की संभावना कम करना; (ग) अन्य आभासी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दावा की गयी प्रणालीगत जोखिमों को आंकना और कम करना; (घ) प्रतिभूतिकरण से संबद्ध प्रोत्साहनों का आकलन और संरेखण; और (ङ) सुरक्षित वित्तीय संविदा जैसे रेपो और प्रतिभूति उधार देने से संबद्ध मन्दक जोखिमों और प्रो-साइक्लिकल प्रोत्साहन जो रन[4] के समय निधियन भार को बढ़ा सकते हैं।

...वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खंडों के बीच परस्पर संबद्धता

4.16 देश का गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, जिसमें *अन्यों के साथ-साथ* गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियाँ सम्मिलित हैं, इन कंपनियों द्वारा स्वीकार की गयी गतिविधियों के लिए यथोचित नियामक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है। फिर भी, इस क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सुधारों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की ऋण मध्यस्थता गतिविधियों का समग्र मैक्रो-मैपिंग(स्थूल-चित्र) प्रमाणित करना होगा। साथ ही, इन कंपनियों की बैंकिंग प्रणाली के साथ परस्पर-संबद्धता की मात्रा भी चिंता का विषय है, जो ऋण और चलनिधि जोखिम खड़ी कर सकता है (अध्याय V)।

4.17 म्युचुअल फंड क्षेत्र, विशेषत: मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों की विश्वसनीयता की मात्रा ने भी संस्थागत निवेशकों के सामने कुछ चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। तनाव के समय ऐसे निवेशकों के द्वारा निधियों के आहरण से गंभीर चलनिधि तनाव खड़े हो सकते हैं, जैसा कि 2008-2009 में पाया गया ।

पहचानी गयी और नियंत्रण में लायी गयी कमियाँ...

4.18 गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के नियमन की कमियों को निरंतरता से पहचाना और नियंत्रण में लाया जाता है और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है। वैकल्पिक निधियों के लिए नियामक ढाँचे की आवश्यकता, पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में जिसके मंद होने का संकेत दिया गया था, उस पर एफ़एसडीसी उप समिति में चर्चा की गयी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उसका ढाँचा बनाया है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा स्वर्ण ऋण देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिये जानेवाले एक्सपोज़र के कारण उद्भूत जोखिमों का ध्यान रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों की एक्सपोज़र सीमा कड़ी कर दी गयी है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिये गये स्वर्ण ऋणों पर मूल्य पर ऋण (loan to value) (एलटीवी) अनुपात निर्धारित किये गये हैं। बैंकिंग प्रणाली के लिए इसतरह के एलटीवी अनुपात निर्धारित नहीं किये गये हैं और भविष्य में इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनियों के लिए वैश्विक पहल भारतीय कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगी...

4.19 दि इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ इन्शोरेन्स सुपरवाइज़र्स (आइएआइएस) वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संयोजन से बीमाकर्ताओं के प्रणालीगत महत्त्व का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया कर रहा है। यह प्रणाली बीमा गतिविधियों का स्वरूप और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के सामने खड़ी जोखिमों की जानकारी हासिल करेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मानदंडों का समावेश किया जा सकता है, जैसे कंपनी के परिचालन का स्वरूप, उसका आकार, परस्पर-संबद्धता और प्रतिस्थापनीयता तथा उसकी वैश्विक गतिविधि। आईएआइएस इस संबंध में समानुक्रमण और आंकडों के विश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस अभ्यास के प्रथम चरण में सहभागी हुआ। तथापि भारत के बीमा परिचालनों का स्वरूप और विद्यमान नियामक ढाँचे को देखते हुए आइएआइएस ने भारत के संदर्भ में उपयुक्त कुछ

[4] http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_111027.pdf

संकेतकों पर विचार किया है। साथ ही भारतीय कंपनियों के वैश्विक परिचालन सीमित हैं और जटिल वित्तीय उत्पादों की तरफ उनके एक्सपोज़र का लगभग अभाव ही है।

बैंक बीमा मॉडेल के अंतर्गत संभाव्य दुर्विनियोजित विक्रय-मूल्य के निराकरण की आवश्यकता होगी

4.20 बैंक बीमा उस बीमा वितरण मॉडेल की ओर संकेत करता है, जहाँ बैंक शाखा नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री की जाती है। इस मॉडेल ने भारतीय संदर्भ में लोकप्रियता अर्जित की है क्योंकि देश के अनेक बड़े बैंकिंग समूह बीमा कंपनियों के भी प्रवर्तक हैं। साथ ही बैंकों की भौगोलिक पहुँच ने उन्हें बीमा उत्पादों के वितरण के लिए आदर्श माध्यम बना दिया है। बीमा उत्पादों की बिक्री से संबद्ध कार्य करने वाले बैंक स्टाफ को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण देने संबंधी मौजूदा नियामक आवश्यक आदेश होने के बावजूद इस वितरण के माध्यम से बीमा उत्पादों के दुर्विनियोजित विक्रय के मामले पाये गये हैं। ऐसे भी कुछ किस्से सुनने में आये हैं कि जमा और ऋण जैसे बैंकिंग उत्पादों के साथ बीमा उत्पादों की 'पैकेज' के तौर पर बिक्री की जा रही है, जिससे हित के टकराव से संबद्ध मामले पैदा होते हैं। सेबी द्वारा निवेश परामर्शदाता और आइआरडीए द्वारा बैंक बीमा पर प्रस्तावित विनियम इस मुद्दे का निराकरण करने की संभावना है। इस संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करने के सम्मिलित प्रयास भी जरूरी होंगे।

वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधाएँ (एफएमआई)

बढ़ी हुई बाजार अस्थिरता के बावजूद देश के एफएमआई का कार्य सहज रूप से चला

4.21 देश की भुगतान और निपटान प्रणालियाँ मजबूत रहीं और उसने बिना किसी प्रमुख बाधा के कार्य जारी रखा। विदेशी मुद्रा बाजार समेत विभिन्न बाजारों में उच्च अस्थिरता के असर का प्रबंधन एफएमआई ने विभिन्न खंडों की केंद्रीय पार्टियों के साथ उल्लेखनीय लचीलेपन से किया (बॉक्स 4.2)।

पहुँच-मानदंडों (एक्सेस क्राइटेरिया) को उदार बनाने से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को गति मिली है

4.22 मार्च, 2012 के अंत तक लेनदेन के कुल भुगतान मूल्यों का 74 प्रतिशत से अधिक भुगतान तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली से किया गया और इस तरह भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तरफ रुझान जारी रहा। परिमाण-वार भी,

बॉक्स 4.2: विदेशी मुद्रा बाजार और सीसीआइएल के यूएस डॉलर / भारतीय रुपया निपटान में वर्धित अस्थिरता

वर्ष 2011-12 और विशेषत: समीक्षाधीन अवधि में उँची अस्थिरता देखी गयी। (अध्याय 2) बढ़ी हुई अस्थिरता और भारतीय रुपये के मूल्य में तीव्र मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप सीसीआइएल के विदेशी खंड के सदस्यों के मार्जिन दायित्व के बाजार मूल्य को बही में अंकित करने (मार्क-टू-मार्केट) में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, सहभागियों के निवल करेंसी स्थितियों पर आधारित असर के साथ जोखिमों के प्रबंधन के कारण प्रारंभिक मार्जिनों में वृद्धि अनिवार्य हुई और घट-बढ़ मार्जिनों में भी वृद्धि के कुछ प्रसंग आए। कुछ प्रसंगों में दिन के दौरान उँची अस्थिरता के परिणामस्वरूप 50 से अधिक प्रतिशत से मार्जिन कवर में कटौती करनी पड़ी, जिससे इंट्रा-डे एमटीएम मार्जिन का संचयन न्यायसंगत ठहराना पड़ा (सारणी 4.1 और चार्ट 4.5)।

सारणी 4.1 : वर्ष 2011-12 के दौरान अस्थिरता मार्जिन के भार के ब्यौरे

तारीख	विदेशी मुद्रा फॉवर्ड खंड (प्रतिशत)	विदेशी मुद्रा निपटान खंड (प्रतिशत)
22 सितंबर 11 से 26 सितंबर 11	37.5	0.25
28 अक्तूबर 11 से 31 अक्तूबर 11	5.0	-
09 नवंबर 11 से 11 नवंबर 11	2.5	-
01 दिसंबर 11 से 02 दिसंबर 11	5.0	-
16 दिसंबर 11 से 19 दिसंबर 11	27.5	0.25
27 जनवरी 12 से 30 जनवरी 12	2.5	-

चार्ट 4.5 समीक्षा अवधि, जिसके दौरान विनिमय दर अत्यधिक अस्थिर रही, में दो दिनों में प्रारंभिक मार्जिन में वृद्धि (मिलियन रुपये में)

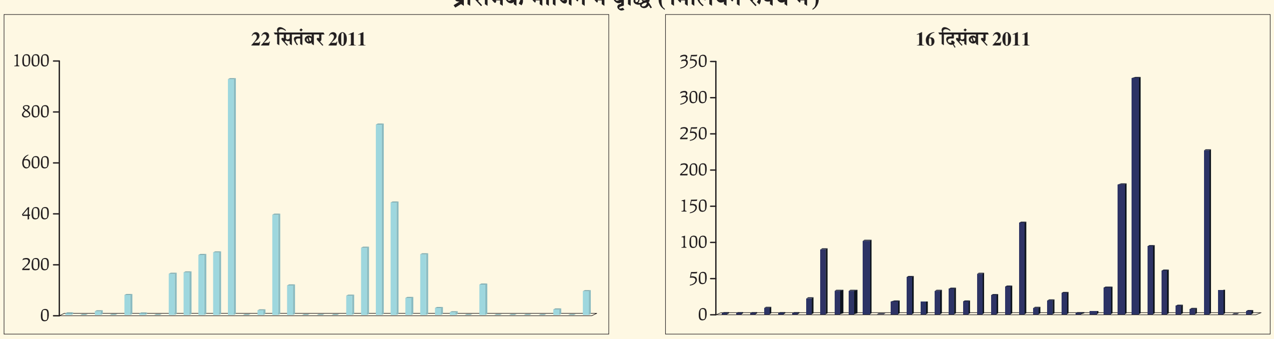

खुदरा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन मार्च 2011 की तुलना में मार्च 2012 में 37 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत हो गया।

4.23 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के पहुँच-मानदंड़ों को उदार बनाने से, आरटीजीएस और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफएफटी) भुगतान माध्यमों[5] की तरफ भुगतान लेनदेनों के बढ़ने की दिशा में तेजी आने की संभावना है। अबतक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में सिर्फ प्रत्यक्ष सदस्यता की सुविधा थी। उप-सदस्यता मार्ग (सब-मेंबरशिप) को चालू कर देने से सभी लाइसेंसीकृत बैंक एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में भाग ले सकेंगे। ऐसी उप-सदस्यता वैसे लाइसेंसीकृत बैंकों के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली होगी, जिनके पास तकनीकी क्षमता तो है पर जो पहुँच-मानदंडों अथवा लागत संबंधी कारणों से केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में भाग नहीं ले रहे हैं।

आरटीजीएस में जोखिम कम हुआ... पर इंट्राडे नकदी प्रबंधन की प्रभाव-क्षमता विभिन्न भागीदारों के बीच अलग-अलग है

4.24 आरटीजीएस प्रणालियाँ वास्तविक समय में सौदा दर सौदा लेनलेन करने की अनुमति देती हैं। इसलिए ये प्रणालियाँ प्रणालीगत और भुगतान-संबंधी जोखिमों को कम करने का प्रयास करती हैं। विशेष तौर पर, आरटीजीएस भुगतान और निपटान प्रणालियाँ राशि जमा करने की अवधि और नकदी-जोखिमों को कम करने में बहुत हद तक योगदान कर सकती हैं। भारतीय संदर्भ में, आरटीजीएस[6] में भुगतान में देरी का एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण दर्शाता है कि औसत दैनिक लेनदेन के 70 प्रतिशत (जो औसत दैनिक निपटान का 65 प्रतिशत है) का तत्काल निपटान हो जाता है (चार्ट 4.6)। बैंकों[7] के सक्रिय इंट्राडे नकदी प्रबंधन, केंद्रीय बैंक द्वारा इंट्राडे नकदी प्रावधान और बैंकों द्वारा बनाये रखे गए प्रूडेंशियल रिजर्व बैलेंसों द्वारा की गई 'डबल ड्यूटी' के कारण यह संभव हो पाता है। तथापि, लगभग 25 प्रतिशत लेनदेनों (राशि) का एक मिनट से अधिक के लैग से निपटान किया जाता है, जबकि 15 प्रतिशत लेनदेन का दस मिनट से अधिक के लैग से निपटान किया जाता है। आरटीजीएस प्रणाली के विभिन्न भागीदारों में सेट्लमेंट लैग के मामले में बहुत उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। अंतर्निहित प्रवृतियों (अंडरलायिंग ट्रेंड्स) की, खासकर आउटलायर के मामले में, बहुत ध्यान से निगरानी करने की आवश्यकता है (चार्ट 4.7 और 4.8)।

चार्ट 4.6 :आरटीजीएस में निपटान अंतर

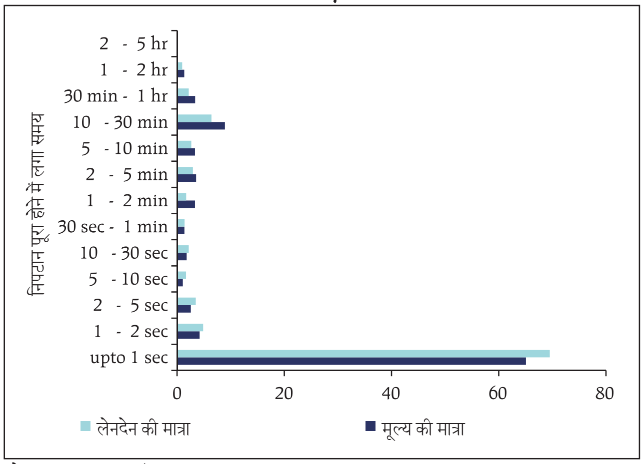

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 4.7 : एक मिनट के अंदर निपटान किए जाने वाले दैनिक औसत ग्राहक लेनदेन

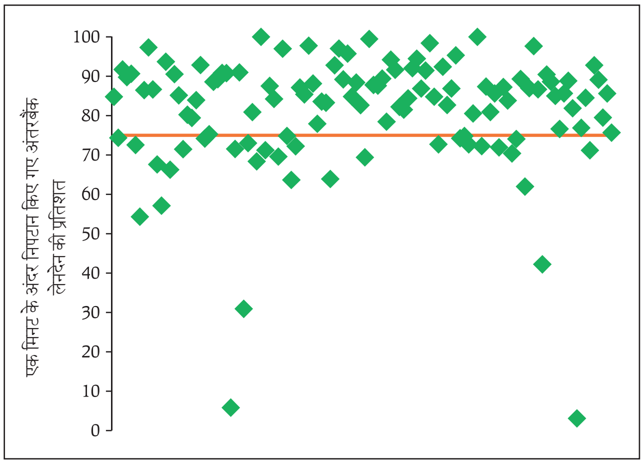

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 4.8: एक मिनट के अंदर निपटान किए जाने वाले दैनिक औसत अंतरबैंक लेनदेन

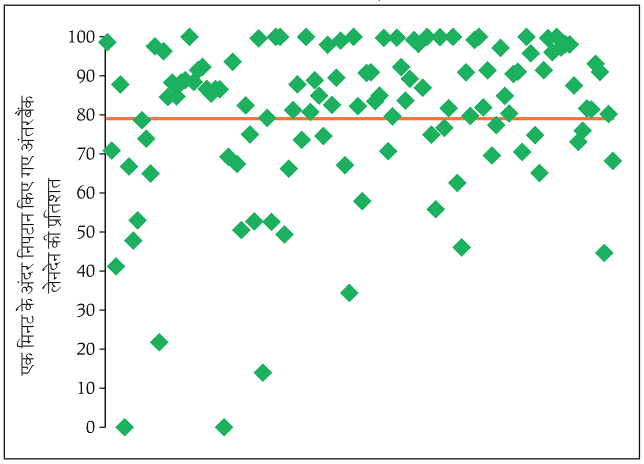

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

[5] http://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=7113&Mode=0

[6] प्रायोगिक विश्लेषण में मार्च 2012 के 15 कार्यदिवसों के आरटीजीएस के व्यक्तिगत लेनदेन आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया।

[7] आरटीजीएस के कई भागीदारों ने इंट्राडे नकदी प्रबंधन प्रणालियाँ लगायी है, जिससे वे भुगतान- कतारों (पेमेंट क्यूज) को आंतरिक रूप से संभाल पाने में सक्षम होते हैं।

सीसीआईएल के नामित निपटान बैंक (डीएसबी) भुगतान की अर्ध-प्रणालियों(क्वैसी पेमेंट सिस्टम्स) के तौर पर काम करते हैं...

4.25 भुगतान की अर्ध-प्रणालियों को सामान्यत: इस प्रकार पारिभाषित किया गया है: *ग्राहकों की तरफ से वैसे भुगतानों का समाशोधन और निपटान करने के लिए जिम्मेदार वाणिज्यिक संस्थाएँ, जो भुगतानों के मूल्य के एक बड़े प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका निपटान एक व्यवस्थित भुगतान प्रणाली के माध्यम से करने की बजाय, संस्था की बहियों में किया जा रहा है*[8]। ऐसी संस्थाओं द्वारा होने वाले जोखिम प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों द्वारा होने वाले जोखिमों की तरह ही हैं।

4.26 संपार्श्विक उधार लेने-देने संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) और सीसीआईएल के प्रतिभूति क्षेत्र में एसोशिएट सदस्यों के दो डीसीबी में संकेंद्रण से होने वाले जोखिम को दिसंबर, 2011 के एफएसआर में उजागर किया गया था। जोखिम इस तथ्य से भी बढ़ जाते हैं कि डीएसबी स्वयं अधिकांश मार्केट सेगमेंटों में बड़े भागीदार (स्वामित्व वाली स्थितियों में) हैं। निपटान परिमाणों का एक विश्लेषण दर्शाता है कि एसोशिएट सदस्य निपटान परिमाणों का एक बड़ा हिस्सा बनाते है (चार्ट 4.9)। इसलिए डीएसबी, भुगतान निपटान की अर्ध-प्रणालियों (क्वैसी पेमेंट सेट्लमेंट सिस्टम्स) की तरह काम करते हैं और संपूर्ण प्रणाली को इनसे होने वाले जोखिम की निगरानी करने की आवश्यकता है।

...डीसीबी को होने वाले बड़े इंट्राडे जोखिम को सीसीआईएल द्वारा ध्यान में रखने की आवश्यकता है

4.27 एसोशिएट सदस्यों के बड़े भुगतान मूल्यों के परिणामस्वरूप सीसीआईएल को डीसीबी को होने वाले महत्त्वपूर्ण इंट्राडे जोखिम को ध्यान में रखना पड़ता है (चार्ट 4.10)। सीसीआईएल ने उन हरेक डीसीबी के लिए सीमा स्वीकृत की है, जो संपार्श्विकृत नहीं (अनकोलैटराइज्ड) हैं। स्वीकृत सीमा से अधिक होने के कारण डीसीबी को जोखिम होने के उदाहरण भी हैं। एक या एक से अधिक डीसीबी का विफल होना प्रणालीगत चिंता का विषय है और सीसीआईएल के वित्तीय संसाधनों, इसकी नकदी, ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और सेंट्रल काउंटरपार्टियों(सीसीपी)[9] से बैंकों को होने वाले जोखिमों के लिए पूँजी पर्याप्तता के नियमों पर मौजूदा विनियमन निर्देशों के समानांतर, इस दिशा में प्रवृतियों का आकलन करने की आवश्यकता है। सीसीपी से बैंकों को होने वाले जोखिमों

चार्ट 4.9 :कुल निपटान मूल्यों के प्रतिशत के रूप में एसोशिएट सदस्यों का औसत निपटान मूल्य

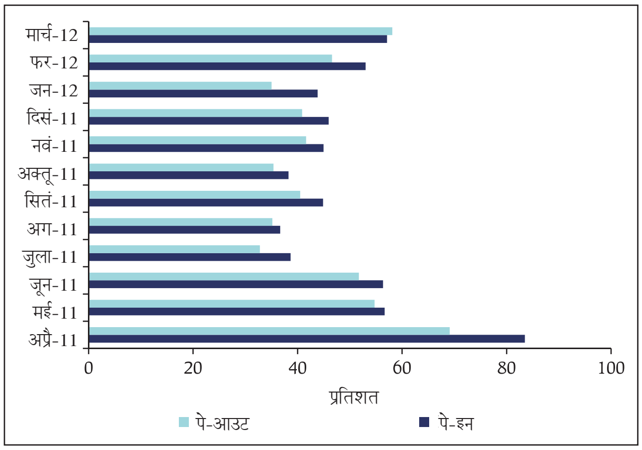

स्रोत: सीसीआईएल

चार्ट 4.10 : विनिर्दिष्ट निपटान बैंकों में सीसीआईएल का एक्सपोजर

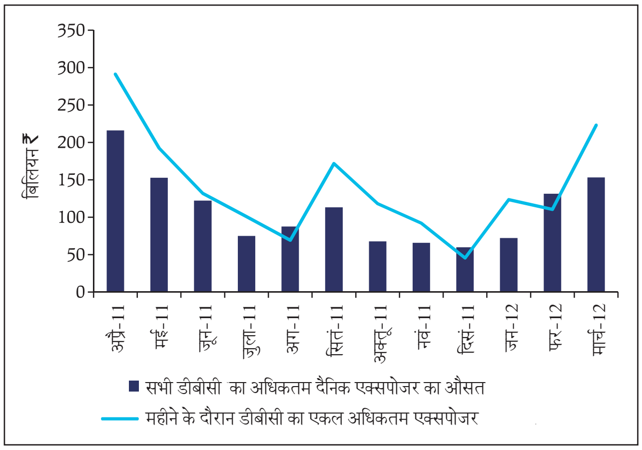

स्रोत: सीसीआईएल

[8] सेंट्रल बैंक ओवरसाईट ऑफ पेमेंट एंड सेट्लमेंट सिस्टम्स, बीआईएस, मई 2005

[9] डेरिवेटिव ट्रेडिंग और उनके विरूद्ध बकाया रहे लेनदेन को वित्त देने वाली प्रतिभूतियों (यथा, सीबीएलओ, रेपो) के कारण सीसीपी से/को होने वाले जोखिमों को वर्तमान में काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए शून्य जोखिम माना गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी को/से उनके काउंटरपार्टियों से/को होने वाला जोखिम दैनिक आधार पर पूरी तरह संपार्श्विकृत(कोलैटराइज्ड) है, जिससे सीसीपी के/से ऋण जोखिम की संभावना से सुरक्षा मिलती है। तथापि, सीसीआईएल के पास बैंकों द्वारा रखे गए जमा(डिपॉजिट)/कोलैटरल में भी 20 प्रतिशत जोखिम-भार होता है। (http://rbi.org.in/scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=5001)।

के लिए समुचित पूँजीकरण संबंधी मुद्दे पर बासेल कमिटी भी काम कर रही है। वर्तमान में बासेल II के अंतर्गत सीसीपी से होने वाला जोखिम शून्य है।

4.28 उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि डीसीबी, बदले में, एसोशिएट सदस्यों और साथ ही इक्विटी मार्केट प्लेयरों को इंट्राडे नकदी उपलब्ध कराते हैं। यदि इनसे जुड़े जोखिमों को सावधानीपूर्वक संभाला नहीं जाता है तो वे सीसीपी को होने वाले जोखिमों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। बासेल III नकदी जोखिम फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने से इन जोखिमों में कमी आ सकती है, क्योंकि इसमें अंतरादिवसीय नकदी का प्रभावी प्रबंधन निहित है।

ओटीसी डेरिवेटिव बाजार

ओटीसी डेरिवेटिव बाजार संबंधी सुधारों को लागू करने में विलंब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है

4.29 भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार द्वारा सामना किए जा रहे अनेक मुद्दों और चुनौतियों, यथा; संकुचित भागीदारी अवसंरचना, बृहत्तर मानकीकरण की आवश्यकता, केंद्रीय समाशोधन की शुरूआत आदि को पिछले एफएसआरों में उजागर किया गया था। ये मुद्दे तो प्रासंगिक बने हुए ही हैं, ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए अंतरराष्ट्रीय सुधार एजेंडा द्वारा भी चुनौतियाँ दी जा रही हैं; *यथा, ''वर्ष 2012 के अंत तक सभी मानकीकृत ओटीसी डेरिवेटिव करारों की एक्सचेजों पर या जहाँ उचित हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों पर ट्रेडिंग की जाए और सेंट्रल काउंटरपार्टियों के माध्यम से समाशोधित की जाए।''* एफएसबी ने पाया है कि नियम बनाने और जी20 के क्षेत्राधिकारों में सुधार प्रक्रिया को लागू करने- दोनों में ही विलंब हो रहा है। तथापि कुछ डेरिवेटिव उत्पादों के कतिपय अपवाद, यथा फॉरेन एक्सचेंज फॉरवाड्र्स विचाराधीन हैं।

4.30 भारत के मामले में, ओटीसी डेरिवेटिवों का बाजार नपे-तुले ढंग से और अधिकांश मामलों में, एक आनुषंगिक विनियामक फ्रेमवर्क के साथ विकसित हुआ है। घरेलू मुद्रा वाले फॉरेन एक्सचेंज फॉरवार्ड कान्ट्रैक्टों के लिए देश में सीसीपी सुविधाएँ पहले से ही हैं। अन्य उत्पादों के लिए भी ऐसी ही सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन क्रेडिट डिफॉल्ट्स स्वैप बाजार जैसे बाजार अब भी शैशव अवस्था में हैं और मौजूदा परिमाण केंद्रीकृत निपटान की मांग नहीं करते। जैसा कि पिछले एफएसआरों में चर्चा की गई थी, ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए मौजूदा रिपोर्टिंग सुविधाएँ विदेशी मुद्रा, ब्याज-दर, सरकारी प्रतिभूति, कॉर्पोरेट बांड और मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट को शामिल करती हैं और वे सशक्त हो रही हैं। आगे भारतीय बाजारों के लिए ओटीसी उत्पादों का मानकीकरण, ऐसे उत्पादों की बड़ी संख्या के लिए केंद्रीकृत समाशोधन सुविधाओं की शुरूआत तथा ट्रेड रिपॉजिटरी में सभी ओटीसी ट्रेडों की रिपोर्टिंग मुख्य प्राथमिकताएँ होंगी।

भारत में ब्याज-दर स्वैप (आईआरएस) बाजार के परिमाण केंद्रीकृत निपटान की मांग कर सकते हैं...

4.31 कुछ डेरिवेटिव बाजारों में कम परिमाण ऐसे उत्पादों के लिए सुनिश्चित समाशोधन की शुरूआत करना चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालिया रिपोर्ट[10], जो एक उत्पाद की "केंद्रीय समाशोधन पात्रता" की परिभाषा गढ़ने का प्रयास करती है, में यह पाया गया है कि किसी उत्पाद को समाशोधित करने में केंद्रीय काउंटरपार्टी के निर्णय में नकदी एक प्रमुख घटक है और केंद्रीय समाशोधन के प्रणालीगत जोखिम कम करने के लाभ तभी हासिल किए जा सकते हैं, जब करारों (कॉन्ट्रैक्ट्स) में पात्रता के मानदंड पूरे होंगे।

4.32 भारतीय संदर्भ में, 1999 में शुरू किया गया आईआरएस एक मात्र ओटीसी डेरिवेटिव उत्पाद है, जिसमें बाजार के परिमाण बहुत हद तक बढ़े हैं। यह वृद्धि खासकर *ओवरनाईट मनी मार्केट इंडेक्स* पर आधारित *ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप* के मामले में देखी गई है (चार्ट 4.11)। तथापि भागीदारी अवसंरचना अब भी संकुचित है, जहाँ विदेशी बैंकों का आईआरएस बाजार में दबदबा है[11]।

चार्ट 4.11 : माह के अंत में बकाया आनुमानिक आईआरएस मात्रा[12]

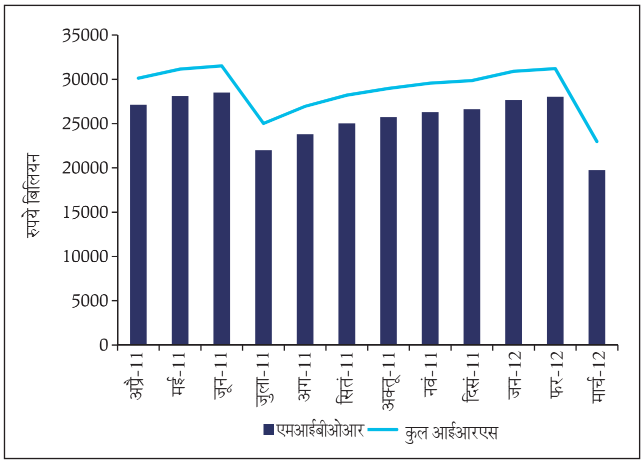

स्रोत: सीसीआईएल

[10] **थॉट्स ऑन डिटरमाईनिंग सेंट्रल क्लियरिंग इलिजीबिलिटी ऑफ ओटीसी डेरिवेटिवज़,** बैंक ऑफ इंग्लैंड, फाइनैन्सियल स्टैबिलिटी पेपर नं. 14, चेसिडानियस एंड एने वेदरलिट, मार्च 2012

[11] फाइनैन्सियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट (दिसंबर 2010, पैरा 3.84) में भारत में ओटीसी डेरिवेटिव द्वारा होने वाले संकेंद्रण जोखिमों का विश्लेषण शामिल है।(http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=23666)

[12] मार्च 2012 में परिमाण में देखी गई अचानक गिरावट बहुत हद तक हाल में सीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए ट्रेड कंप्रेशन के परिणामस्वरूप आनुमानिक स्थितियों में गिरावट के कारण है, जैसा कि पिछले एफएसआरों में चर्चा की गई है।

...लेकिन सीसीपी द्वारा मजबूत जोखिम प्रबंधन और भारी मार्जिन-संबंधी अपेक्षाओं की आवश्यकता होगी

4.33 आईआरएस ट्रेड का केंद्रीय समाशोधन होने से काउंटरपार्टी जोखिमों के प्रबंधन का दायित्व सीसीपी पर चला जाएगा। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि सीसीपी के पास प्रर्याप्त वित्तीय संसाधन हों और यह प्रभावी ढंग से जोखिम प्रबंधन करे। सीसीपी इसके साथ-साथ मार्जिन और अन्य जोखिम प्रबंधन अपेक्षाओं को भी स्वरूप दे, जो अंतर्निहित लिखतों की जटिलता के कारक हैं और पर्याप्त नकदी संसाधन बनाए रखे ताकि संभावित दबावों के परिदृश्यों के एक बड़े दायरे में निपटान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, डेरिवेटिव लेनदेन के केंद्रीय समाशोधन में भाग लेने वाले भागीदारों को लगने वाली कुल लागत का भी आकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अस्थिर/परिवर्तनशील (वोलाटाइल) समय के दौरान कुछ बैंकों की मार्जिन-संबंधी अपेक्षाएँ बहुत ऊँची हो सकती हैं। चूँकि सभी स्थितियों के पार्श्वीकृत होने की आवश्यकता पड़ेगी, आईआरएस लेनदेनों को एक सीसीपी पर ले जाने में बड़ी कोलैटेरल-संबंधी अपेक्षाएँ बनी रहेंगी।

4.34 सीसीआईएल द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के समुच्चय के कारण उत्पन्न होने वाले संकेंद्रण-जोखिमों(कंसनट्रेशन रिस्क्स) को पिछले एफएसआरों में चिह्नित किया जा चुका है। साथ ही, सीसीआईएल को आईआरएस ट्रेड या अन्य ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेड के केंद्रीकृत समाशोधन का दायित्व सौंपना इन जोखिमों को बढ़ाएगा और इसकी क्षमता और नकदी संसाधन समेत वित्तीय संसाधनों का व्यापक आकलन प्रासंगिक और आवश्यक होगा ताकि बाजार की कठिन और असाधारण परिस्थितियों को संभाला जा सके।

ओटीसी डेरिवेटिवों के द्विपक्षीय मार्जिन के सर्वांगी/ प्रणालीगत प्रभाव हो सकते हैं

4.35 सभी ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) का केंद्रीकृत समाशोधन में स्थानांतरण चुनौतीपूर्ण होगा और उतना वांछनीय भी नहीं होगा, क्योंकि ओटीसी उत्पाद, व्यक्तिगत बचाव (हेजिंग) अपेक्षाओं को पूरा करने वाली अनुरूपीकृत संविदाएँ (कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स) पेश करने का महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तथापि ये संविदाएँ प्रतिपक्षी (काउंटरपार्टी) और प्रणालीगत (सिस्टेमिक) जोखिमों को पैदा करती रहेंगी। इसलिए अकेंद्रीकृत रूप से समाशोधित उत्पादों पर द्विपक्षीय मार्जिन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जा रहा है, ताकि ऐसे उत्पादों से होने वाले प्रणालीगत जोखिमों को कम किया जा सके और केंद्रीकृत समाशोधन के लिए प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) सृजित किया जा सके। बढ़ी हुई कोलैटरल-अपेक्षाओं के प्रणालीगत प्रभावों की तुलना में इसके फायदों को आँकने के बाद, ऐसे मार्जिनों पर भारतीय संदर्भ में भी विचार करने की जरूरत है। उच्च गुणवत्ता वाले नकदी- कोलैटरल प्रदान करने की आवश्यकता से उत्पन्न प्रभाव से मार्जिन-अपेक्षाओं के होने वाले संभावित लाभों को अंशत: पूरा/प्रतिसंतुलित(ऑफसेट) किया जा सकता है। यह खासकर तब किया जा सकता है, जब बासेल III की नकदी-अपेक्षाओं से इसी प्रकार की प्रतिभूतियों की अतिरिक्त माँग सृजित होंगी। आईएमएफ के हालिया ग्लोबल फाइनैन्सियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट (अप्रैल, 2012) में भी यह बात उजागर की गई है कि *"विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एडवांस्ड इकॉनॉमिज) में बढ़ी हुई अनिश्चितता, विनियामक सुधार और केंद्रीय बैंकों द्वारा संकटोपरांत की गई असाधारण प्रतिक्रियाओं के कारण सुरक्षित आस्तियों की माँगें, वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभावों के साथ, बढ़ती जा रही हैं..."।*

एफएमआई के लिए नए और कठिन अंतरराष्ट्रीय मानक जारी किए गए...

4.36 भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति (सीपीएसएस) और सिक्युरिटिज कमीशन्स के अंतरराष्ट्रीय संगठन की तकनीकी समिति (आईओएससीओ)[13] द्वारा अप्रैल, 2012 में भुगतान, समाशोधन एवं निपटान प्रणालियों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय मानक जारी किए गए। नए मानक (जिन्हें सिद्धांत कहा गया) सभी प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों, सेंट्रल सिक्युरिटिज डिपॉजिटरीज, प्रतिभूति निपटान प्रणालियों, केंद्रीय प्रतिपक्षों(काउंटरपार्टीज) तथा ट्रेड डिपॉजिटरिज (सामूहिक रूप से "वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं" या "एफएमआई") पर लागू होंगे। 24 सिद्धांतों का एक समुच्चय यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों को समर्थित करने वाली आवश्यक अवसंरचना मजबूत है और वित्तीय झटकों (फाइनैन्सियल शॉक्स) को झेलने के लिए सही जगह पर टिकी हुई है। ये सिद्धांत एफएमआई के विधिक आधार और प्रशासनिक रूपरेखा (गवर्नेंस फ्रेमवर्क), इसकी ऋण, नकदी एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा, निपटान प्रणालियों, चूक (डिफॉल्ट) प्रबंधन, पहुँच-मानदंड (एक्सेस क्रायटेरिया) और एफएमआई की प्रभाविकता और पारदर्शिता से से जुड़े मुद्दों को अपने में समेटे हुए हैं।

...घरेलू एफएमआई द्वारा इन सिद्धांतों के अनुपालन के आकलन की आवश्यकता होगी

4.37 मौजूदा मानकों की तुलना में, नए सिद्धांत एफएमआई के वित्तीय संसाधन तथा जोखिम-प्रबंधन प्रक्रियाओं, चूक प्रबंधन (डिफॉल्ट हैंडलिंग) और कारोबार की कमी एवं परिचालनगत जोखिम जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्यादा सख्त अपेक्षाएँ रखते हैं। भारतीय संदर्भ में, पिछले औपचारिक आकलनों में यह पाया गया कि देश के एफएमआई उस समय प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों, यथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों हेतु मूल

[13] प्रिंसिपल्स ऑर फाइनैन्सियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अप्रैल 2012(http://ww.bis.org/publ/cpss101.htm)

सिद्धांतों, प्रतिभूति निपटान प्रणालियों हेतु सिफारिशों और केंद्रीय प्रतिपक्षों (सेंट्रल काउंटरपार्टिज) हेतु जोखिम-प्रबंधन सिद्धांतों का व्यापकत: अनुपालन कर रहे थे। आगे, घरेलू एफएमआई नए सिद्धांतों का किस हद तक अनुपालन करते हैं, इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।

एफएमआई डिफॉल्ट पर व्यवस्थित कार्रवाई हेतु कानूनी संशोधनों की आवश्यकता है

4.38 एफएमआई की कार्य-पद्धति (फंक्शनिंग) की महत्ता को देखते हुए, डिफॉल्ट की स्थिति में एफएमआई द्वारा वित्तीय स्थिरता को होने वाले संभावित जोखिम इस बात की माँग करते हैं कि ऐसी इकाईयों का व्यवस्थित समापन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी समाधान प्रणाली बने। एफएसबी की वित्तीय संस्थाओं हेतु प्रभावी समाधान व्यवस्था के मुख्य नियम[14] भी एफएमआई पर लागू होते हैं।

4.39 भारतीय संदर्भ में, वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी एफएमआई का पुनर्पूंजीकरण, व्यवस्थित समापन अथवा पुनर्गठन किया जा सके। किसी विशिष्ट कानूनी अधिदेश के अभाव में, दिवालियापन संबंधी प्रक्रियाएँ सामान्य कानून के अनुसार ही लागू होंगी। इन मुख्य नियमों (की-एट्रीब्युट्स) के अनुपालन के लिए यह आवश्यक होगा कि पीएसएस एक्ट में समुचित संशोधन करके भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्याप्त शक्तियाँ दी जाए, ताकि इसके द्वारा विनियमित एफएमआई, यथा, सीसीपी तथा भुगतान प्रणालियों का प्रभावशाली ढंग से समाधान किया जा सके।

सुरक्षा कवच व्यवस्थाएँ (सेफ्टी नेट अरेंजमेंट्स)

निक्षेप बीमा निधि का व्याप्ति (कवरेज) एवं आरक्षित निधि (रिज़र्व) अनुपात कम है...

4.40 भारत में, सभी बैंकों के लिए निक्षेप बीमा अनिवार्य है। निक्षेप बीमा, भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी संस्था निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदान की जाती है (चार्ट 4.12)।[15] अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में, भारत में निक्षेप बीमा की व्याप्ति (कवरेज) का स्तर, समग्र राशि (एबसोल्यूट अमाउंट) तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के प्रतिशत- दोनों दृष्टिकोणों से बहुत कम (चार्ट 4.13) है। हालाँकि भारत में रिज़र्व अनुपात का लक्ष्य निर्दिष्ट

चार्ट 4.12 :विभिन्न श्रेणियों के बैंकों के निक्षेप बीमा का हिस्सा

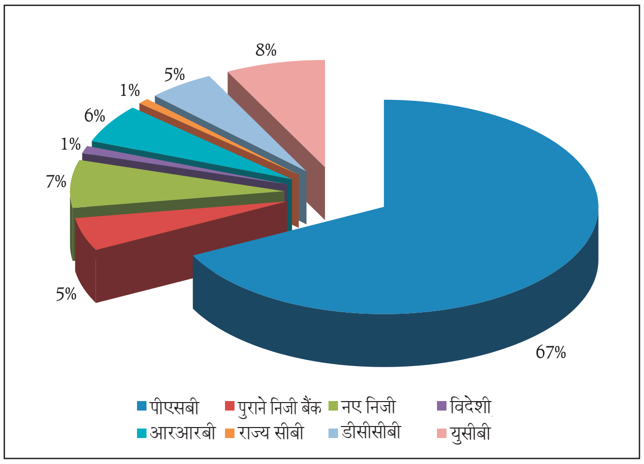

स्रोत: डीआईसीजीसी

चार्ट 4.13 : 2010 के अंत में व्याप्ति स्तर की देश-वार तुलना (समग्र स्तर एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

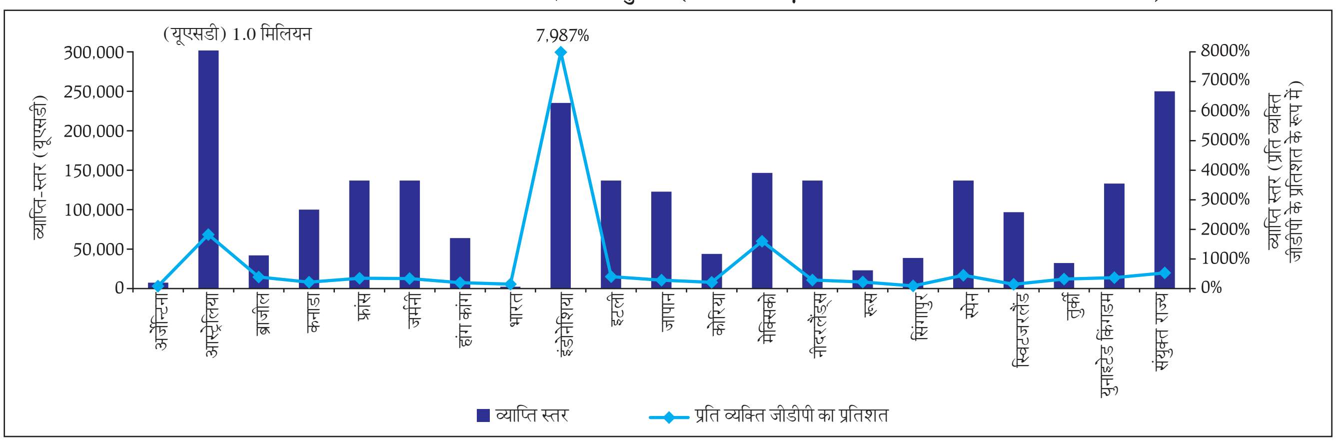

स्रोत: निक्षेप बीमा प्रणाली की एफएसबी विषयक समीक्षा : पीर रिव्यू रिपोर्ट

[14] http://www.financialstabilityboard.org/publications/ r_111104cc.pdf

[15] भारत में निक्षेप बीमा की व्याप्ति (कवरेज) के संपूर्ण विवरण के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अंक सं.1, मार्च 2010 देखें (http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=22230)

नहीं किया गया है, लेकिन उभर रही समान बाजार-अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में रिज़र्व अनुपात (निधि शेष और बीमित निक्षेपों का अनुपात) भी कम है, जो मार्च के अंत में 1.4 प्रतिशत था (चार्ट 4.14)।

...डीआईसीजीसी के निधि-आधार (फंड-बेस) को सुदृढ़ करने के लिए विकल्प ढूँढ़ने की आवश्यकता है

4.41 सहकारिता क्षेत्र के बैंकों के मामलों में, भारतीय संदर्भ में बैंक विचित्र ढंग से विफल हुए हैं। किसी बड़े बैंक के विफल होने की स्थिति में, मौजूदा व्याप्ति (कवरेज) स्तर के अनुसार, डीआईसीजीसी की निधि पर्याप्त नहीं होगी। निधि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, निगम को आयकर और सेवाकर में छूट देना, ली जाने वाली प्रीमियम राशि बढ़ाना, आपातकालीन नकदी सहायता का प्रावधान करना आदि जैसे कई उपायों की संभावनाएँ तलाशने की आवश्यकता है।

एफएसबी द्वारा की गई निक्षेप बीमा प्रणालियों की तुलनात्मक समीक्षा से डीआईसीजीसी को कई सबक मिले हैं

4.42 एफएसबी ने हाल में सदस्य संस्थाओं की निक्षेप बीमा प्रणालियों[16] की समीक्षा की, जो बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति- इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (बीसीबीएस-आईएडीआई)- कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम्स पर आधारित थी। इस तुलनात्मक समीक्षा रिपोर्ट की कई सिफारिशें भारतीय संदर्भ में खास तौर पर प्रासंगिक हैं और उन्हें सावधानीपूर्वक जाँचने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:

i. व्याप्ति-स्तरों (कवरेज लेवल्स) की समीक्षा करना, ताकि जमाकर्ताओं के बचाव और बाजार-अनुशासन के बीच एक समुचित संतुलन बनाना सुनिश्चित किया जा सके;

चार्ट 4.14 : 2010 के अंत में देश-वार रिज़र्व अनुपात की तुलना

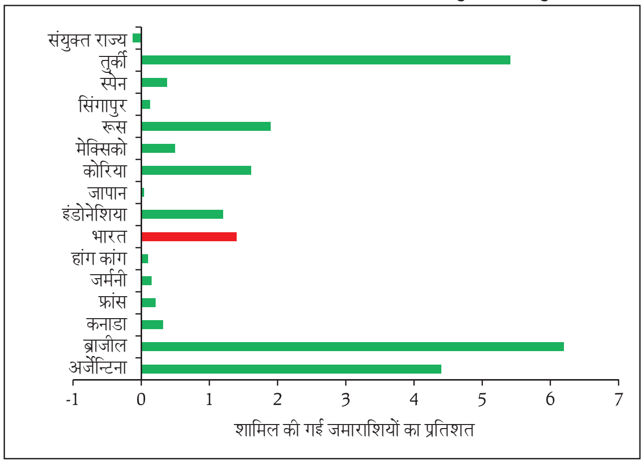

स्रोत: निक्षेप बीमा प्रणाली की एफएसबी विषयक समीक्षा : पीर रिव्यू रिपोर्ट

ii. उन परिस्थितयों में जमाकर्ता को तत्परता से प्रतिपूर्ति करना, जिनमें बैंक के विफल होने पर भुगतान (पे-आउट) एकमात्र विकल्प बचा हो: इसके लिए बैंक के आँकड़ों तक व्यापक और तत्पर पहुँच, एकल ग्राहक दृष्टिकोण (सिंगल कस्टमर व्यू) के जरिए सूचना तक शीघ्रतर पहुँच और मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की मदद की जरूरत होगी;

iii. निक्षेप बीमा एजेंसी और अन्य सुरक्षा कवच प्रदाताओं (सेफ्टी नेट प्लेयर्स) के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाना, ताकि प्रभावी समाधान आयोजना और जमाकर्ताओं को तत्पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके; और

iv. वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, बैक-अप फंडिंग के विकल्पों समेत विश्वसनीय निधि-स्रोतों (फंडिंग सोर्सेज) तक अबाध्य और तत्काल पहुँच।

[16] http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_120208.pdf

अध्याय - V
प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणालीगत जोखिम के संबंध में किए जाने वाले सर्वेक्षणों की श्रृंखला के द्वितीय सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि वित्तीय क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों का घरेलू वित्तीय प्रणाली में विश्वास बना हुआ है। किंतु, पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इस बार विश्वास का स्तर थोड़ा कम हुआ है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया का मुख्य कारण बाजार की अस्थिरता रही है और जिसके साथ-साथ राजकोषीय एवं चालू खाते में उच्च स्तर का घाटा भी जुड़ा रहा है। वर्तमान सर्वेक्षण में नीतिगत जोखिम (नीति बनाने में अनुभव किए गए धीमेपन सहित) भी काफी उभरकर सामने आया है। प्रणाली में चलनिधि की स्थिति बताने वाले संकेतक ने यह संकेत किया था कि मार्च और अप्रैल के दौरान चलनिधि पर कुछ दबाव बना रहेगा क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए चलनिधि के संतुष्टि-स्तर की तुलना में लगातार कम रही है। बैंकों में अल्पकालिक उधार लेने की बढ़ती प्रवृत्ति ने कुछ चिंता पैदा कर दी है क्योंकि पिछले एक वर्ष में कुछ बैंकों का प्रणालीगत महत्त्व बढ़ गया है। बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंड को बैंकिंग प्रणाली के जोखिमों से खतरा बना हुआ है जबकि बैंकों की निधि संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाज़ार के इन खंडों पर निर्भरता बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल मैक्रो-वित्तीय आघातों का बैंकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए की गई दबाव-जांच की श्रृंखला के परिणाम यह बताते हैं कि यहां तक कि अत्यधिक दबाव की हालत में भी बैंकिंग प्रणाली उन दबावों को दृढ़ता से झेल सकती है। बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के बारे में बैंकिंग स्थिरता के अनेक उपायों के माध्यम से किए गए मूल्यांकन यह दर्शाते हैं कि बैंकों में परस्पर निर्भरता संबंधी तनाव हाल के दिनों में बढ़ गया है किंतु तनाव का यह स्तर 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय देखे गए तनाव के स्तर से काफी कम रहा है।

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

5.1 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रथम प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण अक्तूबर 2011 में यह ज्ञात करने के लिए किया गया था कि वित्तीय प्रणाली द्वारा कुल मिलाकर जिन जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में बाज़ार सहभागियों और अन्य स्टेकहोल्डरों की क्या राय है, द्वितीय सर्वेक्षण अप्रैल 2012 में किया गया।

सबसे पहली चिंता के संबंध में मत था वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता

5.2 द्वितीय सर्वेक्षण दर्शाता है कि स्टेकहोल्डर यह अनुभव कर रहे हैं कि वैश्विक एवं राजकोषीय जोखिमों के साथ-साथ बाज़ार में अस्थिरता ही एकमात्र सबसे महत्त्वपूर्ण जोखिम है जिसका सामना वित्तीय प्रणाली कर रही है। पिछले सर्वेक्षण में आस्ति-गुणवत्ता को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जोखिम माना गया था जबकि इस सर्वेक्षण में इसे दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण जोखिम माना गया है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों का यह मानना है कि पिछले सर्वेक्षण से अब तक दोहरे घाटे से तथा नीति-निर्माण में धीमेपन से जोखिम काफी तेजी से बढ़ा है (चार्ट 5.1 और चार्ट 5.2)[1]।

मुद्रा-स्फीति से पैदा होने वाले जोखिम का नियंत्रण देश के लिए सबसे मुश्किल काम

5.3 सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों का मानना है कि मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी

चार्ट 5.1 : अक्तूबर 2011 के जोखिम सर्वेक्षण में पता लगाए गए विशिष्ट जोखिम

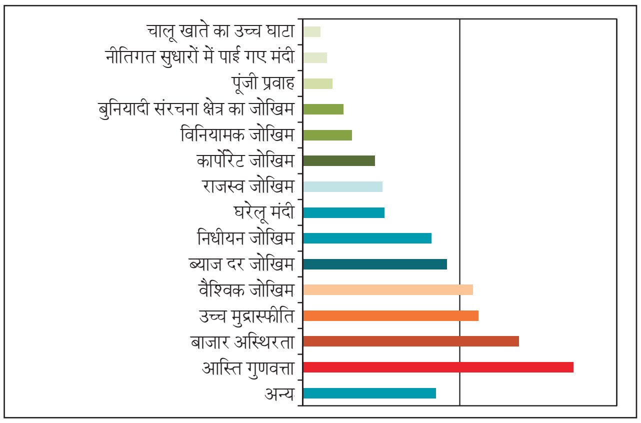

चार्ट 5.2 : अप्रैल 2012 के जोखिम सर्वेक्षण में पता लगाए गए विशिष्ट जोखिम

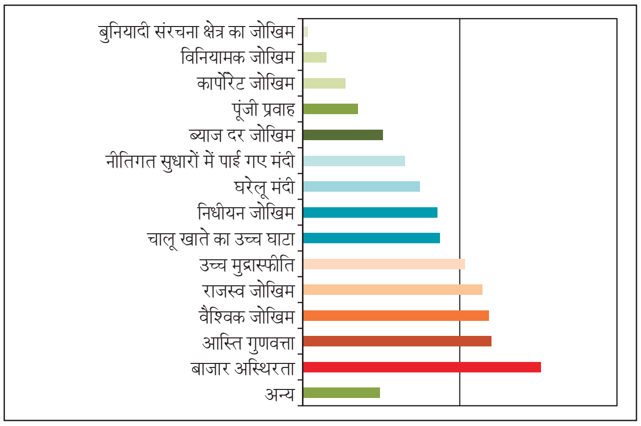

[1] चार्ट 5.1 और 5.2 में दिए गए बार, प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों की भारित सकल संख्या दर्शाते हैं, जिन्होंने तदनुरूपी जोखिम की पहचान की है । भार यह दर्शाते हैं कि प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों द्वारा दिखाया गया है कि जोखिम घटित होने की संभावना कितनी होगी।

चार्ट 5.3 :ऐसे जोखिम जिन्हें देश के द्वारा नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है

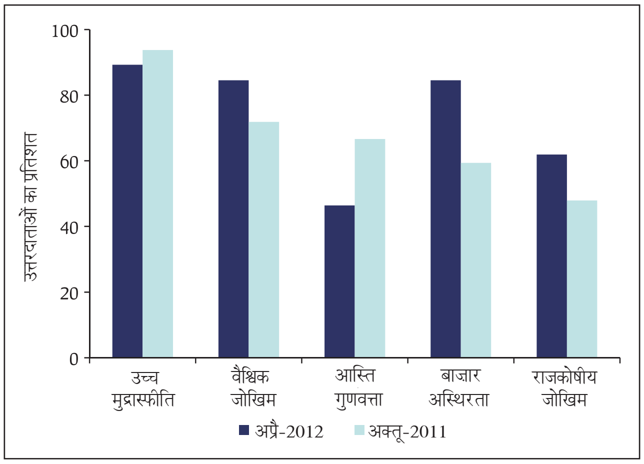

चार्ट 5.4 : ऐसे जोखिम जिन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है

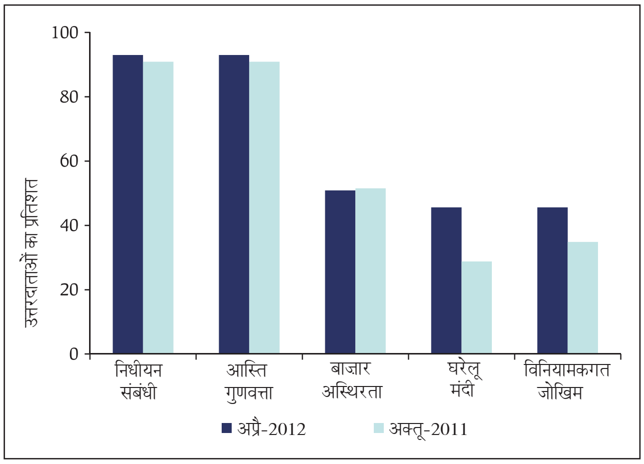

रहेगी (चार्ट 5.3)। सर्वेक्षण में वित्तीय संस्थाओं से प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों का मानना है कि आस्ति की गुणवत्ता और निधीयन संबंधी जोखिम को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल काम रहेगा (चार्ट 5.4)।

अनुभव किया गया है कि घरेलू वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम बढ़े हैं

5.4 प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में लगभग 43 प्रतिशत का यह मानना है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत घटनाओं की अल्पकाल में संभाव्यता अधिक है जबकि 46 प्रतिशत का मानना है कि यह संभाव्यता मध्यावधि में अधिक है। इससे पता चलता है कि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इस बार स्थिति बदल गई है क्योंकि पिछले सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत सहभागियों का मानना था कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत घटनाओं की अल्पकाल में संभाव्यता अधिक थी । प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों का मानना है कि मध्य अवधि में घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का जोखिम बढ़ गया है (चार्ट 5.5 से चार्ट 5.8)।

5.5 सर्वेक्षण के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों की बड़ी संख्या यह महसूस करती है कि वैश्विक

वैश्विक वित्तीय प्रणाली की 'अधिक' प्रभाव वाली घटनाओं की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया (प्रतिशत)

चार्ट 5.5 अल्प अवधि में

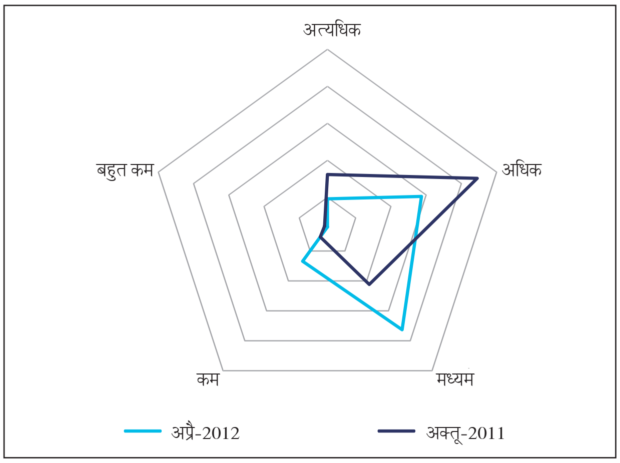

चार्ट 5.6 मध्य अवधि में

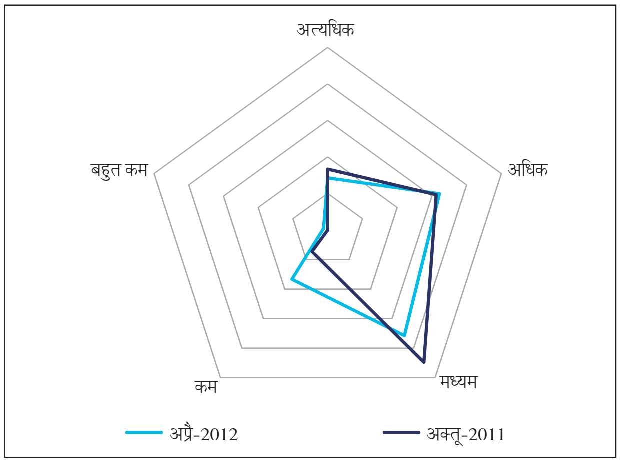

देशी वित्तीय प्रणाली की 'अधिक' प्रभाव वाली घटनाओं की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया (प्रतिशत)

चार्ट 5.7 : अल्प अवधि में

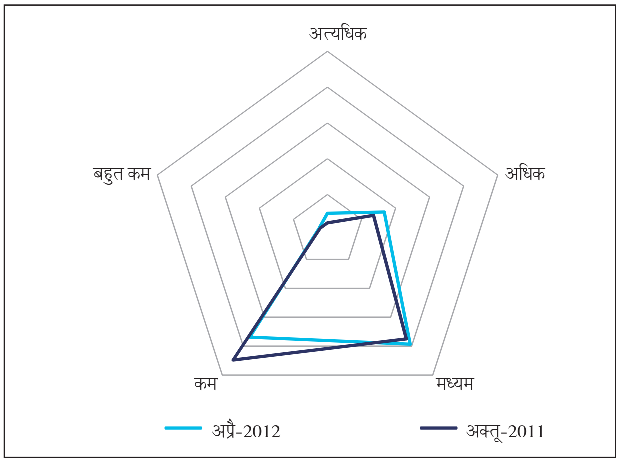

चार्ट 5.8 : मध्य अवधि में

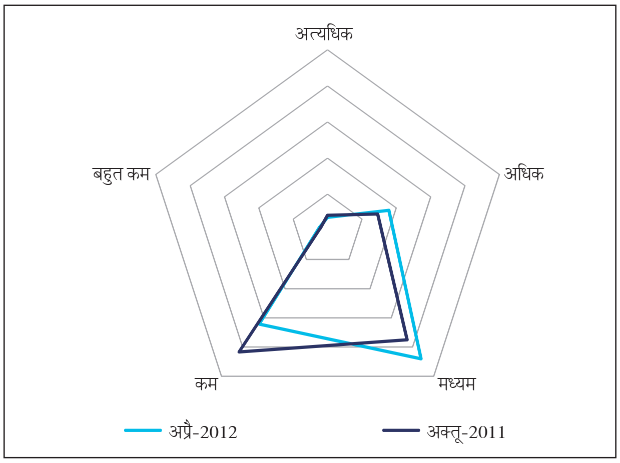

प्रणालीगत घटनाओं का प्रभाव घरेलू वित्तीय प्रणाली पर 'अधिक' रहेगा (सारणी 5.1)।

5.6 सर्वेक्षण में जवाब देने वालों ने घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के संबंध में भरोसा दिखलाया है जिसमें से 25 प्रतिशत घरेलू वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के प्रति 'अत्यधिक आश्वस्त' हैं, जबकि प्रक्रिया देने वालों में से 67 प्रतिशत ने इसके लिए 'काफी हद तक' भरोसा प्रकट किया। किंतु, अक्तूबर 2011 में किए गए प्रथम सर्वेक्षण की तुलना में विश्वसनीयता का स्तर कम हुआ है । प्रतिक्रिया देने वालों में से आधे से अधिक लोग वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के प्रति 'बहुत आश्वस्त नहीं हैं' (सारणी 5.2)।

प्रणालीगत चलनिधि संकेतक

चलनिधि में कमी का स्तर रिज़र्व बैंक के संतुष्टि-स्तर से बाहर रहा है

5.7 समीक्षा अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के संतुष्टि-स्तर की तुलना में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की कमी लगातार बनी रही। इसका मुख्य कारण था सरकारी नकदी जमाराशि का बढ़ जाना, संचलन में मुद्रा का बढ़ जाना, अग्रिम कर का आउटफ्लो तथा अन्य कारण जैसे रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी बाज़ार के परिचालन।

5.8 रिजर्व बैंक ने खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से 24 नवंबर, 2011 से प्रणाली में चलनिधि डालना शुरू कर दिया था और लगभग 1,247 बिलियन प्राथमिक चलनिधि डाल दी। 2011-12 की तीसरी तिमाही के दौरान चलनिधि समायोजन

सारणी 5.1 : वैश्विक प्रणालीगत घटनाओं का घरेलू वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव (प्रतिशत)

	अत्यधिक	अधिक	मध्यम	कम	कोई प्रभाव नहीं
अक्तूबर 2011	8	35	47	10	0
अप्रैल 2012	12	43	35	10	0

सारणी 5.2 : वैश्विक और घरेलू वित्तीय प्रणाली में विश्वसनीयता (प्रतिशत)

	वैश्विक वित्तीय प्रणाली		घरेलू वित्तीय प्रणाली	
	अक्तू -2012	अप्रै-2012	अक्तू-2011	अप्रै-2012
संपूर्ण विश्वास	0	0	0	1
अत्यधिक आश्वस्त	1	4	39	24
सामान्य रुप से आश्वस्त	45	40	58	67
बहुत आश्वस्त नहीं	52	54	3	8
विश्वास नही	2	2	0	0

सुविधा के माध्यम से प्रतिदिन औसतन ₹874 बिलियन की निवल चलनिधि प्रणाली में डाली गई।

5.9 2011-12 की चौथी तिमाही में चलनिधि की स्थिति और भी कठोर हो गई, इसका कारण था विदेशी मुद्रा परिचालन और भारी मात्रा में सरकारी नकदी राशि का जमा हो जाना (विशेषतया मार्च 2012 के मध्य में)। रिज़र्व बैंक ने आरक्षित नकदी जमा अनुपात को 28 जनवरी, 2012 से 50 आधार अंक कम कर दिया, 10 मार्च, 2012 से इसे 75 आधार अंक और भी कम कर दिया। इस प्रकार से लगभग 800 बिलियन ₹ की प्राथमिक चलनिधि डाल दी। बाज़ार सहभागियों को और अधिक सहजता प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने रिपोर्टिंग शुक्रवार 10 फरवरी, 2012 से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत (द्वितीय एलएएफ रेपो) अतिरिक्त रेपो उपाय को पुन: प्रारंभ कर दिया। चौथी तिमाही में चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 1424 बिलियन ₹ की निवल चलनिधि प्रवाहित की गई)।

अत्यधिक मात्रा में प्राथमिक चलनिधि प्रवाहित करना जरूरी था

5.10 चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से प्रवाहित चलनिधि की निवल राशि 30 मार्च, 2012 को समस्त समय में सबसे अधिक हो गई (2027.85 बिलियन ₹) क्योंकि बैंक अपने तुलनपत्र की टेकबंदी कर रहे थे और आरक्षित नकदी को अग्रभाग में रख रहे थे । मार्च 2012 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत नौ बार चलनिधि प्रवाहित की गई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च, 2012 को अतिरिक्त एलएएफ - रिपो तथा 31 मार्च, 2012 को एलएएफ एवं एमएसएफ का परिचालन किया । 30 मार्च, 2012 को चार-दिवसीय मांग-मुद्रा-दर, तीन वर्ष की सबसे ऊंची दर 15 प्रतिशत पर बंद हुई क्योंकि ऋण बाजार में निधि की कमी थी। चलनिधि में और अधिक गुंजाइश (कुशन) प्रदान करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार लेने की सीमा को उनके निवल मांग और मीयादी देयता के हिसाब से एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया । मई 2012 में चलनिधि में कमी की स्थिति बनी रही, इसका आंशिक कारण संचलन में मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना था।

5.11 दिसंबर 2011[2] की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में प्रारंभ किया गया प्रणालीगत चलनिधि संकेतक (एसएलआई), बहु-संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में समग्र निधीयन परिदृश्य को आंकना है जैसे- बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय एवं कार्पोरेट क्षेत्र में निधीयन स्थिति तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार में चलनिधि की स्थिति। जहां निधीयन की स्थिति मार्च 2012 में बेहतर हो गई वहीं वर्ष 2008 में लेहमैन-संकट के बाद के समय में निधीयन के स्तर पर जो दबाव पाया गया था वह इस दौरान काफी कम बना रहा। अप्रैल 2012 में यह संकेतक थोड़ा और बेहतर हुआ (चार्ट 5.9)।

चार्ट 5.9 : प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक

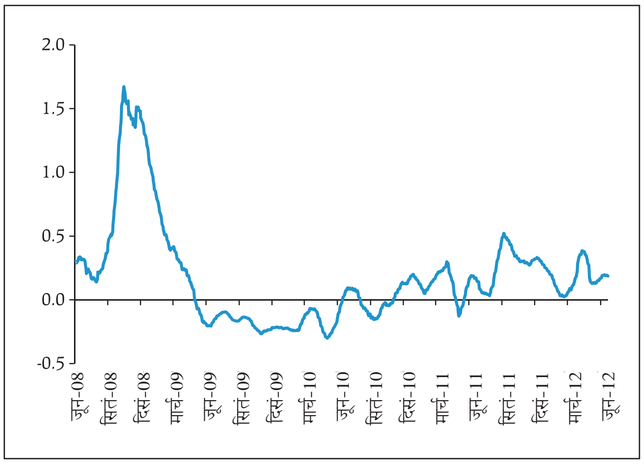

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क विश्लेषण[3]

5.12 वित्तीय यप्रणाली का नेटवर्क विश्लेषण, बैंकिंग/वित्तीय प्रणाली के परस्पर जुड़े रहने को आंकने, तथा संभावित प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के मूल्यांकन में मदद करता है। यह विश्लेषण मैक्रो स्तर पर विवेकपूर्ण निगरानी के महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

5.13 मार्च 2011 से मार्च 2012 के बीच अंतर-बैंक बाजार के आकार में मामूली सी कमी (2.8 प्रतिशत) हुई है। यह कमी पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में काफी अधिक दिखाई दी, जो समस्त बाज़ार का 3 प्रतिशत है (चार्ट 5.10 और चार्ट 5.11)।

[2] एसएलआई में दिए गए चार संकेतकों का प्रयोग किया जाता है जो बाज़ार के विभिन्न खंडों को दर्शाते हैं । भारित औसत मांग-दर-भा.रि.बैं.रिपो दर, और भारित औसत मांग दर - 3 माह ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (ओआइएस) दर। सूचकांक मानक सामान्य अथवा विविध समान भारित निधि पर आधारित है और शून्य से अधिक का मूल्य यह दर्शाएगा कि प्रणाली में चलनिधि सामान्य स्तर से अधिक है।

[3] नेटवर्क विश्लेषण, द्विपक्षीय निधि से संबंधित आंकड़ों के आधार पर, तथा बैंकों के बीच, आस्ति - प्रबंधन कंपनियों, बीमा कंपनियों एनबीएफसी, वित्तीय संस्थाओं और शहरी सहकारी बैंकों के बीच निधिजन्य एवं निधितर एक्स्पोजर के आधार पर किया गया है। ऐसे लेनदेन जिनमें निपटान केंद्रीय काउंटरपार्टी के माध्यम से संपन्न हुआ है, उन्हें गणना में नहीं लिया गया है। इस विश्लेषण में जिस नेटवर्क मॉडल का इस्तेमाल किया गया है उसे प्रोफेसर शेरी मार्कोस (एसेक्स विश्वविद्यालय) और डॉ. साइमन ग्लानसेंटे (बाथ विश्वविद्यालय) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई के संयोजन से किया गया है।

चार्ट 5.10 : अंतर बैंक बाजार की प्रवृत्तियां

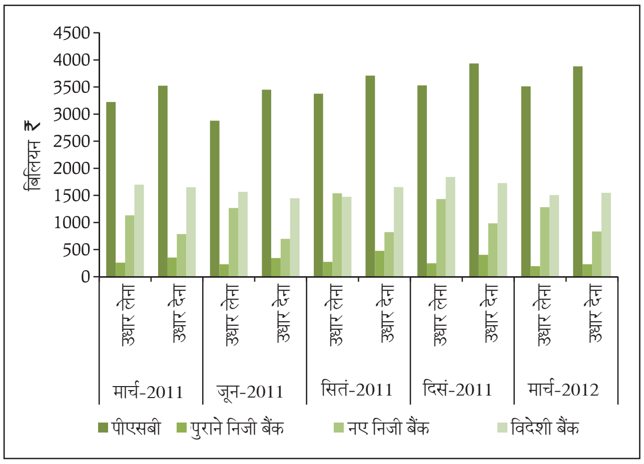

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.11 : अंतर बैंक बाजार में एक वर्ष के दौरान कार्यकलापों में हुए परिवर्तन का प्रतिशत

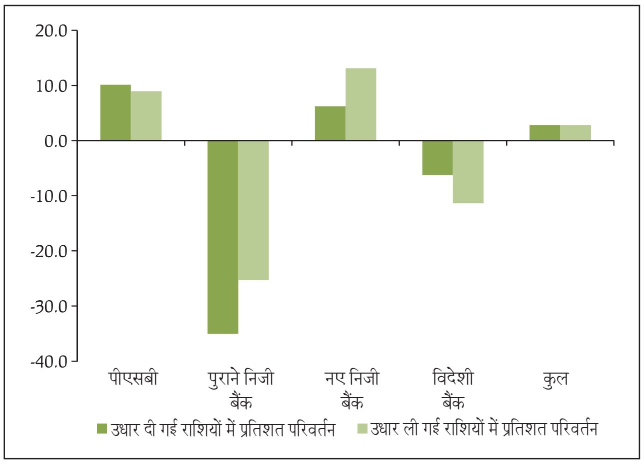

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

बैंकों की अल्पावधि उधार लेने की प्रवृत्ति चलनिधि जोखिम पैदा करती है ....

5.14 बैंकों की अल्पावधि अंतर बैंक उधार लेने की प्रवृत्ति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस उधार में अधिकांशत: जमा प्रमाणपत्र हैं और निधियों का एक बहुत बड़ा भाग अंतरबैंक बाजार के लिए जुटाया गया है। बैंकिंग के अल्पावधि उधार का अनुपात कुल उधार के 27 प्रतिशत के लगभग रहा। साथ ही, अल्पावधि उधार एक वर्ष में लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। हालांकि, अंतर बैंक उधार की समग्र मात्रा में गिरावट हुई है। अल्पावधि उधार से विशिष्ट अन्य जोखिम पैदा हो सकती है और इस संबंध में प्रवृत्तियों की बहुत ज्यादा निगरानी करने की आवश्यकता है (चार्ट 5.12)।

5.15 अल्पावधि अंतर बैंक उधार बैंक की कुल बाहरी देयताओं का एक भाग है (लगभग 3 प्रतिशत) जो ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं था, फिर भी कुछ बाहरी बैंक ऐसे उधार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और इस संबंध में प्रवृत्तियों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है (चार्ट 5.13)।

बैंकिंग प्रणाली एक-दूसरे से संबद्ध हैं

5.16 देश की बैंकिंग प्रणाली में परस्पर संबद्धता की महत्त्वपूर्ण डिग्री को दर्शाता है। इसके साथ-साथ संबद्धता की विशुद्ध टियर संरचना पाई गई, वहीं कुछ बैंक अन्यों की तुलना में कहीं और ज्यादा संबद्ध हैं। परस्पर संबद्धता के लिए उपयोग कर रहे नेटवर्क माडल के विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रणाली में संबद्धता का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा है (बॉक्स 5.1)।

चार्ट 5.12 :अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल उधार का अनुपात अल्पावधि निधि के रूप में (31 मार्च 2012)

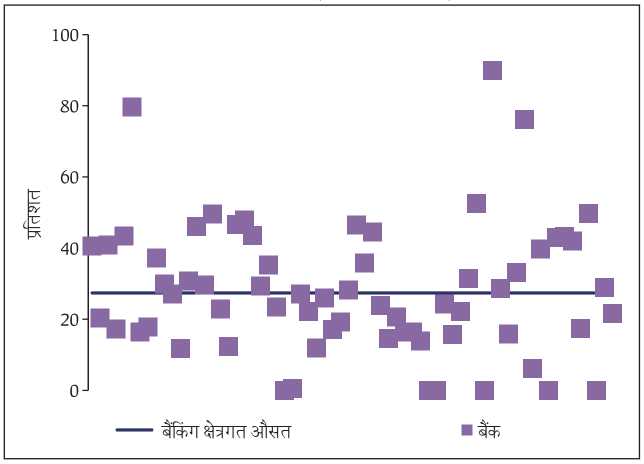

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.13 : कुल बाह्य देयताओं के रूप में अल्पावधि निधि (31 मार्च 2012)

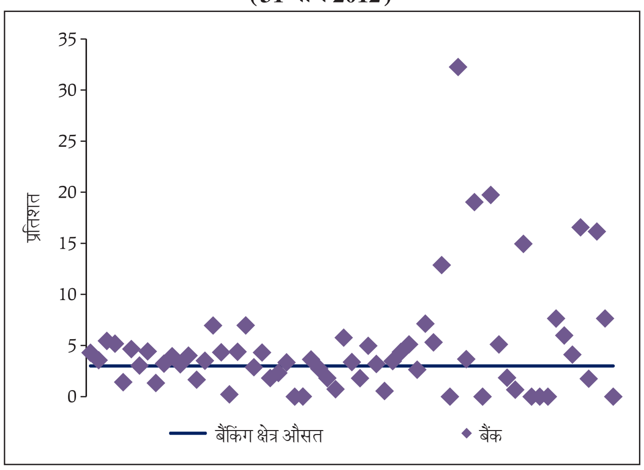

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

बॉक्स 5.1: बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क सांख्यिकी

प्रणाली में अंत:संबद्धता को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल विभिन्न सांख्यिकी उपायों का उपयोग करता है। उसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नानुसार हैं :

- **संबद्धत्ता:** यह वह सांख्यिकी जो किसी पूर्ण ग्राफ के सभी संभव लिंक से संबंधित नोडों के बीच के लिंक की सीमा को मापता है।
- **संघीय गुणांक (क्लस्टर कोऐफिशिएंट):** नेटवर्क में गुणांक यह मापने के लिए होता है कि प्रत्येक नोड की अंत: संबद्धता कितनी है। विशेष तौर पर बढ़ी हुई संभाव्यता यह है कि दो नजदीकी नोड (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक का प्रतिपक्ष) आपस में भी निकट हैं। नेटवर्क के लिए उच्च संघीय गुणांक प्रणाली में मौजूद उच्च अंत: संबद्धता के अनुरूप है।
- **सार्टेस्ट पथ लेंथ:** यह नेटवर्क में किसी नोड और अन्य नोडों के बीच सीधे लिंक की औसत संख्या प्रदान करना करता है। सार्टेस पथ के जरिए इन नोडों को प्रणाली में हब के रूप में जाना जा सकता है।
- **इन - बिटवीन्स सेंट्रालिटी** : यह सांख्यिकी रिपोर्ट यह बताता है कि सार्टेस पथ लेंथ कैसे किसी विशेष नोड के जरिए जाता है।
- **सेंट्रालिटि की आइजेनवेक्टर उपाय:** आइजेनवेक्टर सेंट्रालिटी किसी नेटवर्क में किसी नोड (बैंक) के महत्त्वपूर्ण होता है। यह बताता है कि कोई नोड किसी दूसरे से कैसे जुडा हुआ है और आउट डिग्री से थोड़ा से ज्यादा संख्या को अधिग्रहण करने का प्रयास करता है। यह नेटवर्क में सभी नोडों के लिए रिलेटिव स्कोर निर्धारित करता है जो आइजेन के रूप में होता है। सामान्यतौर पर किसी NxN मेट्रिक्स में एन (N) का भिन्न आइजेनवेल्यू होगा जिसके लिए आइजेनवेक्टर की वयवस्था मौजूद है। प्रत्येक बैंक का एक अनोखा आइजेनवेल्यू होता है जो प्रणाली में इसके महत्त्व को दर्शाता है। नेटवर्क विश्लेषण में इस उपाय का उपयोग किसी बैंक के सर्वांगी महत्त्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है और यहां तक कि यह अति महत्त्वपूर्ण संकेतक है।

भारतीय बैंकिंग सेक्टर में उपर्युक्त नेटवर्क सांख्यिकी की प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि पिछली पांच तिमाहियों में अंत:संबद्धता का स्तर बृहत रूप से स्थिर बना हुआ है हांलाकि कुछ सांख्यिकी यह बताती है कि संबद्धता में हलकी सी वृद्धि हुई है।

	मार्च 2011	जून 2011	सितं 2011	दिसं 2011	मार्च 2012
संबद्धता	28.1 %	27.8 %	28.7 %	26.4 %	29.1 %
क्लस्टर कोऐफिशिएंट	41.4 %	41.1 %	42.7 %	42.0 %	41.4 %
औसत :शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ	1.73 %	1.77 %	1.73 %	1.86 %	1.74 %
औसत इन बिटवीन सेंट्रालिटी	53.38 %	59.96 %	59.06 %	68.66 %	53.44 %
आइजेनवेल्यू	65 %	61 %	57 %	64 %	59 %
अति संबद्ध संस्था की आइजेनवेल्यू	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16

स्रोत: भारिबैं, स्टाफ परिकलन

कुछ बैंकों का प्रणालीगत महत्त्व बढ़ा ....

5.17 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क के अंत:भाग में बैंकों का एक बड़ा हिस्सा पिछले एक वर्ष से अभी भी वैसे ही हैं।[4] तथापि, अंत: भाग (inner core) में नेट उधारकर्ताओं की संख्या में इस अवधि में वृद्धि हुई है जो इन बैंकों के बढ़े हुए प्रणालीगत महत्त्व को बताता है (चार्ट 5.14 और चार्ट 5.15)।

चार्ट 5.14 : बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क - 31 मार्च 2011

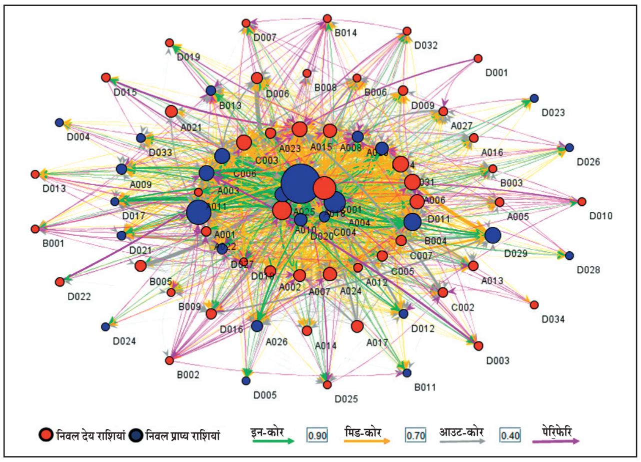

स्रोत: भारिबैं, स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.15: बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क - 31 मार्च 2012

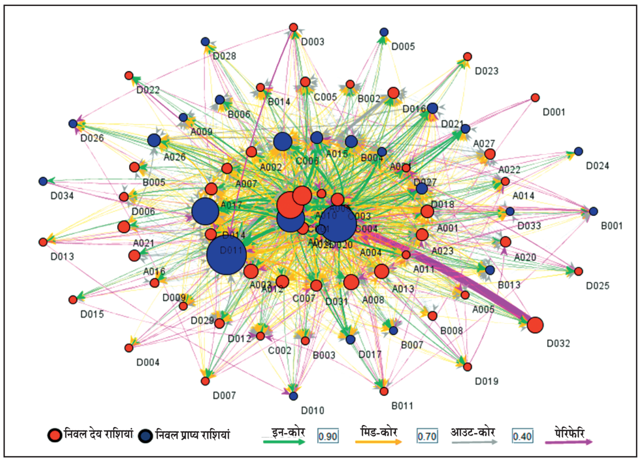

स्रोत: भारिबैं, स्टाफ परिकलन

[4] टियर संरचना वह है जहां विभिन्न संस्थानों की अन्य नेटवर्क के साथ संबद्धता की विभिन्न डिग्री या स्तर है। वर्तमान के विश्लेषण में अति संबद्धता बैंक (आइजेन वेक्टर सेंट्रालिटी के आधार पर) आंतरिक अति कोर में (नेटवर्क चित्र के केंद्र में है चार्ट 5.14 और 5.15) हैं। अतएव बैंकों को उनके संबंधित संबद्धता के स्तर पर मध्य कोर,बाह्य कोर और पेरीफेरी (चित्र में केंद्र के चारों ओर संकेंद्रित दायरे से संबंधित है) में रखा गया है। जो बैंकों उच्च 10 प्रतिशत श्रेणी में हैं वे आंतरिक कोर के अनुपात में आते हैं। इसे मध्य कोर बैंकों के बाद किया गया है जो 90 और 70 प्रतिशत के बीच की श्रेणी में हैं और 3 टियर बैंकों को 40 और 70 प्रतिशत के बीच की श्रेणी में है। जिन बैंकों का संबद्धत्ता अनुपात 40 से कम प्रतिशत है उन्हें पेरिफेरी की श्रेणी रखा गया है। टियर नेटवर्क चित्र में लिकों का कलर कोडिंग नेटवर्क में (उदाहरण के लिए हरा लिंक आंतरिक कोर बैंको से उधार को दर्शाता है) विभिन्न टियरों से उधार को दर्शाता है।

चार्ट 5.16 : उच्च नेट उधारकर्ता[5] की विफलता के कारण संक्रामकता

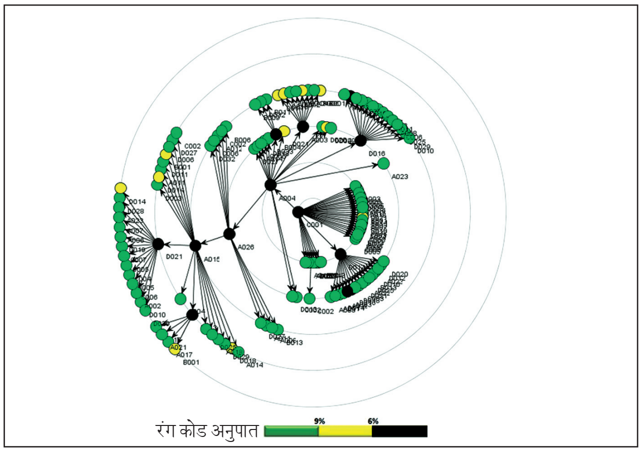

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.17 : बड़े बैंकों के विफल होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में संभावित घाटा

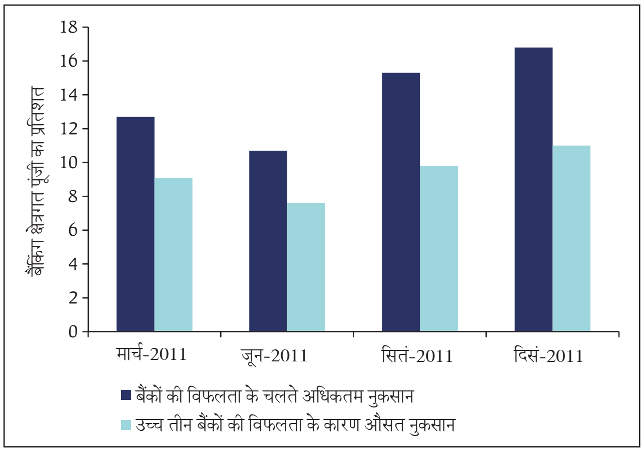

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

.......संक्रामकता विश्लेषण परिणाम द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि

5.18 नेटवर्क मॉडल में उपयोग किये जा रहे संक्रामकता विश्लेषण से यह पता चलता है कि 2011 की चार तिमाहियों में बैंक की अति संबद्धता की विफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली का अधिकांश घाटा हुआ है जो बैंकिंग प्रणाली के पूंजी के 12 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 5.16)। औसत घाटे में वृद्धि भी तीन अति संबद्ध बैंक की विफलता के कारण हुई (चार्ट 5.17)। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि संक्रामक जोखिम कुछ बैंकों तक ही था (चार्ट 5.18)। वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इनर कोर में कुछ बैंकों की बढ़ी हुई अंत:संबद्धता के कारण हुए जोखिम पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है, हालांकि इसके साथ-साथ इन संस्थाओं का कड़ा अतिसूक्ष्म विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।

वित्तीय प्रणाली में बड़े उधारदाता संक्रामक जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं

5.19 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में प्रस्तुत बृहत वित्तीय प्रणाली के विश्लेषण में वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग, बीमा, और म्युचुअल फंड के बीच अंतरसंबद्धत्ता को दिखाया गया था। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रणाली में सबसे बड़ी नेट उधारदाता बीमा कंपनियां और आस्ति प्रबंधन कंपनियां थीं, जबकि बैंक सबसे बड़े उधारकर्ता थे। इससे उधारदाता को बैंकिंग प्रणाली से संक्रामक जोखिम होने की संभावना रहती है। बैंक की बेतरतीब विफलता जिसमें वित्तीय प्रणाली के बीमा और म्युचुअल फंडों से बड़े पैमाने पर उधार लिया गया है, जिसका पूरी प्रणाली में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा (चार्ट 5.19 और 5.20)।

चार्ट 5.18 : बैंकों के विफल होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में संभावित घाटा वितरण

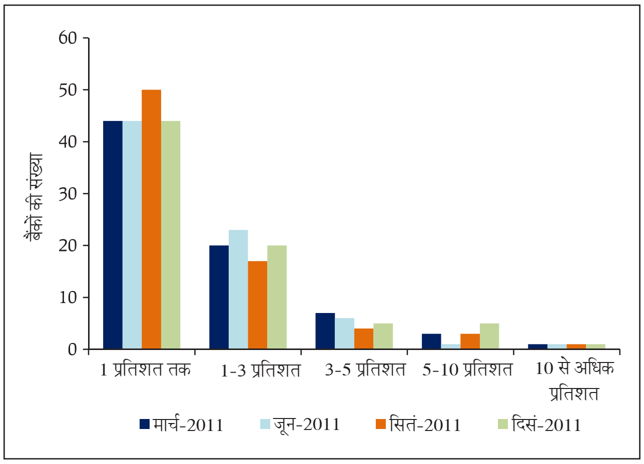

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.19: विभिन्न बैंक समूहों में बीमा कंपनियों का निवेश

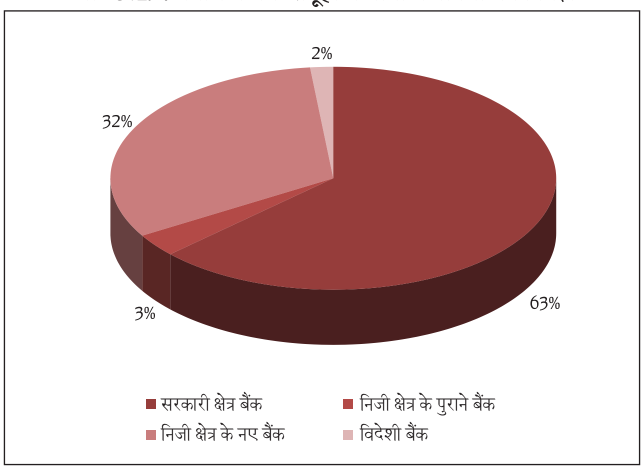

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

[5] संक्रामकता विश्लेषण संबंधी पद्धति का एक संपूर्ण विवरण हेतु कृपया दिसंबर 2011 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट देखें (rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/5SYRA221211.pdf)

बैंक विशेष तौर पर अल्पावधि निधि के लिए बीमा क्षेत्र और म्युचुअल फंडों पर निर्भर...

5.20 अनुसूचित वाणिज्य बैंक उधार के लिए बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंडों पर पूरी तरह से निर्भर थे। मार्च 2012 की समाप्ति पर बैंक द्वारा संपूर्ण अंत: वित्तीय प्रणाली की उधार का लगभग 27 प्रतिशत बीमा कंपनियों से था जबकि अन्य 37 प्रतिशत म्युचुअल फंड से था। निजी क्षेत्र के बैंकों की निर्भरता उच्च थी (सारणी 5.3)। म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों से ऐसा उधार बैंकिंग प्रणाली की बाह्य देयताओं की 6.8 प्रतिशत रहा।

5.21 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का म्युचुअल फंड से अल्पावधि उधार की तादाद (81 प्रतिशत) था जो अन्यों के लिए चलनिधि जोखिम पैदा करती है। इन उधारों में लगभग सभी जमा प्रमाणपत्र थे। उसकी तुलना में बीमा कंपनियों से उधार लंबी परिपक्वता अवधि की है और उधार 88 प्रतिशत से भी अधिक है और कम से कम एक वर्ष की शेष परिपक्वता अवधि है (सारणी 5.4)।

बैंकिंग स्थिरता उपाय और होनेवाली कमी का अनुमान

5.22 बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता का विभिन्न बैंकिंग स्थिरता उपायों के जरिए अध्ययन किया गया, जिससे बैंकों में से किसी एक बैंक की कठिनाई के प्रभाव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिंक के जरिए मापा जा सकता है। इन निर्भरता का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय प्रणाली ने बैंकों (सेगोवियानो और गुडहार्ट, 2009) के विशिष्ट समूह का संविभाग माडल बनाया है। यह माडल बैंकिंग प्रणाली के संविभाग मल्टीवेरियेट डेंसिटी (बीएमएमडी)[6] के द्वारा उपयोग किया जाता है जो बैंकों की संविभाग की व्यकिगत और संयुक्त आस्ति मूल्य की गतिविधि की विशेषता बताता है। बीएसएमडी को विश्लेषणाधीन बैंकों के संभाव्य कठिनाई से ठीक किया जा सकता है जिसे बैंकों के ईक्विटी मूल्यों संबंधी प्रतिदिन विवरणी के 99 प्रतिशत जोखिम मूल्यों[7] पर आधारित पर अनुभव से देखा गया है।

चार्ट 5.20 : विभिन्न बैंक समूहों में म्युचुअल निधियों का निवेश

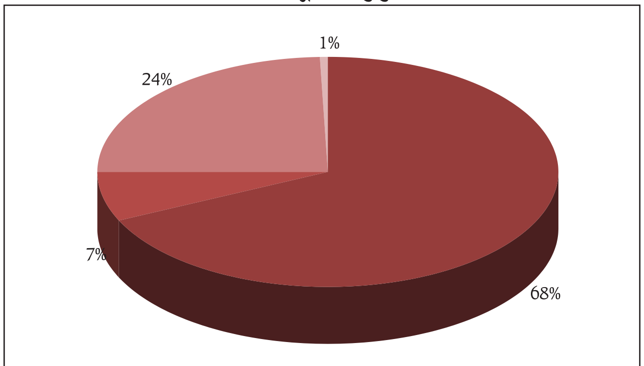

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

सारणी: 5.3 बैंक उधार राशियों में म्युचुअल निधि और बीमा कंपनियों का योगदान

	बीमा सेक्टर से प्राप्त उधार राशियां/निधि		म्युचुअल निधियों से प्राप्त उधार राशियां/निधि	
	₹ बिलियन	कुल उधार का प्रतिशत	₹ बिलियन	कुल उधार का प्रतिशत
बैंकिंग क्षेत्र	1828	26.5	2591	37.1
सरकारी क्षेत्र बैंक	1153	27.2	1761	41.5
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	60	25.2	185	77.7
नये निजी क्षेत्र के बैंक	583	40.7	631	44.2
विदेशी बैंक	32	2.9	14	1.3

स्रोत: भारिबैं, स्टाफ परिकलन

सारणी: 5.4 बैंकिंग प्रणाली में बीमा कंपनियों और म्युचुअल निधियों के निवेश/उधार देना - प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

	बीमा कंपनियां			म्युचुअल निधियां		
	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
बैंकिंग क्षेत्र	11.6	88.4	100	81.0	19.0	100
सरकारी क्षेत्र बैंक	8.2	54.9	63.1	58.2	9.8	67.9
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	1.2	2.0	3.3	5.8	1.3	7.1
नये निजी क्षेत्र के बैंक	1.5	30.4	31.9	16.8	7.6	24.4
विदेशी बैंक	0.6	1.1	1.8	0.2	0.3	0.6

स्रोत: भारिबैं, स्टाफ परिकलन

[6] पद्धति का संपूर्ण विवरण वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2011 के तीसरे अंक में दिया गया है (http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?=24557)

[7] पीओडी की गणना की पद्धति को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2011 में उपयोग किए गए विधि की तुलना में इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में संशोधित किया गया है। गणना किए गए पीओडी का उपयोग पीओडी और बैंकिंग स्थिरता उपायों के साथ अनुमानित कमी के व्युत्पन्न हेतु निविष्टि के रूप में किया गया है। पूर्व में, पीओडी की गणना के लिए सीमारेखा जनवरी 2007 से प्रतिदिन ईक्विटी मूल्य के विवरणियों के आधार पर निकाली जाती थी। चूंकि 2008-09 के वित्तीय संकट के दौरान भारतीय बैंकिंग ईक्विटी मूल्यों को पहले के संकट और वर्तमान समय में विवरणी में उच्चतर गिरावट दर्ज की गई और प्रारंभिक रिटर्न सीमा (वीएआर) को अत्याधिक निम्न स्तर पर निर्धारित किया गया। अत: यह अनुभव किया गया कि पीओडी वर्तमान अवधि में ईक्विटी रिटर्न के संबंधित अंतर को ग्रहण करने में असमर्थ रहे। इसलिए इस पाबंदी से बाहर निकलने के लिए पीओडी की संशोधित गणना वित्तीय संकट (अर्थात् जनवरी 2007 से प्रतिदिन ईक्विटी मूल्य रिटर्न) को छोड़कर निकाली गई सीमा आधार है। सभी उपाय थोड़ा सा उर्ध्वगामी बढ़त दिखाते हैं (पहले प्रकाशित परिणाम की तुलना में)। साथ ही, तनाव कार्यक्रम को बृहत् रूप में ग्रहण करने के लिए संशोधित पीओडी 99.5 प्रतिशत वीएआर के बदले 99 प्रतिशत वीएआर आधार है।

प्रणाली में सामान्य संकट: संकट की संयुक्त संभाव्यता और बैंकिंग स्थिरता सूचकांक

5.23 संकट की संयुक्त संभाव्यता के दौरान मापी गयी संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के संकट की संभाव्यता पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रही है यद्यपि संभाव्यता 2008-09 के दौरान देखे गए स्तर की तुलना में अब भी कम हैं। बैंकिंग स्थिरता सूचकांक जो, यह मान लेने पर कि कम से कम एक बैंक जरूर संकटग्रस्त होता है, संकटग्रस्त होने वाले बैंकों की संभावित संख्या का आकलन करता है 2008-09 के दौरान दर्ज उंचाइयों से 2010 के अंत तक नीचे आ गया है। तदुपरांत यह बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता रहा है (चार्ट 5.21)।

5.24 संकट की संयुक्त संभावना और बैंकिंग स्थिरता सूचकांक दोनों की प्रवृत्तियां इस बात का संकेत देती हैं कि हाल के दिनों में बैंकों के बीच अंतर्निर्भरता बढ़ी है यद्यपि ये वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखे गए स्तर से अब भी काफी नीचे हैं।

विशिष्ट बैंकों के बीच संकट : विषाक्तता (टॉक्सिसिटी) और भेद्यता (वल्नेरेबिलिटी) सूचकांक

5.25 विशिष्ट बैंकों के बीच संकट की माप विषाक्तता सूचकांक और भेद्यता सूचकांक के आधार पर की गयी है[8]। जैसा कि सामान्य संकट सूचकांक के मामले में है विषाक्तता और भेद्यता सूचकांक, दोनों ने वैश्विक वित्तीय संकट से घटने की प्रवृत्ति दर्शाया है किंतु हाल के दिनों में ये सूचकांक विशेषत: 2011 से बढ़ रहे हैं (चार्ट 5.22 और 5.23)।

किसी विशिष्ट बैंक में संकट के कारण प्रपात सरीखा (कैस्केड) प्रभाव

5.26 यह मान लेने पर कि कोई विशिष्ट बैंक संकटग्रस्त हो गया है प्रपात सरीखा प्रभाव एक या अधिक बैंकों के संकटग्रस्त होने की संभाव्यता की माप करता है। यह माप बैंक की प्रणालीगत महत्त्व को प्रतिबिंबित करताहै । यद्यपि ये सशर्त संभाव्यता कारण का संकेत नहीं देते तथापि, ये बैंकों के मध्य प्रणालीगत अंत: संबंध में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रपात सरीखी संभाव्यताएं ये दर्शाती हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली व्यापक रूप से अंत: संबंधित है और वित्तीय संकटों के दौरान इसकी उच्च संकट निर्भरता है। यह

चार्ट 5.21: संकट की संयुक्त संभाव्यता और बैंकिंग स्थिरता सूचकांक का उतार-चढ़ाव

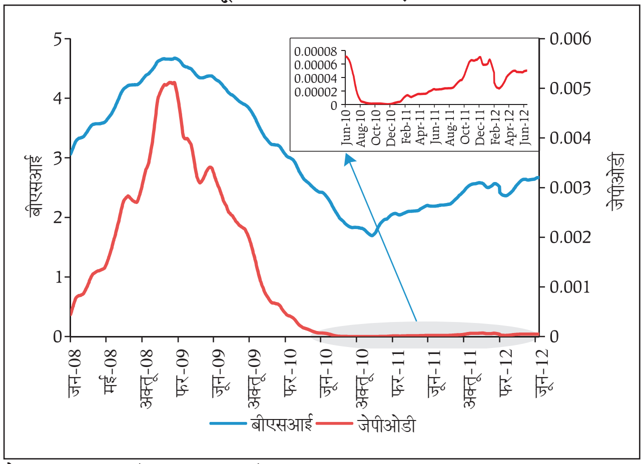

स्रोत: ब्लूमबर्ग डाटा और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.22 : बैंकों की टॉक्सिसिटी इंडेक्स का उतार-चढ़ाव

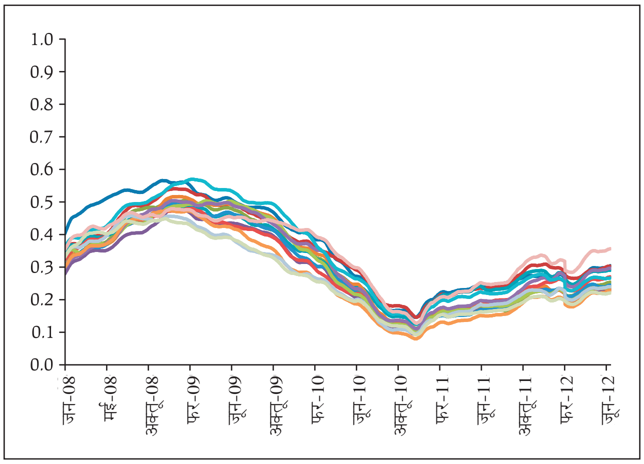

स्रोत: ब्लूमबर्ग डाटा और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.23 : बैंकों के प्रभावित होने वाले सूचकांक का उतार-चढ़ाव

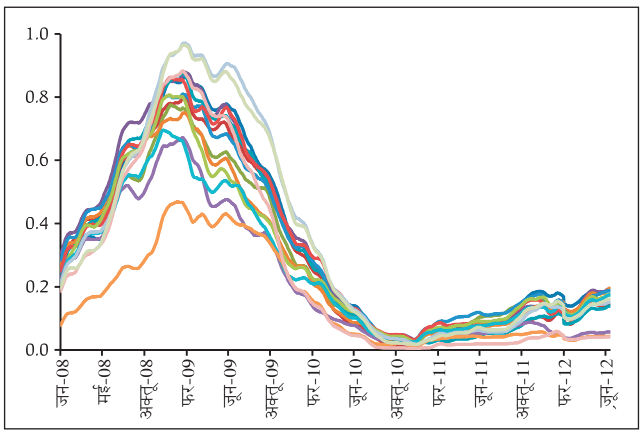

स्रोत: ब्लूमबर्ग डाटा और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

[8] विषाक्तता सूचकांक वह औसत संभाव्यता है जो एक संकटग्रस्त बैंक प्रणाली की किसी अन्य बैंक में संकट उत्पन्न कर सकता है जबकि भेद्यता सूचकांक प्रणाली की अन्य बैंको के संकटग्रस्त मान लिए जाने पर बैंक को मात्राबद्ध करता है।

प्रभाव 2010 में घट गया किंतु हाल के दौरान यह बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है (चार्ट 5.24)।

प्रणालीगत दूरगामी प्रभाव : प्रपात सरीखा (कैस्केड) प्रभाव

5.27 किसी विशिष्ट बैंक के प्रणालीगत महत्त्व और दूरगामी प्रभाव को बैंक में संकट पर निर्भर प्रणाली में संकट की संभावना के रूप में मात्राबद्ध किया जा सकता है (चार्ट 5.25)। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए दूरगामी(डोमिनो) प्रभाव हाल के दिनों में अत्यल्प बढ़ा है।

संभावित गिरावट

5.28 बैंकिंग प्रणाली की संभावित गिरावट[9] जिसमें 2008 से 2010 की अवधि के दौरान ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति देखी गई थी उसमे 2011 से वृद्धि हो रही है। दिसंबर 2008 में संभावित गिरावट के बैंकिंग प्रणाली की संपूर्ण आस्तियों के लगभग 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। तब से संभावित गिरावट में व्यापक कमी देखी गई है। तथापि 2011 के आरंभ से इसमे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है।यद्यपि संभावित गिरावट वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखे गये स्तरो से अभी भी काफी नीचे है। मार्च 2012 के दौरान संभावित गिरावट कुल आस्तियों के 3.4 प्रतिशत पर स्थिर रही। संभावित गिरावट के आगामी तिमाहियों के लिये प्रक्षेपित मान से यह संकेत मिलता है कि गिरावट में हल्की वृद्धि देखी गई है (चार्ट 5.26)।

बृहत् तनाव परीक्षण [10]

5.29 बृहत् तनाव परीक्षणों की एक श्रृंखला बैंकों की ऋण गुणवत्ता पर विविध प्रतिकूल व्यापक आघातों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए की गई। इसके लिए चार अलग-अलग अर्थमिती उपकरण प्रयोग में लाए गए। प्रणाली स्तर पर किये गये परीक्षणों के अतिरिक्त यह अभ्यास बैंक समूह और सेक्टर स्तरों पर भी किया गया। पूर्व की वित्तीय स्थिरता रिर्पोटों में तनाव परीक्षण विविध क्लासिकल मल्टीवेरिएट प्रतिगमनों का प्रयोग कर किया जाता था।यह सुनिश्चित करने के लिए की तनाव परीक्षण अभ्यास अन्तय को भी संज्ञान में लेते हैं, क्वानटाइल प्रतिगमन का अभिग्रहण किया गया है (बाक्स 5.2)। विविध व्यापक आर्थिक आघातों से प्रणालीगत जोखिम का आकलन इस तरह से पूरक दृष्टिकोणों से संभव हुआ है।

चार्ट 5.24: बैंकों के बीच प्रणालीगत अंतर-संबद्धता : कॅस्केड प्रभाव

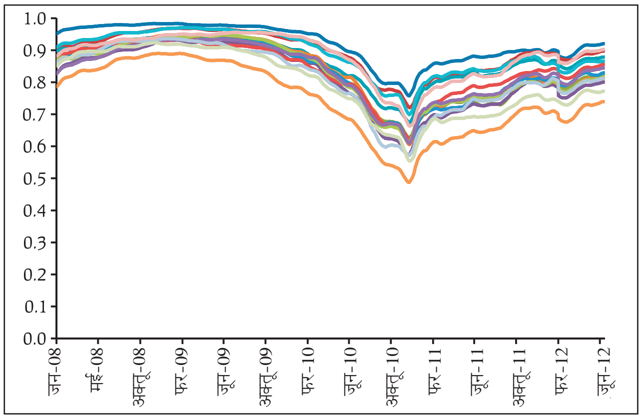

स्रोत: ब्लूमबर्ग डाटा और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.25 : समस्त प्रणाली पर बैंकों का डामिनो प्रभाव: कॅस्केड प्रभाव

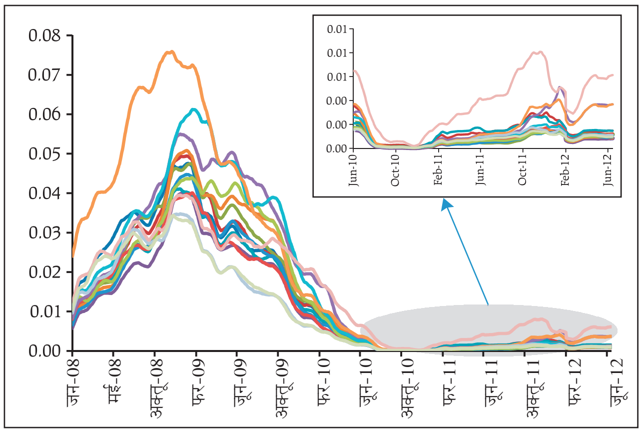

स्रोत: ब्लूमबर्ग डाटा और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

चार्ट 5.26:कुल आस्तियों में प्रत्याशित कमी : प्रणाली स्तर

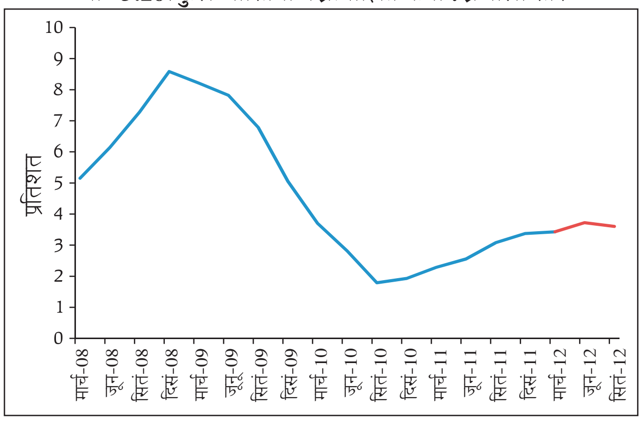

टिप्पणी: जून 2012 तथा सितं 2012 प्रक्षेपित मान हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी और ब्लूमबर्ग डाटा और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन

[9] संभावित गिरावट प्रणालीगत जोखिम की एक प्रचलित माप है। यह वैसी चरम घटनाओं जिनके घटने की संभावना तो कम होती है किंतु जिनके अखिल प्रणालीगत परिणाम हो सकते हैं, उनकी गंभीरता की एक सूचनात्मक सार प्रदान करता है। संभावित गिरावट की माप संबंधित हानि की संभावनाओं को भार के रूप में लेने पर अन्तय जोखिम क्षेत्र में आस्तियों की अनुमानित भारित औसत के रूप में की जाती है। एक सतत हानि वितरण (Z) की स्थिति में संभावित गिरावट (100(1-α) का प्रतिशत विश्वास स्तर(ES_{α} (Z)) पर $ES_{\alpha}(Z) = E[Z \mid Z \geq VaR_{\alpha}(Z)]$ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतएव संभावित गिरावट दी गई हानि की सशर्त संभावना है कि हानि व्ही ए आर (VaR) स्तर के परे है।

[10] प्रणाली अनुबंध में दी गई है।

बॉक्स 5.2 : बृहत तनाव परीक्षण - क्वांटाइल रिग्रेशन अभिगम

बृहत तनाव परीक्षण बैंकिंग प्रणाली के चरम लेकिन सच हो सकने वाले प्रतिकूल व्यापक आर्थिक आघातों से भेद्यता के आकलन करने का एक उपकरण है। बैंकिंग स्थिरता, विशेषत: जब इसे ऋण जोखिम संकेतक के रूप में लिया जाए और अनर्जक अग्रिम अनुपात अथवा स्लिपेज अनुपात द्वारा इसे परिभाषित किया जाए , तथा बृहत चरों के बीच बहु संभाव्य संबंध सांख्यिकी / अर्थमीति मॉडलों के माध्यम से स्थापित की जाती है।

पूर्व की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में प्रस्तुत परिणाम तनाव परीक्षणों, जिन्हें मल्टीवेरिएट लॉजिट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट पैनल रिग्रेशन की तकनीकों का प्रयोग कर किया गया था, पर आधारित था। तथापि, इन क्लासिकल रिग्रेशन विश्लेषणों की अपनी सीमाएं हैं। प्रथमत:, वे दिए हुए स्वतंत्र चरों(रिग्रेशर) के लिए निर्भर चर की सशर्त माध्य का अनुमान लगाते हैं और इसलिए यह रिग्रेशन वक्र रेखा एक अपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करती है। द्वितीयत:, ये तकनीक इसका पूर्वानुमान करते हैं कि निर्भर चरों के विभिन्न स्तरों के लिए स्वतंत्र चर का निर्भर चर पर प्रभाव तद्रूप और समरूप होगा;ऐसा अनुमान,जो समस्त परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता। विशेषत: अंत में घटित होनेवाली घटना के दौरान चरों के बीच के संबंध परिवर्तित हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कि तनाव परीक्षण अभ्यास अंत में घटित होने वाली घटनाओं को संज्ञान में लेते हैं, यह महत्त्वपूर्ण है कि अभ्यास सशर्त माध्य के परे जा कर अंत्य पर ध्यान केंद्रित करे। इस उद्देश्य के लिए क्वांटाइल रिग्रेशन उपकरणों की तकनीकें अपनायी जाती हैं जिससे लक्षित चर के सशर्त वितरण के अंत्य की स्पष्ट मॉडलिंग संभव हो पाती है।

क्वांटाइल रिग्रेशन एक ऐसा उपकरण है जो न केवल औसत/माध्य के मॉडलिंग की सुविधा प्रदान करता है बल्कि लक्षित चर के अन्य क्वांटाइलों का उपयोग कर अंत्य के सशर्त वितरण का भी स्पष्ट मॉडल कर पाता है।

किसी यादृच्छिक चर के τ-th क्वांटाइल ((0.1) के अंतराल में) को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

$$P(Y < \varepsilon_\tau) \le \tau \le P(Y \le \varepsilon_\tau)$$

पारंपरिक रूप से क्वांटाइल की गणना चर के मूल्यों को आरोही क्रम में सजाकर और उस निष्कर्ष को लेकर की जाती है जिस पर थ्रेशोल्ड पर पहुंचा जाता है। कोयंकर और बैसेट (1978) ने क्वांटाइल की गणना का एक सर्वथा नवीन तरीका निकाला जो नीचे दिए गए वस्तुगत फंक्शन पर आधारित है। इसमें 'पृथक्ककरण' के स्थान पर 'ऑप्टीमाइजिंग' की संकल्पना का प्रयोग हुआ है :

$$\hat{Q}_Y(\tau) = \underset{\varepsilon_\tau}{argmin}\left\{\sum_{i\in\{i|Y_i\ge\varepsilon_\tau\}} \tau|Y_i - \varepsilon_\tau| + \sum_{i\in\{i|Y_i<\varepsilon_\tau\}} (1-\tau)|Y_i - \varepsilon_\tau|\right\}$$

उक्त कथित ऑप्टिमाइजिंग तकनीक का विस्तार हम रिग्रेशन सेटिंग्स के लिए भी कर सकते हैं जो निम्नानुसार है :

$$y_t = x_t'\beta_\tau + u_{t,\tau} \qquad t = 1,2,\ldots T$$

यहां पर x_t पर निर्भर त्रुटि का τ-th सशर्त क्वांटाइल शून्य है । अतएव, y का सशर्त क्वांटाइल x_t के सापेक्ष इस तरह से लिखा जा सकता है :

$$Q_\tau(y_t|x_t) = x_t'\beta_\tau$$

उपर्युक्त समीकरण और वस्तुगत फंक्शन को एक साथ जोडने पर परिमीति वेक्टर ---- का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है :

$$\hat{\beta}_\tau = \underset{\beta_\tau \in R^k}{argmin}\left\{\sum_{t\in\{t|Y_t\ge x_t'\beta_\tau\}} \tau|Y_t - x_t'\beta_\tau| + \sum_{t\in\{t|Y_t<x_t'\beta_\tau\}} (1-\tau)|Y_t - x_t'\beta_\tau|\right\}$$

उक्त परीमीति का समाकलन इसे एक एक रेखीय समीकरण में प्रदर्शित कर भी किया जा सकता है । यदि हम y का केवल धनात्मक तत्वों के फंक्शन के रूप में पुनर्लेखन करें तब :

$$y_t = \sum_{k=1}^{K} x_{tk}\left(\beta_{k,\tau}^1 - \beta_{k,\tau}^2\right) + (\epsilon_{t,\tau} - \nu_{t,\tau})$$

और $\beta_{k,\tau}^1$, $\beta_{k,\tau}^2 \ge 0$, k=1,2,...K and $\epsilon_{t,\tau}$, $\nu_{t,\tau} \ge 0$, t=1,2,...T के होने के साथ समाधान निम्नलिखित समस्या का रूप ले लेगी ।

$$\underset{\beta_{k,\tau}^1, \beta_{k,\tau}^2, \epsilon_{t,\tau}, \nu_{t,\tau}{}_\tau}{min} \sum_{t=1}^{T} \tau\,\epsilon_{t,\tau} + (1-\tau)\nu_{t,\tau}$$

बशर्ते कि : $y_t = \sum_{k=1}^{K} x_{tk}\left(\beta_{k,\tau}^1 - \beta_{k,\tau}^2\right) + (\epsilon_{t,\tau} - \nu_{t,\tau})$,

$\beta_{k,\tau}^1, \beta_{k,\tau}^2, \epsilon_{t,\tau}, \nu_{t,\tau} \ge 0(\forall t, k)$

जब कि वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का आकलन तीन विधियों द्वारा किया जा सकता है नामत: सीधी विधि, रैंक स्कोर विधि और पुनर्प्रतिदर्शन विधि ।

क्वांटाइल प्रतिगमन विविध क्वांटाइलों पर सशर्त ऋण जोखिम वितरण के साथ बृहत चरों के बदलते सापेक्षिक महत्त्व को भी अपनी परिधि में लेता है ।

संदर्भ

आईएमएफ *(2009)* 'वैश्विक *वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट*' अप्रैल *2009।*

कोयंकर.आर और बैसेट.जी *(1978)* 'प्रतिगमन क्वाइंटाइल' *इकॉनोमेट्रिका* 46 (1)।

नील शुल्ज *(2004)* 'एप्लाइड क्वाइंटाइल रिग्रेशन : माइक्रोइकोनोमेट्रिक्स फिनांशियल एंड इंवायरनमेंटल एनालिसिस' *उद्घाटन - डिजार्टेशन टुबिंजेन।*

स्केचमेन रिकॉर्डो, गैग लियानोन डब्लू पी (2011) 'माइक्रोस्अ्रेस टेस्टिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क फोकस्ड ऑन द टेल्स' *वर्किंग पेपर सीरीज 241, बैंको सेंट्रल डो ब्रजील।*

सारणी 5.5 : व्यापक आर्थिक परिदृश्य अनुमान[11]

(प्रतिशत)

परिदृश्य	जून 12	मार्च 13	जून 12	मार्च 13
	सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि		थोक मूल्य सूचकांक स्फीति	
आधार रेखा	7.7	7.6	7.0	6.5
मध्यम जोखिम	6.7	5.6	8.4	9.3
चरम जोखिम	5.2	3.5	10.6	12.2
	अल्प अवधि ब्याज-दर		निर्यात/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात	
आधार रेखा	8.2	7.9	16.3	16.4
मध्यम जोखिम	9.1	9.8	15.2	14.2
चरम जोखिम	10.5	11.6	13.5	12.0
	सकल वित्तीय घाटा			
आधार रेखा	5.1	5.1		
मध्यम जोखिम	5.8	6.5		
चरम जोखिम	6.9	7.9		

5.30 बृहत तनाव परीक्षण जोखिम परिदृश्यों की एक शृंखला को ही अपने में समाहित किए रहते हैं जिनमें एक आधार-रेखा तथा मध्यम और चरम जोखिम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रतिकूल व्यापक आर्थिक परिदृश्य,जहां व्यापक आर्थिक मानदंडों में झटके एक साथ घटित होना मान लिया जाता है, भी समाविष्ट रहते हैं (सारणी 5.5)। जोखिम परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन एससीबी के घरेलू परिचालनों के असमेकित तुलनपत्र के आधार पर किया जाता है। निश्चय ही बृहत तनाव परीक्षण विभिन्न ऋण जोखिम परिदृश्यों पर केंद्रित रहते हैं।

ऋण गुणवत्ता चरम बृहत तनाव की स्थिति में बदतर हो सकती है परंतु सीआरएआर पर इसके प्रभाव को रोका जा सकता है

5.31 विभिन्न मॉडलों के द्वारा प्रक्षेपित अनर्जक आस्तियां संकेत देते हैं कि आधार-रेखा परिदृश्य में अनर्जक आस्तियों के मार्च 2013 तक 3.3 से 3.5 प्रतिशत तक की सीमा में रहने की संभावना है। तनाव परिदृश्यों में ये बढ़कर 3.7 से 4.1 प्रतिशत (मध्यम जोखिम परिदृश्य) और 4.1 से 4.6 प्रतिशत (चरम जोखिम परिदृश्य) हो सकते हैं। चरम जोखिम परिदृश्य में वाणिज्यिक बैंकों का प्रणाली स्तरीय सीआरएआर[12] घटकर मार्च 2013 तक 12.5 प्रतिशत हो सकता है जो तब भी विनियामक अपेक्षाओं के स्तर से काफी अधिक रहेगा (सारणी 5.6 और 5.7)।

सारणी 5.6 विभिन्न मॉडलों का प्रयोग कर प्रक्षेपित सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

परिदृश्य	जून 12	मार्च 13	जून 12	मार्च 13
	मल्टीवैरिएट लॉगिट		मल्टी वैरिएट	
आधार रेखा	3.1	3.5	3.0	3.4
मध्यम जोखिम	3.1	3.9	3.0	3.8
चरम जोखिम	3.1	4.5	3.0	4.3
	वीएआर		क्वांटाइल	
आधार रेखा	3.0	3.3	3.2	3.5
मध्यम जोखिम	3.0	3.7	3.3	4.1
चरम जोखिम	3.0	4.1	3.3	4.6

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

सारणी 5.7 : विभिन्न मॉडलों का प्रयोग कर प्रक्षेपित सीआरएआर

(प्रतिशत)

परिदृश्य	जून 12	मार्च 13	जून 12	मार्च 13
	मल्टीवैरिएट लॉगिट		मल्टी वैरिएट	
आधार रेखा	13.50	12.58	13.50	12.59
मध्यम जोखिम	13.50	12.53	13.50	12.55
चरम जोखिम	13.50	12.46	13.50	12.50
	वीएआर		क्वांटाइल	
आधार रेखा	13.50	12.60	13.48	12.58
मध्यम जोखिम	13.50	12.56	13.47	12.52
चरम जोखिम	13.50	12.52	13.47	12.46

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

[11] प्रतिकूल परिदृश्य मध्यम जोखिम के लिए 10 वर्षों के ऐतिहासिक आंकडों के 1 मानक विचलन के आधार पर तथा चरम जोखिम के लिए 10 वर्षों के ऐतिहासिक आंकडों के 1.25 से 2 मानक विचलन के आधार पर निकाले गए हैं । ये तनाव परिदृश्य कल्पित चरम प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्य में सख्त व सतर्क आकलन हैं और इनसे पूर्वानुमान और अपेक्षित परिणामों का संकेत ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये प्रक्षेपण 2011-12 के चौथी तिमाही से संबंधित आंकडों पर आधारित हैं। व्यापक आर्थिक झटकों के 2012-13 के प्रथम तिमाही में घटित होने का अनुमान लगाया गया है।

[12] सीआरएआर बासेल II की अपेक्षाओं पर आधारित हैं।

सारणी 5.8 : बैंक-समूह-वार प्रक्षेपित अनर्जक आस्तियां (मल्टी वैरिएट पैनल रिग्रेशन)

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

	जून 12	मार्च 13	जून 12	मार्च 13
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
आधार रेखा	3.4	3.5	2.2	2.7
मध्यम	3.4	3.8	2.2	3.1
चरम	3.4	4.2	2.2	3.5
	निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
आधार रेखा	2.4	2.7	2.3	3.1
मध्यम	2.4	3.1	2.3	3.5
चरम	2.4	3.5	2.3	3.9

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

सारणी 5.9 : बैंक-समूह-वार प्रक्षेपित सीआरएआर (मल्टीवैरिएट पैनल रिग्रेशन)

(प्रतिशत)

	जून 12	मार्च 13	जून 12	मार्च 13
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
आधार रेखा	12.31	11.58	13.99	12.87
मध्यम जोखिम	12.31	11.54	13.99	12.81
चरम जोखिम	12.31	11.49	13.99	12.75
	निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
आधार रेखा	16.63	15.12	15.95	14.81
मध्यम जोखिम	16.63	15.08	15.95	14.78
चरम जोखिम	16.63	15.02	15.95	14.74

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव बैंक समूहों में अलग-अलग पड़ता है परंतु सारे समूह प्रतिरोधी स्वरूप के हैं

5.32 जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव बैंक समूहों पर अलग-अलग पड़ता है । सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का सीआरएआर चरम जोखिम परिदृश्य के अधीन गिर कर 11.5 प्रतिशत हो सकता है जबकि अन्य बैंक समूहों के सीआरएआर के आधारभूत परिदृश्य के अधीन सीआरएआर के उच्चतर स्तर को ध्यान में रखने पर(सारणी 5.8 व 5.9) उच्चतर रहने की संभावना है ।

जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव विभिन्न सेक्टरों पर अलग-अलग पड़ता है

5.33 विभिन्न जोखिम परिदृश्यों का विभिन्न सेक्टरों में अनर्जक आस्तियों के स्तर पर प्रभाव अलग-अलग रहता है और खाद्य संसाधन, अभियांत्रिकी और लौह और इस्पात सेक्टरों में इसका प्रभाव सर्वाधिक देखा जाता है। इस बृहत तनाव परीक्षण विश्लेषण में कृषि में अनर्जक आस्तियों पर प्रभाव अत्यल्प ही पड़ता है (सारणी 5.10)।

सारणी 5.10 : प्रक्षेपित सेक्टोरल सकल अनर्जक आस्ति अनुपात

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च 2013		
	आधार रेखा	मध्यम जोखिम	चरम जोखिम
कृषि	4.2	4.4	4.5
खाद्य संसाधन	7.6	8.7	9.9
निर्माण	2.9	3.1	3.3
सीमेंट	2.9	3.1	3.5
आधारभूत संरचना	0.9	1.1	1.3
लौह और इस्पात	4.2	4.9	5.6
अभियांत्रिकी	4.9	5.6	6.2
ऑटोमोबाइल	2.4	2.6	2.8
अन्य	3.4	3.7	4.0

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ परिकलन

अनुलग्नक
कार्य-प्रणाली

वित्तीय स्थिरता की रूपरेखा

वित्तीय स्थिरता की रूपरेखा भारतीय वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता संबंधी संपूर्ण स्थिति दर्शाती है। स्थिरता की रूपरेखा मुख्य रूप से तीन घटकों पर आधारित है जैसे समष्टि अर्थशास्त्र स्थिरता सूचक (एमएसआई), वित्तीय बाज़ार स्थिरता सूचक (एफएमएसआई) और बैंकिंग स्थिरता सूचक (बीएसआई)। उपर्युक्त सूचकों के परिकलन संबंधी कार्य-प्रणाली नीचे दी गई है :

समष्टिगत अर्थशास्त्र की रूपरेखा और सूचक

समष्टिगत अर्थशास्त्र की स्थिरता संबंधी रूपरेखा और सूचक सात उप-सूचकों पर आधारित है और प्रत्येक उप-सूचक समष्टिगत-अर्थशास्त्र संबंधी जोखिम के विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। समष्टिगत अर्थशास्त्र के जोखिम संबंधी प्रत्येक उप-सूचक में उस क्षेत्र के जोखिमों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चुनिंदा मानदंड शामिल हैं। इन उप-सूचकों को समष्टिगत अर्थशास्त्र और जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दर बैंकों की आस्ति गुणवत्ता जैसे वित्तीय चर वस्तुओं पर उनके उचित प्रभाव के आधार पर वैधीकरण किया गया है । संपूर्ण समष्टिगत-अर्थशास्त्र स्थिरता सूचकांक के सात उप-सूचक और उनके घटकों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वैश्विक जोखिम सूचक

वैश्विक जोखिम सूचकांक वास्तविक आउटपुट और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मूल्यों पर आधारित है। वास्तविक आउटपुट के संबंध में, अमरीका, यूरो क्षेत्र और जपान के जीडीपी की वृद्धि दर के अधिक अनुपात पर एक संमिश्र सूचकांक तैयार किया गया है। इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। जीडीपी सूचकांक आरोही क्रम में रखा गया है जबकि मुद्रास्फीति को अवरोही क्रम में रखा गया है। वैश्विक जोखिम संबंधी सूचकांक इन सूचकांकों का एक संमिश्र सूचकांक है जिसमें प्रत्येक सूचकांक को समान रूप से प्रमुखता दी गई है।

बाहरी जोखिमवाला क्षेत्र

बाहरी जोखिम संबंधी सूचकांक चालू खाता कमी / जीडीपी, चालू भुगतान, चालू रसीद, औसतन मासिक निर्यात/आरक्षित, कुल ऋण में अल्पावधि ऋण का हिस्सा, ऋण स्टॉक - जीडीपी अनुपात और ऋण सेवा अनुपात पर आधारित है।

राजकोषीय जोखिम

शुरुआत में, सकल प्राथमिक घाटा (जीपीडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और केंद्र और राज्य सरकार की कुल देयताओं के आधार पर बनाया गया है। यह कार्य-पद्धति विस्तृत रूप से बलडक्की, मेकहग और पेट्रोवा (2011) और बलडक्की, पेट्रोवा, बेलहोसिन, डोब्रेस्कु और मज़रानी (2011) द्वारा प्रस्तुत आईएमएफ के दो वर्किंग पेपर पर आधारित है। इस प्रकार से प्राप्त जीएफडी और जीपीडी भारित को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त जीपीडी और जीएफडी संबंधी हाल के डाटा के साथ मिलाया जाता है ताकि राजकोषीय जोखिमों में परिवर्तन को आंका जा सके।

वृद्धि

घरेलू वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अनेक चर वस्तुओं के साथ वृद्धि का संबंध देखा जाता है जैसे निर्यात/जीडीपी, महत्त्वपूर्ण उद्योग की वृद्धि जीएफसीएफ/जीडीपी, वास्तविक बैंक क्रेडिट, पीएमआई और यिल्ड कर्व (दस वर्षीय प्रतिलाभ और एक वर्षीय प्रतिलाभ का अंतर)। इन चर वस्तुओं में यिल्ड कर्व (yield curve) और पीएमआई निर्माण को वृद्धि के अत्यंत उचित सूचकों के रूप में पाया गया है।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय तेल के दाम, विनिमय दर और विश्व की मुद्रास्फीति में परिवर्तन पर आधारित है।

कार्पोरेट क्षेत्र

कार्पोरेट क्षेत्र की दशा लाभ के मार्जिन के ज़रिए आंकी जाती है। इस क्षेत्र से उत्पन्न होनेवाले जोखिम विपरीत रूप से इसी से संबंधित है। कार्पोरेट सेक्टर का वित्तीय क्षेत्र के साथ संबंध का पता लगाने के लिए कार्पोरेट क्षेत्र के शेयरों की बिक्री में तात्पर्य भी सूचकांक में लिया जाता है।

घरेलू क्षेत्र

घरेलू क्षेत्र की ऋणग्रस्तता संबंधी किसी नियमित डाटा के अभाव में घरेलू क्षेत्र को बैंक से बकाया ऋण जैसे खुदरा ऋण को घरेलू ऋण ग्रस्तता के संकेतक के रूप में लिया जाता है। आगे, वैयक्तिक प्रयोग के लिए उपलब्ध आय संबंधी डाटा की उपलब्धता में विलंब के कारण निजी अंतिम उपभोग खर्चे (पीएफसीई) को इसके सूचक के रूप में लिया जाता है। इन दो चर वस्तुओं और खुदरा एनपीए के आधार पर घरेलू क्षेत्र से संबंधित सूचकांक इस क्षेत्र से उत्पन्न जोखिमों का पता लगाता है।

वित्तीय बाजार स्थिरता संबंधी रूपरेखा और सूचक

वित्तीय बाज़ार की स्थिरता को आंकने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी मुद्रा बाज़ार, ईक्विटी बाज़ार और ऋण बाज़ार नामक चार क्षेत्र/बाज़ार के सूचकों के आधार पर तैयार किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों/बाज़ारों से चुने गए सूचक निम्न प्रकार से हैं : i) बैंकिंग क्षेत्र: सीएनएक्स बैंक सूचकांक का बैंकिंग बीटा और निफ्टी सूचकांक, सीडी दर और सीडी दर घटाव निहित वायदा दर। ii) विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार : दैनिक आईएनआर-यूएस डॉलर विनिमय दर का सीमेक्स जो निम्नानुसार परिभाषित है X_t / Max(X_i, i=1,2..एक साल तक)। जिसमें X_t, t समय पर आईएनआर-यूएस डॉलर विनिमय दर है और विदेशी मुद्रा विनिमय दर का 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल, iii) ईक्विटी मार्केट : निफ्टी सीमेक्स और इंडिया VIX का इनवर्स और iv) ऋण बाज़ार : कार्पोरेट बांड जो ए, एए और एएए दर के कार्पोरेट बांडों का औसतन आय है, 10 साल का सरकारी बांड का लाभ और सीपी दर।

चुनिंदा सूचकों के विभिन्न स्तरों के कारण इनको सीधे जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए, सभी सूचकों को एक स्तर पर लाने के लिए अंतर-समान अंतरण (वेरियंस-ईक्वल ट्रांस्फोर्मेशन) का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक सूचकों के सरल औसत के आधार पर चार चुनिंदा क्षेत्रों/बाज़ार के लिए चार सूचक तैयार किया गया और उसके पश्चात प्रारंभिक स्तर पर उत्पन्न चार सूचकों के सरल औसत के आधार पर एफएमएसआई उत्पन्न किया जाता है। दैनिक डाटा के आधार पर एफएमएसआई का अनुमान लगाया जाता है।

आगे, एफएमएसआई का अनुमान निम्न अवरोही समीकरण का प्रयोग करते हुए मासिक एफएमएसआई जो दैनिक एफएमएसआई का मासिक औसत है, क्रेडिट वृद्धि, डब्ल्यूपीआई-निर्मित वस्तु मुद्रास्फीति और आरईईआर के आधार पर किया जाता है :

$$FMSI_t = -\alpha_1 + \beta_1 * FMSI_{t-1} - \beta_2 * FMSI_{t-2} + \beta_3 * Credit\ Growth_{t-1} + \beta_4$$
$$*\text{मुद्रास्फीति (निर्मित उत्पन्न)}_{t-1} - \beta_5 * DL(REER)_{t-4}$$

जिसमें α_1 , β_1, β_2, β_3, β_4 और $\beta_5 > 0$.

बैंकिंग स्थिरता संबंधी रूपरेखा और सूचक

बैंकिंग स्थिरता संबंधी रूपरेखा और सूचक, आधारभूत परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों का संपूर्ण मूल्यांकन और किसी अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर असर करनेवाले जोखिम घटकों को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक सम्मिश्र सूचकांक के निर्माण के लिए निम्न अनुपात का प्रयोग किया जाता है।

तालिका : बैंकिंग स्थिरता संबंधी रूपरेखा और बैंकिंग स्थिरता सूचक के निर्माण के लिए प्रयुक्त सूचक

परिमाण	अनुपात			
दृढ़ता	सीआरएआर	टियर-I पूंजी से टियर-II पूंजी	लीवरेज अनुपात के रूप में कुल आस्ति की तुलना में पूंजी और आरक्षित	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	सकल एनपीए की तुलना में उप-मानक-अग्रिम	मानक-अग्रिमों की तुलना में पुन:संगठित मानक अग्रिम
लाभप्रदत्ता	आस्तियों पर आय	निवल ब्याज मार्जिन	लाभ में वृद्धि	
चल निधि	कुल आस्तियों की तुलना में तरल आस्ति	कुल-आस्तियों की तुलना में ग्राहक-जमा	ग्राहक-जमा की तुलना में गैर-बैंक-अग्रिम	कुल जमाओं की तुलना में 1 साल के भीतर परिपक्व होनेवाली जमाएं
दक्षता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्चों की तुलना में कारोबार (ऋण + जमा)		कुल खर्चों की तुलना में स्टाफ खर्चे

पांच संयुक्त संकेतक पांच आयामों अर्थात दृढ़ता, आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और दक्षता को दर्शाता है। बैंक के कामकाज के किसी आयाम को दर्शाने वाले प्रत्येक संकेतक के लिये शून्य (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) की बीच के मूल्य को लिया जाता है। प्रत्येक संकेतक अपने निर्माण के लिये व्यवहृत नमूना अवधि के दौरान एक सापेक्षिक मापन होता है जहां उच्च मूल्य का अर्थ है उसके आयाम में जोखिम अधिक है। इसलिए, किसी भी विशेष आयाम में संकेतक के मूल्य में वृद्धि यह दर्शाता है कि अन्य अवधियों की तुलना में उस अवधि के लिये उक्त आयाम में जोखिम में वृद्धि है। किसी आयाम के लिये व्यवहृत प्रत्येक अनुपात हेतु, बैंकिंग सेक्टर के लिये भारित औसत की व्युत्पत्ति की गयी है जहां भार बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में बैंक के व्यक्तिगत आस्ति का अनुपात है। नमूना अवधि के लिये प्रत्येक संकेतक को निम्नलिखित पद्धति द्वारा सरलीकृत किया गया है यथा 'दी गई तारीख को अनुपात घटाव नमूना अवधि में न्यूनतम मूल्य को नमूना अवधि में अधिकतम मूल्य घटाव नमूना अवधि में न्यूनतम अवधि द्वारा विभाजित कर'। प्रत्येक आयाम के संयुक्त मापन को उस आयाम के लिये व्यवहृत सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में परिकलित किया गया है, जहां भार कैमेल्स रेटिंग्स के मूल्यांकन के लिये दिये गये अंकों पर आधारित है। प्रत्येक आयाम के लिये व्यक्तिगत संयुक्त संकेतकों के आधार पर बैंकिंग स्थिरता संकेतक को इन पांच संयुक्त उप-संकेतकों के एक सरल औसत के रूप में निर्मित किया गया है।

वर्तमान रूपरेखा और संकेतक के लिये, मार्च 2006 से मार्च 2012 तक को मूल्यांकन की नमूना अवधि के रूप में लिया गया। स्वत: प्रतिगामी चल औसत (एआरएमए) पद्धति का प्रयोग कर बीएसआई का पूर्वानुमान किया गया।

चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

दबाव परीक्षण सबंधी प्रयोग द्योतक नमूना बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो पर आधारित है। दिसंबर 2011 को समाप्त अवधि के अनुसार व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के परिकल्पित मूल्य के अनुसार शीर्ष 26 बैंकों को इस विश्लेषण के लिये चुना गया। अपनायी गयी पद्धति के अनुसार दबाव की अवस्थाओं का खाका तैयार किया गया। नमूना में सम्मिलित प्रत्येक बैंक को 31 मार्च, 2012 के अनुसार उनके संबंधित व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो पर दबाव की इन अवस्थाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये कहा गया।

देशी बैंकों के मामले में, देशी और विदेशी दोनों परिचालनों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो की गणना की गयी। विदेशी बैंकों के मामले में, उक्त प्रयोग के लिये केवल देशी (अर्थात भारतीय) स्थिति पर ही विचार किया गया। व्युत्पन्नी व्यापार जहां बचाव-व्यवस्था स्थापित की गयी, को इस परीक्षण में शामिल नहीं किया गया जबकि अन्य सभी व्यापार इसमें शामिल किये गये।

दबाव परिदृश्यों में छह ऐतिहासिक परिदृश्य और चार संवेदनशीलता परीक्षण शामिल हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य के निर्माण के लिये छह पैरामीटरों (बाजार वेरिएबल्स) को चुना गया और प्रत्येक वेरिएबल के लिये 2007-2011 तक 1 दिन के परिवर्तन की दर को परिकलित किया गया। अधिकतम परिवर्तन (प्रत्येक वेरिएबल में) की तारीख को दबावग्रस्त अवधि के रूप में चुना गया है। छह दबावग्रस्त अवधियों में से प्रत्येक अवधि हेतु, छह विभिन्न परिदृश्यों तक पहुंचने के लिये बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिये आवश्यक बाजार के शेष वेरिएबल्स के लिये 1 दिन के परिवर्तन की दर की गणना की गयी।

सारणी : परिदृश्य विश्लेषण करने के लिये व्यवहृत पैरामीटर और तारीख

पैरामीटर	2007-2001 की अवधि में अधिकतम 1 दिन का परिवर्तन
यूएसडी/आईएनआर	-3.1 प्रतिशत का परिवर्तन दर
एमआईएफओआर 6 माह	-240 बीपीएस का पूर्ण परिवर्तन
ओआईएस आईएनआर 2 वर्ष	-60.5 बीपीएस का पूर्ण परिवर्तन
यूएसडी एलआईबीओआर 3 माह	-38.6 बीपीएस का पूर्ण परिवर्तन
ईयूआरआईबीओआर 6 माह	-17.5 बीपीएस का पूर्ण परिवर्तन
यूएसडी एलआईबीओआर स्वैप कर्व 5 वर्ष	-8.5 बीपीएस का पूर्ण परिवर्तन

पैरामीटरों के रूप में स्पॉट यूएसडी/आईएनआर की दर और घरेलू ब्याज दरों का प्रयोग कर संवेदनशीलता परीक्षण कराए गए।

सारणी : संवेदनशीलता विश्लेषण के लिये आघात

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 1	ओवरनाइट	**+250 बीपीएस**
	1 वर्ष तक	**+150 बीपीएस**
	1 वर्ष से ऊपर	**+100 बीपीएस**

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 2	ओवरनाइट	**-250 बीपीएस**
	1 वर्ष तक	**-150 बीपीएस**
	1 वर्ष से ऊपर	**-100 बीपीएस**

	विनिमय दरें	
आघात 3	यूएसडी/आईएनआर	**+20 प्रतिशत**

	विनिमय दरें	
आघात 4	यूएसडी/आईएनआर	**-20 प्रतिशत**

एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण

तिमाही निगरानी के एक भाग के रूप में, दबाव संबंधी परीक्षण किये गये जिसमें ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी कीमत जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि शामिल हैं। इन आघातों के प्रतिक्रिया स्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के लचीलेपन का अध्ययन किया गया। इस विश्लेषण में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के ऋण जोखिम का एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया।

ऋण जोखिम

बैंकों के लचीलेपन का पता लगाने के लिये, प्रावधानन आवश्यकताओं में समकालिक वृद्धि के साथ-साथ चुनिंदा सेक्टरों एवं साथ ही सम्पूर्ण पोर्टफोलियो के लिये एनपीए स्तरों में वृद्धि कर ऋण पोर्टफोलियो को प्रभावित किया गया। ऋण संकेंद्रण जोखिम के परीक्षण के लिये शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और बृहत्तर समूह के उधारकर्ता के चूक की कल्पना की गई। इसप्रकार व्युत्पन्न अनुमानित प्रावधानन आवश्यकताओं को मौजूदा प्रावधानों के साथ समायोजित किया गया और शेष प्रावधानन आवश्यकताओं, यदि कोई है, के परिणाम बैंकों की पूंजी से निकाले गए।

दिनांक 31 मार्च, 2012 के पर्यवेक्षी आंकड़े के आधार पर समग्र स्तर और साथ ही व्यक्तिगत बैंक स्तर पर विश्लेषण किया गया। परिकल्पित परिदृश्य से मानक, उप-मानक और संदिग्ध/हानि अग्रिम के लिये क्रमश: 1 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की प्रावधानन आवश्यकताएं बढ़ीं। एनपीए में परिकल्पित बढ़ोत्तरी को एनपीए के मौजूदा स्टॉक के अनुसार समान अनुपात में उप-मानक, संदिग्ध और हानि वर्गों में वितरित किया गया। अतिरिक्त प्रावधानन आवश्यकता को ऋण पोर्टफोलियो के परिवर्तित संरचना में प्रयुक्त किया गया।

ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याजदर जोखिम

कल्पित आघात के कारण ईक्विटी कीमतों में बदलाव की वजह से पोर्टफोलियो या आय हानियों की मूल्य में गिरावट, भारतीय रुपये में वृद्धि/गिरावट, भारतीय रुपये के यिल्ड कर्व के अंतरण को बैंकों की कुल हानि का कारण माना गया है। अत: व्युत्पन्न अनुमानित कुल हानि को बैंकों की पूंजी से घटाया गया।

बैंकिंग के किताब में ब्याज दर जोखिम के लिये दो प्रकार के दृष्टिकोण पर विचार किया गया: (1) आय संबंधी दृष्टिकोण, जो भारतीय रुपये के यिल्ड कर्व में अंतरण के कारण बैंकों की आमदनी को प्रभावित करता है और (2) अवधि अंतर विश्लेषण जो मूल्य निर्धारण के प्रभाव (पोर्टफोलियो हानि) की गणना करता है। ब्याज युक्त ऋण अंतर पर आय हानियों की गणना अलग से प्रत्येक समय सीमा हेतु एक वर्ष के लिये की गयी ताकि चालू वर्ष के लाभ-हानि और आय विवरणी पर प्रभाव परिलक्षित हो। प्रत्येक समय श्रेणी के लिए ब्याज धारित करने संबंधी ऋण जोखिम अंतराल पर संविभाग हानि की गणना ड्यूरेशन गैप (आवधिक अंतराल) विश्लेषण प्रणाली के जरिए की जाती है। बैंकिंग बहियों पर इसके कुल(निवल) प्रभाव का आकलन आय संबंधी हानियों/लाभों और संविभाग हानियों/लाभों[1] को जोड़कर किया जाता है और इससे प्रभावित होनेवाले सीआरएआर को जानने के लिए परिणामी हानियों/लाभों का प्रयोग किया जाता था। इन परीक्षणों के लिए मूल्यांकन प्रभाव को इस पूर्वधारणा के तहत परिकलित किया जाता था कि एचटीएम (परिपक्वता तक धारित) संविभाग को बाजार पर चिह्नित किया जाएगा। व्यापारिक बहियों में होनेवाले ब्याज दर संबंधी उतार-चढ़ाव के संबंध में प्रत्येक समय श्रेणी के लिए ब्याज धारित करने संबंधी ऋण जोखिम धारित आस्तियों के लिए मूल्यांकन हानियों को ड्यूरेशन अप्रोच (आवधिक प्रणाली) का प्रयोग करते हुए परिकलित किया जाता है।

नकदी जोखिम

किसी भी बाहरी नकदी स्रोत की सहायता लिए बिना अप्रत्याशित नकदी हानि की स्थिति का दृढ़ता से सामना करने की किसी बैंक की क्षमता का आकलन करना ही नकदी दबावग्रस्त आस्ति परीक्षण का लक्ष्य है। यह विश्लेषण यथा मार्च - 2012 के अंत में किया जाता है। यह परिदृश्य जमाकर्ताओं द्वारा अचानक विश्वास खो देने के कारण उनके द्वारा अप्रत्याशित रूप से जमाओं को आहरित करने (जमाओं के प्रकार के आधार पर) संबंधी भिन्नात्मक अनुपातों के परिदृश्य को प्रस्तुत करता है और बैंक के पास उपलब्ध नकदी आस्तियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करता है।

नकदी आस्तियों की परिभाषा इस प्रकार की जाती है:

1 नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + अंतर बैंक जमाएं + एसएलआर निवेश

2 नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाले निवेश

3. नकदी + अतिरिक्त सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + अतिरिक्त एसएलआर निवेश

4. नकदी + सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाले निवेश

5 नकदी + सीआरआर + 1 माह के भीतर परिपक्व होनेवाली अंतर बैंक जमाएं + अतिरिक्त एसएलआर निवेश

- यह माना जाता है कि नकदी आस्तियों की बिक्री के जरिए बैंक जमाओं के आहरण की इस दबाववाली स्थिति का सामना कर पाएंगे।
- निवेशी की बिक्री उनके बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत हेयर कट (मार्जिन) के अनुसार की जाती है।
- दबाव परीक्षण स्थैतिक माध्यम पर किया जाता है।

बॉटम-अप दबाव परीक्षण

बॉटम-अप संवेदनशीलता विश्लेषण 25 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (उनकी कुल आस्तियों के 75 प्रतिशत) द्वारा निष्पादित किया गया। इन चुने गए बैंकों का एक समान परिदृश्य और दबाव के आकार के सेट के अंतर्गत परीक्षण किया गया। मार्च 2012 डाटा का प्रयोग करते हुए इन परीक्षणों को संपन्न किया गया। प्रत्येक मामले में हानियों की गणना के लिए बैंकों ने अपनी - अपनी प्रणालियां प्रयुक्त की।

शहरी सहकारी बैंक - ऋण जोखिम

मार्च 2012 की समाप्ति को आस्ति संविभागों पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) के ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। दो अलग-अलग परिदृश्यों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का आकलन किया गया। परिकल्पित परिदृश्य इस प्रकार थे:

परिदृश्य I:

- लागू किए गए आघात :सकल निवल अनर्जक परिसंपत्ति में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी।
- अपेक्षित प्रावधानीकरण में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी।
- अतिरिक्त प्रावधानों के द्वारा पूंजी (टियर I एवं II) में कमी।

[1] कुल (निवल) हानियां/ लाभ = आय (हानियां/ लाभ) + संविभाग (हानियां/ लाभ)

परिदृश्य II:

- लागू किए गए आघात: सकल निवल अनर्जक परिसंपत्ति में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी।
- अपेक्षित प्रावधानीकरण में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी।
- अतिरिक्त प्रावधानों के द्वारा पूंजी (टियर I एवं II) में कमी।

1-28 दिनों वाली आवधिक श्रेणी में नकद प्रवाह आधार पर नकदी दबाव परीक्षण को भी निष्पादित किया गया, जहां 1 से 28 दिनों की आवधिक श्रेणी में बहिर्गमन (आउटफ्लो) के 20 प्रतिशत से अधिक के असंतुलन [नकारात्मक अंतराल (नकदी का आगमन नकदी बहिर्गमन से कम होने पर)] को दबाव की स्थिति माना गया।

परिदृश्य I: 1-28 दिनोंवाली आवधिक श्रेणी में नकदी बहिर्गमन (आउटफ्लो) में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी (नकदी आगमन में कोई परिवर्तन नहीं)

परिदृश्य II: 1-28 दिनोंवाली आवधिक श्रेणी में नकदी बहिर्गमन (आउटफ्लो) में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी (नकदी आगमन में कोई परिवर्तन नहीं)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनडी-एसआई) - ऋण जोखिम

यथा दिसंबर 2011 को समाप्त अवधि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमाएं नहीं लेनेवाली और सर्वांगी महत्वपूर्ण) पर उनकी आस्ति संविभाग का प्रयोग करते हुए ऋण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षण निष्पादित किया गया। ये परीक्षण एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। दो अलग-अलग परिदृश्यों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव के आकलन किया गया। परिकल्पित परिदृश्य में मौजूदा निवल अनर्जक परिसंपत्तियों में 200 से 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी मानी गई। निवल अनर्जक परिसंपत्ति में परिकल्पित बढ़ोतरी अवमानक, संदिग्ध और हानिकर श्रेणियों में उसी अनुपात में आबंटित की गई, जिस अनुपात में ये मौजूदा निवल अनर्जक परिसंपत्तियों में हैं। अतिरिक्त प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी की स्थिति से समायोजित किया गया। वैयक्तिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ-साथ कुल स्तर पर इस दबाव परीक्षण को निष्पादित किया गया।

प्रणालीगत नकदी सूचकांक (एसएलआई)

एसएलआई बाजार के विभिन्न उपखंडों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निम्नलिखित चार संकेतकों का प्रयोग करता है :

1. भारित औसत मांग दर - भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर
2. 3 माहवाले वाणिज्यिक पत्र (सीपी) की दर - 3 माहवाले जमाप्रमाणपत्र (सीडी) दर
3. 3 माहवाले जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दर - 3 माह की अंतर्निहित जमा दर
4. भारित औसत मांग दर - 3 माहवाले ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) दर

प्रणालीगत नकदी सूचकांक (एसएलआई) सृजित करने के लिए, अंतर-बराबर या मानक सामान्य रुपांतरण प्रयुक्त किया गया।

समष्टिगत दबाव परीक्षण

बैंकों के आघात सहन करने की क्षमता का आकलन करने के लिए समष्टिगत आर्थिक चरों की कार्यप्रणाली के तौर पर ऋण जोखिम का मॉडल बनाया गया। ऋण जोखिम दबाव परीक्षणों की गणना बैंकिंग प्रणाली की कुल राशियों को समष्टिगत आर्थिक चरों से संबद्ध करनेवाले अनेक आर्थिक मॉडलों का उपयोग करते हुए की गई है, जैसे (i) कुल प्रणाली के एनपीए डाटा पर मल्टीवैरिएट लॉगिट रिग्रेशन; (ii) स्लिपेज अनुपात (नयी निवल अनर्जक परिसंपत्तियों का आगमन) के संदर्भ में मल्टीवैरिएट रिग्रेशन; (iii) स्लिपेज अनुपात का उपयोग करते हुए कुल वीएआर;(iv) स्लिपेज अनुपात का क्वान्टाईल रिग्रेशन, (v) बैंक-समूह वार स्लिपेज अनुपात डाटा पर मल्टीवैरिएट पैनल रिग्रेशन; और (vi) कुल क्षेत्रपरक निवल अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए मल्टीवैरिएट रिग्रेशन। बैंकिंग प्रणाली की कुल राशियों में शामिल हैं- मौजूदा और पहले की कुल निवल अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए अनुपात) और नये एनपीए का आगमन, जबकि समष्टिगत चरों में शामिल हैं-सकल घरेलू उत्पाद का विकास, अल्पकालीन ब्याज दर (मांग दर), थोकमूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति निर्यात का अनुपात, $\left(\frac{Ex}{GDP}\right)$, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सकल राजकोषीय घाटा $\left(\frac{GFD}{GDP}\right)$ और आरईईआर।

एक ओर जहां मल्टीवैरिएट रिग्रेसन बैंकिंग प्रणाली के एनपीए और पूंजी पर चुनिंदा समष्टिगत चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, वहीं वीएआर मॉडल बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव की स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है, जिसके तहत फीड-बैक प्रभाव

को भी शामिल किया जाता है। इन पद्धतियों में, एनपीए/स्लीपेज अनुपात के कंडिशनल माध्य का आकलन किया जाता है और यह माना गया कि ऋण की गुणवत्ता पर समष्टिगत चर वस्तुओं का प्रभाव समान रहेगा, चाहे ऋण गुणवत्ता का स्तर कुछ भी हो जो हमेशा सही नहीं हो सकता है। इस अनुमान को सहज बनाने के लिए ऋण की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वांटाइल रिग्रेशन को अपनाया गया है जिसमें कंडिशनल माध्य की जगह कंडिशनल क्वांटाइल का अनुमान लगाया गया है।

मॉडलिंग ढांचा

एग्रिगेट एनपीए (npa) / स्लिपेज अनुपात (SR) पर समष्टिगत अर्थव्यवस्था के आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मल्टीवेरिएट मॉडलों को चलाया गया: [1]

- एग्रीगेट बैंकिंग प्रणाली मल्टीवेरिएट लॉगिट[2] रिग्रेशन:

$$logit_npa_t = \alpha_1 + \beta_1\, logit_npa_{t-1} - \beta_2\, \Delta GDP_{t-2} + \beta_3\, call_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-2}$$

जहाँ $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ और $\beta_4 > 0$.

- एग्रीगेट बैंकिंग प्रणाली मल्टीवेरिएट रिग्रेशन

संपूर्ण वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली एक मान कर एग्रिगेट स्तर पर स्लीपेज अनुपात के आधार पर विश्लेषण किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1\, SR_{t-1} - \beta_2\, \Delta GDP_{t-2} + \beta_3\, Call_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 \Delta WPI_t + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-1}$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ and $\beta_6 > 0$.

- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर):

समष्टिगत अर्थव्यवस्था के विभिन्न आघातों पर बैंकिंग आघात सहनीयता का अनुमान लगाने के लिए वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर)[3] दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वीएआर मॉडल का लाभ यह है कि इससे समष्टिगत अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली चर वस्तुओं और बैंक की स्थिरता चरों के बीच पारस्परिक प्रभाव पूरी तरह अभिग्रहित होते हैं। यह आवश्यक फीडबैक प्रभाव को भी अभिग्रहित करता है।

अनुमानिक रूप में, आर्डर p (VAR(p)) के माध्य-आधारित वीएआर को इस तरह से लिखा जा सकता है

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \ldots\ldots + A_p y_{t-p} + u_t \quad ; t=0,1,2,3,\ldots.$$

जहाँ $y_t = (y_{1t},\ldots\ldots,y_{Kt})'$ t समय में चर वस्तुओं का वेक्टर $(K\times 1)$ है, A_i (i=1,2,…p) स्थायी $(K\times K)$ गुणांक मेट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t},\ldots\ldots,u_{Kt})'$ आयामीय व्हाइट नॉयस या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

अनुमान लगाने के लिए वीएआर प्रणाली, स्लिपेज अनुपात, कॉल दर, मुद्रास्फीति और आरईईआर चुने गए, इसके बावजूद, सीमित डाटा बिन्दुओं के कारण वैश्विक वित्तीय डाटा (जीएफडी) पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) नहीं लिया जा सका। वीएआर का उचित क्रम न्यूनतम सूचना अर्हता के साथ-साथ दूसरे निदानों के आधार पर चुने गए हैं और उपयुक्त क्रम दो पाए गए। तद्नुसार, क्रम 2 (वीएआर 2) के वीएआर का अनुमान लगाया गया था और एआर विशेषता वाले बहुपदी के घनमूल के आधार पर मॉडल के स्थिरता की जांच की गई थी। चूंकि सभी घनमूल इकाई परिधि के भीतर पाए गए इसलिए चुना गया मॉडल स्थिरता स्थिति को पूरा करने वाला पाया गया था। चुने गए वीएआर के आवेग प्रतिक्रिया प्रकार्य का उपयोग करते हुए समष्टिगत अर्थव्यवस्था के विभिन्न आघातों का प्रभाव को निर्धारित किया गया था।

---

[1] स्लिपेज अनुपात, निर्यात/जीडीपी, और कॉल दर अपेक्षित अवधि के अनुसार समायोजित किए गए।

[2] मॉडल के विस्तृत विनिर्देशों के लिए, कृपया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट -दिसंबर 2010 देखें। एनपीए के लॉगिट रूपांतरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$Logit_npa_t = L(NPA_t) = Ln\left(\frac{NPA_t}{1-NPA_t}\right)$$

[3] वीएआर मॉडल के विस्तृत विनिर्देशों के लिए, कृपया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जून 2010 देखें।

- क्वांटाइल रिग्रेशन:

  कंडिशनल क्वांटाइल के वांछित स्तर पर स्लीपेज अनुपात का अनुमान लगाने के लिए, 0.60 क्वांटाइल (जो स्लीपेज अनुपात का मौजूदा क्वांटाइल है) पर निम्नलिखित क्वांटाइल रिग्रेशन का उपयोग किया गया था:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 Call_{t-4} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \Delta WPI_t + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-1}$$

  जहाँ $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ और $\beta_6 > 0.$

- बैंक समूह वार पैनल फिक्स्ड-इफेक्ट रिग्रेशन:

  बैंक समूह वार पैनल रिग्रेशन को मॉडल बनाया गया जिसमें स्लिपेज अनुपात को समष्टि अर्थशास्त्रमूलक चर वस्तुओं के प्रकार्यों के रूप में विचार किया गया था। समग्र मॉडल विनिर्देशनों के साथ बैंक समूह प्रभाव की पहचान की गई।

$$SR_{it} = \alpha_i + \beta_1 SR_{i(t-1)} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 Call_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-1}$$

  जहाँ α_i बैंक समूह निर्दिष्ट मानदंड है और $\alpha_i, \beta_1, \beta_2, \beta_3,$ और $\beta_4 > 0$

- सेक्टोरल मल्टीवेरिएट रिग्रेशन:

  विभिन्न सेक्टरों पर समष्टि अर्थशास्त्रमूलक आघातों के प्रभाव का मूल्यांकन मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडलों के द्वारा किया गया था जिसमें प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग एग्रीगेट एनपीए अनुपात का इस्तेमाल किया गया। आश्रित चरों में लैग्ड एनपीए, सेक्टोरल जीडीपी ग्रोथ, मुद्रास्फीति और छोटी अवधि के ब्याज दर शामिल हैं।

स्लीपेज अनुपातों से एनपीए और सीआरएआर का विचलन, जिसका अनुमान ऊपर उल्लिखित ऋण जोखिम इकोनोमेट्रिक्स मॉडलों से लगाया गया था, निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे: 17 प्रतिशत का क्रेडिट ग्रोथ; 5 प्रतिशत की वसूली दर; 3.5 प्रतिशत पर बट्टे खाते में डालना; 18 प्रतिशत का जोखिम भारित परिसंपत्ति ग्रोथ; और 10 प्रतिशत का लाभ ग्रोथ। आय का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित खाते में अनिवार्यत: अंतरित करने का अनुमान लगाते हुए विनियामक पूँजी विकास के न्यूनतम रहने का अनुमान है। एनपीए के वर्तमान स्टॉक के प्रचलन के अनुसार विभिन्न उप-श्रेणियों में नए एनपीए का वितरण किया गया था। अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, मानक अग्रिमों के लिए 0.4 प्रतिशत, अवमानक अग्रिमों के लिए 10 प्रतिशत, संदिग्ध अग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत और हानि वाले अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत। अनर्जक अग्रिमों के अनुपात का अनुमानित मूल्य ''तुलनपत्र दृष्टिकोण'' का उपयोग करते हुए पूँजी अनुपातों में रूपांतरित हुए जिसके द्वारा प्रावधानों और निवल लाभों के द्वारा तुलनपत्र में पूँजी प्रभावित होती है। यह माना गया है कि मौजूदा ऋण प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात भविष्य के प्रभाव के लिए नियत रहेगा।